छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **पंचम सत्र**

बुधवार, दिनांक 05 मार्च, 2025
(फाल्गुन 14, शक सम्वत् 1946)

[अंक 07]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 05 मार्च, 2025

(फाल्गुन 14, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[मंगलवार दिनांक 25 फरवरी, 2025 की प्रश्नोत्तरी सूची का स्थगित ता.प्र.सं.- 3. (*क्र. 226)]

प्रदेश में भारतमाला परियोजना के प्रभावितों को मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

3. (*क्र. 226) डॉ. चरण दास महंत : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** भारतमाला परियोजना हेतु जिला रायपुर, बिलासपुर एवं कोरबा में अर्जित निजी, शासकीय एवं वनभूमि के भू-स्वामी का नाम, खसरा नंबर, रकबा, सिंचित, असिंचित सहित तहसीलवार विवरण दें? मुआवजे की दरें क्या हैं? तीनों प्रकार की भूमि में कितने-कितने पेड़ों की कटाई हो रही है ? इस हेतु मुआवजा की दरें क्या है? कितनी राशि जमा की गई है? **(ख)** कितने भू-स्वामियों और शासकीय भूमि का मुआवजा वितरण कर दिया गया है? कितना वितरण किया जाना शेष है? वितरण में विलम्ब का कारण क्या है ? **(ग)** क्या रायपुर जिले के ग्राम नायक बांधा में किसानों के 32 खाते को 247 छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर मुआवजा का निर्धारण एवं वितरण किया गया है? कलेक्टर रायपुर द्वारा संस्थित जांच का निष्कर्ष तथा लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही का विवरण बताएं? **(घ)** कार्य एजेंसी का नाम, पता, अनुबंध की तिथि, लागत राशि तथा कार्य पूर्णता अवधि भी बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। **(ख)** शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है। **(ग)** कलेक्टर, रायपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 26.04.2024 जांच प्रतिवेदन (की प्रति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" भाग के साथ) के अनुसार ग्राम नायकबांधा में 13 मूल खसरों को 53 छोटे-छोटे भू-खण्डों में बटांकन करके मुआवजा वितरण किये जाने का लेख किया गया है। कलेक्टर द्वारा गठित जांच दल से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भूमि अर्जन हेतु प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत क्रय-विक्रय के प्रकरणों को शामिल किए जाने तथा पूर्व दिनांक के फर्जी नामांतरण प्रकरण तैयार कर मुआवजा स्वीकृत किए जाने से शासन को आर्थिक क्षति होना

प्रतिवेदित किया गया है। जिला कलेक्टर से प्राप्त जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए विभाग द्वारा श्री लखेश्वर प्रसाद किरण तत्कालीन नायब तहसीलदार गोबरा नवापारा, श्री जितेन्द्र साहू तत्कालीन हल्का पटवारी क्र. 49 नायकबांधा, श्री दिनेश पटेल, वर्तमान पटवारी हल्का 49 नायकाबांधा, श्री लेखराम देवांगन तत्कालीन हल्का पटवारी 24 टोकरो, निलंबित किया गया है। शेष व्यक्तियों श्री निर्भय साहू, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम अधिकारी (भू-अर्जन), श्री शशिकांत कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर, तत्कालीन तहसीलदार अभनपुर के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। **(घ)** शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स" अनुसार है।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपको प्रणाम करता हूं। वैसे तो रोज ही करते हैं, मगर आज स्पेशल प्रणाम कर रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, पहले आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि प्रणाम क्या होता है, स्पेशल प्रणाम क्या होता है? स्पेशल प्रणाम किन कारणों से कर रहे हैं?

डॉ. चरणदास महंत :- कर रहा हूं न, बता रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्नकाल चल रहा है, इसलिए आपको उसको साबित करना पड़ेगा।

डॉ. चरणदास महंत :- सर, आपकी कृपा से मुझे ये जानकारी अभी साढ़े 10 बजे मिल रही है। सर, इधर देखिए न। ये मेरे प्रश्न के उत्तर जो आपकी कृपा से आज स्थानांतरित किया गया है। साढ़े 10 बजे जवाब मेरे कक्ष में दिया गया। इसको हम कैसे पढ़कर समझेंगे और प्रश्न करेंगे? तो मैं आपसे इसमें दूसरी व्यवस्था चाहता हूं। आपकी कृपा कैसे मुझ पर बरसती है, आज वह देखना है हुजूर कि मुझे करना क्या है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में चूंकि व्यवस्था का प्रश्न होता नहीं है, लेकिन यदि विधान सभा की दृष्टि से देखा जाए तो विधान सभा के अंदर में किसी भी माननीय सदस्य को जानकारी दी जाती है तो ये विधान सभा की दृष्टि से उचित नहीं है, चाहे किसी भी पक्ष के द्वारा दी जाए और इसलिए इसमें व्यवस्था तो आप देंगे, लेकिन जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है, वह सही कहा है, विधानसभा के लिए यह उचित नहीं है। आपने एक हफ्ता पहले इस बात का निर्देश दिया था।

अध्यक्ष महोदय :- आज मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके विभाग के प्रश्नोत्तर हेतु श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री जी को को अधिकृत किया है। आप बैठिए, मैं व्यवस्था देता हूं।

अध्यक्षीय निर्देश

शासन के समस्त विभागों द्वारा विधान सभा के संबंधित प्रश्नों के उत्तर सर्वोच्च प्राथमिकता पर छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 46 (1) की अपेक्षा अनुसार निर्धारित समय पर देना सुनिश्चित करना ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2025 को राजस्व विभाग से संबंधित विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्रमांक 226) का उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त प्रश्न को विभाग के प्रश्नों से संबंधित आगामी तिथि के प्रथम प्रश्न के रूप में लिये जाने का निर्देश दिए गए थे। परंतु राजस्व विभाग से उक्त प्रश्न का उत्तर आज सभा की बैठक के पूर्व प्राप्त हुआ है, जो अत्यंत खेदजनक है। मैं संसदीय कार्य मंत्री को निर्देशित करता हूं कि सभी विभागों को सूचित करें कि शासन के समस्त विभाग विधान सभा के संबंधित प्रश्नों के उत्तर सर्वोच्च प्राथमिकता पर छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 46 (1) की अपेक्षा अनुसार निर्धारित समय पर देना सुनिश्चित करें। अब यदि आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो इसको आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो फिर उसकी अलग व्यवस्था दूंगा।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

डॉ. चरणदास महंत :- सर, मैं तो इसको देख ही नहीं पाया हूं न। इतने सारे पेज हैं। आप कम से कम एक हफ्ते का और समय दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- अगले हफ्ते के प्रथम प्रश्न में या जो अवसर मिलेगा..।

डॉ. चरणदास महंत :- या तो इसमें हमें आधे घंटे की चर्चा दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- अगले सप्ताह पहले प्रश्न के रूप में ले लिया जाएगा ताकि आपको पर्याप्त समय मिले।

डॉ चरणदास महंत :- ठीक है। उसके पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं..।

अध्यक्ष महोदय :- अब इसमें नहीं होगा।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं, इसमें नहीं बोल रहा हूं। मेरे उत्तर आने के पहले विभाग द्वारा अखबार को चला जाता है कि इसको सस्पेंड कर दिए, इसकी जांच कर दिए। तो इस तरह से बातें न हों..।

अध्यक्ष महोदय :- वह अगले प्रश्न में जब आएगा तो आप इस विषय को उठा लीजिएगा। अगले हफ्ते इसे कर लेंगे। श्रीमती संगीता सिन्हा, प्रश्न संख्या 01.

केज कल्चर के लिए स्वीकृत अनुदान राशि में की गई अनियमितता

[मछली पालन]

1. (*क्र. 1196) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बालोद जिला के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 जनवरी, 2025 तक मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिले के किन-किन जलाशयों में, कितने-कितने यूनिट केज कल्चर की किन-किन मछुआ समितियों के नाम से स्वीकृति प्रदान कर, कितनी-कितनी अनुदान की राशि जारी की गई है? वर्षवार विवरण देवें? **(ख)** कण्डिका 'क' के स्वीकृत अनुदान राशि में अनियमितता के संबंध में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई या मामला संज्ञान में आया? शिकायत की जॉच किस स्तर के अधिकारियों द्वारा की गयी? जॉच में कितनी राशि की अनियमितता पायी गई एवं इसके लिए किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा विभाग द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है? जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) बालोद जिला अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि तक मछली पालन विभाग द्वारा किसी भी मछुआ समितियों को केज कल्चर इकाई में मछली पालन की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। अतः जानकारी निरंक है। **(ख)** कण्डिका 'क' की जानकारी निरंक होने से प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आज बहुत खुश थी कि आज मुख्यमंत्री जी से मेरा प्रश्न है तो मुख्यमंत्री जी से उत्तर मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आपको पूरा उत्तर मिलेगा।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- मेरे उत्तर देने से खुशी नहीं हो रही है क्या? (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न था और मुख्यमंत्री जी ने उत्तर में दिया है कि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 यानी लगभग चार वर्षों तक बालोद जिले में किसी मछुआ समिति को केज आवंटित नहीं किया गया है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रश्न है कि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025 तक बालोद जिले में कुल कितने केज कल्चर को स्वीकृति प्रदान की गई है और केज कल्चर की स्वीकृति हेतु क्या-क्या प्राथमिकताएं दिए जाने का प्रावधान है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- अध्यक्ष महोदय, बालोद जिले में सन् 2021-22 से 31 जनवरी, 2025 तक 39 केज कल्चर हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है । जिसके लिए 92 आवेदन प्राप्त हुए थे और 53 अभी लंबित हैं, उन पर प्रक्रिया चल रही है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, केजों का भौतिक सत्यापन किनके द्वारा किया जाता है और इसमें क्या सब्सिडी जारी करने के लिए भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जी हां, अनुदान देने से पहले भौतिक सत्यापन किया जाता है । इसका समय-समय पर मछुआ निरीक्षक या उप संचालक स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है और अभी तक इन 2021-22 से अभी 31 जनवरी तक 7 करोड़, 74 लाख रूपए अनुदान दिया गया है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि क्या जिले में पूर्व के वर्षों में बिना सत्यापन के कोई अनुदान राशि जारी की गई है, ऐसा मामला आया है क्या ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि बिना भौतिक सत्यापन के अनुदान राशि का भुगतान किया गया हो ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह मेरे जिला बालोद का मामला है पूर्व में जो अधिकारी है, उसने अपने रिश्तेदार और अपनी पत्नी के नाम पर केज कल्चर की राशि लिया है और साथ में बिना भौतिक सत्यापन के सब्सिडी जारी कर दी गई, आवंटन कर दिया गया । इस मामले की शिकायत आपको प्राप्त हुई है और आपने जांच भी प्रारंभ कर दी है लेकिन वह जांच कोई अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही जांच की प्रक्रिया बता रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है, जिले का मामला और 6 करोड़ की राशि के गबन का मामला है । मैं, महोदय से निवेदन करती हूं कि आपके पास वह मामला आया है, अधिकारी आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं । कृपा करके आप उसमें कार्यवाही करेंगे । वह अधिकारी जिसने अपने पूरे परिवार के नाम पर केज कल्चर का आवंटन किया है और बिना भौतिक सत्यापन के राशि भी निकाल ली गई है । क्या उस अधिकारी पर उचित कार्रवाई करेंगे, एफआईआर दर्ज करके गबन की राशि, उनसे निकलवाएंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शिकायत की बात कही है, वह शिकायत सही है और उस समय के तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन ने अपनी पत्नी के नाम से 19 लाख 20 हजार रूपए की सब्सिडी आहरित किया है । चूंकि अब वे सेवा निवृत्त हो चुके हैं लेकिन शासन के नियमानुसार निर्देशक संचालनालय द्वारा सेवा निवृत्त तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन के विरूद्ध आरोप पत्र जारी हो गये हैं । 03 मार्च, 2025 को जारी किया जा चुका है और इसमें जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनेगी, उसमें नियमानुसार जांच होगी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है । इसको सिर्फ जांच कर देना ही उचित नहीं है । 6 करोड़ का मामला है जो लोगों को, जनता को प्राप्त होना चाहिए, उनके अधिकार का हनन् हुआ है । ये अधिकारी अगर खुद ही अपने रिश्तेदार और अपनी पत्नियों को काम दिलाने लगें तो जनता का क्या होगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- पत्नियों मतलब ? उस अधिकारी की कई पत्नियां हैं क्या ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पत्नी, पत्नी । अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह घोषणा करवाना चाह रही हूं कि इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और जो शासकीय राशि का गबन हुआ है उसकी आप वसूली करें ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसमें कुंवर सिंह निषाद जी ने शिकायत की थी। इसमें सिर्फ इतना ही है कि सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 की धारा 3 (16) के तहत अगर कोई शासकीय व्यक्ति अपने शासकीय पद पर रहते हुए अपने परिवार के नाम से लाभ नहीं ले सकता। उस नियम के तहत् उस पर जांच भी चल रही है और मैंने बताया कि उसके विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। मामला 19 लाख 20 हजार रूपए का है, 6 करोड़ का गबन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। एक मिनट कुंवर सिंह जी को पूछने दीजिए। आपका जवाब आ गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, एक मिनट। आपने प्रश्न पढ़ा होगा, आप उनकी मंशा समझ रहे हैं, वे किसी एक मामले में जांच चाहते हैं। आप तीन बार उठे तीन बार बैठे, आपने आखिरी में कहा कि उस अधिकारी ने ऐसा किया है। आप उसी को एक बार में बता दीजिए न कि उस अधिकारी ने गड़बड़ की है, जांच करा रहे हैं और उसमें कार्रवाई करेंगे। ये बताईए कि कितने दिन से जांच चल रही है और कार्रवाई क्यों नहीं हुई ? अगर किसी अधिकारी ने 19 लाख रूपए अपनी पत्नी के नाम से निकाल लिया तो कितने दिन से जांच चल रही है, यह घटना कब की है, इसमें कितने समय से जांच चल रही है और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई बताईए?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 01.06.2024 को शिकायत हुई है और शिकायत पर जांच तीन दिन बाद 04.06.2024 को चालू हो गया है। इसमें जांचकर्ता अधिकारी उप संचालक मछली पालन जिला रायपुर के द्वारा जांच भी की गई और जांच प्रतिवेदन 24.07.2024 को पेश भी कर दिया गया है। इसमें बहुत जल्दी ये सब हो रहा है, चूंकि यह शासकीय प्रक्रिया होती है, किसी के उपर ऐसी FIR भी नहीं की जा सकती।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, बिना सत्यापन के किया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बहुत आपत्तिजनक जवाब है। वर्ष 2019 से लेकर 2024 आ गया और उसके बाद आप बोल रहे हैं जल्दी कर रहे हैं। आपने कहा कि वर्ष 2019 में कम्प्लेन दर्ज हुआ और 2024 तक आपके पास रिपोर्ट नहीं आई है। अध्यक्ष महोदय, यह क्या है ?

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, उनको रिटायर होने का मौका दिया गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- वर्ष 2019 से 2024 के मामले में आपको तो कोई तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। यह वर्ष 2019 से 2024 का मामला है। इसमें सख्त कार्रवाई करना चाहिए, घोड़ा थोड़ा तेज दौड़ाना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में आपकी यह भी जानकारी चाहिए कि जिस दिन की यह घटना है और आरोप पत्र उनको रिटायर होने के बाद दिया गया क्या ? आपने उत्तर में कहा कि 2025 में जारी किया गया है। क्या उनके रिटायर होने का इंतजार किया गया ? जब भी ऐसा मामला आता है तो शासन के उत्तरों में कई बार आता है कि अब वह रिटायर हो गया है। क्या ऐसे मामलों में जो पकड़ में आती है तो रिटायर होने का इंतजार किया जाता है ? रिटायर हो जाए तो कोई वसूली कार्रवाई नहीं होगी।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला पिछली सरकार का था, हमारी सरकार होती तो जांच हो जाती।

श्री अजय चंद्राकर :- सरकार से मतलब नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आपत्ति लेती हूं।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय मंत्री जी, यह मामला पिछली सरकार का है तो इसमें कार्रवाई कराईए न। आप कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे हैं ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मामला किसी भी शासनकाल का हो कार्रवाई होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब सुन लीजिए न।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- संगीता जी, 01 जून, 2024 को शिकायत मिलती है और दो दिन बाद हम 04 जून, 2024 को जांच चालू कर देते हैं। इससे तीव्र जांच और क्या हो सकती है। हमने 2 दिन में ही जांच कमेटी गठित करके जांच चालू कर दी।

अध्यक्ष महोदय :- कुंवर जी आप पूछ लीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शिकायत मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सभा में जब मेरे समाज का कार्यक्रम हो रहा था, उसमें 8 महीने पहले दिया था। उसी प्रकरण में राजनांदगांव में तत्कालीन सहायक संचालक के उपर FIR होती है, कार्रवाई हो जाती है, सेम प्रकरण है लेकिन हमारे जिले में जब यही बातें आती हैं तो 8 महीने, 9 महीने, यह 10वां महीना जारी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, न उनके उपर कोई FIR होता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत वह अपने परिवार के नाम से 192 केज कल्चर है, 108 मनीष बंजारे के नाम से है और 148 विद्‌या बंजारे के नाम से है। ऐसा करके वह पूरे परिवार के नाम से केज कल्चर को स्थापित करवाता है और लगभग 3 करोड़ 45 लाख 60 हजार रूपए की सब्सिडी को तत्कालीन सहायक संचालक

आर.के.बंजारे मैंने नाम भी ले लिया। अपने परिवार के नाम से लेता है उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी राशि वसूलनी चाहिए जिन्होंने हमारे जैसे मछुआरे समाज की समिति को रोजी पर रखा है, काम पर रखा है। आज केवल उनका नाम है और सारा संचालन उनके परिवार के द्वारा हो रहा है। मैं इसमें आपसे संज्ञान लेता हूं और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनके उपर FIR होनी चाहिए और वसूली भी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए कड़ी कार्रवाई बता दीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक उनकी पत्नी के नाम से ही शिकायत मिली है लेकिन आप बता रहे हैं कि और कई लोगों के नाम से लाभ लिया है। निश्चित रूप से जो मछुवारा समाज है, उनके हितों की रक्षा करते हुए इसकी विस्तृत जांच की जाए और अगर ऐसा है तो इसमें उनसे जुड़े हुए जो-जो दोषी होंगे उनकी संपत्ति से वसूला भी जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- बोल दिए, पूरा बता दिए। धरमलाल कौशिक जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं संतुष्ट नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी जांच के लिए बोल रहे हैं, और क्या कर लेंगे? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. दर्ज करके उस राशि की वसूली की जाये।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी तो बोल रहे हैं कि जांच करने के बाद जो तथ्य आएंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- अध्यक्ष महोदय, बुल्डोजर चलाया जाए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उनकी जांच पूरी नहीं हुई है। मंत्री जी यह जो जानकारी दे रहे हैं, उसके आधार पर यह उसकी और जांच करायेंगे। मतलब, पहले जो जांच कराई गई, उसका क्या रिजल्ट आ गया? क्या आपकी जांच के बिंदु सीमित थे या आपने इसकी पूरी जांच ही नहीं कराई? आपने सिर्फ उनकी पत्नी का नाम ले लिया।

श्री ओंकार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी विषय में प्रश्न है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, कुंवर सिंह निषाद जी की माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो शिकायत थी, वह उनकी पत्नी विद्या बंजारे के नाम पर थी। लेकिन अभी सदस्य बता रहे हैं कि और भी रिश्तेदारों के नाम पर लिया गया है तो इसकी जांच के दायरे को बढ़ाना होगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी। मनीष बंजारे, विद्या बंजारे, परमजीत, नावेद मिर्जा, उर्वशी। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है। जब जांच होती है तो पूरे बिंदुओं की जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, हम बिल्कुल इसकी जांच कराएंगे। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आपका मतलब है कि जो शिकायत हुई है, उसके आधार पर ही जांच हो जाएगी। आप जांच के बिंदु बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इसी शिकायत के आधार पर राजनांदगांव के सहायक संचालक के ऊपर एफ.आई.आर. हुई थी और कार्रवाई हुई थी।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यदि आप जांच कराते हैं तो सारे बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। जो शिकायत हुई है, क्या आप केवल उसी की जांच कराएंगे? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह कैसे जांच करा रहे हैं? ऐसे में तो आपके जांच अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि उन्होंने सिर्फ पत्नी का नाम लिख दिया तो क्या आप सिर्फ उनकी पत्नी के नाम पर ही जांच कराएंगे? क्या आप बाकी लोगों की जांच नहीं कराएंगे कि उस पूरे एपिसोड में क्या-क्या हुआ? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने उस जांच में क्या-क्या पाया?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी उसकी जांच चल रही है और जांच के आधार पर आरोप पत्र भी दाखिल किये गये हैं। यदि आपको उसकी जांच की विस्तृत रिपोर्ट चाहिए तो हम आपको वह भी उपलब्ध करा देंगे।

श्री उमेश पटेल :- नहीं-नहीं, यह उपलब्ध कराने की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसका पूरा प्रूफ है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दो माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि उन्होंने लगातार उनके परिवार के अलग-अलग लोगों के नाम से यह काम किया है और आप कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी के नाम से यह काम किया है तो आप मुझे यह बता दीजिए कि यदि आपने उसकी जांच कराई है तो आपको जांच में क्या मिला?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 साल से अभी तक उसकी लीज की राशि भी जमा नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच में उसकी पत्नी के नाम से 19 लाख, 20 हजार रूपये सब्सिडी लेना पाया गया है और यदि माननीय सदस्य को इसमें आशंका है। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इस मामले को छिपाने का काम कर रही है। (व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, कोई छिपाने का प्रयास नहीं हो रहा है। उसकी निष्पक्ष जांच की जा रही है और यदि आप जानकारी देंगे। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इसको सिर्फ 19 लाख रूपये का छोटा सा अमाउंट कहना चाह रही है, जबकि हमारे सदस्यों ने कहा है कि उन्होंने अपने परिवार के अलग-अलग लोगों के नाम पर यह काम किया है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सभी की लिस्ट है। 108, 36, 198, 56, 48, 72, इतने लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करने से काम नहीं होगा। आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आपके संरक्षण में यह विधान सभा चलती है। यदि हमारे दो सदस्य इस मामले को उठा रहे हैं तो आप मंत्री जी को निर्देशित करिये कि विभाग इसके सारे बिंदुओं की पूरी और निष्पक्ष तरीके से जांच करें।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप इसकी निष्पक्ष और पूरी जांच कराइये। ठीक है। धरमलाल कौशिक जी।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जी, अध्यक्ष महोदय। मैं इसकी निष्पक्ष और पूरी जांच करवा लूंगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 192 केज कल्चर तो केवल उनके परिवार के नाम से हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, क्या आप इसकी समय-सीमा निर्धारित करेंगे?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच कराकर अगले सदन तक इसका उत्तर लाइयेगा। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप इसकी समय-सीमा निर्धारित करेंगे कि कब तक आप इसकी जांच कराकर देंगे या आपको एक साल का समय लगेगा? आप मुझे इसकी समय-सीमा बता दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, समय नहीं बता सकते हैं। आपका हो गया।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 192 केज कल्चर उनके परिवार के नाम से हैं। (व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको हम जल्द से जल्द करेंगे। जितनी जल्दी हो सके, हम इसकी जांच करायेंगे और इसकी व्यापक जांच करायेंगे। आपकी जो चिंता है, वह सरकार की भी चिंता है। इसलिए हमने इसकी जांच को सुनिश्चित कर लिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- जल्द से जल्द कराएंगे। बहुत हो गया। धरमलाल कौशिक जी। (व्यवधान)

श्री ओंकार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय में मेरा प्रश्न है। आप धमतरी के केज कल्चर को भी ठीक कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसकी जांच के लिए एक समिति गठित कर दीजिये और हम लोगों को भी उस समिति में शामिल कर लीजिए, ताकि उस जांच में हम लोग भी सम्मिलित हो सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। सुन लिये हैं, समझ लिये हैं। धरमलाल कौशिक जी, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री ओंकार साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी विषय केज कल्चर में धमतरी का अनुपूरक प्रश्न है। आप सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। देख लेंगे।

जिला रायपुर, अमलीडीह की शासकीय भूमि का आवंटन में प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

2. (*क्र. 1221) श्री धरमलाल कौशिक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सितम्बर, 2024 की स्थिति में जिला रायपुर के अमलीडीह में कौन-कौन से खसरा क्रमांक की कितनी-कितनी शासकीय भूमि उपलब्ध है? उक्त शासकीय भूमि में से दिनांक 31-01-2025 तक कब-कब, किसके द्वारा, किन-किन को, किन-किन खसरा की, कितनी-कितनी भूमि, कितना बाजार मूल्य की एवं किन-किन प्रायोजनों हेतु, कुल कितनी-कितनी शासकीय भूमि का आवंटन किया गया है? आवंटनवार जानकारी देवें। **(ख)** कंडिका 'क' अनुसार उपलब्ध भूमि के संबंध में वर्ष 2024 में किसके द्वारा, कब एवं क्या-क्या शिकायतें विभाग एवं शासन को की गई हैं? शिकायतवार जानकारी देवें। **(ग)** कंडिका 'ख' अनुसार शिकायतों पर किसके-किसके द्वारा कब-कब जांच की गई एवं जांच उपरांत शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? शिकायतवार जानकारी देवें।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में ग्राम अमलीडीह में उपलब्ध शासकीय भूमि की खसरा वार जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[1] **"अ"** अनुसार है। आबंटित शासकीय भूमि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र "ब"** अनुसार है। **(ख)** कण्डिका ''क'' के अनुसार वर्ष 2024 में मान. श्री मोतीलाल साहू, विधायक, रायपुर ग्रामीण द्वारा श्री लीलाधर चंद्राकर, अध्यक्ष, शाला विकास एवं प्रबंधन समिति, अमलीडीह, जिला रायपुर के पत्र दिनांक 12.09.2024 की प्रति संलग्न कर मान. मुख्यमंत्री जी को दिनांक 13.09.2024 को तथा दिनांक 17.09.2024 को संभागीय आयुक्त, रायपुर संभाग को प्रेषित कर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रामा बिल्डकॉन - भागीदार श्री राजेश अग्रवाल तहसील व जिला रायपुर को आबंटित शासकीय भूमि खसरा नंबर 233/1 व 233/5 रकबा 3.203 हे0 भूमि के आबंटन को तत्काल

[1] परिशिष्ट ''एक''

निरस्त करने की शिकायत करते हुए नवीन शासकीय महाविद्यालय अमलीडीह को आबंटित करने का निवेदन किया है। उक्त के अलावा श्री दीपक कुमार चंद्राकर एवं अन्य निवासी चंद्राकर रेसीडेंस अमलीडीह रायपुर द्वारा खसरा नं. 252 रकबा 0.324 पर अतिक्रमण के संबंध में शिकायत प्राप्त है। **(ग)** कण्डिका "ख" के अनुसार सुनवाई की अधिकारिता संभागीय आयुक्त को होने के कारण शिकायतकर्ता श्री मोतीलाल साहू, विधायक, रायपुर ग्रामीण से प्राप्त शिकायत की जांच संभागीय आयुक्त, रायपुर संभाग से कराई गई। जांच प्रतिवेदन दिनांक 11.12.2024 अनुसार रामा बिल्डकॉन - भागीदार श्री राजेश अग्रवाल तहसील व जिला रायपुर को आबंटित शासकीय भूमि खसरा नंबर 233/1 व 233/5कुल रकबा 3.203 हे. भूमि को निरस्त करने की अनुशंसा/निष्कर्ष के तारतम्य में विभागीय आदेश दिनांक 17.12.2024 द्वारा आवेदक संस्था को दिनांक 28.06.2024 को आबंटित शासकीय भूमि को निरस्त किया गया है। शिकायतकर्ता श्री दीपक कुमार चंद्राकर से प्राप्त पत्र को कलेक्टर, जिला रायपुर को दिनांक 20.11.2024 को मूलतः नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शासकीय जमीन के आवंटन का मामला है। मैं मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह जो आवंटन हुआ तो आवंटन होने के बाद में उसको निरस्त किया गया तो इसको निरस्त करने का क्या कारण है ? मैं यह माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ विधायक ने जानकारी चाही है कि जो भूमि एलाट हुआ था, उसके निरस्त होने के क्या कारण हैं। अमलीडीह में रामा बिल्डकॉन को जमीन आवंटित किया गया था, शासन के पुराने प्रचलित नियम के हिसाब से आवंटित किया गया था। लेकिन जुलाई में शासन की नीति में मंत्रिपरिषद ने बदलाव किया, जिसमें भूमि आवंटन के पुराने नियम थे, उन सभी नियमों को निरस्त कर दिया गया था। चूंकि उनको भूमि पूर्ण रूप से आवंटित नहीं हुआ था, केवल आवंटन की कार्यवाही के लिए सचिव से कलेक्टर को पत्र गया था। आवंटन कई शर्तों के तहत दिया गया था, उसमें मद परिवर्तन कराना है, आदि लेकिन उन्होंने समय-सीमा में मद भी परविर्तित नहीं कराया और इसी बीच मंत्रिपरिषद का निर्णय भी आ गया कि जितने भी भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, सबको निरस्त किया जाता है। उस आदेश के तहत वह निरस्त हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- वह निरस्त हो गया है। चलिये, आगे पूछ लीजिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, निरस्त होने की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आप और क्या चाहते हैं ?

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उनको दोनों खसरा नंबर की जमीन को उस समय के प्रचलित रेट में दिया। उस समय उस जमीन का बाजार रेट क्या था ? कृपया बतायेंगे। उसमें कितना अंतर आ रहा है ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन के निर्धारित दर के हिसाब से जमीन का एलाटमेंट कई शर्तों के तहत दिया जाता था।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मामला यह है कि चराई की जमीन को किसी को एलाट किया ही नहीं जा सकता है। उसके बाद भी जानबूझकर सरकार के द्वारा एलाट किया गया। उनसे 9 करोड़ रूपये की राशि जमा कराया गया और इन्हीं के द्वारा बताया गया है, उसके हिसाब से वह जमीन कम से कम 29 करोड़ रूपया का है नहीं तो उन्हें 56 करोड़ रूपये की राशि पटाना था। उनको मात्र 9 करोड़ रूपये में जमीन आवंटित किया गया। जिस अधिकारी ने उसका प्रतिवेदन बनाया, उसकी सिफारिश की कि उनको दिया जाना चाहिए। आपने निरस्त किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। वर्तमान उस जमीन की क्या स्थिति है ? निरस्त करने के बाद शासकीय रिकार्ड वह जमीन उनके नाम में है या शासन के नाम में दर्ज हो गया है ? दूसरा, जिस अधिकारी ने यह कार्यवाही की, उसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि वह जमीन रामा बिल्डकॉन को आवंटित ही नहीं हुआ है और ना ही उनके द्वारा राशि जमा कराया गया है। वह जमीन आवंटन की प्रक्रिया में था। उन्होंने एक रूपया भी जमा नहीं किया है और ना ही उनको demand letter भेजा गया है। वह जमीन अभी भी शासन के नाम में ही है, किसी के नाम पर हस्तान्तरित नहीं हुआ है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब परिशिष्ट में है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। आप नाम लिए हैं। खसरा नं. 233/1, 233/5 कुल 3.6740 हैक्टेयर घास (च) बंजारा भवन, सब स्टेशन बना है। शेष भूमि रामा बिल्डकॉन को राज्य शासन द्वारा बंटन किया गया है। तो आपने उनके नाम में चढ़ा दिया। यह आपके जवाब में ही है। जब उनका नाम चढ़ा दिए तो मैं पूछ रहा हूं कि आज वह जमीन शासन के नाम में अंकित है या उनके नाम में अंकित है ? उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय :- किसके नाम में अंकित है ? शासन के नाम में अंकित है या नहीं ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन के नाम में ही अंकित है।

अध्यक्ष महोदय :- वही पूछ रहे हैं।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको आवंटित ही नहीं किया गया है। उनके द्वारा पैसा नहीं पटाया गया है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जवाब देख लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- इनका जवाब आ गया।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आवंटन की कार्यवाही कलेक्टर करते हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो इनका जवाब है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पैसा पटाने की बात नहीं आई है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी या तो आप परिशिष्ट को पढ़ लीजिये और आप यह बोलिये में मैंने गलत जवाब दिया है। आप उसको स्वीकार कीजिये।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका निर्धारण किया था।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह स्वीकार कीजिये कि मैं असत्य जानकारी दे रहा हूं।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं, जानकारी गलत नहीं दिया है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रश्न नहीं करूंगा, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। यह जवाब मंत्री जी का है। अभी बोल रहे हैं, वह ठीक है या अभी जो जानकारी दिया गया है, वह ठीक है। मंत्री जी इस बात को बतायें ?

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा ना तो राशि जमा कराया गया है और ना ही उनको जमीन एलाट किया गया है। अभी भी शासन के नाम में दर्ज है। उस जमीन एलाटमेंट की प्रक्रिया को शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप परिशिष्ट देख लीजिये। आप परिशिष्ट-एक में पृष्ठ क्रमांक-2 को देख लीजिये। मैं मंत्री जी से केवल यह जानना चाह रहा हूं कि आपने जो लिखकर दिया है, वह ठीक है या अभी आप जो बोल रहे हैं, वह ठीक है ? इसमें कौन सा असत्य है ? आप इसका जवाब दीजिये।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राशि पटाया जाता है तब इनका आवंटन कलेक्टर के द्वारा होता है। कलेक्टर द्वारा न ही वह राशि लिया गया है न ही सम्बन्धित पक्ष के द्वारा राशि पटाया गया है। इनके आवंटन के आदेश को ही शासन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वह जमीन अभी भी शासन के नाम में है, रामा बिल्डकॉन के नाम से नहीं है। आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन इसी बीच मंत्रिपरिषद् का निर्णय आया कि शासन के पुराने प्रचलित नियम हैं, उनको निरस्त किया जाता है। चूंकि वह जमीन कई शर्तों के अधीन दिया गया था, आप मद परिवर्तन करवायें इत्यादि, लेकिन उन्होंने वह कार्य नहीं किया था। इसलिए वह निरस्त हो गया है। भूमि अभी शासन के नाम में ही है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय मंत्री जी, आपने निरस्त किया है, यह मैं नहीं पूछ रहा हूं। आपने पहले क्यों निरस्त किया, यह आपने बता दिया है कि इस कारण से निरस्त किया है। आप कह

रहे हैं कि आवंटन नहीं किया गया। मैं आपको पढ़ कर बता देता हूं। मैंने एक बार पढ़ कर बता दिया है। अब आप थोड़ा सा सुन लीजिये। घांस (च) चराई भूमि, बंजारा भवन, सब-स्टेशन बना है, शेष भूमि रामा बिल्डकॉन को राज्य शासन के द्वारा बंटन किया गया है। दूसरा, आप यह कह रहे हैं कि पहले पैसा पटाएगा फिर बंटन किया जाएगा। ऐसा नहीं होता है, बल्कि बंटन पहले किया जाएगा, फिर उसके आधार पर उसको पैसा पटाया जाएगा। यही आदेश होता है। अभी आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? आप उसको सुनिश्चित करिये। यह परिशिष्ट-एक में लिखा है। आप इसको पढ़ लीजिये।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस भूमि के आवंटन हेतु कलेक्टर के द्वारा उसको डिमांड लेटर दिया ही नहीं गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर के द्वारा, कमिश्नर के द्वारा या एस.डी.एम. के द्वारा आवंटन किया होगा, उससे मतलब नहीं है। गलत आवंटन किया, उसको आपने स्वीकार किया। गलत आवंटन होने के बाद आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे?

श्री टंक राम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आवंटन की प्रक्रिया में कहीं पर कोई गलती नहीं हुई है। जो प्रचलित नियम है, उसके अनुसार आवंटन किया गया था।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। मंत्री जी का जवाब आ गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्नोत्तरी के परिशिष्ट -एक में लिखा गया है। यह मंत्री जी का जवाब है और मंत्री जी के जवाब में यह लिखा गया है इसलिए मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो आवंटन किया, उसको गलत तरीके से आवंटित किया गया है। जिस अधिकारी ने आवंटित किया है, उन्होंने सरकार को अंधरे में रखकर आवंटित किया है। क्या आप उस अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? सरकार की जमीन है तो क्या वह अफरा-तफरी करेंगे? क्या 56 करोड़ रूपये की जमीन को 9 करोड़ रूपये में दे देंगे? इस प्रकार का सिर्फ एक मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। मंत्री जी, प्रक्रिया में जो भी गलती होगी, उसकी आप जांच करा कर जो दोषी होगा, उसके ऊपर कार्रवाई कर लीजिये।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आवंटन की प्रक्रिया में कहीं कोई अनियमितता नहीं की गई है। आवंटन की प्रक्रिया के तहत् भूमि आवंटित की गई है। यह आवंटन पहली बार नहीं किया गया है। शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले भी मध्य प्रदेश के समय से समय-समय में आवंटन किया है और प्रक्रिया के तहत ही आवंटन किया है। शासन के जो प्रचलित नियम है, उसी के तहत यह आवंटन की कार्यवाही की गई थी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत प्रश्न हो गये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मामला यह है कि शासकीय भूमि की अफरा-तफरी हो रही है। कौन व्यक्ति है, कौन संस्था है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब, क्या शासकीय भूमि को कितने भी पैसे में किसी के भी नाम में में चढ़ा देंगे, जब चाहेंगे तब उसको निरस्त कर देंगे? मैं आपसे दूसरी बात यह कहता हूं कि जो संशोधन की बात करते हैं। मान लीजिये कि आज किसी को जमीन दिया है, यदि कल आपका नियम में परिवर्तन होगा तो क्या आप कॉलेज की जमीन को निरस्त कर देंगे? आप उसको निरस्त नहीं कर सकते हैं। आपने एक बार आवंटित किया है तो नियम के तहत आवंटिन किया है। आप बाद में संशोधन करेंगे तो संशोधन का नियम बाद में लागू होगा। वह नियम पहले लागू नहीं होगा। नहीं तो वैसे में सरकार ने जितनी जमीनें आवंटित की है, वे सारी जमीनें ध्वस्त हो जायेंगी कि नियम में परिवर्तन हो गया। इसलिए आपको सबको निरस्त करना पड़ेगा। मंत्री जी, वह गलत तरीके से असत्य जानकारी दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस प्रकार से सरकारी जमीन का [xx] हुआ है, यह एक प्रकरण नहीं है। मैं ऐसे अनेक प्रकरण लाकर दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो जवाबदार अधिकारी हैं, उसके खिलाफ मंत्री जी पूरी जांच करायें। जांच कराने के बाद उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे और कितने दिन में कार्रवाई करेंगे, यह सुनिश्चित करें।

श्री मोतीलाल साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। इस विषय में मैंने ही संज्ञान में लेकर आवेदन दिया था कि उपरोक्त जमीन का कॉलेज निर्माण के लिए आवश्यकता है। इस हेतु माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क भी किया गया। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि इनको निरस्तीकरण किया गया, लेकिन दिक्कत इस बात है कि अभी माननीय वरिष्ठ सदस्य भी प्रश्न रख रहे थे कि इस प्रश्नोत्तरी के परिशिष्ट-एक के पेज क्र. 2 में उल्लेख किया गया कि उनके नाम में ऐसा जमीन दर्ज है। एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको आवंटित हीं नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि उसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज है। यह कैसे संभव है?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ विधायक कह रहे थे कि इस आदेश के तहत पूर्व के जो आवंटन आदेश कैसे निरस्त हो जायेंगे? मैं बताना चाहूंगा कि पुरानी सरकार में वर्ष 2019, 2020 एवं 2022 में शासकीय भूमि का आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, भूमि स्वामी हक प्रदान करने संबंधी निर्देश परिपत्र जारी किया गया था। राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि का आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, भूमि स्वामी हक प्रदान करने संबंधी पूर्व में जारी संदर्भित निर्देश प्रपत्रों को निरस्त किया जाता है और एक चीज और बताना चाहूँगा कि इस बीच में जितने प्रकियाधीन थे, किसी का पैसा भी पट गया था, उसका भी आदेश निरस्त किये हैं, कई प्रकरण ऐसे भी हैं कि उसके पैसे को लौटाया गया है । यह आदेश प्रभावशील हो गया है, वह भी आदेश इसी के तहत निरस्त हुआ है ।

प्रश्न संख्या : 3 XX XX

प्रश्न संख्या : 4 XX XX

इंदिरा निकुंज माना रोपणी में संचालित श्री कुंवारा देव महिला स्व सहायता समूह के कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

5. (*क्र. 1254) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या इंदिरा निकुंज माना रोपणी, वन मंडल रायपुर में श्री कुंवारा देव महिला स्व सहायता समूह संचालित है? क्या इस स्व सहायता समूह के सचिव का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, विवरण दे? **(ख)** उक्त स्व सहायता समूह कब से संचालित है तथा उसके द्वारा रोपणी परिसर में क्या-क्या कार्य किया जाता है तथा उसका कारोबार (टर्न ओव्हर) वर्ष 2021-22 से 2024-25 (जनवरी 2025 तक) तक कितना-कितना रहा है? वर्षवार बताएं? **(ग)** इस स्व सहायता समूह का औचित्य क्या है, किसकी सहमति या अनुमति से इसे गठित किया गया? क्या इस स्वसहायता समूह के कार्यों का निरीक्षण तथा ऑडिट प्रश्नांश 'ख' अवधि में हुआ है? यदि हुआ है तो विवरण दें?

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) इंदिरा निकुंज माना रोपणी, वन वनमंडल रायपुर में श्री कुंवारा देव महिला स्व सहायता समूह संचालित नहीं है। महिला स्व सहायता समूह के विषय में किये गये प्रश्नांक "क" की जानकारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ख)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वन मंडल रायपुर में श्री कुंवारादेव महिला स्व-सहायता समूह संचालित नहीं है । इसी आधार पर प्रश्न के सभी भागों के उत्तर के लिये यह बताया गया है कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूँगी कि माननीय मंत्री जी का उत्तर पूरी तरह से असत्य है । मेरे पास इस बात का पर्याप्त शासकीय दस्तावेज है, जिससे प्रमाणित होता है कि श्री कुंवारादेव महिला स्व-सहायता समूह इंदिरा निकुंज माना रोपणी वन मंडल, रायपुर में संचालित है और शासकीय रोपणी के भवन और भूमि में है तथा वन विभाग का एक फारेस्ट गार्ड संस्था का सचिव भी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं दस्तावेज प्रस्तुत करूँ ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न करिये । दस्तावेज तो बाद में देंगे ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस दस्तावेज के अवलोकन के बाद क्या जवाब देंगे, मैं उनका जवाब जानना चाहूँगी ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जवाब दे दीजिए ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सदस्य को जानकारी उपलब्ध कराई है और विभाग ने जो जानकारी दी है, उसके आधार पर वर्तमान में या पूर्व में भी वहां पर हमारे स्व-सहायता समूह के माध्यम से इस तरह की योजना संचालित नहीं है और आप जो कह रहे हैं तो उसका दस्तावेज दीजिए, उसमें जानकारी लेकर आपको उपलब्ध करवाऊँगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप जानकारी दे देंगे तो उसकी जांच करवा लेंगे । आप दस्तावेज दे देंगे । कोई और प्रश्न ?

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला समूह की आड़ में प्रतिवर्ष 50 लाख से 1 करोड़ तक के घोटाले वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी करते हैं । इस दस्तावेज में महिला समूह के खाते भी हैं और आडिट भी होता है, यह तथ्य वन मंडल डी.एफ.ओ. के संज्ञान में है । अध्यक्ष महोदय, मैं सारे दस्तावेज माननीय मंत्री जी को भेज रही हूँ, माननीय मंत्री जी इसमें दस्तावेज का ही अवलोकन कर लें, उसके बाद बतायें ?

अध्यक्ष महोदय :- आप दस्तावेज भेज दें, वह जॉच करा लेंगे । प्रश्न क्रमांक 6, कविता प्राण लहरे जी ।

बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों को आवंटित लैपटॉप एवं कंप्यूटर

[स्कूल शिक्षा]

6. (*क्र. 1257) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल एवं मिडिल स्कूलों में शासकीय लैपटॉप/ कंप्यूटर वितरण किया गया था? यदि हां तो, पुनः उसे वापस क्यों लिया गया है? **(ख)** विकासखंड वार लैपटॉप वितरण की जानकारी देवें? (ग) शालाओं से वापस मंगाए गए लैपटॉप का क्या उपयोग और कहाँ किया गया है?जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) : (क) समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत शासन की स्वीकृति अनुसार चयनित विद्यालयों में सत्र 2019-20 में ऑनलाईन निविदा उपरांत स्मार्ट क्लास व आईसीटी लैब स्थापित की गई थी। स्मार्ट क्लास में लैपटॉप व आईसीटी लैब में कम्प्यूटर स्थापित किये गये थे। सत्र 2020-21 में भारत शासन द्वारा स्वीकृति सूची में संशोधन करते हुए कुछ विद्यालयों को निरस्त किया गया इसके अनुसार उक्त विद्यालयों से प्रदान किये गये लैपटॉप / कम्प्यूटर वापस लिये

गये। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ**[2] अनुसार है। **(ग)** शालाओं से वापस मंगाए गए लैपटॉप को अन्य शालाओं में वितरित किया गया। जिसकी जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहथंव कि मोर बिलाईगढ़ विधान सभा में जतना भी हायर सेकेण्डरी स्कूल हे, हाई स्कूल हे, मिडिल स्कूल हे, एमा शासकीय लैपटॉप दे गे रिहिसे, लेकिन एला फेर से वापस मांग ले रहिसे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहथंव कि वोला काबर वापस मांगिस ? अगर वापस मांगे गिस तो वोखर उपयोग कोन-कोन से विद्यालय में करे गिस ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-2020 में भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्कूलों में ऑनलाईन निविदा स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब स्थापित करने हेतु यह लैपटॉप और कम्प्यूटर लगाये गये थे । उनमें से इनके विधान सभा क्षेत्र में 71 हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी और अन्य स्कूलों में लगाया गया था। चूंकि भारत सरकार के नियमानुसार उसमें छात्रों की संख्या, दर्ज संख्या और शिक्षकों की स्थिति उसके अनुसार जो ज्यादा संख्या में लैपटॉल लगे थे, उन विद्यालयों से दूसरे विद्यालयों में लगाया गया और उन लैपटॉप को बिलासपुर संभाग के 26 स्कूल, बस्तर संभाग और ऐसे ही रायगढ़ में, कुछ कोरिया में, मुंगेली में, इस तरह से 99 स्कूलों में उसे स्थानांतरित किया गया है ।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के कहना हे कि सत्र 2021 म भारत शासन द्वारा स्वीकृति सूची म संशोधन करत कुछ ही विधालय ला निरस्त करे गे हे । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहथंव कि का कुछ ही विद्यालय के लिये भारत सरकार द्वारा ये योजना ए तो का भारत सरकार के पास का लैपटॉप के कमी रहिसे, जो कुछ विद्यालय ला निरस्त करे गिस हे, स्वीकृति होए के बाद बच्चा मन ला कतना तकलीफ होवत होही । अईसे भ्रष्टाचार, अईसे सौतेला व्यवहार भारत सरकार ह हमर छत्तीसगढ़ के साथ काबर करथे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का स्पष्ट गाईड लाईन रहता है, उसको राज्य सरकार ही क्रियान्वित करती है । जैसा की 2019-20 की बातचीत है, मैं किसी सरकार के ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा, परन्तु जो गाईड लाईन है, उसके हिसाब से जितना लैपटाप देना था । जैसे उदाहरण के लिए इनके बिलाईगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ही एक-दो स्कूलों को कोड कर देता हूं। जैसे हाईस्कूल भिनोदी में तीन लैपटाप दिया गया था, उसमें से एक लैपटाप को वापस लिया गया है, वहां दो लैपटाप शेष है । ऐसा नहीं है कि वहां पूरा लैपटाप खाली कर दिया गया । उसी प्रकार से भंडोरा

[2] परिशिष्ट "तीन"

में तीन लैपटाप दिया गया था, उसमें से एक लैपटाप को वापस लिया गया है, वहां दो लैपटाप अभी भी शेष है । उन लैपटापों को अन्य स्थानों पर बस्तर, सरगुजा जैसे तमाम क्षेत्रों में भेजा गया है ।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहथौं कि अगर एला निरस्त करे गिस हे तो किस आदेश के तहत ऐला निरस्त करे गे हे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो भारत सरकार की जो गाईड लाईन है, उसके आधार पर राज्य सरकार का शिक्षा विभाग उसका परीक्षण करके वापस लेता है । आदेश के कॉपी मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा कि वह किस आदेश पर वापस किया गया है ।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । आप सबसे मोर निवेदन हे कि मोर बिलाईगढ़ विधान सभा में बाबा गुरू घासीदास जी के तपोभूमि गिरौधपुरी मा बाबा जी के मेला लगे । मैं ए सदन ला पूरा न्यौता देवथौं, आप सब उहां आवव, आप सब बाबा जी के आशीर्वाद लेवव । धन्यवाद ।

सर्पदंश से हुई मृत्यु का प्रदत्त मुआवजा

[राजस्व एवं आपदा प्रबंधन]

7. (*क्र. 1188) श्री सुशांत शुक्ला : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर एवं जशपुर जिले में वर्ष 2022 से 31.01.2025 तक कुल कितने व्यक्तियों की सर्पदंश/जहरीले जन्तु के काटने से अकाल मृत्यु हुई ? वर्षवार, विकासखण्डवार, जानकारी उपलब्ध करावें। (ख) प्रश्नांश "क" के प्रकरणों में शासन द्वारा अकाल मृत्यु पर कितनी राशि प्रदाय किए जाने का प्रावधान है? किस-किस को, कब-कब, कितनी-कितनी मुआवजा राशि प्रदान की गई ? कितने प्रकरणों में मुआवजा राशि लंबित है ? कितने प्रकरणों को निरस्त अथवा अपात्र घोषित किया गया ? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें । (ग) प्रश्नांश "क" के सर्पदंश के कितने प्रकरणों में मृतक को स्नेक एन्टीवेनिन इंजेक्शन नहीं लगाया जा सका और क्यों ? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें ।

राजस्व मंत्री (श्री टंक राम वर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में बिलासपुर एवं जशपुर जिले में सर्पदंश/जहरीले जन्तु के काटने से कुल 547 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। वर्षवार एवं विकासखण्डवार जानकारी पुस्तहकालय में रखे "प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) शासन द्वारा मृत व्यक्तियों के परिजनों को रूपये 4.00 लाख प्रति व्यक्ति देने का प्रावधान है। किस-किस को कब-कब राशि प्रदान की गई, लंबित, निरस्त अथवा अपात्र घोषित के संबंध में वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ग) सर्पदंश से मृत व्यक्तियों को जिन्हें स्नेक एन्टीवेनिन इंजेक्शन नहीं लगाया गया है, के संबंध में जानकारी विकासखण्डवार पुस्तकालय में रखे "प्रपत्र-स" अनुसार है।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तारांकित प्रश्न क्रमांक 1188 के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए है और माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, वह अपने आप में बड़ा विसंगतिपूर्ण है । जशपुर को छत्तीसगढ़ का सर्प लोक कहा जाता है और वहां पर सर्प के काटने से पिछले तीन वर्षों 2022, 23 और 24 में वहां पर 96 मौतें हुई हैं और बिलासपुर जैसे उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में 431 मौतें हुई हैं । इस प्रश्न के माध्यम से मेरा स्पष्ट विषय है कि पूर्ववर्ती सरकार में व्यापक तौर पर राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत करके मुआवजे का, भ्रष्टाचार का रैकेट संचालित हो रहा था । इसी प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि बिलासपुर में 17 करोड़, 24 लाख का मुआवजा दिया गया है और जशपुर में 3 करोड़, 84 लाख रूपए का मुआवजा दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन मरीजों को फर्जी मुआवजा के आधार पर एक रैकेट के माध्यम से भुगतान किया गया, क्या उसकी जांच कराई गई है ? यदि जांच कराई गई है तो कौन दोषी अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

अध्यक्ष महोदय :- सांप फर्जी था या आदमी फर्जी था ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक का कथन है कि फर्जी प्रकरण बनाकर आरबीसी 6 (4) के तहत मुआवजे का वितरण किया गया है । यह बात पहली बार जानकारी में आई है । अगर वास्तव में ऐसा होगा कि फर्जी प्रकरण बनाकर शासन के करोड़ों रूपयों को मुआवजे के रूप में लिया गया है, ऐसी जानकारी उनके पास हो तो वे दें । निश्चिय ही यह जांच करने लायक विषय है। हम उसकी जांच करवाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप जानकारी दे दें ।

श्री सुशांत शुक्ला :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से स्पष्ट पूछा है कि जांच कराई गई है क्या ? क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के समय में शिकायतें हुई हैं । मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि इस प्रकार की विसंगतिपूर्ण अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का व्यापक नजरिया है । यानी जशपुर जिले को सर्प लोक कहा जाता है, वहां 96 मौतें होती हैं और बिलासपुर में 4 सौ से ऊपर मौत हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं । मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, वह उनके जी जवाब में उल्लिखित है कि राजस्व का अधिकारी सीएमओ से पोस्ट मार्टम के रिपोर्ट की जानकारी मांगता है और सीएमओ उस पोस्ट मार्टम रिपोर्ट को बगैर डाक्टर के प्रतिवेदन के विरूद्ध जाकर उसको सत्यापित करते हैं । यह राजस्व के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत में लगभग करोड़ों रूपए का घोटाला है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी सचिव स्तरीय जांच कराएंगे ?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुआवजे की प्रक्रिया ही यही है कि जैसे सर्पदंश से कोई पीडित है, अस्पताल गए, सर्पदंश से मृत्यु हो गई, तो स्वास्थ्य विभाग के प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा उनको मुआवजा दिया जाता है। जैसा पूछा गया कि फर्जी प्रकरण बनाकर आहरण करने की शिकायत मिली है क्या, तो अभी तक मेरी जानकारी में इस तरह की शिकायत नहीं मिली है और यदि माननीय सदस्य के पास शिकायत है, तो इस शिकायत को मुझे दें, मैं निश्चित रूप से इसकी जांच कराउंगा और दोषी अधिकारी के ऊपर जो कार्रवाई करते बनेगा, उसमें कार्यवाही करेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जांच के बारे में नहीं पूछना चाहता, उसे तो माननीय सदस्य ने पूछ लिया है। मैं अपने, सदन और पूरे प्रदेश के लिए यह जानकारी चाहता हूं कि फ़र्ज करिए कि दूरस्थ किसी वनांचल में किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया, तो वहॉ से शुरु करके आप बताइए कि उसकी मौत के बाद तक क्या-क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, क्या-क्या प्रमाण रखना पड़ेगा, किसके-किसके सर्टीफिकेट लगेंगे, कौन से फोटोग्राफ्स लगेंगे, पी.एम. की कौन सी रिपोर्ट मानी जाएगी, कब मानी जाएगी, कहां से मानी जाएगी, तब उसे 4 लाख रुपए मिलेंगे? इसकी एक सामान्य प्रक्रिया बता दीजिए। आप कल्पना कर लीजिए कि आप बस्तर के किसी बहुत घने जंगल में हैं, जो कि पी.एच.सी. से 50 किलोमीटर दूर है। आप यह कल्पना करके बताइए कि सांप काटने के बाद क्या-क्या करना पड़ेगा और किन-किन परिस्थितियों से, किन-किन विषय वस्तुओं को निपटाते हुए उसके परिवारजनों को 4 लाख रुपए पाने की पात्रता होगी? यह जरा बता दीजिए।

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्पदंश के इलाज के लिए वैक्सीन प्राय: सभी नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध रहती है। जब किसी को सर्पदंश होता है, तो पीड़ित परिवार या गांव वालों के सहयोग से उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में उसका इलाज होता है। यदि वह समय पर पहुंच जाता है, तो उसका इलाज हो जाता है और इलाज होने के बाद वह बच जाता है। यदि समयाभाव या साधन के कारण पहुंच नहीं पाता, तो रास्ते में ही या अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज के दौरान मौत हो जाती है, तो उसका सर्टीफिकेट स्वास्थ्य विभाग ही देता है कि इनकी मौत कैसे हुई और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए सर्टीफिकेट के अनुसार उनके मुआवजा का प्रकरण बनता है, जो कि राजस्व विभाग, कलेक्टर और एस.डी.एम. के थ्रू पीड़ित पक्ष को मिलता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग कैसे देता है, मैं यही तो पूछ रहा हूं। मान लीजिए तरेगांव के जंगल में किसी को सांप काटा और बोड़ला लाते तक या तो वह जिन्दा रहेगा तो उसे एन्टी स्नेक वेनम लगायेंगे, तो वह बच सकता है। मान लीजिए कि वह मर गया, तो वहां जिस स्पॉट पर सांप काटा है, वहां से क्या-क्या प्रमाण चाहिए, जो अस्पताल में आते तक हमको बताना पड़ेगा कि सांप काटने से इनकी मौत हुई है। वह तो कुछ भी बोल देंगे कि ये सांप काटने से नहीं है। बताइए ना कि क्या वहां पर गांव में पटवारी या सरपंच या अन्य से कुछ पंचनामा होता है या प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र में पोस्टमार्टम के बाद ही माना जाता है? हम यही तो जानना चाहते हैं ताकि लोगों को जो आप मदद दे रहे हैं, उसके बारे में तो हम बता सकें। वह तो मालूम है कि हर ब्लॉक, पी.एच.सी. में एन्टी रैबीज़ और एन्टी स्नेक वेनम रहता है। ये बताइए ना कि बहुत दूरस्थ अंचल में सांप काटने से कोई एक व्यक्ति मर गया या घायल हो गया, तो वहां पहुंचते तक अगर जिन्दा है, तब तो कोई बात नहीं, चार लाख का मामला ही नहीं है लेकिन यदि मर गया, तो 4 लाख कैसे मिलेगा? मर गया तो 4 लाख कैसे मिलेगा, इसे बता दीजिए, ताकि किसी जरुरतमंद की मदद कर सकें?

श्री टंक राम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी पी.एम. रिपोर्ट में आएगा कि कैसे उनकी मृत्यु हुई, उस रिपोर्ट के आधार पर उनका प्रमाण पत्र बनेगा, फिर उसका मुआवजा मिलेगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत सिंह जी जवाब गलत पूछ डाले, वह ठेकेदारों से संपर्क करना पड़ेगा, जो इसमें प्रशिक्षित होते हैं। परंतु मेरा विषय स्पष्ट नहीं हुआ। इसमें कलेक्टर के द्वारा और एस.डी.एम. के द्वारा मुआवजा देने का विषय है, तो मैं फिर आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि इस पूरे विषय की सचिव स्तरीय जांच करायेंगे क्या?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो वही कह रहा हूं कि वह 4 लाख कैसे मिलता है, उसे बताइए। मैं गलत नहीं पूछ रहा हूं, बाकी आप अपना पूछकर, उनको बता दीजिए। मैं प्रक्रिया पूछ रहा हूं।

श्रीमती भावना बोहरा (पण्डरिया) :- अध्यक्ष महोदय, मेरा इस विषय में एक छोटा-सा सवाल था। अभी यह विषय आया है कि सर्पदंश से मृत्यु के बाद मुआवजा मिलेगा। लेकिन इसमें यह विषय भी आता है कि कभी इलाज में जो देरी होती है, उसकी वजह से भी मृत्यु हो जाती है। आपने कहा कि सब जगहों पर उसकी दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन सिर्फ जिला चिकित्सालयों में ही वैक्सीन उपलब्ध होती है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। गांव के अंदरूनी क्षेत्रों से जिला चिकित्सालय पहुंचने की जो दूरी है, वह भी मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी सर्पदंश की वैक्सीन और दवाइयां उपलब्ध रहे, ताकि जिला अस्पताल तक जाने की दूरी से बचा जा सके और मुआवजे की जरूरत ही न पड़े। उनका समय पर इलाज हो जाये और उन्हें आगे किसी प्रकार की दिक्कत ही न आये।

लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब टंकराम जी नहीं दे पायेंगे चूंकि यह स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामला है इसलिए उनको इसकी जानकारी नहीं होगी। भावना जी, हमारे सभी जिला चिकित्सालयों में सर्पदंश के लिये एंटी वेनम इंजेक्शन उपलब्ध है। इसके अलावा जहां सी.एच.सी. और पी.एच.सी. प्रभावित है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां भी दवाइयां उपलब्ध हैं। यदि कहीं दवाइयां उपलब्ध नहीं है तो आप मुझे बता दीजिये।

श्रीमती भावना बोहरा :- अध्यक्ष महोदय, ऐसा मामला आया है इसलिए मैं बोल रही हूं। गौरी ग्राम में सर्पदंश से एक मृत्यु हुई है। आप चाहे तो जांच भी करवा लीजिये।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में नाग लोक और सर्प के नाम से जिस जगह की पहचान है, वह जिला-जशपुर और तपकरा है। लेकिन मुझे प्रश्न के माध्यम से जानकर यह आश्चर्य लगा कि बिलासपुर में उन जगहों से चार गुना ज्यादा मामले हैं। वहां 100 लोगों की सांप के काटने से मृत्यु हुई और बिलासपुर में 400 लोगों की सांप के कांटने से मृत्यु हो गयी। बिलासपुर एवं जशपुर में सर्पदंश के कुल 527 मामले हैं। यह जो पहचान बदल रही है, यह निश्चित रूप से आश्चर्य का विषय है। अब उसके लिए जो मुआवजा दिया गया है, मैं उस विषय में जाना नहीं चाह रहा हूं। मेरा उसमें केवल यह प्रश्न है कि क्या सारे लोगों का पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ ? यदि सारे लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और यदि कोई लिखकर दे कि इसकी मृत्यु सांप के कांटने से हुई है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वह प्रमाणित नहीं है। यदि उस इंसान का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो उसको मुआवजा की राशि नहीं मिलेगी। यदि कोई लिखकर देगा तो भी संभव नहीं है। उसमें केवल यही प्रक्रिया है कि पहले उसका पंचनामा होगा, पंचनामा करने के बाद लिखा जायेगा कि शरीर के किस अंग को सर्प ने काटा है और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होगा। डॉ. पोस्टमार्ट में जो रिपोर्ट देंगे, वह फाईनल रिपोर्ट होगी। जहां तक मेरी जानकारी है और मुझे जितनी समझ है, उसमें यही प्रक्रिया है। आश्चर्य का विषय यह है कि छत्तीसगढ़ में सर्पलोक की पहचान बदल गयी है और वह बिलासपुर हो गया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो मुआवजे की राशि दी गयी है, जिसके संबंध में हमारे माननीय विधायक सुशांत शुक्ला जी ने प्रश्न किया कि उसमें कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ या कुछ और मामला तो नहीं है ? उसमें सभी लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयी या नहीं आयी ? यदि बिना पोस्टमार्टम के मुआवजे की राशि दी गयी है तो मंत्री जी, उस विषय में कुछ जानकारी होगी तो बताने का कष्ट करें।

श्री टंकराम वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने आंकड़े के हिसाब से जो शिकायत की है कि बिलासपुर में सर्पदंश से मौत की संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि नागलोक जशपुर में संख्या ज्यादा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मेरे पास कुछ प्रमाण है और शिकायत के आधार है कि फर्जी प्रकरण बने हैं और फर्जी भुगतान हुआ है। मैं यही कहना चाहूंगा कि उनके पास जो शिकायत और प्रमाण है, वे वह हमको दे दे। हम उसकी पूरी जांच कराकर उसमें कार्रवाई करायेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी, मैंने उसकी बेसिक दो चीजें कही हैं। मैंने पहला, पंचनामा और दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कहा है। आप इतना सुनिश्चित करा लीजिये कि सभी मामलों में पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी वह देंगे या नहीं देंगे वह उनके ऊपर छोड़ दीजिये। सारे रिकॉर्ड

आपके पास है, वह रिकॉर्ड कहां से लायेंगे ? आप उनको यह बताईये कि सभी का पोस्टमार्टम हुआ है। आप केवल उसकी जांच करवायेंगे। आप केवल इतनी बात की ही जांच करा लीजिये।

श्री टंकराम वर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जो बिलासपुर में 421 प्रकरणों में मुआवजा वितरण हुआ है। हम उसकी एक बार जांच करायेंगे।

श्री सुशांत शुक्ला :- अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा मुआवजा दिया जाता है। मैं फिर से मांग कर रहा हूं चूंकि कलेक्टर की जांच बाबू नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह कर रहा हूं कि क्या इस पूरे प्रकरण की जांच सचिव स्तर से करायेंगे ?

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में जो भी मामला गड़बड़ दिख रहा है, आप उसकी जरूर जांच कराईये। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में कई मामले ऐसे हैं, जिनको जानबूझकर रोका जा रहा है। पी.एम. रिपोर्ट होने के बाद कलेक्टर उसको बिसरा के लिए भेज देते हैं। वह मामला Unnecessary दो साल, तीन साल और चार साल तक लंबा खींच जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे प्रकरणों का भी जल्दी निराकरण करा दीजिये। हमारे रायगढ़ जिले में ऐसे 3-4 प्रकरण हैं, जो पिछले ड़ेढ़, दो साल से अटके पड़े हैं। आपसे निवेदन है कि उनमें जो प्रकरण गलत हैं, उनमें मैं नहीं कहूंगा लेकिन जो प्रकरण सही है, आप उन प्रकरणों को दिखवाकर उन्हें जल्दी मुआवजे की राशि दिला दीजिये।

प्रदेश के शराब दुकानों में कैशलेस व्यवस्था

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

8. (*क्र. 544) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या छ.ग. के सभी शराब दुकानों को कैशलेस (ऑनलाईन पेमेंट सिस्टम) लागू किया गया है? यदि नहीं, तो कब तक लागू होगा? **(ख)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार छ.ग. की कितनी शराब दुकानें कैशलेस हैं ? कितनी दुकानें नकद भुगतान से संचालित हो रही हैं ? विवरण प्रदाय करें ?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) छत्तीसगढ़ के कुल 674 शराब दुकानों में 420 शराब दुकानों में कैशलेस (ऑनलाईन पेमेंट सिस्टम) लागू किया गया है जिनमें से 418 शराब दुकानों में ऑनलाईन एवं नगद दोंनो माध्यमों से भुगतान प्राप्त किया जा रहा है तथा 02 शराब दुकानें (1. विदेशी मदिरा दुकान टाटीबंद बार दुकान रायपुर, 2. प्रीमियम विदेशी मदिरा दुकान दुर्ग) पूर्णतः कैशलेस हैं। शराब दुकानों को कैशलेस करने के संबंध में कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के

अनुसार छत्तीसगढ़ के कुल 02 शराब दुकानें पूर्णतः कैशलेस है। 254 शराब दुकानें केवल नगद भुगतान से संचालित हो रही है।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछा था, जिसमें उन्होंने उत्तर दिया है कि छत्तीसगढ़ के कुल 674 शराब दुकानों में 420 शराब दुकानों में कैशलेस लागू किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि यहां पर शेष 254 शराब दुकानों में नगद बिक्री की जा रही है, बाकी प्रदेश के 254 शराब दुकानों को कब तक कैशलेस लागू किया जाएगा?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य महोदया को जानकारी भी दी है और उन्होंने उस जानकारी को पढ़ा भी है। छत्तीसगढ़ के कुल 674 शराब दुकानों में 420 शराब दुकानों में कैशलेस सिस्टम लागू किया गया है और जो बचे हुए 254 शराब दुकानें हैं, उनको जल्द ही प्रक्रिया के तहत ले रहे हैं। हमारी सरकार की आपसे भी ज्यादा चिंता है कि उन शराब दुकानों में कैशलेस लागू किया जाए। क्योंकि वैसे भी हमारे प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री जी का डिजिटल ट्रांजेक्शन पर विशेष जोर है।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के 254 शराब दुकानों में जल्द कैशलेस लागू किया जाएगा, ऐसा आप कह रहे हैं। उन दुकानों में इतने दिनों तक कैशलेस लागू क्यों नहीं किया गया? मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रही हूँ कि जब इस प्रदेश में 420 दुकानों में कैशलेस लागू किया गया है तो यह 254 शराब दुकानों में कैशलेस सिस्टम लागू क्यों नहीं किया गया और यह कब किया जायेगा ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद हमने इसमें बड़ा निर्णय लिया है और आज यह खुशी का विषय है कि हम लोगों ने 60 प्रतिशत शराब दुकानों में कैशलेस लागू कर दिया है, लेकिन एक साथ शतप्रतिशत करने से लोगों को दिक्कत भी न हो इसलिए अभी हमने यह दोनों सुविधाएं जारी रखी हैं। मैं आपके लिए बता देता हूँ कि यह खुशी की बात है। आपके विधान सभा क्षेत्र में 6 शराब दुकानें हैं। आपके क्षेत्र की 6 शराब दुकानों में कैशलेस लागू है। वहां पर उन शराब दुकानों से चाहे लोग नगदी में शराब ले सकते हैं या कैशलेस ले सकते हैं। वहां दोनों कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने बता दिया कि आपके क्षेत्र की 6 दुकानों में कैशलेस कर दिया।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के मगरलोड की बात बता रही हूँ कि वहां पर सड़क के ऊपर भरदा में एक शराब दुकान है, वहां पर कई बार जिसे मैंने हटाने के लिए कलेक्टर महोदय जी एवं आबकारी अधिकारी के सामने बात रखी, लेकिन आज पर्यन्त तक वहां से शराब दुकान नहीं हटी है। क्योंकि वहीं से स्कूल के बच्चे आना-जाना

करते हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहती हूँ कि वहां से उस शराब दुकान को तत्काल दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाये, जिससे बच्चे प्रभावित न हों।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह प्रश्न उससे उद्भुत नहीं है। परंतु माननीय सदस्य महोदया की चिंता है तो ..।

श्रीमती अंबिका मरकाम :-माननीय मंत्री जी, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है। आप कह रहे हैं कि प्रश्न उद्भुत नहीं होता।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए। यदि आपकी इस विषय में चिंता है और स्कूली बच्चों की बात है तो मैं निश्चित रूप से विभाग से कहूंगा कि उसे देखे और अगर इसमें आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से वहां से चेंज कराकर, दूसरी जगह स्थानांतरित किया जायेगा।

डिजिटल मीडिया एवं समाचार पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

[जनसंपर्क]

9. (*क्र. 1173) श्रीमती भावना बोहरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत प्रदेश के कुल कितने समाचार पोर्टल और कितने राष्ट्रीय समाचार पोर्टल पंजीकृत हैं? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में दिनांक 31/01/2025 तक राज्य सरकार द्वारा डिजिटल समाचार पोर्टल्स, समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और रेडियो स्टेशनों को कितने सरकारी विज्ञापन जारी किए और कितनी राशि आवंटित की गई? **(ग)** डिजिटल मीडिया और समाचार पोर्टल्स के लिए पंजीकरण एवं सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने की क्या मानक प्रक्रिया है? क्या पिछले 1 वर्ष में इस प्रक्रिया में कोई बदलाव किया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :(क) जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज पोर्टल्स का पंजीकरण नहीं किया जाता है। राज्य शासन कीजनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए समाचार पोर्टल्स का इम्पेनल किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के कुल 243 समाचार पोर्टल इम्पेनल हैं। किसी भी राष्ट्रीय समाचार पोर्टल इम्पैनल नहीं किया गया है।**(ख)** वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक राज्य सरकार द्वारा डिजिटल समाचार पोर्टल्स, समाचार पत्रों, टी.वी. चैनलों रेडियो स्टेशनों को जारी सरकारी विज्ञापन और आवंटित राशि निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2023-24**		**वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 31.01.2025 तक)**	
		जारी आदेश कार्यादेश संख्या	**जारी (आर ओ राशि) रूपये में**	**जारी आदेश कार्यादेश संख्या**	**जारी (आर ओ राशि) रूपये में**
1	डिजिटल समाचार पोर्टल	3189	67,16,89,759	1968	13,16,27,516
2	समाचार पत्रो	12,881	1,47,36,54,282	8,379	59,20,52,884
3	टी.वी. चैनलों	901	1,40,93,32,923	597	58,52,43,484
4	रेडियो स्टेशनों	187	5,29,55,891	145	2,71,31,424

(ग) जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज पोर्टल का पंजीकरण नहीं किया जाता है। प्रचार-प्रसार की सुविधा की दृष्टि से न्यूज पोर्टल का इम्पैनलमेंट किया जाता है। विज्ञापन नियमावली -2019 यथा संशोधित नियम-2020 के अंतर्गत विज्ञापन स्वीकृत किए जातेहैं। पिछले एक वर्ष में इस प्रकिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद्। मेरा प्रश्न जनसंपर्क विभाग से है। मुझे इस प्रश्न के जवाब में एक लाईन आयी है, पहले मैं उसको पढ़कर कहना चाहूंगी। जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज पोर्टल्स का पंजीकरण नहीं किया जाता है। राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए समाचार पोर्टल्स का इम्पेन किया जाता है। महोदय जी, मेरा पहला प्रश्न यही है कि जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज पोर्टल्स का पंजीकरण नहीं किया गया है तो जनसंपर्क विभाग के द्वारा इसको इम्पेनल करने के लिए क्या मापदण्ड तय किये गये हैं ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपना प्रश्न एक बार दोहरा दीजिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में यह उत्तर आया है कि जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज पोर्टल्स का पंजीकरण नहीं किया जाता है। राज्य शासन की

जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए समाचार पोर्टल्स का इम्पेनल किया जाता है तो इसको इम्पेनल करने का Criteria क्या है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इम्पेनलमेंट करने के लिए एक विस्तृत गाईड लाईन हैं और इसमें टेण्डर भी निकाले जाते हैं और उसके आधार पर इम्पेनलमेंट किया जाता है। उसके पूरे सर्क्यूलर(Circular) विस्तार से हैं। यदि आप बोलेंगे तो मैं माननीय सदस्या को उसको उपलब्ध भी करवा दूंगा।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में प्रदेश के कुल 243 समाचार पोर्टल इम्पेनल किया गया है तो इसमें 243 टेण्डर निकाले गये हैं? इसमें प्रदेश के कुल 243 समाचार पोर्टल इम्पेनल किये गये हैं, पंजीकृत नहीं हुआ है, लेकिन विभाग से कुल 243 समाचार पोर्टल इम्पेनल किये गये हैं तो क्या इसमें 243 टेण्डर निकाले गये हैं?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी उत्तर के परिशिष्ट में उपलब्ध भी है। 243 टेंडर के माध्यम से सभी को निकाले गये हैं। लेकिन कुछ ऐसी पत्रिकायें या स्थानीय अखबार होते हैं जिनको उनके रेट के आधार पर विज्ञापन उपलब्ध कराया जाता है।

श्रीमती भावना बोहरा :- अगर हम किसी को विज्ञापन दे रहे हैं तो उसका क्या मापदण्ड है?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मापदंड का मुख्य आधार होता है, जो इम्पेनलमेंट हैं, उनके यूजर्स की संख्या और पहुंच के आधार पर संचालनालय स्तर पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक का मासिक विज्ञापन स्वीकृत किया जाता है कि उनकी लोकप्रियता कितनी है और कितने लोग देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है। अच्छा जवाब है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में मैं अगली लाईन पढ़ना चाहूंगी कि विज्ञापन नियमावली-2019 यथा संशोधित नियम-2020 के अंतर्गत विज्ञापन स्वीकृत किए जाते हैं। पिछले एक वर्ष में इस प्रक्रिया में कोई बदलाव और संशोधन नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में जो जवाब आया है, उसी से मेरा प्रश्न है। अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 को जो विज्ञापन है और मुझे जो डिटेल जानकारी दी गई है, आप जनसंपर्क विभाग के खर्च देखेंगे तो जैसे डिजिटल समाचार पोर्टल का 67 करोड़ रुपये, समाचार पत्रों का 147 करोड़ रुपये, टी.व्ही. चैनलों का 140 करोड़ रुपये और रेडियो स्टेशन का लगभग 5 करोड़ 29 लाख के आसपास है जो टोटल 360 करोड़ रुपये का है। वहीं अगर हम वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो क्योंकि कोई बदलाव और संशोधन नहीं हुआ है, 2024-25 का ऑउटकम टोटल 134 करोड़ रुपये आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अंतर है, वर्ष 2023-24 का 360 करोड़ रुपये और 2024-25 का 134 करोड़ रुपये, इन दोनों में विसंगतियां क्यों हैं? क्या इसकी जांच होगी, क्या इसका ऑडिट होगा कि किस आधार पर ये विज्ञापन दिये गये हैं?

क्योंकि एक वर्ष जहां 134 करोड़ रुपये है, वहीं 2023-24 में इसका डबल से भी ज्यादा है। इसका क्या कारण है? अगर इसमें कोई विसंगति दिख रही है तो क्या इसकी जांच होगी?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो व्यय का आंकड़ा है, यह अभी वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, यह जनवरी तक का है, अभी फरवरी और मार्च का भी आंकड़ा आना शेष है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 10 महीनों में उसका आधा भी खर्च नहीं हुआ है तो अगले दो महीनों में कैसे संभव है कि वह आंकड़ा टच कर जायेंगे? 360 करोड़ रुपये मतलब लगभग 134 और 140 करोड़ रुपये फिर से खर्च करना अगले 02 महीने में संभव नहीं है। मैं वर्ष 2023-24 का बताना चाहूंगी कि यह जो पुरानी सरकार थी, उनका मुझे लग रहा है। मैं एकदम कन्फर्म नहीं हूं इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन हम जो अंदाज लगा रहे हैं, वह वर्ष 2023-24 के आंकड़े जो कांग्रेस के कार्यकाल के थे, शायद तभी के हैं। क्या इस पर जांच होगी? क्योंकि विषय ऐसे आये हैं, अगर समाचार पत्रों की या होर्डिंग्स की बात करें, इसमें हुआ यह था जो हमारे पास शिकायतें आती हैं कि लगभग 3 महीने के लिए होर्डिंग्स के लिये या समाचार के लिए अनुबंध किया गया, जो विज्ञापन दिये गये या जो होर्डिंग्स लगी हैं वह सिर्फ 1 महीने के लिए लगी हैं। मतलब जो 2 महीने का बकाया किराया था, वह उनको किस आधार पर दिया गया? अगर हम 3 महीने के लिए होर्डिंग्स लगाते हैं, पेमेंट 3 महीने का हुआ और होर्डिंग्स सिर्फ 1 महीने के लिए लगी। तो जो पेमेंट किया गया है, उसमें विसंगतियां हैं और यह 2023-24 और 2024-25 में साफ अंतर दिख रहा है और स्पष्ट है कि हम इशारा किस ओर कर रहे हैं। मैं यही चाहूंगी कि चूंकि डबल से भी ज्यादा राशि है तो क्या इसकी जांच, ऑडिट होगी?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही जिनाईन प्रश्न उठाया है। यह पिछले एक साल में जो खर्च हुआ है, पिछले 10 महीनें में उसका आधा या 55 प्रतिशत के आसपास खर्च हुआ है। लेकिन सिर्फ आंकड़ा के आधार पर।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट शेष हैं, आप यह बता दीजिए कि क्या जांच होगी? क्या इसका ऑडिट होगा? क्योंकि यह सरकारी राशि का साफ-साफ दुरूपयोग दिख रहा है। क्योंकि समय मुश्किल से आधा मिनट बचा हुआ है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आपके नालेज में अगर कोई विषय होगा तो आप उसको प्रकाश में लायेंगी तो निश्चित रूप से उस पर परीक्षण करायेंगे।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परीक्षण नहीं कराना है। मेरा विषय पूरा है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट भी हैं। मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी, क्या उस पर जांच होगी? देखिये, क्योंकि यह सरकारी पैसे का दुरूपयोग है।

अध्यक्ष महोदय :- आप जानकारी उपलब्ध करायें, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि जांच कर लेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- परीक्षण बोले हैं।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी परीक्षण कराने के लिए बोले हैं। आप एक बार बोल दीजिए कि जांच करायेंगे? मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दूंगी।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिये, इस आधार पर केवल यह नहीं कह सकते। आप कुछ भी कागज देंगी तो उस पर परीक्षण करायेंगे।

श्रीमती भावना बोहरा :- देखिये, आधार तो साफ दिख रहा है न। वर्ष 2023-24 का आप देखिये, 336 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 को 134 करोड रुपये है। महोदय जी, इसमें अंतर तो साफ दिख रहा है। यह भी साफ दिख रहा है कि सरकारी पैसे का दुरूपयोग हो रहा है, आप यह बता दीजिए कि क्या जांच होगी?

श्री रामकुमार यादव :- मुफ्त में होर्डिंग्स टगे रहथे, तेकर जांच करवाईहा का?

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप द्वारा किया गया है । माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर किया गया है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

समय :
12.00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) विद्युत विभाग की विभिन्न अधिसूचनाएं

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार :-

(i) अधिसूचना क्रमांक 107/सी.एस.ई.आर.सी./2024, दिनांक 6 मई, 2024 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण और संबंधित विषय वस्तु की निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024

(ii) अधिसूचना क्रमांक 108/सी.एस.ई.आर.सी./2024, दिनांक 2 अगस्त, 2024 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 तथा

(iii) अधिसूचना क्रमांक 109/सी.एस.ई.आर.सी./2024, दिनांक 29 जुलाई, 2024 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (चतुर्थ संशोधन), 2024 पटल पर रखता हूं ।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024 पटल पर रखता हूं ।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन (2025-30) एवं उस पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (4) तथा अनुच्छेद 243-म के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन (2025-30) एवं उस पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अब नियम-138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण की सूचनाएं पढ़ी जायेंगी। सर्वश्री अजय चंद्राकर जी ।

समय :
12.02 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) प्रदेश के शासकीय सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ में सिकलसेल मरीजों को भर्ती कर इलाज की सुविधा नहीं होना।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश में सिकल सेल बीमारी से लगभग 25 लाख लोग प्रभावित हैं तथा उससे भी चिंताजनक विषय यह है कि प्रतिवर्ष एक फीसदी मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं । ऐसे में इसके ईलाज व रोकथाम के लिये राज्य में सिर्फ एक ही शासकीय सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर है जहां की स्थिति ऐसी है कि मरीजों को भर्ती करने की सुविधा तक नहीं है । सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर जहां प्रतिवर्ष लाखों का बजट प्रावधान होने के बावजूद भी न तो पर्याप्त विशेषज्ञ हैं और न ही किसी प्रकार का अनुसंधान या रिसर्च किया जाता है । वहीं सिकल सेल की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना दो वर्ष से कागजों में ही अटकी पड़ी है, यहां तक कि संचालन हेतु स्वयं का भवन तक नहीं है । मरीजों के ईलाज के नाम पर ओपीडी में सिर्फ दवा दी जाती है तथा लाखों की मशीनें आज तक डंप पड़ी हुई हैं । आज प्रदेश में सिकलसेल के मरीज इस संस्थान में जाने तक को डर रहे हैं और ईलाज के लिए दर-दर भटक रहे हैं तथा कई मरीज अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, राज्य में सिकलसेल बीमारी के मरीजों की दयनीय स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण प्रशासन के प्रति आमजनों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिकलसेल संस्थान छत्तीसगढ़ प्रदेश का एकमात्र चिकित्सालय है, जहां पर केवल सिकलसेल मरीज़ों का उपचार किया जाता है । वर्तमान में संस्थान द्वारा पंजीकृत मरीज़ों की संख्या 8943 है । प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से आने

वाले मरीज़ों की तकलीफ को देखते हुए 30 अक्टूबर 2022 से प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं जिला चिकित्सालयों में “सिकल सेल प्रबंधन केंद्र” प्रारंभ किया गया है, जहां पर सिकल सेल मरीज़ों को उपचार एवं आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं ।

यह कहना सही नहीं है कि प्रतिवर्ष लाखों रूपया बजट प्रावधान होने के बावजूद भी न तो पर्याप्त विशेषज्ञ हैं और न ही किसी प्रकार अनुसंधान या रिसर्च किया जाता है बल्कि सत्य तो यह है कि वर्तमान में संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा 19 शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं। आईसीएमआर/सीजीकास्ट/युनिसेफ आदि से फंडेड 05 प्रोजेक्ट पूर्ण हो चुके हैं तथा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। नॉन-फंडेड 02 प्रोजेक्ट एवं 03 पी.एच.डी. प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्यवाही एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु गठित समिति से मानव संसाधन की आवश्यकता संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इसी प्रकार यह भी कहना सही नहीं है कि सिकल सेल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना दो वर्ष से कागजों पर ही अटकी पड़ी है, यहां तक कि संचालन हेतु स्वयं का भवन तक नहीं है सिर्फ उधार की व्यवस्था पर चल रही है, बल्कि सत्य तो यह है कि दिनांक 23 जून, 2023 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के भूमिपूजन के पश्चात् लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप. क्रमांक 4791/14-108/सिकल सेल/तक/2023-24 दिनांक13/10/2023 द्वारा भूमि में अंतर पाए जाने पर, कान्सेप्ट प्लान में संशोधन हेतु कहा गया। पूर्व प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट एवं ब्लड बैंक आदि की सुविधा नहीं होने के कारण संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित समिति द्वारा कान्सेप्ट प्लान में संशोधन किया गया है। वर्तमान प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जो कि छ.ग. प्रदेश का एकमात्र शासकीय चिकित्सालय होगा। लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप क्र. 614/14-108/तक./2024-25 दिनांक 24.01.2025 द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संशोधित कान्सेप्ट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसे दिनांक 25.01.2025 को समिति द्वारा अनुमोदित कर लोक निर्माण विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। चिकित्सालय के तय मानकों के अनुरुप संबंधित कार्यालयों (अप्रूवल एजेंसी/ लायसेंसिंग अथॉरिटी) से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

यह कहना सही नहीं है कि मरीजों के इलाज के नाम पर ओपीडी में सिर्फ दवा दी जाती है तथा लाखों की मशीन आज तक डंप पड़ी हुई हैं, सत्य तो यह है कि संस्थान में सिकल सेल संस्थान छ.ग. के ओपीडी, में निःशुल्क दवा प्रदान की जा रही है तथा नवीन निर्माणाधीन भवन में डे-केयर की सुविधा प्रस्तावित है। संस्थान में सॉलुबिलिटी एवं इलैट्रोफेरेसिस जांच की जा रही है। मशीनों के लिए उपलब्ध रिएजेंट का उपयोग किया जा रहा है, आवश्यकता अनुरूप उपकरणों के रिएजेंट उपलब्ध नहीं होने पर, डीकेएस, हॉस्पिटल, रायपुर से एचपीएलसी जांच कराई जा रही है। संस्थान में उपलब्ध मशीनों में रियल

टाईम पीसीआर, एचपीएलसी-वैरियेंट-2, डायरेक्ट हीट सीओटू इन्क्यूलेटर, आईस फेलाकर रिसर्ववाईवल स्टोरेज, फुल ऑटोमेटेड ऑटो ऑनलाईन जैसी अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध व संचालित हैं।

यह भी कहना सही नहीं है कि प्रदेश में सिकलसेल के मरीज इस संस्थान में जाने तक को डर रहे है और इलाज के लिए दर-दर भटक रहे हैं तथा कई मरीज अपनी मौत का इंतजार कर रहे है, राज्य में सिकल सेल बीमारी के मरीजों की भयावह स्थिति बनी हुई है। सत्य तो यह है कि वर्तमान में सिकल सेल संस्थान में उपलब्ध मशीनों एवं मरीजों को निःशुल्क दवाई वितरण, समुचित उपचार एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों का इलाज किया जाता है।

अतः प्रशासन के प्रति आमजनों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में आपसे थोड़ा संरक्षण चाहूंगा । ये संस्थान आपकी प्रेरणा से शुरू हुआ था और मैं स्वास्थ्य मंत्री था। भूपेश बघेल जी ने नारियल फोड़कर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित कर दिया है। आगे पूछे तो कुछ होगा नहीं। तो इसमें आपका थोड़ा संरक्षण चाहिए। देखिए, एक भी चीज पूरा है, ये इन्होंने उत्तर में स्वीकार नहीं किया। एक भी चीज। कोई प्रक्रियाधीन है जैसे भर्ती के बारे में क्या उत्तर दिया है, वह मैं बता देता हूं। प्रस्तावित निर्माणाधीन भवन में डे-केयर की सुविधा है। अभी क्या सुविधा है? ध्यानाकर्षण आज में लगा है। बता रहे हैं कि भविष्य में उसका जब होगा । माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सिकल सेल संस्थान कब बना? उसका सेटअप कितने का है, उसके विरुद्ध कितने लोग काम कर रहे हैं और उसमें कितने डॉक्टर और विशेषज्ञ हैं?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं भी अलग से थोड़ा समय लेना चाहता हूं । जैसा कि मैंने अपना वक्तव्य में भी बताया कि 23 जून 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की थी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कब हुआ, यह नहीं पूछ रहा हूं ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट यार..सॉरी । एक मिनट, माननीय मंत्री जी मेरे साथ एक तकलीफ है मैं प्वाइंटेड प्रश्न पूछता हूं और प्वाइंटेड उत्तर दीजिए । कृपया, उसको घुमाने की कोशिश न करें । मैंने पूछा है कि सिकलसेल संस्थान कब शुरू हुआ, कितने का सेटअप स्वीकृत है, उसके विरूद्ध कितने लोग कार्यरत् हैं, उनमें डॉक्टर और विशेषज्ञ कितने हैं, वर्तमान में ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपका जवाब भी प्वाइंटेड दूंगा, जवाब मेरे पास है । उससे पहले एक बात बताना जरूरी है ।

अध्यक्ष महोदय :- भूमिका रखने दो । जल्दी-जल्दी क्यों कर रहे हो, उनको भूमिका रखने दो ?

श्री अजय चन्द्राकर :- चलने दीजिए फिर ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही जब मुख्यमंत्री थे तो यहां सिकलसेल की जांच चालू हुई और प्रदेश में उसके लिए बहुत अच्छा काम भी किया गया । प्रदेश में एक बड़ा संस्थान है उसके लिए काम किया गया लेकिन पिछली सरकार में, मैंने अपने वक्तव्य में भी इसीलिए लिखा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने 23 जून 2023 को इसका भूमि पूजन किया । आनन-फानन भूमि पूजन सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि क्रेडिट लेना था और बिना किसी तकनीकी जांच के, बिना किसी सुनियोजित व्यवस्था के अगर वह सेंटर आज चालू हो जाता तो न तो उसकी लैब जांच की अनुमति मिलती, न तो बोनमेरो ट्रांसप्लांट की अनुमति मिलती और आज छत्तीसगढ़ का करोड़ो रूपया डूब चुका होता। मैं बता रहा हूं कि हमारी सरकार आने के बाद हमने इसमें मैं खुद अभी तक इसमें 11 मीटिंग किया । इसमें छोटे से छोटे अधिकारी के साथ, डायरेक्टर के साथ, सीएमई के साथ, डीएमई के साथ, सचिव स्तर के और..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह भूमिका है या पठन है या प्रश्न का उत्तर है । वे जितना पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा मैं अभी यहीं खड़े खड़े बता देता हूं। यह कागज दे देता हूं, आप पढ़ लेना इसको । जो आप बता रहे हो, मैं कागज दे देता हूं उसको पढ़ लेना । आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, यह प्रश्नों में उत्तर देते जाएंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- चलिए मैं संक्षिप्त में प्रश्न का ही उत्तर दे देता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संक्षिप्त नहीं, प्रश्न का पूरा उत्तर दीजिए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- चलिए, प्वाइंटेड प्रश्न आपने पूछा, मैं जवाब दे देता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने दो बार तो पूछा है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सेटअप 180 का है, कार्यरत् 27 हैं और रिक्त 153 पद हैं, और कुछ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं पूछा है । मैंने पूछा है सेटअप कितने का है, कौन से स्तर के लोग काम कर रहे हैं, कितने पद डॉक्टरों के और कितने विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद हैं और विशेषज्ञ डॉक्टरों के कितने रिक्त हैं ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- शायद आपने जवाब को सुना नहीं । सेटअप कुल 180 पदों का है, उसमें 27 कार्यरत् हैं और 153 रिक्त हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे, डॉक्टरों का पूछ रहा हूं । कितने डॉक्टर कार्यरत हैं, कितने विशेषज्ञ डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं जो कार्यरत हैं या रिक्त हैं, यह पूछ रहा हूं । मैंने चारों बार यही पूछा है आपसे ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- उसमें 4 डॉक्टर कार्यरत हैं, जिसमें 2 विशेषज्ञ हैं और 2 मेडिकल ऑफिसर हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने 11 बैठकें ली हैं तो अब कृपा करके यह बता दीजिए कि आप डॉक्टरों की भर्ती कब तक करेंगे ? इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- देखिए, डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया आजकल पीएससी के माध्यम से होती है । इसके सेटअप स्वीकृत हैं और सारे सेटअप के विरूद्ध हमारा प्रयास होगा कि जल्द से जल्द भर्ती करें । वैसे हम लोग अटेचमेंट करके उसको बढ़ाने की सोच रहे हैं । जब तक भर्ती नहीं हो जाती तब तक उस संस्थान में प्रदेश से अन्य डॉक्टरों को लगाकर काम करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, अत्यंत दुखद विषय है । आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 8000 मरीज हैं और 27 पदों में 2 डॉक्टर और 2 विशेषज्ञ डॉक्टर कार्यरत हैं और अगर विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी डिग्री पूछूंगा तो वे विशेषज्ञ सिकलसेल एनीमिया के नहीं निकलेंगे । अब मुझे यह बताइए साहब, आपने नाम लिखा है । अवधि तो आप बताएंगे नहीं, पीएससी के माध्यम से होती नहीं, आपके विभाग में वॉक-इन-इंटरव्यू ही होता है । वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से भी आप इनको भर सकते हैं, यदि इच्छाशक्ति हो तो, नहीं है तो अलग बात है । आपके संस्थान में कितनी मशीनें उपलब्ध हैं और उनके संचालन के लिए मानव संसाधन उपलब्ध है या नहीं ? मशीनों का नाम पढ़ेंगे तो मैं सुनूंगा और यदि वे मशीनें क्या काम आती हैं यह बताएंगे ता और अच्छी बात है ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ठीक है। सिकल सेल संस्थान छत्तीसगढ़ में 4 महत्वपूर्ण मशीन उपलब्ध हैं। पहला नंबर सालुबिलिटी टेस्ट, दूसरा इलेक्ट्रो फोरेसिक टेस्ट, तीसरा एचपीएलसी टेस्ट और चौथा आरएफटी एलएफटी टेस्ट मशीन है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी, आप प्रश्नों को थोड़ा ठीक से सुन लिया करें। मैंने पूछा कि कितने मशीन उपलब्ध हैं और उसके संचालन के लिए तकनीशियन उपलब्ध हैं या नहीं हैं या वे डिब्बे में बंद हैं या काम कर रहे हैं ? मैं आपको बता देता हूं, आप चार मशीन बोल रहे हैं, उससे ज्यादा मशीन वहां उपलब्ध हैं। आप बोलेंगे तो मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा देता हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसा लिस्ट बनायेंगे तो बड़ा लिस्ट होगा। छोटा सा ब्लड निकालने वाला सिरिंज भी मशीन में आएगा। उसकी जांच थंबिग वाला भी आएगा लेकिन जो बड़ी मशीन लगती है, वह चार मशीन है। हमारे पास जांच करने के लिए मानव संसाधन उपलब्ध हैं। मैं आपको इस बात का प्रमाण देता हूं कि प्रतिदिन सिकल सेल संस्थान में 60 मरीज एवरेज आ रहे हैं, 60 ओ.पी.डी. हो रहा है, सालुबिलिटी टेस्ट जिसमें हीमोग्लोबिन का इलेक्ट्रो फोरेसिक टेस्ट है, वह लगभग प्रतिदिन 28 हो रहा है। पैथोलॉजी जांच प्रतिदिन तीन हो रही है, बॉयोकैमेस्ट्री जांच प्रतिदिन

21 हो रहा है, इस प्रकार से यह जांच चालू है। अभी इन मशीनों को चलाने के लिए हमारे पास 9 तकनीशियन उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए बहुत अच्छा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित की गई तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित करने के बाद आप वहां क्या-क्या सुविधाएं जुटाना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास कितना फंड है, बजट में है कि समिति के पास है या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने के बाद क्या सेटअप में कोई परिवर्तन हुआ है ? उसके प्रोजेक्ट क्या हैं, ये बता दीजिए और वह कब तक क्रियान्वित हो जाएगा।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये डिजाईन जो पहले था, उसके अनुसार भारत सरकार से जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट हैं, वह इसमें महत्वपूर्ण है जिसके लिए लाखों रूपए लगते हैं, यहां तक कि 30-30, 35 लाख रूपए तक लगते हैं, उसकी अनुमति नहीं मिलती। उसकी जो और टेस्ट है, जैसे पैथोलॉजी टेस्ट है, जो ब्लड ट्रांसफिजन वगैरह करते हैं उसकी भी अनुमति नहीं मिलती, इसलिए उस डिजाईन को भारत सरकार के नये मॉडल के अनुसार चेंज किया गया है, उसके लिए मेरी PWD से बात हुई है, इस महीने के अंत तक वे दे देंगे और संभवत: हम लोग अप्रैल लास्ट या मई के पहले सप्ताह में फिर से टेंडर कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी प्रश्न करिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- 8 प्रश्न हो गए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपका बनाया संस्थान है, यह जनहित का विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपसे आग्रह करता हूं, गिनती में मत लीजिए। मैं एकाध प्रश्न कर लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए एक प्रश्न कर लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आपका बनाया संस्थान है। मैंने उनसे पूछा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के बाद क्या-क्या करेंगे, कितने दिन में स्वीकृति हो जाएगी ? उन्होंने भवन के बारे में बताया कि भवन की डिजाईन भेजे हैं और बोन मेरो प्लांट है, उन्होंने कम्प्लीट कॉनसेप्ट नहीं बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित करने से ये-ये चीजें वहां बढ़ेंगी।, शोध की, जांच की, ईलाज की सारी चीजें आती हैं, उसमें बोन मेरो प्लांट भर नहीं आता। इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपको जानकारी दे देता हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मेरे पास जानकारी है। आप पूछिए मैं बता रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- है तो उत्तर तो दे नहीं रहे हो। आपके पास पूरा उत्तर है तो आप PWD की डिजाईन को बताते हो और बोन मेरो भर को बताते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूं, आखिरी की ओर बढ़ जाता हूं। आपके पास खुद का भवन है, जमीन है या नहीं है, यदि है तो कितनी जमीन है ? दूसरा, चूंकि आखिरी प्रश्न कहा, क्या आपके संस्थान में किसी प्रकार की आर्थिक अनियमितता की शिकायत आपको प्राप्त हुई है ? यदि प्राप्त हुई है तो क्या उसकी जांच करवाएं हैं ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुविधा की बात माननीय सदस्य कह रहे थे।

श्री अजय चंद्राकर :- अब तो आगे बढ़ गए, उसको छोड़ दीजिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- जवाब नहीं जानेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- मैंने दूसरा प्रश्न कर लिया है। आपने पहले प्रश्न में उत्तर नहीं दिया।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आपने जमीन पूछा है न ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपको फिर से प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आप स्वयं प्रश्न पूछते हैं और उत्तर भी मालूम रहता है तो मैं क्या करूं। जो-जो पूछे हैं, उसका जवाब दे दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं पूछता दूसरा हूं, आप बताते दूसरा हो। आप एक बात बता दीजिए मैं आपको बता देता हूं, जानकारी दे देता हूं, उस संस्थान के बाजू में जो बंगलो है, जिसमें मिनिस्टर्स रहा करते थे, उस संस्थान को भी देना था। आज कि तारीख में दिया या नहीं दिया, यह मैं नहीं जानता। उससे वह संस्थान पूरा कैम्पस बन जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय ने वह बात कही थी और घोषणा की थी कि हम इसको खाली करवाकर जल्दी देंगे। खैर, मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा है कि कितनी जमीन है और वह जमीन आपको प्राप्त हुई या नहीं हुई ? मैं इसको अतिरिक्त जोड़ देता हूं। यदि आपको बताना हो तो बताइयेगा और यदि नहीं बताना हो तो मत बताइयेगा। फिर मैंने कहा कि क्या आपको इस संस्थान में किसी भी प्रकार की आर्थिक अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि आपको शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो आपने उसकी जांच करवाई है या नहीं करवाई है? यदि आपने उसकी जांच नहीं करवाई है तो क्या आप उसकी जांच करवाएंगे?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए वहां पर 2 एकड़, 96 डिसमिल जमीन है, जो पहले की डिजाइन से कम पड़ रही थी। लेकिन अभी उतनी ही जमीन में समाहित करके इसको कर लिया गया है। हमें अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता नहीं है। उससे संबंधित अभी तक मुझे या विभाग को किसी भी प्रकार की लिखित में शिकायत प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं। मंत्री जी, मैंने जमीन संबंधी शिकायत नहीं कहा है। मैंने आर्थिक अनियमितता की शिकायत कहा है। क्या आपको आर्थिक अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं प्राप्त हुई है।

श्री अजय चंद्राकर :- यदि मैं आपको आर्थिक अनियमितता की शिकायत की कॉपी दूंगा तो क्या आप उसकी जांच करवाएंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- हां, निश्चित रूप से हम उसका परीक्षण करवाएंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- परीक्षण नहीं, क्या आप उसकी जांच करवाएंगे ? परीक्षण की पूरी कॉपी है।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- परीक्षण कराने के बाद यदि उसमें कोई गड़बड़ी होगी, तब हम उसकी जांच कराएंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- यह परीक्षण शब्द नहीं, मैं आपसे जांच करवाने के लिए पूछ रहा हूं। आप मुझे बोल दीजिए आप इसकी जांच नहीं करवाएंगे।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नहीं-नहीं, हम जांच क्यों नहीं करवाएंगे। आप हमें उसकी कॉपी उपलब्ध करवा दीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- आप जांच बोलिये न, परीक्षण मत बोलिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है कि सिकलसेल संस्थान, जिसको आपने 27 जून, 2023 को स्वीकृत किया था, इसके बाद अपनी सरकार आने के बाद इस बीच में आपने काफी प्रयास किया। मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन हेल्थ मिनिस्टर थे और कौन-कौन क्या-क्या थे, लेकिन यदि किसी ने भी इस दिशा में सार्थक पहल की होती तो आज यहां पर लाखों लोगों को सिकलसेल की इलाज की सुविधा मिलती। मैंने इसकी 11 बार बैठकें ली हैं और इस संबंध में मैं गंभीर हूं। मैं आपको इस सदन में विश्वास दिलाता हूं कि जब हमारा अगला कार्यकाल होगा तो उसमें आपको कार्य प्रगति पर दिखेगा। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, यदि मैं आपको इसकी शिकायत की कॉपी दूंगा तो क्या आप इसकी जांच करवाएंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आप हमें जो शिकायत की कॉपी देंगे, यदि वह प्रकरण जांच करवाने के लायक होगा तो निश्चित रूप से हम उसकी जांच करवाएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण को उठाने के पीछे आपको कुछ कहना नहीं है और हम आपकी क्षमता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में यह बहुत बड़ी समस्या है तो इसका सरकार की तरफ से प्रभावी और त्वरित निराकरण हो।

इस ध्यानाकर्षण की मंशा के कारण हम लोगों ने यह प्रश्न पूछा है। आप ही बता रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग के ज्ञापन क्रमांक so and so के द्वारा भूमि में अंतर पाये जाने पर concept plan में संशोधन किया गया। पहले तो आप यह बता दीजिए कि जिसने concept plan बनाया है, उसने भूमि को पहले नापा था या भूमि को बिना नापे ही बना दिया और बाद में वह उसमें सुधार कर रहा है। यह लेट-लतीफी का कारण होता है कि पहले जितनी जमीन हो, उसके हिसाब से concept plan बने। यदि आपको concept plan में और विस्तार चाहिए तो फिर दुनिया भर की और सब चीजें जोड़ दी गईं। जैसे - blood bank, marrow transplant, bone marrow transplant. आप इसको एक बार में ही ठीक-ठाक से बनवाकर भेज दीजिए। आपने सिर्फ डेट दे दिया है कि approval agency licensing authority से स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कृपया करके आप इसकी समय-सीमा बताने का कष्ट करेंगे कि यह कहां से approve होगा, कब तक approve होगा और कब तक इसको स्वीकृति प्राप्त होकर यह काम शुरू होगा ? अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार में ही प्रश्न पूछ लेता हूं। मेरे छोटे-छोटे 2-3 प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप पूरा पूछ लीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, दूसरा, चिकित्सकों की नियुक्ति की कार्रवाई center of excellence हेतु गठित समिति से मानव संसाधन की आवश्यकता संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यह मानव संसाधन की आवश्यकता संबंधी कार्रवाई कौनी सी समिति से होगी और कैसे होगी ? माननीय मंत्री जी, आप मुझे इसके बारे में भी बता दीजिएगा। जैसा कि माननीय अजय चंद्राकर जी ने कहा कि वहां पर जांच में तकलीफ होती है और कुछ नहीं हो रही है। आपने यह भी लिखा है कि मशीनों के लिए उपलब्ध रिएजेंट का उपयोग किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार उपकरणों के रिएजेंट उपलब्ध नहीं होने पर DKS Hospital, बिलासपुर में जांच कराई जाती है और रायपुर में जांच कराई जाती है। ये छोटी-छोटी चीजें हैं, इसलिए इसको तो उपलब्ध हो जाना चाहिए न। आपको DKS Hospital भेजने की जरूरत क्यों पड़ रही है ? क्या आप इसको सुनिश्चित करेंगे ? अस्पताल की बिल्डिंग और उसमें आपका जो नया concept बना है, वह कब तक पूरा हो जायेगा ? यह मानव संसाधन, जो आपको करना है, वह कब तक आप कर पाएंगे ? आप हमें यह बताइये। ताकि मरीजों में यह आशा जगे कि सरकार के अस्पताल में सिकलसेल की बीमारी का इलाज होगा और हम सदन के माध्यम से यह संदेश जनता तक देने का प्रयास कर रहे हैं कि सिकलसेल की इलाज के लिए हमारी सरकार और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत गंभीर हैं। इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा भी विचलित, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। आपकी क्षमता पर बिलकुल भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। आप 11 बार मीटिंग लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जनता के प्रति चिंतित हैं। अगर आपको 24 बार और मीटिंग लेना पड़े तो मीटिंग ले लीजिये।

लेकिन इसको हल कीजिये और तीनों चीज का जवाब दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, छोटा सा जवाब दे दीजिये। प्रश्न बहुत लम्बा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक-एक पाइंट में जवाब दे दें।

अध्यक्ष महोदय :- बस छोटा सा जवाब दे दीजिये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक रेग्युलर भर्ती नहीं हो जाती तब तक हमने walk in interview से भरना तय कर लिया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने पी.एस.सी. का कहा था।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.एस.सी. से भर्ती होने में समय लगेगा। सब जानते हैं कि एकाध साल समय लग सकता है, तब तक walk in interview से भर्ती करेंगे। हम चाहेंगे कि जून महीने से निर्माण कार्य चालू हो जाये। आप समय-सीमा पूछ रहे थे, तो जून महीने से निर्माण कार्य चालू हो जाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- बहुत अच्छा।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि संस्था में पंजीकृत मरीजों की संख्या लगभग 8,943 है। तो क्या विभाग ने अनुमान लगाया है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सिकलसेल मरीज की संख्या कितनी है, क्योंकि उससे स्थिति सही ढंग से पता चलेगा कि इस बीमारी के पीड़ित लोगों की क्या स्थिति है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इसको बताना चाह रहा था, लेकिन कोई इसको पूछ ही नहीं रहा था। हम लोगों ने प्रदेश में अभी तक 1 करोड़ 52 लाख 39 हजार 860 लोगों का स्क्रीनिंग कर चुके हैं। इसमें 24,834 सिकलसेल के मरीज हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसमें एक मरीज होता है और एक दूसरा ऐसा होता है उसे सिकलसेल होने के बाद भी वह वाहक होता है, carier होता है, बीमारी नहीं होता है। ऐसे carier की संख्या 3,21,417 हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 24 हजार मरीजों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। मैं उत्तर देख रहा था तो इसमें शोध भी प्रकाशित हुआ है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि किस तरह के शोध हुए हैं और इसके ईलाज के लिए शोधकर्ताओं ने कुछ बारीकियां बताई है क्या, किस तरह से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां से भी शोध हो रहा है और भारत सरकार की ओर से विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इस पर फोकस है। इस पर शोध हो रहा है और उनको पर्याप्त रूप से hydroxyurea भी दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती सावित्री मण्डावी जी, आप अपना ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय :- बस हो गया, उत्तर आ गया।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आरोप-प्रत्यारोप का विषय नहीं है। मैं बहुत ही साधारण सा प्रश्न कर रहा हूं। जो शोधकर्ता हैं और जितने मरीजों की संख्या है, आपने बिलकुल सही कहा कि इसमें एक बीमारी है और एक वाहक है। बीमारी वालों की संख्या 24 हजार है या दोनों को मिलाकर 24 हजार है ? दोनों को मिलाकर 24 हजार है या सिर्फ बीमारी वालों की संख्या 24 हजार है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल मरीज 24 हजार हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इन 24 हजार मरीजों के लिए डाक्टरों की भर्ती जल्द से जल्द करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि उसकी भर्ती walk in interview से करेंगे। उनको नियमित रूप से hydroxyurea जो बहुत महंगा आता है, उसे भारत सरकार नि:शुल्क दे रही है। हम लोग पर्याप्त रूप से दे रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त स्टाक भी है।

(2) शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय आड़ावाल, जगदलपुर के बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन वितरण किया जाना।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय आड़ावाल, जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़) में अध्ययनरत बच्चों को हास्टल वार्डन के द्वारा गुणवत्ताहीन भोजन दिया जाता है। साथ ही वहां पर कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा भी बच्चों के साथ बदसलूकी की जाती है। जिसकी शिकायत बच्चों ने अपने उच्चाधिकारियों को भी किया, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। इसकी जांच नहीं होने और जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी के ऊपर कठोर कार्यवाही नहीं होने के कारण शासन-प्रशासन के प्रति आम जनता में भारी रोष व्याप्त है।

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय, आड़ावाल, जगदलपुर, जिला बस्तर (छत्तीसगढ़) में अध्ययनरत बच्चों को हॉस्टल वार्डन के द्वारा गुणवत्ताहीन भोजन दिया जाता है, अपितु बच्चों को विभाग द्वारा शासकीय मानक आहार तालिका के अनुसार गुणवत्तायुक्त भोजन नियमित रूप से दिया जा रहा है। यह भी कहना सही नहीं है कि वहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों

द्वारा बच्चों के साथ बदसलूकी की जाती है। संस्था में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा बच्चों के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार किया जाता है। संस्था के कर्मचारियों द्वारा बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार करने की शिकायत विभागीय अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत होने पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय, आड़ावाल, जगदलपुर, जिला बस्तर का संचालन व्यवस्थित रूप से नियमानुसार किया जा रहा है। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जा रहा है।

श्री सावित्री मनोज मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया समाज कल्याण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय आड़ावाल, जगदलपुर, जिला बस्तर में अध्ययनरत बच्चों को हॉस्टल वार्डन के द्वारा गुणवत्ताहीन भोजन दिया जाता है, साथ ही वहां पर कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा भी मासूम बच्चों के साथ बदसलूकी की जाती है और साथ ही साथ बच्चों को डराया-धमकाया भी जाता है। उनको यह बोला जाता है कि यदि आप लोग हॉस्टल की घटनाओं को बाहर लीक करेंगे या किसी को बतायेंगे तो आपको हॉस्टल से बाहर कर दिया जाएगा। इस तरह से जब बच्चों का सब्र का बांध टूट गया तो उन्होंने उसकी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से की, लेकिन तब भी व्यवस्था में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। इसकी जांच नहीं होने एवं वहां पर जितने भी जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होने के कारण शासन-प्रशासन के प्रति आम जनता में काफी रोष व्याप्त है। यह अव्यवस्था केवल आड़ावाल का ही नहीं है। बस्तर संभाग में जितने भी संचालित छात्रावास आश्रम हैं, चाहे वह एकलव्य हो या प्रयास हॉस्टल हो, यहां सभी जगह ऐसी समस्याएं हैं। यह गंभीर मामला है, यह हमारे बस्तर के आदिवासी बच्चों का मामला है। इसलिए मैं चाहती हूं कि इस मामले पर जांच हो और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई हो।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया सदस्य ने ध्यान आकर्षण में जो सवाल पूछा है। मैं माननीया सदस्य को यह अवगत करा देना चाहती हूं कि विभागीय अधिकारियों के द्वारा समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है। बच्चों के द्वारा कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह भोजन की बात हो या चाहे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की बात हो। क्योंकि मैंने भी वहां जानकारी ली है और पहले भी जानकारी लेते रही हूं, लेकिन इस तरह की शिकायत हम तक नहीं पहुंची है।

श्री सावित्री मनोज मण्डावी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभागीय अधिकारियों के द्वारा वहां हॉस्टल में नहीं जाया जाता है। मैं स्वयं एक-दो जगह के हॉस्टल में गई थी। वहां बहुत सारी अनियमितताएं हैं। मैं चाहती हूं कि वहां पर अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे। हॉस्टल की जो अव्यवस्था

है, वह वहां पर देखें और उनको सही गाईडलाईन दें ताकि हमारे बच्चे हैं, वह अच्छे से हॉस्टल में रह कर पढ़ाई कर सकें।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीया सदस्य स्वयं विद्यालयों में गई होंगी और वहां अनियमितताएं पाई गई होगी तो उन अनियमितताओं को सुधारने के लिए मैं अधिकारियों को साफ निर्देश दूंगी। समय-समय पर अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार विद्यालयों में जाना होता रहता है। वे बच्चों को मार्गदर्शन भी देते हैं। वहां जो छोटी-मोटी अव्यवस्था रहती हैं, उस पर भी अधिकारियों के द्वारा साफ निर्देश दिये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- हर्षिता जी, आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही एक घटना है। हमारे विधान सभा क्षेत्र की एक लड़की हेमलता वर्मा है, जो वहां की पी.जी. गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। उसके गायब होने के बाद हमको जानकारी मिली कि वहां न अटेंडेंस होता था, ना ही वहां कोई लड़कियां हैं या नहीं है उसकी जानकारी होती थी। चार दिन बीतने के बाद जब उनके पिता जी को फोन नहीं आया तो वे हॉस्टल में आये तब पता चला कि वह लड़की गायब है और हॉस्टल वार्डन कहते हैं कि वह हॉस्टल में हैं। ऐसी घटनाएं पूरे छत्तीसगढ़ में घटित हो रही हैं। अभी हम बहुत सारे अपराध की खबर समाचार पत्रों में देख रहे हैं। अगर हॉस्टल वार्डर व्यवस्था नहीं कर सकते या ऐसी स्थिति व्यवस्थित नहीं होगी तो कहीं न कहीं हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए कैसे भेजेंगे? यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसमें कहां से आ गये?

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में भी माननीय मंत्री महोदया जी से विशेष आवासीय प्रशिक्षण स्कूल दिव्यांग कचांदूर के सबंध में बात रखा था। यह बजट में नहीं आया, यह मेरे लिए दु:ख की बात है। क्योंकि वहां ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, जहां कुछ बच्चों के अभिभावक भी नहीं हैं और कुछ ऐसी परिस्थिति है कि वे चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते। आज वह बच्चे सुविधांए और संसाधन के लिए तरह रहे हैं, वहां भी वही शिकायत माननीय सावित्री मंडावी जी ने किया है, वहां भी शिकायत आ रही है कि लगातार वहां के वार्डन द्वारा बच्चों को न ही पर्याप्त सुविधायें दी जा ही है और न खाने की सुविधा मिल रही है । यदि उनके खिलाफ शिकायत होती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने पर उतारू हो जाते हैं और वार्डन की अनुपस्थिति में 4 कर्मचारियों का वहां से

स्थानांतरण हो चुका है, वहां से हटा दिये गये हैं । इस तरह से लगातार शिकायतें आ रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय जी, इसमें जरूर संज्ञान लें और उचित कार्यवाही करें, ताकि उन बच्चों को सुविधायें मिल सके । मेरा आपसे यह निवेदन है कि कम से कम उन बातों का भी संज्ञान लें ।

अध्यक्ष महोदय :- चातुरी नंद जी ।

श्रीमती चातुरी नंद (सराईपाली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-एक हॉस्टल वार्डन मन ला दो-दो हॉस्टल के जिम्मेदारी दे गे हे । तेखर सती वोमन न हॉस्टल के देखरेख कर सकें, अऊ न ही लइका मन के देखरेख कर सकें । इहू तरफ घलो ध्यान दे के आवश्यकता हे ।

समय
12.36 बजे

नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचनायें सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री अजय चंद्राकर
(2) श्री बघेल लखेश्वर
(3) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल
(4) श्री जनक ध्रुव
(5) श्री धरमलाल कौशिक

समय
12.37 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेगी :-

(1) श्री ललित चन्द्राकर
(2) श्री इन्द्रशाह मंडावी
(3) श्री दलेश्वर साहू
(4) श्री संदीप साहू
(5) श्री उमेश पटेल
(6) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
(7) श्री गुरू खुशवंत साहेब
(8) श्रीमती रायमुनी भगत

अध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिये आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा । श्री किरण देव चर्चा प्रारंभ करेंगे ।

समय
12.38 बजे **वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिये आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)**

श्री किरण देव (जगदलपुर) :-माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-2026 के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास के लिये लाया गया बजट निश्चित रूप से सरकार के विकास की प्रतिबद्धता और प्रमाणिकता की ओर इंगित करता है । अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट की विशेषता यह है कि बजट सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है, बहुआयामी है, इसके अंतर्गत जितने भी निहित योजनाओं पर प्रावधान किया गया है, यह निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के दृष्टिकोण से है । अध्यक्ष महोदय, सभी क्षेत्र हो, सभी वर्ग हो, सभी समाज हो, चाहे उसमें हमारे युवा हैं, युवाओं के उत्थान के विषय को लेकर हमारे किसान भाईयों और अन्नदाताओं के लिये हो, चाहे मातृत्व शक्ति को संबल प्रदान करने की दृष्टि से हो, चाहे हमारा व्यवसाय वर्ग हो, उद्योग एवं लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग एवं मध्यम उद्योग हो, यहां तक कर्मचारी वर्ग की भी चिन्ता इस अनुमानित बजट में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किया है, मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ । अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य अजय चंद्राकर जी ने अनुपूरक बजट पर अपना विषय रख रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि हमारे बीच जो युवा वित्त मंत्री हैं और जिस तरह से दूरदृष्टि के साथ छत्तीसगढ़ के समग्र विकास की चिन्ता करते हुये अपनी प्रतिबद्धता आपने इस बजट में प्रस्तुत किया है । मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, इससे सरकार के डेवलपमेंट का जो विजन है, जिसमें प्रदेश के हर समुदाय और हर वर्ग के लोगों का समावेश करते हुये योजनाओं में प्रावधानित किया गया है, इस पर अग्रसर होंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में विगत वर्ष की जो प्रभावशाली योजना है, वर्ष 2024-2025 का जो हमारा पिछला बजट था, जिसमें हमारे आदरणी मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा था, वह ज्ञान का था । क्योंकि ज्ञान के अंतर्गत गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और नारी के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनको प्रावधान में लाकर उनको किस तरीके से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल जाये, यह उसमें दिखा भी है । 2025-26 के बजट में उस ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए उसमें गति प्रदान करने की बात की है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। इसके लिए बहुत-बहुत अभिनंदन । (मेजों की थपथपाहट) बहुत ही सोच के साथ यह बजट लाया गया है । जब गति की बात करते हैं तो निश्चित रूप में उसमें इन योजनाओं को संबंधित सरकार, प्रशासन के माध्यम से G for

Good Governance, A for Accelerating Infrastructure, T for Technology जिसको हम प्रौद्योगिकी मानते हैं और I for Industrial Growth. इस वर्तमान अनुमानित बजट में सभी विषयों का उल्लेख है । इसमें अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। कल ही इस बजट पर व्यापक रूप से चर्चा हुई, दोनों तरफ के सदस्यों ने इसमें भाग भी लिया। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मुझे अर्थशास्त्र के विषय में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है इसलिए मैं आंकड़ों पर नहीं उलझूंगा और आंकड़ों के विषय पर चर्चा भी नहीं करूंगा, लेकिन वर्तमान परिवेश में इतना जरूर कहूंगा कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र में इसकी विशेषता यही है कि आप सरकार में रहते हुए जनहित के विषय में प्रभावशाली योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं का लाभ सीधे-सीधे आम जनता तक पहुंचे । सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र में सबसे बड़ा प्रमाण आम जनता के प्रति सरकार की योजनाएं हैं और उसका प्रमाण-पत्र इस बात का द्योतक है कि उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं आत्मसात किया । जैसा कि मैंने कहा कि मुझे अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, यहां हमारे काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, जिनको वर्षों का अनुभव है । मैं तो पहली बार चुनकर इस सदन में आया हूं, लेकिन इसका प्रभाव पिछले 24 घंटों में, 48 घंटों में प्रतीत हुआ, जब पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से, हम बस्तर और सरगुजा क्षेत्र से ही ले लें तो ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का इतनी बड़ी मात्रा में वनवासी अंचलों में इसका समावेश किया है । कोई भी वर्ग हो, जब उनसे इस बजट की प्रशंसा सुनने को मिलती है तो यह उसका सच्चा और सीधा प्रमाण माना जा सकता है । अब उसका प्रमाण यह दिया है कि पिछले बजट में जो प्रावधान किया गया, हमारी नारी शक्ति को सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से हो, किसान भाइयों की दृष्टि से हो, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो और इस दृष्टि से उसका प्रमाण पत्र जनता ने दिया । लोकसभा चुनाव हुए लगभग 9-10 महीने हो गए, अभी-अभी नगरीय निकाय के चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बहुत बड़े बहुमत के साथ जनता ने अपना मत दिया, अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, वह उसका प्रमाण-पत्र है । (मेजों की थपथपाहट)

समय :
12:44 बजे **(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं)**

सभापति महोदया, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा मूल विषय यह होता है कि सरकार की योजनाएं त्वरित गति से जिन हितग्राहियों के लिए योजनाओं का निर्माण किया गया है, उन योजनाओं को जिस तीव्र गति से उनको लाभ पहुंचे और वह हितग्राही लाभान्वित होकर लाभार्थी के रूप में परिवर्तित हो, यह पिछले 1 साल, 4 महीने में विष्णु देव साय जी की सरकार ने करके दिखाया है । इसके लिए मैं बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत बधाई देता हूं । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति जी, योजनाओं का सिर्फ निर्माण करना ही आवश्यक नहीं है, योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन करना एक बहुत बड़ा विषय

है । अगर मैं बजट के विषय को लेकर ध्यान दिलाऊं तो बजट की जो आकार है, वह छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रारंभ में 2001-02 में 5700 करोड़ रूपए का बजट था और क्रमशः 2010-11 में 24685 करोड़, 2020-21 में 95,685 करोड़, 2024-25 में 1,47,446 करोड़ और इस वित्तीय वर्ष में 1,65,000 करोड़ का अलग-अलग योजनाओं में प्रावधान अपने आप में सारी कहानी बताता है। (मेजों की थपथपाहट)

मानननीय सभापति महोदया, ज्ञान को गति देने के विषय पर मैंने जब इस विषय को रखा और पिछले वर्ष में बजट में जो प्रावधानित किया गया था, तो सबसे पहले मैं उस विषय को रखूंगा। चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ अन्नदाताओं का प्रदेश है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मैं अपने विषय को बहुत ज्यादा किसी के अगेंस्ट या किसी के ऊपर प्रहार करना, यह मेरे स्वभाव में भी नहीं है लेकिन मैं बातों-बातों में जरुर इस बात को इंगित करना चाहूंगा कि किसान भाईयों के लिए सबसे प्रमुख विषय जो रहा है, जिसमें हमारी सरकार ने विधान सभा चुनाव के पहले वचन दिया था कि हमारी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों से प्रति क्विंटल 3100 रुपए में धान खरीदेंगे और लगातार उस समय भी और इस वर्ष भी प्रति क्विंटल 3100 रुपए में धान खरीदने का जो निर्णय लिया था, उसे चरितार्थ करके दिखाया है। यह हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री श्री विष्णु देव साय जी की किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है। इसके साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। हम जब कहते हैं कि हमारी पार्टी हो या हमारी सरकार हो, न सिर्फ छत्तीसगढ़ और विभिन्न प्रांतों बल्कि देश में आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हम जो कहते हैं, वह करते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदया , माननीय सदस्य जी 3100 रुपए राशि की बात कर रहे हैं लेकिन आप लोगों ने उसमें एक बात और कही थी कि आप काउंटर लगाकर पंचायत के सामने राशि देंगे लेकिन वह राशि नहीं मिली। उसके लिए आवाज उठानी पड़ी, तब आप 17 जनवरी वाली राशि भी बहुत लेट से डाले हैं।

श्री किरण देव :- आदरणीय सभापति महोदया , इसीलिए मैंने संक्षेप में माननीय सभापति जी के सामने कहा था कि कहीं इधर का मामला उधर न मुड़ जाए। मैं साफ तरीके से कह रहा हूं कि किसी भी योजना के लिए जो प्रावधान है, उसके क्रियान्वयन में कहीं थोड़ी बहुत इंचभर की इधर-उधर होगी, उससे ज्यादा यह जरुरी है कि उस योजना का कितना प्रतिशत लाभ उन लोगों को प्राप्त हो रहा है, जिनके लिए वह बनाई गई है। क्षमा सहित मैं इतना जरुर कहना चाहूंगा कि योजनाएं तो पिछले पांच सालों में भी आपने बनाईं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदया , यदि आप 3100 रुपए प्रति क्विंटल की राशि दे रहे हैं, तो वह माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की देन है, अन्यथा आप तो पिछले 15 सालों से 1500 रुपए में अटके हुए थे।

श्री किरण देव :- माननीय सभापति महोदया, अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूं। आपने इतनी सारी योजनाएं कागज में बनाईं, अगर उनका क्रियान्वयन सही प्रतिशत में होता, तो ये कश्ती मझधार में डूबी क्यों?(मेजों की थपथपाहट) ये आत्म अवलोकन का विषय है।

माननीय सभापति महोदया, इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे सीधे-सीधे बजट पर बात करने दिया जाए। बहुत स्पष्टत: मैंने पहले भी कहा है कि यह आत्म अवलोकन का विषय है कि किन कारणों से आज आप उधर है और किन कारणों से आज हम इधर हैं। अगर इस पर चर्चा निकलेगी, तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए इसे रहने दिया जाए, तो ज्यादा अच्छा होगा।

माननीय सभापति महोदया, हम जब अपनी योजनाओं के विषय में बात करते हैं कि हमारी सरकार में आदरणीय मुख्य मंत्री विष्णु देव साय जी ने यह काम किया है, तो उस विषय पर मैं जरुर कहूंगा कि जैसा कि कृषक उन्नति योजना का विषय भी आया था, उसके अंतर्गत किसानों को फसल का अधिकतम दाम दिलाने की दृष्टि से खरीफ सीज़न वर्ष 2024-25 की अगर हम बात करें, तो 149 लाख टन से अधिक धान की खरीदी की गई, जिसमें किसान को आर्थिक मजबूती प्रदान की गई है और प्रदेश के किसान भाइयों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरस्कृत भी किया है। इसके आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी का धन्यवाद। उनके दो वर्ष के बकाया बोनस की राशि भी दी गयी। हालांकि बकाया बोनस की मांग आयी नहीं थी। किसान भाइयों ने इस बकाया बोनस की मांग नहीं की थी, फिर भी 3,716 करोड़ रूपये सहित लगभग 1 लाख करोड़ रूपये का भुगतान कर 14 माह में किसान भाइयों को दो बार के बकाया बोनस की राशि दी गयी है। मैंने जिस तरीके से पहले भी कहा कि यह किसान भाइयों के प्रति चिंता को प्रदर्शित करता है। पूर्ववर्ती सरकार में जब हमारे वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी, तब उन्होंने 3 एच.पी. तक के कृषि पंपों, 6 हजार यूनिट तक बिजली के तहत 3 से 5 एच.पी. के पंपों पर 7,500 यूनिट प्रतिवर्ष नि:शुल्क बिजली प्रदाय की। हमारे जो ट्राईबल क्षेत्र हैं, वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की दृष्टि से किसानों को संपूर्ण खपत पर नि:शुल्क विद्युत उपलब्ध कराने की योजना हेतु इस बजट में 3,500 करोड़ रूपये का भी प्रावधान किया गया है, मैं उसके लिए भी वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन।

सभापति महोदया, मैं महिला सशक्तिकरण की बात करना चाहूंगा। मैं वास्तविकता में ज्ञान पर आ रहा हूं। ज्ञान को गति देने का विषय है। हमने महतारी वंदन योजना के तहत वचन भी दिया था और उसको पूरा करने का काम भी विगत एक वर्ष में किया गया है। पिछले बजट के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी और आदरणीय वित्तमंत्री जी ने उस योजना के लिए राशि प्रावधानित की थी। हमारे छत्तीसगढ़ की करीब-करीब 70 लाख माताओं और बहनों को इसका लाभ मिल रहा है। इसकी विशेषता यह है कि यह पिछले 10 माह से और यह 11वां माह हो रहा है, प्रत्येक माह की पहली तारीख

को उनके खाते में 1,000 रूपये भेजने का निर्णय लिया गया है, ताकि वह महिला जो आर्थिक रूप से कमजोर है या किसी तरीके से उनका परिवार विपन्नता की ओर है, उसमें नारी शक्ति को थोड़ा-सा सशक्तिकरण प्राप्त हो सके। उनकी जो रोजमर्रा की आवश्यकता है या उनके जो तीज तिहार होते हैं, वह राशि उसमें काम आ सके। हमारा प्रदेश तो त्यौहारों का प्रदेश है और उसमें किसी प्रकार से उनको सरकार की ओर से मदद मिल जाये।

श्री रामकुमार यादव :- किरण देव जी, आप बढ़िया बोलत हव। आप ला धन्यवाद हे। आप हमारे आदरणीय जी हरे। महोदय, लेकिन में हर ये कहात हव तुंहर भाषा ला में हर सुनत बइठे हव अउ तुंहरे सदस्य हर भाग गे हे। आप मन प्रदेश अध्यक्ष हरव। थोड़ा ये बात ला चिंता करिहव।

श्रीमती भावना बोहरा :- रामकुमार जी, पीछे ए डहार ला देख ले, हमन बइठे हन।

श्री किरण देव :- रामकुमार जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। संख्या तो दोनों तरफ देख लीजिए। मैं संख्या के विषय पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप तो दो बार के विधायक हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं। आपका बड़ा सम्मान है और आप हमारे अच्छे मित्र भी है।

सभापति महोदया, इसी तरीके से वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रावधानित 3,000 करोड़ रूपये में 83.33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसी महतारी वंदन योजना के लिए और 5,500 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। इसके आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी महतारी शक्ति, जो इस दुनिया की आधी आबादी है, उनको इस दृष्टि से संबल प्रदान करने का काम किया है। सभापति महोदया, उसके लिये भी मैं इस सदन में आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय ला रहा हूं। आंगनबाड़ी में बच्चों को प्रदाय किये जाने वाला जो गुणवत्तायुक्त पोषण, रेडी टू ईट का विषय है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, रमन सिंह जी की पूर्ववर्ती सरकार में रेडी टू ईट का काम, महिला स्व सहायता समूह का निर्माण करने का काम भी प्रारंभ हुआ था। तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में बीच में रेडी टू ईट का काम महिला स्व सहायता समूह से पृथक करके दूसरी एजेंसी को सौंपने का निर्णय हुआ था। इस बार महिला स्व सहायता समूह को पुन: रेडी टू ईट का काम सौंपने का निर्णय बहुत ही प्रशंसनीय है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदया, मैं मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के विषय पर आना चाहूंगा। क्योंकि यह जो नारी शक्ति है, मैं बार-बार इस विषय को दोहराऊंगा। इनको संबल और ताकत प्रदान करना बहुत आवश्यक है। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने भी इसको अपने स्वप्न में रखा है। निर्धन बेटियों का जीवन और जब ऐसे परिवार में विवाह की स्थिति आती है। जिस परिवार में आर्थिक परिस्थितियों से विपन्नता रहती है और उसके साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और मुख्यमंत्री कन्या दान योजना के लिए इस बजट में अतिरिक्त 40 करोड़ रूपये का प्रावधान

किया। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। हमारे प्रदेश की माताओं एवं बहनों को स्वावलंबन प्रदान करने के लिए यह आर्थिक रूप से बहुत आवश्यक है। पूर्व में एक वर्किंग वूमन हॉस्टल का विषय आया था। यहां पर 7 वर्किंग वूमन हॉस्टल निर्माण हेतु 79 करोड़ रूपये का प्रावधान है। हमारे जो ट्रायबल क्षेत्र बस्तर और सरगुजा हैं जब इन क्षेत्रों में सरकारी स्तर पर हमारी बहनें या बेटिया सरकारी रूप से रोजगार या स्वावलंबी बनने की दृष्टि से अन्य विभागों में जाती हैं या जब वहां पर उनकी पोस्टिंग होती है तो यह अक्सर देखने में आता है कि वह जब अकेली रहती हैं तो उनको कई अव्यवस्थाओं का बड़ा शिकार होना पड़ता है। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद् देता हूँ कि उन्होंने इसे ध्यान में रखा और वह वहां पर रहकर सुविधाजनक ढंग से कार्य कर सकें। इसके लिए रायपुर, बिलासपुर, नवा रायपुर अटल नगर में कामकाजी महिलाओं को बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु 7 वर्किंग वूमन हॉस्टल निर्माण हेतु 79 करोड़ का प्रावधान है। इसके लिए 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, यह अद्भुत है। मैं, आपका इसके लिए भी अभिनंदन करता हूँ। कृषि एवं प्रौद्योगिकी में कहना चाहूंगा। मैं यह बात समय-समय पर करता रहा हूँ। जब मैं सदन में हमारे वरिष्ठ सदस्यों के माध्यम से यह प्रश्न सुनता था कि प्रदेश में कहीं गुड़ बंद हो गया है, कहीं पर चना बंद हो गया है, उसके लिए प्रावधान किया गया है। हमारे पूरक पोषण आहार में इस योजना के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। गुड़ नियंत्रण प्रयोगशाला, हमारे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में स्थापित करने के लिए अलग से भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ 25 लाख का प्रावधान किया गया है मैं, उसका भी अभिनंदन करता हूँ। आपको इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। विशेषकर ट्राईबल क्षेत्रों में हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के महिला कृषकों के प्रोत्साहन हेतु बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन शुल्क पर अनुदान हेतु 1 करोड़ 97 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, यह अपने आप में बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। हमारे कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने की दृष्टि से मुंगेली के परिसर में नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालय मुंगेली की स्थापना हेतु राशि 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है यह भी बहुत ही प्रशंसनीय है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारे राज्य के सभी परिवारों को खाद् सुरक्षा उपलब्ध करने के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत 4 हजार 500 करोड़ का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है। वह भी निश्चित रूप से बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं करोनाकाल की बात करूं। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। कल यहां पर यह विषय आया था। यहां एक प्रश्न के माध्यम से कोरोना का विषय आया था। कोरोना के विषय में जिस तरीके से सराहनीय काम हुयें क्योंकि कोरोनाकाल ऐसा समय था जब हमने खुद अपनों की ही पहचान खो दी थी। सारा देश और विश्व मुख में पट्टी बांधकर, घूम रहा था ऐसे समय में देश के

यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने जिस तत्परता के साथ कदम उठाये। हमारे देश में यहां एक सुई निर्माण का कार्य कठिन हो जाता था कोई नई दवाई के ईज़ात में फार्मासिस्ट में कठिनाई हो जाती थी। उस समय हमारे देश में कोवैक्सिन और कोविशिल्ड का तत्परता से निर्माण हुआ तथा उन्होंने हमारे देश के अलावा, बाहर भी 112 देशों में भेजकर, सहायता प्रदान की । इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के सदन में जितने सदस्य एक साथ बैठे हुए हैं और हम अपने जीवन में श्वास ले रहे हैं और हम खुशहालीपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करूंगा। इस तरीके से स्वास्थ्य के विषय में अनेक निर्णय लिये गये हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका भी बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बस्तर संभाग एवं सरगुजा संभाग के जिलों को बहुत ही प्राथमिकता के साथ इस बजट में स्थान दिया गया है इसलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद् देता हूँ। क्योंकि बस्तर और सरगुजा को वनांचल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वहां पर आज भी सरकारों के माध्यम से समय-समय पर अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती है। आज भी हमारे बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी, वनवासी क्षेत्र के दूरस्थ अंचलों में विकास की अनंत संभावनाएं हैं। इस दृष्टि से मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद् दूंगा कि उन्होंने इस बार प्राथमिकता के साथ और बहुतायत में इन ट्रायबल क्षेत्रों की चिंता की है।

समय
1.00 बजे

माननीय सभापति महोदया,प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रदेश के आवासहीन परिवारों की चिंता देश के प्रधानमंत्री जी ने की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मैं निश्चित रूप से इस बात को कहना चाहूंगा कि विगत 05 वर्ष में विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी कल्याणकारी योजनायें छत्तीसगढ़ में बाधित थीं, छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से उतना आकार नहीं लिया और गरीब परिवार के हितग्राहियों को जिस प्रकार से उसका लाभ मिलने से वंचित किया गया और आवासहीन परिवारों की चिंता जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने की। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद सरकार ने आवासहीन परिवारों को घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 8500 करोड़ रुपये का पृथक से प्रावधान किया है। उसके लिए वित्त मंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) पीएम जन मन आवास योजना में भी इसी तरीके से पिछड़ी जनजाति समूहों के आवास निर्माण के लिए विशेष रूप से 300 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आवास मित्रों के प्रोत्साहन के लिये भी बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। अगर हम विकास की दृष्टि से देखें, मेरा यह कहने के पीछे सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अगर

हम नगरीय निकाय क्षेत्र में विगत 1 वर्ष की बात करें, हमारे नगरीय निकाय मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से मैं इस सदन में उनका, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं। पिछले 01 वर्ष में नगरीय निकाय क्षेत्र में एक ईंट नहीं लगी थी, वहां 7 हजार करोड़ रुपये का काम करके उसमें तेजी से मूलभूत बुनियादी सुविधायें जैसे सड़क की जहां भी आवश्यकता है, उसके लिए उन्होंने दिया है। उसके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 845 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में 129 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 845 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अत्यंत पिछड़ी आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए भी प्रावधान किया गया है। हमारे यहां वनवासी क्षेत्रों में, हमारे ग्राम, टोला से छोटी-छोटी सड़कें जो मुख्य मार्ग से आकर जुड़ती हैं, वहां पर इनकी उपयोगिता विशेष कर बरसात के मौसम में बहुत है। उस दृष्टि से मुख्य मार्ग को ऐसी सड़कों से जोड़ने के लिए पी.एम. जन मन सड़क निर्माण योजना अंतर्गत बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदया, मैं धन्यवाद दूंगा कि स्वास्थ्य विभाग में जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा, कुनकुरी में चिकित्सा महाविद्यालय के साथ-साथ बस्तर में मनोउपचार की दृष्टि से भी जो चिकित्सालय खोलने का निर्णय लिया गया है, उसके लिए भी अभिनंदन। राज्य के युवाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 13 नर्सिंग महाविद्यालय, 6 फिजियोथैरेपी कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है, यह अपने आप में अद्भूत है। इसको बजट में प्रावधानित करने के लिए अभिनंदन। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदया, गृह विभाग सुरक्षा का विभाग है। इसके विषय पर कई तरह की बातें होती हैं। पुलिस के बुनियादी ढांचा के विकास की दृष्टि से प्रश्नों के माध्यम से प्रतिदिन अलग-अलग विषय आते हैं, गृह विभाग में निश्चित रूप से इस ओर चिंता की गई है। पुलिस के बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि से बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहता हूं। इस राशि का उपयोग वास्तव में पुलिस थानों का निर्माण, पुलिस कर्मियों के आवास, प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्रों की दृष्टि से यह बहुत ही उपयोगी होगा। इसमें बहुत सारे प्रावधान किये गये हैं, मैं सबको नहीं लूंगा। इसके पहले के आपके माध्यम से निर्देश आयें, समय की भी अपनी बाध्यता है। इस तरीके से श्रम विभाग में, विधि विधायी कार्य विभाग में हैं। इसमें सभी विभागों को लिया गया है। सभापति महोदया, आपके माध्यम से अपने को यहीं पर रोकते हुए कि यह बजट वास्तव में सर्वव्यापी है, सर्वहारा, बहुआयामी है। इसमें बहुत सारे विषय हैं। ऊर्जा विभाग से लेकर अन्य विषयों पर प्रमुख विभागों के आवंटन में भी जिस तरीके से प्राथमिकता के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए जिस विभाग में काम करने की दृष्टि से और जितनी संभावनायें हैं, उसमें निरंतर बढ़ोतरी हुई है । मैं

आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को प्रमाणिकता के साथ और सभी योजनाओं पर और चूंकि इसको उसमें स्थान दिया गया है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं ।

मानननीय सभापति महोदया, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय सभापति महोदया, वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं ।

माननीय सभापति महोदया, लोकतंत्र में चुनाव जीते जाते हैं और लोकतंत्र का यह बुनियादी नियम है लेकिन पार्टी स्तर पर और न ही व्यक्तिगत स्तर पर यहां कोई खत्म नहीं होता । आदरणीय सभापति महोदया, पहले हमारी सरकार थी और आज आपकी सरकार है । मैं याद दिलाना चाहूंगी कि वर्ष 1977 में जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हारी थीं तो अमृतसर से लेकर पूरा कोलकाता तक पूरे कांग्रेस का सफाया हुआ था, मैं उस दिन को याद दिलाना चाहती हूं और आज का दिन याद दिलाना चाहती हूं । सम्माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी करेक्ट ढ़ाई साल बाद पूरी उसी चमक-धमक के साथ वह बहुमत के साथ आईं । मैं उस दिन को याद दिलाते हुए सामने बैठे हुए लोगों से यह कहना चाहती हूं कि हम तो आज 35 हैं, आप तो सिर्फ 15 थे और जब 15 थे और उसमें आप सरकार लाए तो हम तो 35 हैं, आप सोच लीजिए, हमारी सरकार आना निश्चित है । सरकार आने की खुशी में एक-बार ताली बजा दो । (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदया, बोल के ताली बजवानी पड़ रही है । आप अब reaction समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदया, क्योंकि आप लोग ऐसे बैठे हैं, देख रहे हैं, घूर रहे हैं । आप लोग एकदम चिंता में हैं तो हम लोग भी आपका उस चिंता में साथ दे रहे हैं ।

श्रीमती भावना बोहरा :- मैं आपका घूरने का मतलब नहीं समझ पाई । माननीय सभापति महोदया, इनका घूरने से क्या मतलब है ? कौन घूर रहा है ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सही बात के लिये समर्थन मांगा जाता है, वह कोई गलत बात नहीं है, सही बात के लिये समर्थन मांगा है ।

श्रीमती भावना बोहरा :- अपनों में समर्थन बिना बोले मिल जाता है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मेडम, हर सही बात के लिये समर्थन मांगा जाता है। आपने भी कई अवसरों पर समर्थन मांगा है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदया, जब यह बजट आया तो मैं बहुत उत्साहित थी । यहां वित्त मंत्री जी हैं, मैं बहुत उत्साहित थी कि इसमें महिलाओं के लिए होगा, इसमें किसान

भाइयों के लिए होगा, युवा साथियों के लिए होगा । मैंने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया लेकिन मुझे निराशा ही हाथ लगी क्योंकि हमने कुछ और सोचा था और कुछ और हुआ । कई लोगों की आशाएं थीं, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की जनता पूरे बजट को देख रही थी कि हमारे लिए कुछ होगा लेकिन सभी ने अपनी-अपनी झोली को खाली महसूस किया । आदरणीय सभापति महोदया, वर्ष 2024-25 में जो अभी स्वीकृत हुआ है वह 1 करोड़ 65 लाख का बजट है और आपने जो वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 का पिछला बजट पेश किया है। वह राशि अभी तक पहुंची नहीं है, न ही एक पुल बना है, न ही यहां एक सड़क बनी है, कुछ भी नहीं है जो धरातल पर दिखे । यदि आप 10 करोड की राशि भी लाएंगे तो वह पेपर में ही रहेगा ।

आदरणीय सभापति महोदया, हमारे वित्त मंत्री जी ने खुद हाथ से लिखा है इसके लिये मैं माननीय वित्तमंत्री जी को बहुत बहुत-बधाई देती हूं कि आपने इतना अच्छा बजट लिखकर तैयार किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामना- बधाई । मैं इसके साथ में पृष्ठ-12 की बात रखना चाहूंगी, इसमें लिखा है कि लालफीताशाही को खत्म करने के लिए हम ई-ऑफिस प्रणाली अपना रहे हैं ताकि online तरीके से समय पर फाइलों का निपटारा हो, विलंब की ज़िम्मेदारी तय हो सके, भ्रष्टाचार की आशंका को भी कम किया जा सके । आदरणीय सभापति महोदया, अभी आपने देखा होगा सभी online होता है और हमारे वित्त मंत्री जी ई-ऑफिस प्रणाली की बात कर रहे हैं तो मैं यह कहना चाहती हूं कि स्कूल में, हॉस्पिटल में, तहसील कार्यालय में सब जगह पंचायत स्तर पर ई- ऑफिस लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब धान खरीदी की बात चल रही थी तो किसान लोग अपने पोते से ऑनलाइन करवाते थे। सिर्फ एक बोरा का धोखे से कटता था। आज भी किसान भाई लोग सिर्फ उस कंप्यूटर के सर्वर के कारण धान नहीं बेच पाए। पोर्टल का सर्वर डाउन होता था। सुबह 4:00 बजे उठकर वे लोग पोर्टल करते थे। हमेशा सर्वर डाउन मिलता था। तहसील ने आज भी जो भी रजिस्ट्री हो रही है, वह ऑनलाइन हो रही है। खाता विभाजन हो रहा है, वह ऑनलाइन हो रहा है। आपकी फौती उठ रही है, वह ऑनलाइन हो रही है, आपका जाति-प्रमाण पत्र बनाना है, वह ऑनलाइन हो गया, लेकिन क्या ये भ्रष्टाचार रुका है? आज भी लोग भ्रष्टाचार के शिकार हैं। सभापति महोदय जी, आज भी वहां पर लोगों को लाइन लगाना पड़ता है और जितने भी काम हैं, वह बल्कि और लेट से होता है। मैं कारण बता देती हूं, लोग , कंप्यूटर से काम करवाने के लिए जाते हैं, ऑनलाइन हो रहा है, बताया जाता है, ऑनलाइन से करवाते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता हैं कि वहां सर्वर डाउन है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तो ये बताओ, सर्वर तो सबका डाउन हो जाता है। आप लोगों का भी सर्वर 5 साल डाउन ही था। इसमें वित्त मंत्री जी ने क्या खराब काम कर दिया है? यह बताओ। हम लोग उसके लिए बैठे हैं। जो आपको लग रहा है, बहुत खराब काम किए है। सड़क बनाना है तो वह सब बताओ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं बता रही हूं। अगर ये ई-ऑफिस की बात कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि पहले तैयारी तो कर लें। पहले उस गांव में जाकर देख तो लें कि वहां की परिस्थिति क्या है? अगर आप गांव की स्थिति जाकर देखेंगे तो वहां पर टावर भी नहीं लगा है, आज ई-ऑफिस की बात कर रहे हैं। पहले बुनियादी स्तर तो तैयार कर लें।

श्री ओ.पी. चौधरी :- ये ई-ऑफिस मंत्रालय का है। मंत्रालय की फाइलों का है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप घर बनाने जा रहे हैं। अगर कोई भी घर बनता है तो नींव पहले डाला जाता है, यहां तो छत की ढलाई कर दिए हैं। आपने वहां पर नींव डाला ही नहीं। आपने 1 साल में ई-ऑफिस का ऐलान कर दिया। आप अगर गांव में जाकर देखेंगे, वहां भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। लोगों के पास मोबाइल नहीं है। लोगों के पास टावर नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ है, वहां पर जितने भी सरपंच है, तो उनमें से कई संरपचों को मोबाइल चलाना नहीं आता। अगर आपने ई- ऑफिस डाला है तो पहले तैयारी तो कीजिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- मंत्रालय का है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं मानती हूं कि वित्त मंत्री जी मंत्रालय की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को भी तो सुविधा चाहिए। वहां तहसील ऑफिस में तो अगर कंप्यूटर बिगड़ जाता है तो वे लोग मैकेनिक को बुलाकर वे ठीक करवाते हैं, नहीं तो वह एक सप्ताह, डेढ़ सप्ताह, दो सप्ताह तक कम्प्यूटर पड़े रहता है। आप स्कूल में जाकर देखिए, स्थिति वही है। तो मैं निवेदन करना चाहती हूं..।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं आपके क्षेत्र में गया था तो वो मुझे तो बताये कि संगीता सिन्हा जी बहुत बढ़िया काम करा रही हैं। सब काम ठीक-ठाक है। यहां पर आप सब गलती निकाल रही हो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं तो जमीनी स्तर पर बात कर रही हूं। मेरा काम है, गरीबों और नीचे तबके तक वहां पर आपकी योजना को पहुंचाना।

श्री धर्मजीत सिंह :- सरपंचों को मोबाइल चलाना नहीं आता। माननीय पंचायत मंत्री जी, अगली बार नियम बना देना कि जिसको मोबाइल चलाना नहीं आता, वह सरपंच का चुनाव नहीं लड़ेगा, फिर इनका हल्ला देखना ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं रोजगार में आती हूं। हमारे आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जो अभी सांसद हो चुके हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भर्ती की घोषणा किये तो आप लोगों ने उनको यहां से ट्रांसफर कर दिया। बृजमोहन जी का यहां से ही पूरा सफाया कर दिया । मतलब उन्होंने इतनी बड़ी क्या गलती की है? उनको यहां छत्तीसगढ़ राज्य से ही सीधा दिल्ली में पहुंचा दिया। बृजमोहन अग्रवाल जी ने घोषणा की थी कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती की जायेगी तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए..।

श्री धर्मजीत सिंह :- दिल्ली वाले को यहां बुला लिये हैं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- 1 मिनट। माननीय विधायक महोदया ये बोल रही हैं कि अभी तक शासकीय कर्मचारी अधिकारी का ट्रांसफर होता था, अब उधर से ऐसी व्यवस्था है कि नेता का होने लग गया। महोदय, ऐसा बोल रही हैं, उनके बोलने का आशय यह है।

श्रीमती भावना बोहरा :- शायद, नेता की जगह तो नेता ही आये हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- देखिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। आपने वहां से लाकर, आपने दिल्ली से वापस बुलाकर आपने कहां बैठा दिया? उनको सम्मानजनक जगह तो देनी था, जहां पर जगह है, वहां पर तो जगह ही नहीं दिए। बेचारे चुपचाप अकेले बैठे हुए हैं और वे तो यहां भी नहीं रहते।

श्री राजेश अग्रवाल :- उनको मंत्री का दर्जा है। सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- केवल दर्जा दे दिये न। मंत्री तो नहीं बनाये। हम तो उनका नाम मंत्रिमंडल में देख रहे थे।

श्री धर्मजीत सिंह :- जैसा आप लोगों ने टी.एस.बाबा का सम्मान किया था, वैसा सम्मान नहीं कर रहे हैं । उनको मंत्री बनाकर बैठाये हैं यहां पर ।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी, आप मन अइसना हो कि डायरेक्ट जहाज ले उतार के रिक्शा मा बइठा देव ।

श्री संगीता सिन्हा :- कल हमारे भाई साहब मूणत जी ने बहुत अच्छा स्पीच दिया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह पवित्र सदन आपको रिक्शा दिखता है । अगली बार रिक्शा में बैठने के लिए तरस जाओगे ।

श्री रामकुमार यादव :- हम लोग जो बोल रहे हैं उसको आपने एकदम से जोड़ दिया । आपने जिस प्रकार का सम्मान किया है केन्द्रीय मंत्री को बैठाकर रखा है, दीदी बोल नहीं रही है लेकिन हम उनकी भावनाओं को समझते हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हम उनके साथ हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- हम उनके साथ हैं । यह बात कह रहे हैं हम ।

श्रीमती भावना बोहरा :- मतलब आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि यह सदन रिक्शा है । आपने कहा ना । क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि हम रिक्शे में बैठे हैं। जो सम्मानित सदन है, हमारी बातों को रखने का प्लेटफार्म है, आप उसको रिक्शा कह रहे हैं । सभापति जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगी कि ..।

सभापति महोदय :- आप लोग अपनी अपनी बारी में अपनी बात रखिएगा ।

श्रीमती भावना बोहरा :- इस सदन को रिक्शा कहा गया, आपत्ति इसी बात पर है महोदय ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उदाहरण है, उपमा है ।

श्री रामकुमार यादव :- हमारी भावनाओं को समझिए ।

श्रीमती भावना बोहरा :- भावनाओं को तो आप बैठे बैठे भी समझा सकते हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, मैं डी.एड., बी.एड. के बारे में बोलना चाहती हूं । जिन बेचारों को नौकरी मिली थी, आपने उनको बिठा दिया । वे सिर्फ दो साल नौकरी कर पाए, उनको पेमेंट भी मिला है, उनको दो साल के बाद बिठा दिया । जब वे हड़ताल पर बैठे थे तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, बाहर के लोगों ने भी देखा कि कैसे उनको घसीटते हुए ले गए, महिलाएं चिल्लाती रहीं, बेटियां चिल्लाती रह गईं । आपने उनको पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में ले गए । क्या डी.एड., बी.एड वालों को नौकरी का अधिकार नहीं है । आपने उनको बिठाने का काम क्यों किया ? वित्त मंत्री जी इसको स्पेशल संज्ञान में लीजिए क्योंकि वे बच्चे ऐसे हैं जो इस नौकरी के लिए दूसरी नौकरी को छोड़कर आए हैं । उन्होंने इसी नौकरी के भरोसे शादी कर ली, अब उनका घर उजड़ रहा है । वित्त मंत्री साहब से विशेष निवेदन है कि इसको विशेष संज्ञान में लीजिए । अभी बजट पास हो रहा है उससे पहले इस बात तो जुड़वाएं कि डी.एड., बी.एड वालों को फिर से नौकरी में लिया जाए ताकि उनकी जिंदगी संवर सके । वे पुरानी नौकरी छोड़कर आए हैं, वे कहीं के नहीं रहे, अब वे केवल संघर्ष कर रहे हैं । वे हड़ताल कर रहे हैं, उनको सम्मान भी नहीं मिल रहा है, उनको घसीटकर ले जाया जा रहा है ।

आदरणीय सभापति महोदय, पूर्व में हमारी सरकार थी, जो बेरोजगार साथी आत्महत्या कर रहे थे । लगातार आत्महत्या की बातें सुनाई देती थीं, उनको बचाने के लिए, क्योंकि उनको घर से भी डांट पड़ती थी कि आप नौकरी नहीं कर रहे हो । बेरोजगार युवा साथी नौकरी के लिए तरसते थे, यहां तो नौकरी लगने का नाम नहीं है । वे आत्महत्या की ओर जा रहे थे । उसके लिए पूर्ववर्ती सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी ने बेरोजगारी भत्ता दिया था । मैं निवेदन करती हूं कि उस बेरोजगारी भत्ते को फिर से शुरू किया जाए । वित्त मंत्री जी यहां हैं, मुझे विश्वास है कि मैं जो बता रही हूं उनमें से कुछ कुछ योजनाओं को जरूर इसमें सम्मिलित करेंगे।

सभापति महोदय, आत्मानंद स्कूल ऐसी स्कूल है जिसमें गरीब के बच्चे, जो गरीब है, जो प्रायवेट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते । अगर बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है तो 2 से 3 लाख का खर्च होता है । मजदूरी करने वाला व्यक्ति इतना खर्च नहीं कर सकता है । मैं आपको बताना चाहूंगी कि निपानी गांव में जब मैं दौरे पर गई तो आत्मानंद स्कूल में एक गरीब बच्चा मैला-कुचैला कपड़ा पहनकर बैठा हुआ था । मैंने उससे यह पूछा कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहां हैं, क्या करते हैं तो उसने जवाब दिया कि मेरी मम्मी खेत में रोजी काम करने गई है । सभापति महोदय, मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई कि एक गरीब का बच्चा जो मैला-कुचैला कपड़ा पहना हुआ है और वह इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहा है । यह हमारे लिए गर्व की बात थी और मैं निवेदन करती हूं कि आत्मानंद स्कूलों को जिस तरह से चल रही हैं, वैसे ही चलने दिया जाए । उसको बंद करने का प्रयास न करें । मैं इस

सरकार से निवेदन कर रही हूं कि आत्मानंद स्कूल शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है जिसका लाभ हमारे हर वर्ग को मिलना चाहिए ।

सभापति महोदय, छात्रावासों की स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा । आज हमारी दीदी सावित्री मंडावी जी ने ध्यानाकर्षण सूचना लगाया था, मैंने उस समय कुछ नहीं कहा क्योंकि छात्रावास की स्थिति के बहुत सारे मामले मेरे पास हैं क्योंकि मैं जांच में भी गई हूं । सभापति महोदय, पखांजूर में छोटेडोंगर की घटना है। छोटेडोंगर में बच्चे शौचालय में सोने को मजबूर हैं। मैं उसके जांच के लिए भी गई थी। बच्चे ने कबूल किया कि मैडम हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। टायलेट सीट को ढककर उसके उपर बोरा बिछाकर सोने का काम कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप बड़े-बड़े बजट ला रहे हैं, उसमें छात्रावास के लिए भी बजट दी जाए, उसमें उचित व्यवस्था हो, वहां बिल्डिंग बने और बच्चे उचित व्यवस्था के साथ रहे। वहां पर रोटी बनती है तो पेपर में गेहूं का नाम लिखा है, खाने में कुछ नहीं है। हमने वहां पर बैडसीट के बारे में पूछा, नया-नया बैडसीट बिछा है, कहां का है, उन्होंने बताया कि आज ही बैडसीट बिछा है। आप उनको कुछ नहीं दे रहे हो, बजट आवंटन हो रहा है, वह बजट कहां जा रहा है। छात्रावास के लिए करोड़ों का बजट आता है लेकिन छात्रावास का जो बजट है, वह पेपर में ही रहता है, धरातल पर कुछ नहीं है, आप जाकर देखिए, वहां की स्थिति बहुत जर्जर है। CCTV कैमरे का भी मामला आया था लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगी, वह बजट से बाहर है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कोई बच्चा छात्रावास में है तो उनको उचित व्यवस्था मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए, जल्दी समाप्त करिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जी। आदरणीय सभापति महोदय, अधिकारियों कर्मचारियों का 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा है। यह तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ा है, वह बजट में आया है। यह तो सतत् प्रक्रिया है, महंगाई भत्ता हर 6 महीने साल भर में बढ़ता ही है। वित्त मंत्री जी स्वयं कलेक्टर रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या नया कर दिया कि कर्मचारियों अधिकारियों के 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते को बजट में शामिल किया। मैं बजट के मामले में यह भी कहना चाहती हूं कि महिलाओं से अच्छा बजट कोई नहीं बना सकता। अगर एक हजार में घर चलाना है तो महिलाएं अच्छी से जानती हैं कि कैसे चलाएं। सभापति महोदय, यही वह सरकार है जिन्होंने 500 रूपए में गैस सिलेण्डर देने की बात कही थी। आज तक हमने बजट में यही इंतजार किया कि इस बार 500 रूपए में सिलेण्डर मिलेगा लेकिन नहीं मिला, सिलेण्डर का नामों निशान नहीं हैं, आज जितने भी चर्चे हो रहे हैं, वहां सिलेण्डर का नाम नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुर्भाग्य है। उज्ज्वला योजना भी आपने ही लाया था। महंगाई इतना बढ़ गया है कि उज्ज्वला योजना कोई काम नहीं कर रहा है। मैं यह चाहती हूं कि जो गरीब तपके के लोग हैं, उनके लिए सिलेण्डर में पैसा थोड़ा कम करें, उनको 500 रूपए में सिलेण्डर दे

दीजिए, बड़े लोगों के लिए नहीं चाहिए, आयकर वालों के लिए नहीं चाहिए लेकिन गरीब लोगों को 500 रूपए में सिलेण्डर दी जाए।

सभापति महोदय, महतारी वंदन में जो छूटे हुए लोग हैं, उनको जोड़ने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, जितने लोगों को दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं। इसमें बहुत सारी महिलाएं छूटी हैं। अगर इसको देखा जाए तो यह संवैधानिक दृष्टि से ठीक नहीं है। किसी भी योजना का लाभ किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो यह संविधान का विरोध है। मैं निवेदन करती हूं कि यह लाभ दिया जाए। कामकाजी महिलाओं को बेहतर आवासीय सुविधायुक्त दिया। आपने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के लिए 5 करोड़ रूपए दी, सखी सेंटर के लिए 20 करोड़ है। यह मुझे आज तक धरातल पर दिखाई नहीं देता। आपने अभी 15 महीनों की स्थिति देखी होगी, बच्चों के साथ बहुत रेप हो रहे हैं। बच्चियों के लिए बीच-बीच में एक पुलिस थाना खोल देना था ताकि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें, बेटियां सुरक्षित रहें।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, बड़ी जल्दी चिंता हो गई, पिछले पांच साल चिंता नहीं किए। ये क्या बात हुई।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं उस बात पर आ रही हूं। इन्होंने दारू में छूट दी है। यहां पर ये 15 लोग बैठे थे। दारू बंद करो-दारू बंद करो। मतलब, यदि एक दिन भी कार्रवाई होती थी तो वह पूरा दिन दारू पर रहता था। आज वह कहां गये ? आज आपने दारू को सस्ता किया है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदया, 2 काउंटर चलाने वाले बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं। आप पूर्ववर्ती सरकार के 2 हजार करोड़ रूपये के घोटाले का भी तो जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ की अस्मिता को तार-तार करने वाले आज प्रश्न पूछ रहे हैं। यह अच्छा नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदया, आज 50 प्रतिशत महिलाएं आपसे दु:खी हैं। आप महतारी वंदन योजना के तहत उनको प्रतिमाह 1 हजार रूपये का लाभ दे रहे हैं, उसके बाद आप उनके सारे पैसे ले जा रहे हैं। सभापति महोदया जी, आप समाप्त करने के लिए कह रही हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि आपने पेट्रोल के रेट को कितना कम किया? केवल 1 रूपये कम किया। आज की महंगाई के जमाने में यदि आप 1 रूपये लेकर जाएंगे तो उसकी कोई वेल्यू नहीं है। यदि आप भीख मांगने वाले को भी 1 रूपये देंगे तो वह उसको accept नहीं करता है। मैं यह कहना चाहती हूं कि जब हमारी सरकार केन्द्र में थी तो पेट्रोल का रेट 70 रूपये था, तब आपने चिल्ला-चिल्ला कर बोला था। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदया, जब पूरे देश ने पेट्रोल के रेट को कम किया था तो इनके कार्यकाल में वह भी कम नहीं हुआ था। यह ध्यान नहीं देती हैं और इतिहास को पढ़ती नहीं हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदया :- सुशांत जी, आप इनको बोलने दीजिए। संगीता जी, आप जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदया, मुझे बोलने का मौका दिया जाये। अभी मेरे बहुत सारे विषय शेष हैं।

सभापति महोदया :- नहीं-नहीं, आप जल्दी समाप्त करें। आपको 20 मिनट से ऊपर हो चुके हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदया, उस समय पेट्रोल का रेट 70 रूपये था और आज 102 रूपये हो गया है। यदि आप पेट्रोल के रेट को 1 रूपये कम कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है?

सभापति महोदया :- संगीता जी, आप उस तरफ देखकर मत बोलिये। आप सीधे-सीधे बोलिये। आप जल्दी 2-3 मिनट में समाप्त करिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, हम लोगों ने शराब के रेट को भी कम किया है। हमने विदेशी मदिरा के रेट को भी कम किया है और उसमें तो लंबा कम किया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदया, आपने क्या किया है? आपने दारू को इतना बढ़ावा दिया है कि अब हर रेस्टारेंट में दारू मिलेगी। यह आपके लिए कितनी लज्जा की बात है। कितनी लज्जा की बात है। आप दारू की बात करते हैं और यह बोलते हैं कि अब हर रेस्टारेंट में दारू मिलेगी। यह उचित नहीं है। हर रेस्टारेंट में दारू मिलेगी और वहां पर बैठकर भी दारू पीने की व्यवस्था होगी तो यह कहां से उचित है कि हर रेस्टारेंट में दारू मिलेगी ? लोग दारू पीयेंगे और वहां पर बैठकर दारू पीयेंगे और उनके घर में एक्सीडेंट होंगे। यह स्थिति होगी। आपको तो दारू को बंद करना चाहिए और अभी के अभी बंद करना चाहिए। आप दारू पर छूट दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- संगीता जी, शर्म की बात तब भी थी, जब कोरोनाकाल में ऑनलाइन घर-घर शराब मिल रही थी। तब भी शर्म की बात थी, लेकिन उस समय सत्ता पक्ष के आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदया, जो कोरोनाकाल में 5 साल तक दवा नहीं दे पाये, वह ऑनलाइन घर तक दारू बेच रहे थे। उस पर कोई बोलना नहीं चाहता है। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- दो मिनट, सुनिये न। आप दो मिनट तो शांत रहिये। हम लोगों ने गंगाजल उठाकर कसम तो नहीं खाई है, जो हम उसको बंद करें। कसम तो आप लोगों ने खाई थी तो आप लोगों ने उसको बंद क्यों नहीं किया ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- देखिये, आपके पक्ष के अजय चंद्राकर जी ने ही कहा है कि क्वालिटी-क्वालिटी की दारू मिलेगी। आप इसको नकार नहीं सकते हैं। मैं इसको पटल पर रख दूंगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप यह बताइये कि गंगाजल कौन उठाया था ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- किसी ने नहीं उठाया था। आपने तो इस्तीफा देने की मांग की थी। (व्यवधान)

सभापति महोदया :- संगीता जी, आप विषय पर आइये और अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदया।

सभापति महोदया :- सुशांत जी, आप बैठिये। आप इनको बोलने दीजिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा। यह सदन को गुमराह कर रही हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से वायदा यह करें और उसको निभाये हम तो यह कहां की बात हुई ? (व्यवधान)

सभापति महोदया :- नहीं-नहीं, आप इनको बोलने दीजिए। जब आपकी बारी आएगी, तब आप बोलियेगा। संगीता जी, आप जल्दी समाप्त करें। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदया जी, आप इनको बोलिये कि यह बीच में न बोलें। आप मुझे बोलने दीजिये।

सभापति महोदया :- आपको 20 मिनट से ऊपर हो गये हैं। आप जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदया, वर्ष 2023-2024, 2024-2025 में पुल व सड़क निर्माण के लिये बजट में जितनी भी राशि आई थी, उसमें से 1 रूपये भी खर्च नहीं हुआ है। हम तरस गये। हमारी जितनी भी राशि थी, वह वापस हो गई। 52 करोड़ रूपये की राशि संजारी-बालोद जिले से वापस हुई है। आप उसको तो दे दीजिये। उस राशि को न देकर आज नया बजट लाया गया है। चूंकि पहले के बजट का 1 रूपये भी खर्च नहीं हुआ है और आपने इतने लाख करोड़ रूपये का नया बजट लाया है। मेरा यह कहना है कि जो बजट था, उसको खर्च क्यों नहीं किया गया ? हमारी पूरी राशि को आपने वापस ले लिया और आज आप नया बजट ले आये हैं। यह तो सिर्फ पेपर वर्क रहेगा। एक पुल भी नहीं बना है। पिछले बजट की राशि से एक पुल भी नहीं बना है। यदि यह मुझे दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगी।

सभापति महोदया :- आप जल्दी समाप्त करिये। आपको आधा घंटा हो गया है। सुशांत जी, आप प्लीज उनको बोलने दीजिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदया, यह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास देने की बात करते हैं। लेकिन 18 लाख आवास में से सिर्फ 6 घर बने हैं, जो इस सरकार के लिए बहुत लज्जा की बात है। सभापति महोदया जी, आपने मुझे इतने समय तक बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आपने मेट्रो व मेट्रो सिटी की बात कही है तो आप उसको धरातल पर लाइये। ऐसा न हो कि सिर्फ पेपर में मेट्रो सिटी लिखाये। यह कहते हुए मैं इस बजट का घोर से घोर विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदया, माननीय वरिष्ठ साथी हमारी बहन बोल रही थीं कि कोई पुल नहीं बन पाया। सामान्य तौर पर निविदा में निर्माण कार्य को 24 महीने लगते हैं। आप अपनी सरकार की कहानी को हमारे ऊपर क्यों थोपती हैं कि एक भी पुल नहीं बन पाया?

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, आप यह बताइये कि आपके भाषण में हम लोगों ने टोका-टाकी की तो क्या आपको बुरा लगा ? छेड़छाड़ तो होना चाहिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नहीं, धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह :- जब हम लोग आपको थोड़ा सा छेड़ेंगे, तब आपका भाषण ज्यादा निखरेगा। इसलिए हम लोग बोले हैं। (हंसी)

श्री राजेश मूणत :- संगीता जी, क्या है कि आपके लोग आपके भाषण को महत्व नहीं दिए, कम से कम हम लोग ही आपके भाषण को गंभीरता से सुनते रहे कि आप इतना अच्छा बोल रही हैं। लेकिन भाषण के अंदर आपका दर्द भी झलक रहा था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति जी, मुझे कल बुहत दर्द महसूस हुआ। कल मेरे भाई साहब बहुत चिल्ला-चिल्लाकर बोल रहे थे, तो मैं उस दिन को याद कर रही थी, जब मंत्रिमण्डल का शपथ-ग्रहण हो रहा था और मैं आपको ढूंढ रही थीं।

श्री रामकुमार यादव :- आज तो दरपण में देखकर बहुत तकलीफ होवत होही।

श्री सुशांत शुक्ला :- [xx] कहीं थोड़ा तो छोड़ा करो।

सभापति महोदय :- वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का आज अंतिम दिवस है। अभी 11 माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है। पूर्व के वक्ताओं द्वारा पर्याप्त रूप से आय-व्ययक पर अपनी बातें रखीं जा चुकी हैं। अत: आगामी वक्ताओं से यह अपेक्षा है कि वे अपने विचार 10-10 मिनट में रखें। श्री सुनील सोनी जी।

श्री सुनील सोनी (रायपुर नगर दक्षिण) :- धन्यवाद सभापति जी। मैं वर्ष 2025-2026 के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

समापति महोदय, यह बजट रजत जयंती वर्ष में विकसित छत्तीसगढ़ की नींव रखने वाला है। अगर इस बजट को देखेंगे, मैं बहुत पुरानी बात नहीं करता, आज से डेढ़ साल पहले जायेंगे तो उस समय भी यही छत्तीसगढ़ था, इसके संसाधन भी वही थे, अधिकारी भी वही थे। लगभग डेढ़ वर्ष के बाद सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। व्यवस्था कैसे बदलती है और तेजी से विकास कैसे होता है, हमको यह सब बजट में देखने को मिल रहा है। यह इच्छाशक्ति का परिणाम है। अगर काम करने की नीयत हो, छत्तीसगढ़ के तस्वीर और तकदीर बदलने की नीयत हो तो जिन योजनाओं को लेकर इस बजट में प्रावधान किया है, मैं उन दो योजनाओं से अपनी बात की शुरूआत कर रहा हूं। क्योंकि मैंने इसको लोकसभा में लगभग 5 बार कहा था। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ये दो ऐसे राज्य हैं, जहां पर मोदी जी की सबसे ड्रीम योजना के तहत एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए मोदी जी का सपना है, जब मैं प्रभारी था, जब मैंने इसको बस्तर के अंदर एक भाई से पूछा था कि यह मकान किसने बनाया ? उसने

कहा- मोदी जी ने बनाया। मैंने उसके आंख की चमक और चेहरे के भाव को पढ़ा कि उसको दुनिया का सब कुछ मिल गया है। इस रूकी हुई योजना को लेकर पूरे संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता के बीच गई और जनाधार प्राप्त की। हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने पहली कैबिनेट में पास किया कि गरीब आदमी को 18 लाख आवास मिलना चाहिए, इस संकल्प को पूरा करने के बाद हमारी सरकार ने पहली बजट को पास किया, यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है।

सभापति महोदय, दूसरी योजना, सन् 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा के अंदर 2 लाख 67 हजार रूपये इस बात के लिए रखा था। क्योंकि उन्होंने गांव की महिलाओं को देखा था, उनके दर्द को समझा था कि हमारी बहनें पानी भरती हैं, उनको तकलीफ होती हैं, बुर्जगों की चिंता करना, बच्चों की चिंता करना, वह जब एक किलोमीटर, दो किलोमीटर दूर चलकर पानी लाती है और रात को सोती है तो उसको लगता है कि मेरा जीवन केवल मेहनत करने के लिए है। उसके दर्द को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुना, समझा। जलजीवन मिशन, भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना के लिए 2 लाख 67 हजार करोड़ रूपये पहले बजट में रखा। मुझे इस बात का दु:ख है कि मैंने दो बार लोकसभा में भी इस बात को उठाया था कि छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य है, जहां पर जल जीवन मिशन के लिए सरकार ने टेंडर जारी किया, वहां हमारी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने उस टेंडर के ऊपर में आपत्ति की, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और इसी सरकार ने उस टेंडर को निरस्त भी किया। यह प्रमाणिक भ्रष्टाचार पूरे देश के अंदर में देखा गया और जो गंगाजल को हाथ में लेकर कसम खाने वाले लोग हैं, वे गरीब के घर में पानी मिले, उसके अंदर भी उन्होंने अर्थ ढूंढने का काम किया। यह दुर्भाग्य था। मेरे द्वारा वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में यह बात लोक सभा में उठाने के बाद जब मैं शुक्रवार को देश के जल जीवन मिशन के जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री श्री गजेन्द्र शेखावत जी के साथ यहां आया था तब उस समय हमने समीक्षा की थी तो वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में लगभग 10 प्रतिशत काम हुआ था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीया सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और यहां एक भी मंत्री नहीं बैठे हैं। यहां सिर्फ एक ही मंत्री बैठे हैं और यहां पूरी जगह खाली है। आप थोड़ा इस बात को संज्ञान में लें।

श्री सुनील सोनी :- सभापति महोदय, जब हमने इसकी द्वितीय समीक्षा की थी, उस समय लगभग 34 प्रतिशत काम हुआ था। 875 करोड़ रूपये आवास के लिए रखना, जल जीवन मिशन के लिए 450 करोड़ रूपये रखना।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, आप अच्छा बोलत हौं।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप जितना बोलेंगे, आपके समय में कटौती होगी।

श्री रामकुमार यादव :- कोई बात नहीं। ये सब के लिए लागू होथे।

श्री सुनील सोनी :- सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं उनके लिए ही बोल रहा हूं। भैया, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूं।

श्री सुनील सोली :- रामकुमार जी, मैं आपको कभी नहीं टोकता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- एक मिनट। मैं आपको नहीं टोक रहा हूं। मैं आपके लिए ही बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप ज्यादा बोलेंगे तो आपके समय में कटौती होगी।

श्री रामकुमार यादव :- भैया, आप सांसद रहे हौ। इंहे ले आप गे रहा, आप मोदी जी के साथ बइठत रहे हओ अऊ हमर छत्तीसगढ़ के जी.एस.टी. के 15 हजार करोड़ रूपया ला नई देवत रिहीस हे, ओ समय आप अईसनहे गोठियाय रइता ता आज छत्तीसगढ़ के दशा हर दूसरा रइतिस। अब आप गोठियावौ।

श्री सुनील सोनी :- मैंने इस बात को भी लोक सभा में उठाया था। आपने मुझको अच्छा याद दिला दिया। सभापति महोदय, भारत सरकार ने तीन बार चिट्ठी लिखा था कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा चला जाएगा, आप प्रधानमंत्री आवास बनायें। लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना। भूपेश बघेल जी की सरकार में लगभग 8 लाख आवास का 11,000 करोड़ रूपये लौटा था। केन्द्र सरकार व मोदी जी ने कभी भी पक्षपात नहीं किया है।

श्रीमती अंबिका मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी सांसद रहे हैं। माननीय सोनी जी, मेरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा सुन लीजिये। नगर पंचायत क्षेत्रों में जो बड़े झाड़ का जंगल है, वहां पर लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है। क्या आप उसके लिए व्यवस्था बनायेंगे? क्योंकि आप सांसद रहे हैं और आपकी डबल इंजन की सरकार है। यह केन्द्र से स्वीकृत होना है। यह कैसे स्वीकृत होगा, उसको आप थोड़ा बता दीजिएगा?

श्री सुनील सोनी :- सभापति महोदय, मैंने अपने भाषण की शुरूआत वहीं से किया था कि डबल इंजन सरकार का क्या लाभ मिलता है। पिछली सरकार ने आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने वाली केन्द्र की 210 योजनाओं को रोक दिया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उन सारी योजनाओं को लागू किया और जो राज्य सरकार का अंश होता है, उसको भी उन्होंने देना चालू किया। आज उन योजनाओं के साथ में उन्होंने अपनी भी अनेक योजनाएं भी चालू की हैं। आज हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। आप भी सांसद रहे हैं। उस समय में हम नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के अंदर में देखते थे कि सामान्य मद के अंदर में 1 रूपया नहीं होता था। पिछले 5 साल के अंदर में कोई भी पंचायत क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका के अंदर एक भी सामान्य मद नहीं आया है। टोटी लगाने का पैसा नहीं था। हमारी सरकार बनने के बाद में सारी नगरों का उत्थान हो, हर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम को उसकी आबादी के हिस्से का उसकी आवश्यकतानुसार पैसा देने का है, जो सैकड़ों करोड़ रूपया है, 7000 करोड़ रूपया एक साल के अंदर में देना है, कोई

छोटी-मोटी बात नहीं थी । सभापति महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने अब फिर से प्रावधान रखा है कि नगरों का उत्थान होना चाहिये । वह छत्तीसगढ़ का एक चेहरा है कि जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो देखता है कि यहां के शहर और कस्बे कैसे हैं और उसके आधार पर एक बड़ी योजना बनाकर लाये हैं कि नगरों का उत्थान होगा और विध्वंश नहीं, केवल विकास होगा ? सभापति महोदय, पाईप लाईन है, ड्रेनेज सिस्टम है, इसके होने के बाद डामरीकरण होगा । हमारा छत्तीसगढ़ विध्वंश रूकने के साथ ही विकास की ओर बढ़ेगा, यही नीति है और इसी को नीयत कहते हैं । सभापति महोदय, योजनाबद्ध तरीके से जो काम किया जाना है, वह हमारी सरकार कर रही है। मैं लंबे समय से देख रहा हूँ कि राजधानी रायपुर के अंदर एक मेकाहारा अस्पताल है, अंबेडकर अस्पताल है, उस अस्पताल के अंदर में लगभग आधा छत्तीसगढ़ ईलाज कराने के लिये आता है, वह केवल अब रायपुर का नहीं रहा है । सभापति महोदय, मैंने उसकी दुर्दशा को देखा है, पिछली सरकार में श्री टी.एस.सिंहदेव जी बाबा साह उपमुख्यमंत्री थे, वह हमारे अध्यक्ष थे, हमने जब इस संबंध में बात किया तो इंस्ट्रूमेंट के लिये पैसा नहीं था । सभापति महोदय, वे और भी शब्द बोले थे, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में 700 बेड का और वहां अतिरिक्त अस्पताल बने, उसके लिये 2.5 करोड़ से अधिक धनराशि का प्रावधान रखा है और वह बनने जा रहा है, उसका टेंडर भी हो गया है । सभापति महोदय, आज मेकाहारा के स्वास्थ्य विभागों के अंदर देखेंगे तो अंबेडकर अस्पताल के भीतर आईव्हीएफ तकनीकी हेतु 10 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, मेकाहारा में चिकित्सा उपकरण क्रय करने के लिये 20 करोड़ का प्रावधान, 28 करोड़ की तीन एस्टेला एम.आर.आई. मशीन, 26 करोड़ से 256 सिटी स्कैन मशीन, कोई भी इंन्स्ट्रूमेंट्स है, उसको बढ़ाया गया है ताकि छत्तीसगढ़ के हमारे भाई-बहन वहां पर आते हैं तो सही ईलाज मिलना चाहिये । सभापति महोदय, यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेस के नाम पर जो है, मोदी जी की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत है । हम छत्तीसगढ़वासियों को इस बात का गर्व है कि आयुष्मान भारत के नाम से जो मोदी जी ने योजना लागू की थी, वह छत्तीसगढ़ के बीजापुर से लागू किया गया था, जो आज पूरे देश को 5 लाख रूपये का लाभ मिल रहा है । सभापति महोदय, यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेस के नाम पर उसे रोक दिया गया । विष्णुदेव साय जी की सरकार आने के बाद आयुष्मान भारत कार्ड का पुन: शिविर लगाकर लोगों को लाभ मिले, इस बात की व्यवस्था की है और 1500 करोड़ से अधिक का प्रावधान भी रखा है ।

सभापति महोदय :- समाप्त करेंगे ।

श्री सुनील सोनी :- अभी तो चालू किया हूँ ।

सभापति महोदय :- 10 मिनट का समय था ।

श्री सुनील सोनी :- मुश्किल से 7 मिनट हुआ है ।

सभापति महोदय :- नहीं, नहीं । आपका समय हो चुका है ।

श्री सुनील सोनी :- आप बोलेंगे तो मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन चालू किये 7 मिनट ही हुये हैं, कोई दिक्कत नहीं है ।

सभापति महोदय :- 12 मिनट से ऊपर हो गये हैं ।

श्री सुनील सोनी :- नहीं, 7 मिनट हुये हैं, मैं घड़ी देख रहा हूँ ।

सभापति महोदय :- मैं भी घड़ी देख रही हूँ ।

श्री सुनील सोनी :- सभापति महोदय, अभी बात किया जा रहा था कि पेट्रोल-डीजल की कीमत में 1 रूपया कम किया गया है । प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 रूपया कम किया था और पुरानी सरकार ने 25 पैसा भी कम नहीं किया था । सभापति महोदय, आप समाप्त करने बोल रहे हैं तो अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह आने वाले समय में 2047 में एक विकसित छत्तीसगढ़ का नींव रखेगा । सभापति महोदय, इसके अंतर्गत सभी वर्गों की चिन्ता है, महतारी वंदन के नाम गरीबों की चिन्ता है, 1000 रूपये यदि उसके घर का छोटा-मोटा खर्च हो जाये, वह किसी की मोहताज न हो, हमारी बहनों का सम्मान बढ़े, केन्द्र की योजनाओं को डबल इंजिन सरकार जो है, उसका अर्थ यह है कि इसके माध्यम से जो यहां पर काम हो रहा है, उसमें भारत सरकार की योजनायें और राज्य सरकार की योजनायें, इन दोनों योजनाओं का लाभ मिल रहा है । सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदया :- श्री रामकुमार यादव । 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री राम कुमार यादव (चन्द्रपुर) :- बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदया जी। आज मैं अपना बात शुरू करौं, ओकर पहिली मैं हमर गुरू के पंक्ति याद आवथे, खैर एमेर तो कोई मंत्री नहीं हे । एक झन मंत्री जी हे, उहूं ह जावथे । एक मंत्री आवथे। कोई बात नहीं हे । लेकिन मंत्री मन सुनौ चाहे झन सुनौ, मोर छत्तीसगढ़ के जनता ह सुनथे अउ सब देखथे । रविदास जी कहे रिहीसे कि *ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिलै सबन को अन्न।* छोट बड़ो सब सम बसै, रविदास रहै प्रसन्न । एला रविदास जी केहे रिहीसे और जब छत्तीसगढ़ में युवाओं के हृदय सम्राट आईकॉन ऐसा शायद इंग्लिश में कहिथे । अउ हमन छत्तीसगढ़ में युवा मन के हृदय सम्राट कहिथन, जेनला युवा मन देखके अइसने बनबो, कहिथे अउ सोचथे । अइसने ओ.पी. चौधरी साहब पहिली कलेक्टर रिहीसे । अब वह कलेक्टरी ला छोड़िस तो ओ ह मंत्री बन हे त युवा मन के मन में एक ठी संशय पैदा होगे कि अब कलेक्टर बनन या मंत्री बनन, लेकिन कोई बात नहीं, जब मंत्री बनिस, जब वित्त विभाग के प्रभार लिस और बजट बनईस त पूरा प्रदेश के जनता ह टकटकी लगाकर देखत रिहीन हे कि यह युवा प्रदेश के लिए अच्छा करेगा, विष्णु देव सरकार ने चुनाव के पहले जो वादा किया था, उसके लिए यह कुछ करेगा । सभापति जी, मैं आज इस अवसर पर कहना चाहथौं कि भले ही एमन छत्तीसगढ़ ला गरीब बनावथे, लेकिन छत्तीसगढ़ के महतारी गरीब नो हय । छत्तीसगढ़ में का नहीं हे ? छत्तीसगढ़ में जो एक प्रदेश ला आगे बढ़े के लिए जो

संसाधन चाहिए, चाहे नदी हो, आज राजस्थान में जावव तो उहां नदी नहीं हे, उहां के उद्योगपति मन छत्तीसगढ़ आवथे काबर की इहां नदी हे । पहाड़, पर्वत, सरई, सागौन इहां का-का पेड़ नहीं हे, जन हर हीरा मोती हे, लेकिन अतेक अकन संसाधन ला पाए के बाद भी आज ए प्रदेश के सरकार बजट ला अईसे बनाए हे कि आज ए छत्तीसगढ़ के जनता मन देखके हताशा और निराशा होगे हे । हमन ला चौधरी साहब से बहुत उम्मीद रिहीसे, लेकिन ए सरकार ह उम्मीद में पानी फेरे के काम करे हे, ए मन बजट बनाए हे, वह सिर्फ मायाजाल हे । उसका टोपी उसका सर, उसका टोपी उसका सर । किसी प्रकार के कोई बने काम नहीं हे । आप देखौ कि एमा के ला ओमा घूमा दिस। अगर कृषि के बात किया जाये, पहिली के बजट के तुलना करके आप मन देखव तो मात्र 4 प्रतिशत ज्यादा बढ़े हे । ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान हे । बड़े-बड़े बात करने वाला मन, किसान के आंसू पोछने वाला मन अगर बजट ला बढ़ाए रहितिन त कहितीन के देखव, हमन कृषि के बजट ला 30 प्रतिशत किसान के सम्मान में बढ़ाए हन त हमूं मन ताली बजातेन । जतका अकन महंगाई बढ़े हे, ओकर के ज्यादा तो आप मन बढ़ाए के काम करे हवव । मात्र 4 प्रतिशत कृषि के बजट ला बढ़ाए हवव, लेकिन अब सुन लौ, ऊर्जा के क्षेत्र में आप मन 15 प्रतिशत कम करे हवव । आप मन बिजली तो देत हवव, लेकिन अभी के बिजली कईसना हे । हमन गांव के मन देखथे दर्शक दीर्घा में, अईसना-अईसना बिजली आप मन देथौं कि दीया ला धरके बिजली ला खोजथन, ओतके अकन अंजोर हे । बिजली बारथन त कुछ दिखबे नहीं करथे । ओ पीढ़ा मा हपट जात हन । अईसने तुमन बिजली ला अतके कम देवथौ । ए बिजली कहां गिस ? हम जानथन कि तुमन बिजली ला उद्योगपति करा बेच द हवव । अउ तुमन ला वोट देकर कुर्सी में बैठाए हवय, लाल बत्ती में बैठाए हे, जहाज मा उड़ावथव, जेकर बदौलत तुमन सत्ता पाए हवव, ओला तुमन सिर्फ अंधियार दे दे हवव । तुमन बिजली ला उद्योगपति ला दे दे हवव ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- रामकुमार भाई, तुमन के समय में टमड़ाऊ हो गे रिहीसे, बिजली एकदम गोल रिहीसे । ओकर बारे में कुछ बता।

श्री रामकुमार यादव :- ये तुमन के समय में बिजली एकदम टमड़ाऊ हो गे हे, तुमन बिजली ला उद्योगपति ला बेच द हवव । अभी कोनो गांव चलौ, मैं आपके क्षेत्र में जाकर बता देहं, बिजली ल बारिही त सीं करके ओखर लाल दिखथो, तहां बत्ती ह बस। कहां गीस बिजली? ये बिजली ल तूमन उद्योगपति ल बेचे हव। आज मैं कहना चाहत हों।

श्री राजेश मूणत :- रामकुमार भैय्या, सब बने-बने ना? कोई परेशानी तो नई हे ना?

श्री रामकुमार यादव :- मोला परेशानी होबे नई करय, ये धरती मोर हे, आकाश मोर हे। ये राम कुमार यादव ला तूमन कतको रोके के प्रयास करव, मैं अमिताभ बच्चन हों, छत्तीसगढ़ के सबो ल मना के रहिहं।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामकुमार जी, पूरा संसार आपका है।

श्री रामकुमार यादव :- तुम्हर छोड़। तुम्हला मैं नइ सकंव। ये संसार मोर हे लेकिन तू मन मोर नई हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कार्यसूची पढ़ लो और उसमें ये जान लो कि वार्षिक आय-व्यय में चर्चा हो रही है। आय-व्यय में बोलो न।

श्री रामकुमार यादव :- तुम्हरो आय पे आय ल देखें हववं। तुमन ह आय ल देखथव, व्यय ल नई देखव। केवल कितना आया। ये मन मोर बात ल काटत हे।

सभापति महोदया :-आप अपनी बात समाप्त करें, टोंकाटाकी के विषय में मत जाइए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- उस युग में भगवान राम भांचा के साथ अन्याय हुआ था और इस सदन में मेरे भांचे के साथ जो अन्याय हो रहा है, उससे मैं दुखी हूं। पहला बजट भाषण है, जिसमें आपके जैसे विद्वान को पूरे छत्तीसगढ़ की जनता और दूसरे प्रदेश के भी सम्मानित विधायक आपकी बातों से सीखते हैं, लेकिन आपके दल ने आपकी स्थिति यह बना दी है कि इसमें आपको बोलने के अवसर में भी शामिल नहीं किया गया है। यह कैसी सरकार चल रही है? इतने विद्वान सदस्य मेरे भांचे के साथ अन्याय हो रहा है, तो जनता के साथ क्या हो रहा होगा?

सभापति महोदय :- 6 मिनट हो गया, 4 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामकुमार यादव :- मोर समय ला आने मन सब ले ले हें दीदी, मोरेल कहिह। तीन मिनट होहे अऊ एक मिनट ल हमर चन्द्राकर जी ह खा दिस।

श्री राजेश मूणत :- भाई द्वारिका भैय्या, यादव ला आपके सपोर्ट करे के का जरुरत पड़ गे, ओ खुद ही सक्षम हे। ओ पर्वत ला हाथ में लेके घूमे हे, पूरा छत्तीसगढ़ में।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, व्यवस्था को जोड़ रहा हूं। आप हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार में ये-ये है, लेकिन इतने वरिष्ठ सदस्य के साथ आप क्या कर रहे हैं?

श्री राजेश मूणत :- द्वारिका भैय्या, यही तो तकलीफ है। ये इतना अच्छा बोलते हैं और आप पड़ोस में बैठकर बार-बार उंगली करते हो। ये गलत बात है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं उंगली नहीं किया हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- (वित्त मंत्री का बजट भाषण 2025-26 की पुस्तक हाथ में लेकर) ये किताब ले जाओ। ये बजट ले जाओ ना।

श्री रामकुमार यादव :- मैं सब जानथौं। मैं इग्लिंश भी जानथौं, उर्दू भी जानथौं लेकिन मैं सिर्फ तुम्हला नई समझ पायेंव आज तक। तुम्हर में ज्ञान भरे हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सब बोलिए, लेकिन बजट में बोलिए।

सभापति महोदया :- रामकुमार जी, आपका तीन मिनट बाकी है।

श्री रामकुमार यादव :- दीदी जी, आप इतना क्यों डरा रही हैं? कहो तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- ओ रामकुमार जी, तोला बइठना नइ हे, तें खड़े रह। आय-व्यय में बोल, आंय-बांय मत बोल।

श्री रामकुमार यादव :- इन लोग इतना आंय-बांय गोठियाते हैं, मेरे को समय का क्यों डरा रही हैं?

सभापति महोदया :- यह सब दोनों तरफ से होता है। आप जल्दी संवाद खत्म करें।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, आप संरक्षण नहीं देंगी, तो कौन देगा बताओ?

सभापति महोदया :- आप जल्दी अपनी बात खत्म करें।

(श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के सदन से बाहर जाने पर)

श्री राजेश मूणत :- देख भाई, तोर बात सुनके दोनों चले गे।

श्री रामकुमार यादव :- मोर बात ला सुनके तुम्हर सरकारो जाने वाला हे।

श्री राजेश मूणत :- अइसे का? सही में?

श्री रामकुमार यादव :- मोर बात ला सफ्फा सुन लिही ना, तोर जनता सुन लिही तो तूमन ला एको ठन वोट नई दिही।

श्री राजेश मूणत :- वो आगे वाली पूरी बेंच खाली है।

श्री रामकुमार यादव :- मोर गोठ ल जनता ह सुन लिही ना तुमन के करतूस ला त तूमन ला एकोठन वोट नई देवय। मैं कहना चाहत हों, ये मन ताली बजवाथे कि हमारी सरकार ने किसान का धान खरीदा, त कौन सा मार तीर मार देस, हमन नई खरीदे रहेन का? हमारी सरकार ने स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था बनाई, त हमन नई पढ़ात रहेन का? हम मन स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलेन, तूमन ओला एक चाकमिट्टी दे नई सकथव।

श्री राजेश मूणत :- मोर भाई यादव भैय्या, चल रायपुर में आत्मानंद स्कूल खोले ना, साथ में चल तें यहीं से निकल के, का हाल हे, जरा देख ले। समझ में आ जाहि आत्मानंद स्कूल के नाम लेते थे। हम लोग साथ में चलें आज? दोनों खाना खा लें, दोनों मोटरसाईकिल में साथ में चलें और देखकर आ जाएं, समझ में आ जाएगा कि आत्मानंद का क्या हाल है।

समय :
1.54 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्री रामकुमार यादव :- आदरणीय सभापति जी, सादर प्रणाम। ख्याल करिहौ मोर, ये मन दबा देत हावय।

सभापति महोदय :- बोलिए ना। बोलिए।

श्री राजेश मूणत :- संरक्षण मिलिही, चिन्ता मत कर।

श्री रामकुमार यादव :- बिल्कुल। व्यक्तिगत रूप से ओ मोर पिताजी के समान हे, बाप समान हे। हमेशा मोर गुरु हे, मैं सीखत रथौं ओखर कनी।

श्री राजेश मूणत :- आजकल ना चेला होशियार हो गया और गुरु गुरु ही रह गया। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- नहीं आदरणीय। सदन में कुछ भी हो, आज भी हमारे आदरणीय धर्मजीत सिंह जी की आवाज अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। वह गूंजेगा ही गूंजेगा।

सभापति महोदय :- बाकी बात छोड़कर 5 मिनट में समाप्त करिए।

श्री रामकुमार यादव :- नई, आप बइठे ह 10 मिनट दे दीह साहब।

सभापति महोदय :- चलिए, बोलना तो शुरु करिए।

श्री रामकुमार यादव :-आज मैं बात करना चाहत हों कि ये सरकार दुहाई देत रहिस अऊ धान खरीदी के बात करत रहिस, त धान हमू मन खरीदेन अऊ आपो मन खरीदे। फर्क बस अतका रहिसे अभी के किसान डरत रहिसे कि मोर धान ल बेचे पाहां कि नई बेचे पाहां। जइसे ही धान खरीदी शुरु होइस तो आप मन अपन पटवारी, तहसीलदार ला खेत में भेज दिहा कि जा समारू, दुकारू, दुखालू अउ इतवारू के खेत ला देखबे, ओ मन हर एकड़ में कतका कन धान उगा पात हे, ओकर बाद खरीदी करबो। आज किसान ये बात ले भयभीत रिहीसे। आप मन धान हा जरूर लेवत हव लेकिन ओ मन ला ओ बात ले भयभीत रिहीस। किसान मन के मन में वो बात रह चुके हे, में हर ये बात ला आप मन ले अवगत कराना चाहत हव।

सभापति महोदय, आज में हर मोदी जी के गारंटी बर बात करना चाहत हव। ये मन कहात रिहीसे कि मोदी जी के गारंटी हे। हमर ओ.पी. चौधरी साहब आइस हे। ओ मन जब कलेक्टर साहब रिहीसे, तभो में हर ओला नमस्ते करे रेहव अउ आज भी सेल्यूट करत हव। लेकिन हमन ला कलेक्टर साहब जी अउ युवा हृदय सम्राट से अइसने उम्मीद नइ रिहीस। ये मन मोदी जी के गारंटी के बात करे रिहीसे तो मितानिन जे मन स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ के हड्डी हे, ओ मन के बजट के भी बात आना रिहीसे। स्वीपर, जे मन दो घण्टा काम करथे ओकर बाद में कहिथे कि आप मन चले जाओ, ओ मन आज कही के नहीं रिहीस। ओ मन ला आज 1800 अउ 1500 रूपये पेमेंट मिलथे। आज ओकर घर परिवार कैसे चलही ? आज दिल्ली में खाली एक पान खाबे तो 1500 रूपये केवल पान के कीमत हे अउ वो स्वीपर मन 1500 रूपये में महीना भर गुजारा करथे। वइसने परिवार के चिंता अगर इस बजट में होतिस तो ये रामकुमार यादव, गरीब के लइका घलो आप मन बर ताली बजा देथव। लेकिन आप मन ओ गरीब के चिंता नइ करव।

सभापति महोदय, आज में हर युवा के बारे में बात करना चाहत हव। कहते हैं कि युवा बोलता हैं तो प्रदेश डोलता है। आज आप मन युवा मन के का चिंता करे हव ? हमर सरकार रिहीसे तो हमर सरकार में हम ओ मन ला बेरोजगारी भत्ता देवत हव। आज ऐसे भी बहुत युवा है। आज तुंहर अउ हमर

लइका तो दिल्ली में जाकर कोचिंग करत हे। में हर कतका झन ऐसे नेता बर बता देवव, जेकर लइका मन दिल्ली का विदेश में जाकर कोचिंग करत हे। लेकिन गरीब किसान के लइका मन बर रायपुर अउ बिलासपुर में पढ़े बर, फीस पटाये बर पैसा नइ हे। जे मन के पास फीस के पैसा नइ हे, ऐसे गरीब लइका बर हमर सरकार बेरोजगारी भत्ता देबे के काम करे रिहीसे। में हर सरकार से कहना चाहत हव। आप मन सरकार के घमंड मत करिहव। हमूं हमन सरकार में रेहेन। कह गया कहने वाला, "जीत गये तो इतराना मत अउ हार गये तो घबराना मत"। यह संसार के रीत हे। यदि दिन हे तो रात होही अउ रात हे तो फिर से दिन होही, यह प्रक्रिया हे। आज ठीक हे आप मन हर सरकार में हव लेकिन किस बात का घमंड हे ? जब देखव तो आप मन डराय के अउ चमकाय के बात करत हव। ऐसे लागथे कि जो बजट ला बनाये हन, वो पूरा खेत ला बेचकर बनाये हन का ? यह पैसा काकरो घर के थोड़ी न हे, यह सरकार के खजाना हे। आज हम सब ला मौका मिले हे अउ आप ला सरकार बनाये के रूप में मौका मिले हे तो हमन ला विधायक के रूप में मिले हे। लेकिन मौका सब ला मिले हे। आप मन ये बजट में कभी घमण्ड मत करिहव कि ये ला हमन घर के देत हन। ये छत्तीसगढ़ के भोली भाली जनता हमन ला रखवाली करे बर भेजे हे, लेकिन में हर ए मेर ले आप मन ला देखत हन कि बजट बनाये हे तो उहुं में कपट होये हे, ये बात ला याद रखिहव। में हर जतका पढ़त रेहव कि इहां पर 100 बिस्तर के अस्पताल होही। छत्तीसगढ़ी में एक ठन कहावत हे , "भरे ला भरे जुच्छा ला ढरकाय"। अगर कहीं पर रोड बन गे हे तहान ओ रोड ला उखाड़ के अउ रोड बनत हे। चौधरी साहब, में हर आप ला बताहुं के छत्तीसगढ़ में अइसने-अइसने काम चलत हे। आप ओकर सर्वे करावव। जहां एक पुरूत के रोड नइ बने हे, आज भी छत्तीसगढ़ के वइसने गरीब आदमी हर, किसान हर अपन लइका ला पढ़ाये बर चिखला में जाथे। आप मन ला ओकर बर चिंता करना रिहीसे। चाहे काकरो सरकार रिहीसे। में हर नहीं कहात हव कि आप ही मन ला ये काम करव। हमरो हो सकत हे मदोसी। ऐसे जगह ला चिन्हांकित करना चाहिए। चूंकि हम छत्तीसगढ़ के रहने वाला हन। काकरो घर बर दु:ख पड़त हे, तो हमर पूरा गांव हर त्यौहार नइ मानन। हमन का कहथन कि ओकर दु:ख हर हमर गांव भर के दु:ख हे। उसी प्रकार से यदि छत्तीसगढ़ में कोई विधान सभा क्षेत्र में एक पुरूत के रोड नइ हे, तो में हर सभापति महोदय के माध्यम से ओ.पी. चौधरी जी से निवेदन करे हव कि पहली वहीं से शुरूआत करना चाहिए। आप मन हर बड़े दिल के हव, बता देत हव कि यहीं एक पुरूत रोड नइ बने हे, में हर यहीं से शुरूआत करिहव कहत हव तो रामकुमार यादव आपके लिये जरूर ताली बजाही, यह आप ला वादा करिहव।

सभापति महोदय :- चलिये, आप समाप्त करिये। आपको भाषण देते 15 मिनट हो गये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- रामकुमार जी, आप मन आज कल गांव तरफ नइ जा रहे हो ?

श्री रामकुमार यादव :- में हर गांव जात हव।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अभी तो जन मन योजना के तहत पूरे गांव-गांव तक रोड हर बनत हे। तै कइसने कहिथस ?

सभापति महोदय :- कृपया आप आपस में बात मत किरये। रामकुमार जी, आप अपना भाषण समाप्त करिये। अभी 8-9 लोग शेष हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त हो जाही। में हर आपकी योजना आप ही के सामने गोठिया देत हवव। मोर निवेदन हे कि ए में सुधार करिहव। ये आप मन जो 5 लाख रूपये वाले आयुष्मान योजना चलात हौ । ए जतका प्राईवेट अस्पताल हे, ओ ला चना-मुर्रा खाये बर वही ला चखना समझथे। जब छत्तीसगढ़ के गरीब आदमी किसान के लइका मन हॉस्पिटल में जाथे तो कोर्ट-पैंट ला पहिन के बड़े मैनेजर आथे अउ कहिथे कि हमारे अस्पताल में आयुष्मान योजना से सरकारी पैसे में ईलाज होगा।

श्री राजेश मूणत :- माननीय यादव जी, ये चखना का होथे?

श्री रामकुमार यादव :- ओला सब समझ गे हौ। आप चखना नहीं, आप साग खाकर बइठे हावव। आप [3][XX] आदमी हो, मैं जानत हौं।

सभापति महोदय :- माननीय रामकुमार जी, आप सीधे अपना भाषण करिये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं काय करौं। आप ओमन ला देखवव न।

सभापति महोदय :- आप अपना भाषण बोलिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ। आप जल्दी समाप्त करिये। अभी 9-9 लोग बाकी है, बहुत समय लगेगा।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं काय करौं। मोरे भाषण ला एमन देखवव न कईसे कर देथे।

सभापति महोदय :- आप बोल लीजिए। अब समाप्त करिये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन पूर्वक कहात हौं। जब ओमन अस्पताल जाथे तो बड़े मनेजर आकर कहिथे कि इसमें यह नियम प्रक्रिया नहीं है आप 20 हजार रूपये अलग से जमा करिये और यह इधर से कट जाएगा। ओति सुरक ले ओकर कम्प्यूटर हा 20 हजार रूपये अलग से जमा करथे। आप ए बात ला पता कर लिहौ। अगर अध्यक्ष महोदय के अनुमति से आ जही ता ए बात ला में ध्यानाकर्षण में भी लाए हौं। आज छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के बात कहे जाए तो आप उड़ीसा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र चले जाओ। हमर लइका मन बीमार पड़थे। तुहंर घर के सुआरी बीमार पड़ही ओला अंते जाकर ईलाज करवौ। छत्तीसगढ़ के किसान के लोग लइका मन बीमार पड़ही ता जाकर के सरकारी अस्पताल में भरती कर देथौ। आप ला एक व्यवस्था ला सुधारे ला लागही। अंत में मोर क्षेत्र के बात करत हुए अपन वाणी ला विराम दिहौं। आप एक मिनट के समय दे देवौ। इहां सदन में हमर

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

माननीय वित्त मंत्री चौधरी साहब हा बइठे हे। मोर क्षेत्र से चूंकि खरसिया अउ चन्द्रपुर विधान सभा लगे हे। ओ समय में आप मन हा बहुत सारा फैक्ट्री खोले हावव। अभी भी जतका फैक्ट्री के गाड़ी हे, मोरे क्षेत्र के तरफ से निकलथे। माननीय चौधरी साहब, मे आपसे निवेदन करिहौं।

सभापति महोदय :- आप उनको लिखकर दे दीजिएगा।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय चौधरी साहब, मे आपसे निवेदन करत हौं कि मोर क्षेत्र में कुण्ड्री में एक आई.टी.आई., चारपारा में हाईस्कूल, सिंघरा में सब स्टेशन विद्युत, मोर गांव जमगहन में उप स्वास्थ्य केन्द्र के स्थापना हो जाए, आप एला बजट में जोड़ दे हौ। जब अपने भाषण ला बोलिहौ तो समतामूलक समाज बनाने के लिए जरूर करिहौ। एखरे खातिर में कहिथौ कि अउ कुछु नहीं ता एला कहिथे...।

सभापति महोदय :- ऐसा नहीं होगा। आप बैठिए। अब हो गया। आपने बता दिया और माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दीजिगएगा।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, आप ला सम्मानजनक धन्यवाद् देते हुए बैठ जहूं। आप अइसे झन बैठावौ। मैं आप ला सम्मान देते हुए कहात हौ कि महूं ला सम्मान देते हुए बिठारौ।

सभापति महोदय :- मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ। आपने 15 मिनट से ज्यादा बोल लिया है। अब मैं, आपसे बोल रहा हूँ कि अभी बहुत से लोग बाकी हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं अइसने बइठ जावत हौं।

सभापति महोदय :- नहीं। आप अपना भाषण बोल लीजिए और दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिये। दो मिनट का मतलब आप दो मिनट में ही समाप्त करें।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक ही मिनट में समाप्त कर देथौं। आप मोला बहुत अच्छा बोले के समय देहौ। आपके ह्रदय बहुत ही विशाल हे।

सभापति महोदय :- आपको बोलते हुए 15 मिनट का समय तो हो गया। 9.00 बज जाएगा।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, हमू मन देखे हन। जब हमर सरकार रिहिस हे तो इहां रात 11.00 बजे तक हाऊस चले हे, लेकिन अब एक मिनट लेट हो जाथे तेखर लिये मैं अपन बात ला समाप्त करत हौं। आप विपक्ष ला बहुत अच्छा बोले के मौका देव, तेखर बर आप ला बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा।

श्रीमती भावना बोहरा(पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

माननीय सभापति महोदय, मैं, सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत धन्यवाद् ज्ञापित करती हूँ कि इस बार फिर से इतना अच्छा बजट

आया है। पिछली बार जो पहला मुख्य बजट आया था उसमें बहुत सारे बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया था और हम यह समझते हैं, हमें यह विश्वास है कि जिस क्षेत्र से हम जनप्रतिनिधि आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं शायद किसी और सरकार को उन योजनाओं को पूरा करने में लगभग दो से तीन, चार साल लग जाते। लेकिन जिन योजनाओं में जिस तरीके से बजट के लिए अलग-अलग प्रावधान किया गया है तो मुख्य तरीके से सारी चीजें इस बजट में समाहित हुई और उसका क्रियान्वयन भी किया गया है।

महोदय जी, मुझे ऐसा लगता है कि यह पहला ऐसा मुख्य बजट होगा, जो किसी वित्त मंत्री के द्वारा अपने हाथों से लिखा गया तो मैं, उनको इस बात के लिए बहुत धन्यवाद् भी देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी नई पहल की है। एक बड़ी शुरूआत की है। क्योंकि किसी चीज को हाथ से लिखना, मतलब यह आपकी भावनाओं से संबंधित है। उसके लिए मंत्री होने के बाद भी उतना समय निकालकर, एक दो पन्ने नहीं, बल्कि 101 पन्नों का बजट अपने हाथों से लिखा है तो उन्होंने जितनी लगन से इसे लिखा है निश्चित ही हम सब उसके एक-एक पन्ने को पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे, मैं उनको इस चीज का आश्वासन देती हूँ। चूंकि रजत जयंती का स्वर्णीम आगाज हो चुका है। हमें बजट में भी यह बात देखने को मिली है। कहीं न कहीं   रजत जयंती के स्वर्णीम आगाज के बाद, आज हम स्वर्णीम युग के द्वार पर खड़े हैं। तो यह जो बजट आया है यह लगभग 1 लाख 65 हजार करोड़ रूपये का बजट आया है और जिस तरीके से बजट में प्रावधान किये गये हैं तो इसमें बहुत सारे विषय हैं। चूंकि 10 मिनट का समय है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बाकी विषयों पर बोला है पहले मैं, महतारी वंदन, प्रधान मंत्री आवास और विभिन्न विषयों के लिए एक साथ धन्यवाद् ज्ञापित करती हूँ कि जिस तरीके से पुराने बजट में बहुत अधिक प्रतिशत में महतारी वंदन को सम्मान दिया गया था, इस बार भी महतारी वंदन योजना के लिए बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। हम सबको ज्ञात है कि 25 साल पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जब मध्यप्रदेश से अलग होने के बाद यह बात आती थी कि एक बीमारू राज्य के रूप में उस समय छत्तीसगढ़ राज्य को गिना जाता था। जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार बनी और आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री पहली बार बने, उस समय के बजट और अभी के बजट में अगर तुलना करें तो दोनों में जमीन-आसमान का अंतर है। जिस तरीके से पिछले वित्तीय वर्ष का बजट "ज्ञान" पर आधारित था और ज्ञान के बाद "गति" देने वाला बजट आया है। निश्चित ही यह साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले एक सालों में छत्तीसगढ़ जिस तरीके से प्रगति करेगा और हम सब उसका एक बहुत अहम हिस्सा भी बनने वाले हैं। यह बजट में गति भी है, प्रगति भी है और छत्तीसगढ़ की जनता ने जब से इस बजट को देखा है उसमें उनकी सहमति भी है। क्योंकि कल मैं अपने क्षेत्र में जाकर आई हूं तो सभी लोगों ने इस चीज को सराहा है। जो बहुप्रतीक्षित मांगे थीं, जो विषय थे, उन अनछुये पहलुओं को हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने

इस बजट में शामिल किया है। पिछला बजट ज्ञान का था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केन्द्रित था और किसी समाज के उत्थान के लिए 4 मुख्य पहलू हैं। सभापति महोदय, मैं फिर से एक बार अपनी बात कहना चाहूंगी कि किसी सरकार का काम सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान देना नहीं रह गया है। सरकार का काम यह भी है कि लोगों के रहन-सहन का स्तर भी सुधरे, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनका जीवन स्तर उच्च हो। उनको अच्छी अधोसंरचना मिले, डेव्हलपमेंट, रोड़ के कार्य हों। यह जो भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय जी की सरकार है, वह सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान तक सीमित नहीं रह करके सारे बिन्दुओं पर बहुत अच्छा बजट आया है। जिस समय भा.ज.पा. की सरकार थी, वर्ष 2003 में 9270 करोड़ रुपये का बजट था और वर्ष 2018 में 95 हजार करोड़ रुपये तक का यह बजट पहुंच चुका था जो 2003 की तुलना में 10 गुना ज्यादा बड़ा बजट का आकार था। वर्ष 2025-26 में लगभग 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट है। जैसा कि उस दिन आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि छत्तीसगढ़ का औसतन जी.एस.डी.पी. 7.5 प्रतिशत पहुंच चुका है जो कि भारत की जी.डी.पी. का लगभग 6.4 प्रतिशत से भी अधिक है। मुझे लगता है कि विपक्ष जितने आरोप लगा रहे थे कि बजट में ये है, वो है। महोदय जी, भाषण करना अलग बात है, लेकिन बजट को पढ़ करके अगर उन विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर हम उस तरीके से भाषण करें तो भाषण दो-तीन घंटे का भी हो सकता है। अगर बजट के बिन्दुओं पर पक्ष और विपक्ष द्वारा क्रमश: चर्चा की जाये तो मुझे लगता है कि सत्तापक्ष उस बात को ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से रख सकता है, अगर हम क्रमवार उन विषयों पर चर्चा भी करें। मुझसे पहले सम्माननीय सदस्य बता रहे थे कि स्कूल पहले भी बने, धान खरीदी पहले भी हो रही थी, आपने नया क्या किया है? सभापति महोदय, किसी भी चीज के implementation का महत्व सबसे ज्यादा होता है। किसी चीज को बोलना कि हम यह चीज करने वाले हैं, हम धान खरीदी करने वाले हैं, हमने आत्मानंद स्कूल खोल दिया, यह कहना बहुत आसान है। लेकिन धान खरीदी के विषय में अगर हम बात करें तो आज जब आप किसान से बात करेंगे, उस समय भी वही किसान थे, आज भी वही किसान हैं। लेकिन सरकार की नीति और नियत साफ दिखाई दे रही है कि एकमुश्त में धान के पैसे देने की जो बात की गई थी या धान की बोनस राशि देने की बात की गई थी, अगर आज भी आप किसानों के बीच में जाकर पूछेंगे तो कहीं न कहीं किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर आकर्षित भी हैं और वह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो कहा है वह करके दिखाया है। सरकार में अंतर यही है कि भा.ज.पा. अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करती है और उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाती भी है।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय सभापति महोदय, अभी आदरणीय महोदया जी एकमुश्त की बात कह रही हैं। क्या आप लोगों ने एकमुश्त धान खरीदी? क्या किसानों को एकमुश्त राशि मिली? आप लोगों ने एकमुश्त देने का वादा किया था, पंचायत या सोसायटी में मिलना था, ऐसा आप लोगों का

कहना था। क्या किसानों का मिला? तो फिर आप लोगों ने कैसे कहा? हमारी सरकार ने 4 किश्त में देने की बात कही थी और 4 किश्त में दिया। आपने जो कहा था, वह किया ही नहीं।

श्रीमती भावना बोहरा :- आपकी सरकार ने 4 किश्त में देने की बात नहीं कही थी, आपकी सरकार ने देने की बात कही थी।

सभापति महोदय :- भावना जी, आप इधर देखकर बोलिये और अपने भाषण पर आईये।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपने भाषण पर आ रही हूं क्योंकि मुझे 10 मिनट का समय दिया गया है। मैं उसी पर आ रही हूं। कुछ समय पहले यह कहा गया कि दिया ले करके लाईट ढूंढनी पड़ती है। मैं थोड़े दिन पहले की ही बात आपको बताना चाहूंगी, मेरे विधान सभा क्षेत्र पंडरिया का यह मामला है कुईकुकदुर वनांचल क्षेत्र है, जहां पर सालों से लाईट की व्यवस्था नहीं थी, बैगा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वहां की महिलायें माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से मिलने गई थीं और उनको धन्यवाद करने गई थीं कि उनकी व्यवस्था के कारण आज उस जगह पर लाईट पहुंच पाई है। सभापति महोदय, शायद जो कार्यकाल की बात कर रहे है, मुझे लगता है कि आपने 5 साल के कार्यकाल को याद कर रहे हैं जहां पर light का बटन लग जाता था लेकिन light के बटन दबाने से बिजली नहीं आती थी, इतनी बिजली कटौती हमारे छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में हुई है जो कि छत्तीसगढ़ बिजली सरप्लस हमारा राज्य था जिसमें भी कटौती की गई है लेकिन चूंकि विपक्ष में हैं तो कुछ तो बोलना है । वे इस बजट के लिये हमारे वित्त मंत्री जी का आभार या धन्यवाद तो कर नहीं सकते इसलिये निश्चित ही हम उनकी भावनाओं को भी समझते हैं और जिस तरीके से infrastructure का जो प्रावधान किया गया है, चूंकि infrastructure को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है और infrastructure के बजट में लगभग 18 प्रतिशत की जो वृद्धि की गई है तो निश्चित ही infrastructure चाहे किसी क्षेत्र के विकास के लिए देखें या रोज़गार उन्मूलक की तरीके से देखें तो infrastructure डवलप होने से किसी राज्य में निश्चित ही उस राज्य के विकास की गति को मेजर किया जा सकता है जो पिछले congress के कार्यकाल में अछूता था। अभी विषय आ रहा था कि सड़क को उखाड़ करके उसी को वापस बनाया जा रहा है। मैं कांग्रेस का कार्यकाल याद दिलाना चाहूंगी कि सड़क उखड़ने और उसको बनाने की बात बहुत दूर की है, कांग्रेस के कार्यकाल में उस सड़क में डामर की एक layer भी नहीं बिछी है तो पुल-पुलिया आज भी उसी स्थिति में थे जो पिछले 5 साल जिस स्थिति में थे, आज उसको भाजपा की ही सरकार बना रही है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात बहुत ही स्पष्टता से कहना चाहूंगी कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो । चूंकि भाजपा की सरकार की एक खासियत है कि अगर वह किसी चीज़ के लिए बजट दे रही है और बजट में प्रावधान कर रही है और वह कार्य चालू हो रहा है तो

उसका भूमि-पूजन भी अभी जो माननीय सदस्य हैं, वही करेंगे और उसका जो लोकार्पण है वह भी करेंगे और कांग्रेस के कार्यकाल में जो भूमि लोकार्पण हुए थे ।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से माननीय सदस्या बोल रही हैं कि सबकी तरफ ध्यान दिया गया है तो मैं बताना चाहूंगा कि गरियाबंद जिले के अंतर्गत जहां लोग कहते थे कि अमीर धरती के गरीब लोग, जहां हीरा का खदान है ऐसी जगह में न बिजली के संबंध में कोई बजट लाया गया और मैं यहां तक बता दूं कि जो पुल-पुलिया की बात कर रहे हैं । हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जब थे, उस समय की बेलाट नाला की घोषणा । आज लगातार 15 से 20 साल हो गये हैं, इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी घोषणा की है लेकिन पता नहीं वह घोषणा कब तक केवल घोषणा ही रह जाएगी ? और साथ ही साथ एक अमलीपदर का मामला है ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्यामबिहारी जायसवाल) :- जनक राम जी, आपको डॉ. रमन सिंह जी के कार्यकाल की घोषणा का ध्यान है तो आप लोग 5 साल क्या कर रहे थे ? क्या आप लोग सो रहे थे ?

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, अमलीपदर और बेलाट नाला की जो घोषणा हुई है आज तक किसी प्रकार का पुल में बजट में सम्मिलित नहीं किया गया है । न मेरे क्षेत्र में किसी प्रकार का बजट नहीं हुआ है । मैं यहां तक बता दूं कि महतारी वंदन का जहां 2 दर्जन लोग आज भी रोज़ तहसील कार्यालय मैनपुर में आना-जाना कर रहे हैं, आज तक उनका महतारी वंदन का पैसा नहीं मिल रहा है, मैं जिसमें आंकड़ा भी बता दूंगा ।

सभापति महोदय :- हो गया, अब आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं न । थोड़ा सुनिये, आपकी बात माननीय वित्तमंत्री जी सुन रहे हैं । आप चाहें तो एक चिट्ठी लिखकर उनको दे दीजिये, वे दिखवा लेंगे ।

श्री जनक ध्रुव :- जी-जी । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- भावना जी ।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय सभापति महोदय, हम जो Good governance की बात करते हैं उसके क्रियान्वयन की जो हम बात करते हैं । यदि हम क्रियान्वयन के लिये आंकलन करते हैं तो जो अटल monitoring portal है उसके लिए लगभग 10 करोड़ का प्रावधान इस बजट में रखा गया है । सरकारी खरीदी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो जैम portal की खरीदी को अनिवार्य रूप से किया गया है, मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट निर्णय माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का है । जो भी ट्रांसपेरेंसी है, वह बहुत clear है । जिस तरीके से लगातार हर चीज़ में, हर tender में या जिस भी विषयों पर लगातार जो भ्रष्टाचार होते आ रहा था । मुझे लगता है कि पारदर्शिता को बनाए रखने में जैम portal काफी सहयोगी साबित होगा उसके अलावा मैंने बजट में अधोसंरचना की बात की है । मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूंगी कि महिला होने के नाते हमें शुरूआत से ही जो चीज ज़्यादा आकर्षित

कर रही है वह है working womens के लिए जो hostel की सुविधा दी गई है ।

माननीय सभापति महोदय, हमारा विधान सभा जिस rural area से आता है वहां निश्चित ही बच्चियों को बाहर job बहुत आकर्षित करता है कि बाहर जाकर के अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम job भी वहां पर करें । पढ़ाई करने से hostel की सुविधा उनको मिलती है लेकिन बाहर जब job करने की बात आती है तो कहीं न कहीं परिवार भी सुरक्षा की दृष्टि को प्राथमिकता देता है और जिस तरीके से working womens के लिए जो hostel की व्यवस्था की गई है, मैं उसके लिए आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और शायद यह पहली बार ऐसा है कि किसी का ध्यान इस विषय पर गया है तो इसके लिए भी मैं बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी ।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में महाविद्यालयों के निर्माण के लिए उनके पुनरुत्थान के लिए 212 करोड़ का, पी.एम. श्री स्कूल के लिए जो भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी की है उसके लिए लगभग 227 करोड़ रूपये का, 12 नर्सिंग कॉलेज जो नए खुलने हैं, उसके लिए 34 करोड़ रूपये का और फिजियोथेरेपी कॉलेज जो खुलने हैं, उसके लगभग 6 करोड़ रूपये सहित बहुत सारी अन्य व्यवस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र की गई हैं।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- महोदय जी, बहुत जल्दी, बस 2 मिनट। मैं महाविद्यालय के बारे में जरूर बोलना चाहूंगी।

सभापति महोदय :- आपको अपने क्षेत्र की कुछ बात करनी हो, वह कर लीजिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- जी, महोदय, मैं जरूर उस विषय पर भी रखना चाहूंगी, क्योंकि आपने संज्ञान दिलाया, मैं आपका धन्यवाद करती हूं। महाविद्यालय का विषय आ रहा है तो निश्चित ही मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में चूंकि विधान सभा का क्षेत्रफल लगभग बहुत बड़ा है। अगर मैं सेकंड लार्जेस्ट क्षेत्रफल के दृष्टि से कहूं तो शायद गलत नहीं होगा और उसके अनुसार कॉलेजों की संख्या काफी कम है। आज भी बच्चियों को या छात्र-छात्राओं को जो दूरी तय करनी पड़ती है, वह लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पर बस की व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना पर्याप्त होगा तो महोदय जी से एक निवेदन भी मैं जरूर करूंगी कि दो-तीन कॉलेज खोलने के लिए मांग है, विशेष रूप से रणवीरपुर, वीरेंद्र नगर और एक मरका के लिए कॉलेज की जो मांग की गयी थी, उसको अगर हो पाए तो उसको संज्ञान में एक बार जरूर लें। इसके साथ ही विषय इतने सारे हैं, अगर हम बजट पर बोलें तो मुझे लगता है कि समय भी कम पड़ जाएगा। चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, मैं फिर से बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए जिस तरीके से बजट आया है, सारी आम जनता भी उस बजट से बहुत संतुष्ट है और मुझे विश्वास है कि बजट पर पूरा

implementation होगा। महोदय जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत अभिनंदन है। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- श्री द्वारिकाधीश यादव।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- सभापति महोदय, धन्यवाद । विकसित भारत 2047 का विजन लेकर आये 1 लाख 64 हजार करोड़ रूपये, संभावित व्यय का बजट प्रस्तुत किया गया है, जिस बजट में छत्तीसगढ़ की जनता के हित में, युवाओं के हित में, किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में कोई बात नहीं है, इसलिए मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं। माननीय सभापति महोदय, यह बात सच है और सबको इस बात की उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जब ओ.पी. चौधरी साहब आए तो लोगों के मन में था कि एक विद्वान व्यक्ति, पढ़ा-लिखा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और जब अच्छे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में रहेंगे तो उनकी योग्यता, उनकी बुद्धिमत्ता का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा, लेकिन पता नहीं डबल इंजन की सरकार अब तीसरी इंजन की सरकार बन गई है और माननीय ओ.पी. चौधरी साहब इतना विद्वान होते हुए छत्तीसगढ़ की उम्मीद के हिसाब से अभी तक दूसरा बजट प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन बजट पेपर में अलग और इस टाइम तो आप अपने हाथ से लिखकर दिए हैं तो हो सकता है कि गारंटी पूरी हो जाए, क्योंकि इस टाइम हाथ में लिखे हैं तो धरातल में दिखे। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की जब आंदोलन की बात चलती थी तो एक ऐसे ही विद्वान नेता, मैंने उनका भाषण सुना था, जब छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा तो छत्तीसगढ़ राज्य में इतने संसाधन हैं कि देश का पहला राज्य हो सकता हैं, जो टैक्स मुक्त राज्य बन सकता हैं। जब मैं युवा कांग्रेस में था तब छत्तीसगढ़ के वैसे विद्वान नेता बोले थे, जैसे कि आप लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य बने 24 साल हो गए, 1 लाख 64 हजार करोड़ का बजट और पूंजीगत व्यय में मात्र 26 हजार करोड़ है और इस 26 हजार करोड़ में कर्ज का ब्याज भी पटाना शामिल है। माननीय सभापति महोदय, एक तरफ सब नेता भाषण दे रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बजट से वे बातें बजट में सम्मिलित प्रस्तावित से ही तय हो गयी हैं कि कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, अगर कोई भी परिवार का मुखिया भी ज्यादा कर्ज लेता है तो उस पिता को बेटा भी अच्छा नहीं समझता। पड़ोसी भी अच्छा नहीं समझता। समाज में भी उसको अच्छा सम्मानित नहीं किया जाता। इस सरकार की स्थिति यह है कि 1 साल में 35 हजार करोड़ का कर्जा और जो बातें लिखी गई हैं, अगर उसमें कहा जाएगा तो लगभग 34 हजार करोड़ के आसपास और कर्ज लेने की तैयारी में यह सरकार है। अगर कर्ज की बात करें तो जिस रफ्तार में कर्ज लिया जा रहा है और जैसे खर्च किया जा रहा है तो जब ये सरकार बदलेगी और हम लोग 5 साल बाद आएंगे तो डेढ़ सौ करोड़ रूपये से ऊपर के कर्ज में हम आएंगे, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। इस बजट में बहुत सारी कविता के माध्यम से ध्यान भटकाने का भी प्रयास किया गया है। 2047 में सम्मिलित विकसित भारत की बात

कही जा रही है । देश की भी वही स्थिति है दिल्ली की सरकार इतने कर्ज में चल रही है । 2047 का सपना दिखाकर वर्तमान के ध्यान को भटकाने का काम दिल्ली की सरकार कर रही है और राज्य की सरकार कर रही है । बातें तो वर्तमान की होनी चाहिए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और न ही होगा । डबल इंजन की सरकार जब चुनाव में जाते हैं तो नेता बोलते हैं कि हमारी दिल्ली में सरकार है 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री हैं, धनराशि की कोई कमी नहीं होगी ।

समय
2.21 बजे **(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं)**

श्री रामकुमार यादव :- 36 रहिस हे, धीरे-धीरे कम होत हे । डब्बा गोल हे तुंहर ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- द्वारिकाधीश जी, आपका तो नाम द्वारिकाधीश है, कम से कम नाम के अनुरूप तो सत्य-सत्य बोलिए ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं । असत्य बोला हूं तो बता दीजिए ।

श्री रामकुमार यादव :- एकर चक्र चल ते अभी चक्र ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं । दिल्ली में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी ही पार्टी और दल की सरकार है । लेकिन वित्त मंत्री जी मैं जानना चाहता हूं, जब आप भाषण देंगे तो कौन-कौन से विभाग में, कौन-कौन सी योजना में बगैर राज्यांश जमा किए, इस सरकार को दिल्ली से धनराशि प्राप्त हुई है, उसको जरूर बताएंगे । सभापति महोदय, पिछले बजट में युवाओं पर फोकस था । इस बार युवाओं को थोड़ा सा साइड करके 2047 की बात की गई है । इस सरकार में आने पर युवाओं को आप पर बहुत भरोसा था, महतारी वंदन तो है ही लेकिन युवाओं का सर्वाधिक विश्वास आपके ऊपर था लेकिन सरकार में आने के बाद आप ने ही गुमराह कर दिया । युवा धोखे के शिकार हुए हैं, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है ।

प्रधानमंत्री आवास की बात हमारी सरकार के समय होती थी और आपकी सरकार में भी हो रही है । 18 लाख प्रधानमंत्री आवास यानी वित्त मंत्री जी 18 लाख परिवारों के लिए छत जरूर बना रहे हैं । लेकिन उस छत में उनको शांति नहीं मिलेगी इसलिए पांच साल पुराने एसओआर दर पर प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं । ऐसा प्रधान मंत्री आवास बनाने वाले गरीब के ऊपर 30 से 40 हजार रूपए का कर्ज हो रहा है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस गरीब का आवास बन रहा है । जैसे किसानों को अतिरिक्त धनराशि दी जा रही है वैसे ही गरीब को 30 या 40 हजार रूपए अतिरिक्त देने की व्यवस्था सरकार करे तो ज्यादा अच्छी बात होगी ।

सभापति महोदय, एक और महत्वपूर्ण बात है । हमारी सरकार में एक नेता प्रतिपक्ष थे । जो हमेशा बोलते थे कि छत्तीसगढ़ के युवाओं की जवानी और छत्तीसगढ़ का पानी, वे सदन में इस बात को

लाते थे, दुर्भाग्य से वे सदन में नहीं आ पाए हैं। हमारे क्षेत्र में सिकासेर से बांध खल्लारी महासमुंद में आने का प्रस्तावित है, पिछले बजट में शामिल था लेकिन अभी तक उसमें प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । सिंचाई के क्षेत्र में सिकासेर बांध का । मैं आपसे एक और निवेदन कर रहा हूं, कई बार बड़े उद्योगपति आते हैं तो वे अपनी व्यवस्था पहले बना लेते हैं । कोडार बांध के आजू-बाजू उद्योग लगना शुरू हो गया है । एक तो निवेदन करता हूं कि सिकासेर बांध वाले प्रस्ताव को आपसे स्वीकृति मिले, निर्माण कार्य प्रारंभ हो । डीपीआर बन रहा है लेकिन मुझे आशंका है कि वह पानी केवल किसानों के लिए रहे, कोडार बांध के बाजू में उद्योग लगना शुरू हो गया है, उस पानी को उद्योगपति को न दिया जाए । अभी सी डीपीआर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए वह केवल किसानों के लिए हो । मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं ।

सभापति महोदय, किसानों के धान की खरीदी तो हुई, ठीक है मैं मानता हूं । बार-बार सत्ता पक्ष के साथी लोग हमारे ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि हमने पांच साल में कुछ किया ही नहीं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार में किसानों के हित में सबसे पहले काम हुआ तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुआ, 2 घंटे के अंदर दस्तखत हुआ जिसमें 2 घंटे के अंदर 10 हजार करोड़ कर्जमाफी की प्रक्रिया की शुरूआत हुई। हमारे दल के उपर ये आरोप लगाते हैं कि हमने शराबबंदी के लिए गंगाजल उठाया था, वह शराबबंदी के लिए नहीं था, वह कर्जमाफी के लिए था। हमारे राष्ट्रीय नेता ने 10 दिन में कर्जमाफी नहीं होने पर मुख्यमंत्री बदलने की बात की थी, दो घंटे में प्रक्रिया की शुरूआत हुई थी।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय सभापति महोदय, आपने स्वीकार किया है कि गंगाजल उठाए थे, कर्जमाफी के लिए उठाए थे तो यह बता दीजिए कि बेरोजगारों को भत्ता देने और महिलाओं को 500 रूपए देने के लिए गंगाजल उठाए थे या नहीं उठाए थे।

श्री रामकुमार यादव :- जायसवाल जी, आपके नाम जायसवाल हे और आप बार-बार सवाल करथव।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- कर्जमाफी के लिए उठाए थे। सभापति महोदय, हम लोग पहले सुना करते थे, हरियाणा, पंजाब में जमीन का दाम 1 करोड़ है, छत्तीसगढ़ में 15 साल की हुकूमत में केवल 2 लाख से शुरू हुई और 5 लाख तक गया। हमारी सरकार में किसानों का कर्ज माफ हुआ और 2500 धान की कीमत दी तो छत्तीसगढ़ की गांव में भी जमीन का दाम 15 लाख से 20 लाख रूपए तक पहुंच गया। हमारी सरकार में 10 एकड़ के किसान को 8 लाख का मुनाफा हुआ। अगर पूंजीगत व्यय बढ़ाने का काम कोई किया है तो हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार के पहले 10 एकड़ के किसान की पूंजी 50 लाख रूपए हुआ करता था, हमारी सरकार बनने के बाद केवल और केवल 5 साल में डेढ़ से दो करोड़ रूपए हुआ। मेरे भांचा तो खरबोपति हो गए, कई सौ एकड़ जमीन हे।

श्री रामकुमार यादव :- एखर पैसा ला दींयार चरत हावए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, किसानों के हित की बात करते हैं। सरकार ने धान खरीदी की है, अव्यवस्था में की है। लेकिन किसानों को कैसे लूटा जा रहा है, जैसे आप कितनी भी महंगी गाड़ी ले लीजिए, बगैर पेट्रोल डीजल की वह गाड़ी नहीं चल सकती। आज की तारीख में किसानों की सर्वाधिक आवश्यकता है, जैसे घर में बिजली की जरूरत है, वैसे किसानों को बिजली की जरूरत है। बिजली के स्थाई कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। स्थाई कनेक्शन में किसानों को 2200 रूपए जमा करना पड़ता है, अस्थाई कनेक्शन में 4000 रूपए जमा करना पड़ता है। हमारे वरिष्ठ नेता माननीय धरमलाल कौशिक जी अभी यहां पर उपस्थित नहीं हैं, वे हमारी सरकार में हर समय स्थाई कनेक्शन और अस्थाई कनेक्शन के मुद्दे उठाते थे। वर्तमान में जो बजट प्रावधान किया गया है, उसमें विद्युत मंडल को जो पूर्व में धनराशि दी गई थी, उससे कम दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने जो धनराशि दी है, उसमें किसानों को 25 प्रतिशत भी स्थाई कनेक्शन नहीं मिलेगा। आप जब भाषण देंगे तो आप इस बात को जरूर बताएंगे, मैं पूरे छत्तीसगढ़ के किसान के लिए निवेदन कर रहा हूं, आप उनके स्थाई कनेक्शन की व्यवस्था के लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाह रहा हूं। मैंने पिछली बजट में थर्ड जेंडर का मामला उठाया था। आपने हृदय से इस बात का आश्वासन दिया था कि बिना बजट के भी एक ऐसी बजट है जिसमें शामिल करके उनके हित में कोई न कोई योजना बनाएंगे, ऐसा आपने कहा था। मैं इस बजट पुस्तिका में खोजता रहा, थर्ड जेंडर के लिए क्या है लेकिन आपने उसमें केवल एक बात का उल्लेख किया है समानता में सम्मिलित किया जाएगा जिसको मैं स्पष्ट समझ नहीं पाया। आप अपने भाषण में जरूर बताएंगे और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप ही के विधान सभा में सर्वाधिक हैं और प्रथम नागरिक भी बने हैं। उनके हित में कोई न कोई योजना बननी चाहिए, बहुत ज्यादा धनराशि की जरूरत भी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जब भाजपा की सरकार थी तो गरीब का बेटा और बेटी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बिल्डिंग को देखा करते थे, बाउंड्री को देखते थे, अंग्रेजी में बोर्ड लिखा रहता था पढ़ नहीं पाते थे लेकिन उनकी इच्छा जब हमारी सरकार बनी तो स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से गरीब का बेटा केवल दीवार को नहीं देखता है और गरीब का बेटा केवल उसकी बिल्डिंग को नहीं देखता है, बल्कि गरीब के बेटा-बेटी उस स्कूल में पढ़ें। दूसरा, अंग्रेजी बोलने में भी आजादी के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ कि गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन जीने वाले माता-पिता के बेटा-बेटी भी अंग्रेजी में बात करने लगे।

सभापति महोदया :- यादव जी, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, ओ डहार एक भी मंत्री नहीं बइठे हें।

सभापति महोदया :- मंत्री जी आ गये हैं। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदया, यह तो रसगुल्ला खाते हुए इधर-उधर घूम रहे हैं। (हंसी)

सभापति महोदया :- यादव जी, आप समाप्त करें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदया, केवल दो मिनट। मैं एक महत्वपूर्ण बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। विकसित भारत 2047 की बात है तो आज समूचे हिंदुस्तान या विदेश में भी अंग्रेजी के ज्ञान के बगैर कोई भी प्रदेश या कोई भी युवा आगे नहीं बढ़ सकता है। स्वामी आत्मानंद स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई हो रही थी, लेकिन केवल और केवल चूंकि वह योजना हमारी सरकार की थी, इसलिए यहां के बच्चों के साथ अन्याय करने का काम यदि कोई कर रही है तो यह वर्तमान की सरकार कर रही है। उस स्कूल को पी.एम. श्री का नाम तो दे दिया गया। जब हमने स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर उस स्कूल का नाम रखा था तो यहीं के वरिष्ठ सदस्य ऐसा कोई सत्र नहीं था, जिसमें केवल उनके नाम का विरोध करते थे। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि पी.एम. श्री स्कूल में भी वैसी ही व्यवस्था दी जाये, जैसे कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के समय थी। दूसरी बात, बजट में एक और बात आई है कि ढाई सौ करोड़ रूपये के डी.एम.एफ. फण्ड से दंतेवाड़ा में मेडिकल बनाया जा रहा है। यह केवल मंच में बोलने के लिए और सदन में बोलने के लिए है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदया, माननीय सदस्य को शायद जानकारी नहीं होगी। पिछली सरकार में आप विधायक भी रहे हैं। उस समय आपके PCC के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हुआ करते थे। सभापति महोदया जी जानती हैं। उन्होंने डी.एम.एफ. की राशि का जो घोटाला हुआ था, उसपर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया था।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- हां, किया था।

श्री केदार कश्यप :- आज डी.एम.एफ. का सदुपयोग हो, इसके लिए सरकार इस तरीके से प्रस्ताव लायी है।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदया, कतना सदुपयोग होए रीहिस हे, तेला हमन जानत हन। तुमन केवल swimming pool बनवाये हो। तुमन डी.एम.एफ. से swimming pool बनाथो।

सभापति महोदया :- यादव जी, समाप्त करें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- महोदया जी, एक मिनट। माननीय मंत्री जी, आप मुझे दिशा से भटका रहे हैं। प्रदेश के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी से और यदि वह यहां पर उपस्थित नहीं हैं तो आपसे निवेदन है। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। हम इसका स्वागत करेंगे। जैसे दंतेवाड़ा में डी.एम.एफ. से हॉस्पिटल बन रहा है। लेकिन समूचे छत्तीसगढ़ में अभी तक डी.एम.एफ. से जितने कार्य स्वीकृत हुए हैं,

वह गलत हुए हैं तो क्या उसकी जांच होगी ? माननीय मंत्री जी, हमारे समय में तो कम से कम डी.एम.एफ. कमेटी की बैठक होती थी।

श्री केदार कश्यप :- आप अपनी सरकार के कार्यकाल की जानकारी दीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदया, यदि हमारी सरकार में गलती हुई है तो आप उसकी जांच करवाकर उसपर कार्रवाई कीजिये। हम आपको मना थोड़ी न कर रहे हैं। अच्छा, यदि हमारी सरकार के समय गड़बड़ी हो गई तो क्या आपकी सरकार में भी वही होगी और क्या आप भी वही करेंगे? (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- आपके ही PCC के अध्यक्ष ने उसमें प्रश्नचिन्ह खड़ा किया था। आप चाहे तो PCC अध्यक्ष के पत्र से करवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदया, मेरा यह कहना है कि डी.एम.एफ. में आपने दंतेवाड़ा का जो उदाहरण दिया है। ठीक है, वहां पर ढाई सौ करोड़ रूपये का काम सही हुआ है। वहां पर डी.एम.एफ. की राशि से हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन समूचे छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, जो यह जांच का विषय है ? डी.एम.एफ. कमेटी की बैठक नहीं हो रही है।

सभापति महोदया :- द्वारिकाधीश जी, आप बात समाप्त करिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदया, वित्त मंत्री जी तो यहां पर नहीं हैं, लेकिन अंत में मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन कर रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 सड़कों को विधान सभा चुनाव के पहले प्रशासकीय स्वीकृत मिल चुकी थी और विभाग में उसकी धनराशि भी जा चुकी है, उसमें निविदा प्रक्रिया से आगे हो। उस सड़क में चलने वाले मतदाता भाई-बहनों की गलती नहीं है कि मैं विधायक हूं। सभापति महोदया, मैं आपको बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

सभापति महोदया :- श्रीमती गोमती साय जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, ट्रेजरी बैंच में सिर्फ एक ही मंत्री बैठे हैं। निवेदन है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा चल रही है। निवेदन है कि कुछ मंत्री आ जाये और हमारी बात सुने।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- सभापति महोदय, मैं हूं। हमारे मंत्रीगण अभी भोजन कर रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- एक मंत्री का करही, मोला बतावा त? अउ हमार बात ला कागज में कोनो लिखत भी नइ ए। ये सरकार केतका गंभीर है, हमन समझ गयन। भाषण ला भी सुने बर तैयार नइ हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- एक घंटे पहले भी भोजन कर रहे थे। सभापति महोदय, लंच ब्रेक कर दीजिये।

श्री केदार कश्यप :- आप लोगों के पास कोई नहीं बात नहीं है, आप लोगों के पास विषय नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं बोल रही हूं कि लंच ब्रेक कर दीजिये। लंच हो जायेगा तब सभी आ जायेंगे।

सभापति महोदय :- गोमती साय जी, अपनी बात शुरू कीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- एक भी मंत्री नहीं हैं तो हम किनको सुना रहे हैं?

श्रीमती गोमती साय (पत्थलगांव) :- माननीय सभापति महोदया जी, वर्ष 2025-26 का जो बजट पेश हुआ है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। हमारे युवा वित्तमंत्री जी को बहुत- बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं, साथ ही हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को भी बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदया जी, यह बजट पुस्तिका है। भले ही हम लोगों को पकड़ने और उठाने में हल्का लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर जो बजट प्रावधान है, वह वाकइ में प्रदेश की जनता के हिसाब से बनाया गया है और एक-एक जनता तक पहुंचने वाला बजट है। जब से इस प्रदेश में विष्णु देव साय जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की गारन्टी वाला सरकार बना है, तब से आज सवा साल हो गया है। इसके पूर्व हमारे प्रदेश की बजट की क्या स्थिति थी, यह सभी लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता तो जानती ही है। आज जितने भी लोग सदन में बैठे हैं, वे लोग भी जानते हैं।

माननीय सभापति महोदया, यह बजट गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के सपनों को साकार करने वाली बजट है। आम जनता के भविष्य को गढ़ने वाली बजट है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारन्टी को पूरा करने वाला बजट है। यह बजट डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने वाला बजट है। यह बजट किसानों को खुशहाली और उनकी समृद्धि का बजट है। यह बजट छत्तीसगढ़ को विकसित, सुरक्षित और समृद्ध करने वाला बजट है। माननीय सभापति महोदया, आज से सवा साल पहले की बजट याद करें, स्मरण करें तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कर्ज तो जरूर लिया जाता था, लेकिन स्थिति कैसी थी, उस चीज को छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत करीब से देखा है।

माननीय सभापति महोदया जी, कुछ पंक्ति है, मैं उसको बोलकर बजट की सामान्य चर्चा की शुरूआत करूंगी :-

"कश्ती चलाने वालों ने जब हार की पतवार दी हमें,
लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मझधार हमें,
फिर भी दिखाया है हमने और फिर यह दिखा देंगे सबको,

कि इन हालत में आते हैं, दरिया करना पार हमें। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, हमारे युवा वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देश अनुसार, ये लोग किस तरह से बजट को छोड़कर गये थे और किस तरह से हमारे युवा वित्त मंत्री जी ने संभाला है, मैं इस पंक्ति के द्वारा उन्हें समर्पित करती हूं।

माननीय सभापति महोदया जी, कृषि उन्नत योजना, खेती के फायदे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना था और उनका कहना भी था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो, उसके हिसाब से उनके लिए योजना बनाई गई है। आज सबके सामने साक्षात् रूप से दिख रही है। मैं भी एक किसान हूं, किसान होने के नाते मैं बहुत अच्छे ढंग से जानती हूं कि धान का 3100 रूपया प्रति क्विंटल मूल्य होने के कारण आज प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी हुई है। यह निश्चित है कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से खेतों में उपयोग होने वाली मशीनरी की खरीदी-बिक्री हो रही है, इसका यह साक्षात् प्रमाण है, हम लोग उसको झुठला नहीं सकते हैं। माननीय महोदया जी, आज जिस तरह से वंचित वर्ग खेती के माध्यम से अनेको पैदावार चाहे रबी फसल हो, चाहे खरीफ फसल हो, आज हमारे युवा उर्जावन वित्तमंत्री जी ने बजट में राशि विभाजित किया है, खरीफ फसल को खरीदने की योजना को भी इस बजट में शामिल किया है। आज जिस तरह से महतारी वंदन योजना संचालित है । जब तक महिलाएं सक्षम नहीं होंगी, सशक्त नहीं होंगी तब तक न हमारा छत्तीसगढ़ सशक्त हो सकता है और न ही हमारा देश सशक्त हो सकता है। आज महतारी वंदन योजना के तहत् महिला बहनें अपने आपको देश चलाने में सक्षम महसूस कर रही हैं। मैं एक और चीज कहना चाहती हूं कि जिस तरह से हमारी संगीता सिन्हा दीदी कह रही थी कि अगर देश चलाना हो या राज्य चलाना हो तो उससे पहले आप घर चला लीजिये। जिस तरह से घर व परिवार चलाया जाता है, उसी तरह से प्रदेश भी चलाया जाता है। यह कोई दूसरा विषय नहीं है। परिवार चलाना छोटा विषय हो सकता है। प्रदेश चलाना उससे बड़ी बात है, लेकिन ज्ञान एवं अनुभव वहीं से होता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय जी, मैंने वही बात कही थी कि अगर बजट देखा जाये तो सबसे अच्छा महिला करती है। क्योंकि वह कम बजट में पूरा घर चलाती है।

श्रीमती गोमती साय :- सभापति महोदय, यदि बजट की बात करें तो महिलाओं से अच्छा बजट का हिसाब-किताब कोई नहीं जान सकता है कि कम खर्च में किस तरह से सुनियोजित ढंग से घर-परिवार को चलाया जा सकता है। यह बात महिला लोगों से छिपा नहीं है। इसलिए महिलाएं इस बजट को जानती हैं। आज जिस तरह से चिकित्सा शिक्षा में बढ़ोत्तरी हुई है। मैं आज वर्ष 2024-2025 के प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। आज जांजगीर-चांपा, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा, कवर्धा, कुनकुरी में जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है। एक जमाना हुआ करता था कि पूरे छत्तीसगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज था, जिसके कारण हम लोगों को डॉक्टर एवं नर्स का अभाव

था। आज बच्चे इन मेडिकल कॉलेजों से पढ़ कर आयेंगे, डॉक्टर बनेंगे, नर्स बनेंगे तो हमारे प्रदेश में डॉक्टर एवं नर्स की संख्या भी बढ़ेगी। जैसे जशपुर जैसी जगह में यहां से कोई डॉक्टर जाना ही नहीं चाहता है, वहां रहना ही नहीं चाहता है, लेकिन आज हमारे जशपुर के बच्चे डॉक्टर एवं नर्स बन जाते हैं तो जशपुर के बच्चे जशपुर में ही रहेंगे। वे बाहर कहीं नहीं जायेंगे। इसका फायदा हमारे इस बजट में मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस तरह से उद्योग की बात करूं। इस बजट में रेशम उद्योग के लिए भी नीति लागू किया गया है। इसके लिए मैं हमारे युवा वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं, क्योंकि यदि रेशम का उद्योग होगा, कोसा का खेती किया जाये। चाहे हमारा जांजगीर-चांपा हो, चाहे सारंगढ़ हो या चाहे रायगढ़ हो, आप विश्वास नहीं करेंगी कि जब मैं सांसद थी तो मैं क्षेत्र में दौरे में जाती थी तो घर-घर एक मशीन लगा हुआ है, जो हर घर में कोसा का साड़ी एवं कोसा का कपड़ा बनता है। अगर पूरे देश में कोसा साड़ी या कोसा कपड़ा की बात होती है तो हमारा छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर आता है। इसलिए इसको भी बजट में शामिल किया गया है, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

सभापति महोदय, नक्सलवाद क्षेत्र में 300 नये बस्तर फाईटर पदों का सृजन होगा। यह इस बजट में लागू किया गया है। यह नई योजना है। क्योंकि हमारे प्रदेश के लिए इसकी जरूरत है। बस्तर एवं जशपुर जैसे क्षेत्र के लिए फाईटर की बहुत ही जरूरत है क्योंकि जब फाईट करने का समय आता है, जब विपरीत परिस्थिति आती है, जब मुठभेड़ का समय आता है तब अपना बचाव करने के लिए यह फाईटर जरूरी है। इसलिए इसको इस बजट में शामिल किया गया है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। माननीय सभापति महोदय, साइबर सेल का बहुत बात कर रहे थे। मैं सांसद भी थी, मैं साइबर सेल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं क्योंकि जब मैं महिला समिति में थी तो हम लोग जगह-जगह देश में जाकर बैठक करते थे तो अपराध को कंट्रोल करने के लिए साइबर सेल का अधिकारी बहुत ही कम संख्या में हैं। लेकिन आज जिस तरह से हमारी छत्तीसगढ़ सरकार इस विषय में कदम उठा रही है, उसके लिए भी इस बजट में शामिल किया गया है। चाहे महिला सुरक्षा का विषय हो, चाहे हमारे बच्चों व हमारी बेटियों की सुरक्षा का विषय हो, यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बजट में शामिल किया गया है। अगर उच्च शिक्षा की विषय का बात करूं तो सभी जगह नवीन शासकीय महाविद्यालय खुल रहे हैं। जैसे नारायपुर हो गया, फरसाबहार हो गया, कड़ेगा हो गया, किनेपाल हो गया, बस्तर हो गया, यहां स्थापना हो रही है, जिस तरह से हमारे बस्तर और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बच्चे हैं, युवा और नवजवान हमारे बच्चे हैं, जो मध्य छत्तीसगढ़ में आकर नहीं पढ़ पाते हैं, यह सबके बस का बात नहीं है कि रायपुर के मकान में किराये पर आयें और पढ़ें लिखें, ऐसा विषय नहीं है । सभापति महोदय, जो दूरस्थ अंचल में वनवासी बच्चे रहते हैं, वही लोग जानते हैं कि पढ़ाई का महत्व क्या है ? घर से बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिये जाने वाले बच्चों को

कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, महाविद्यालय खुलने से बच्चे वहीं से आना-जाना करेंगे, इसका प्रभाव दोनों संभाग के बच्चों पर पड़ेगा ..।

सभापति महोदय :- जल्दी समाप्त करेंगे ।

श्रीमती गोमती साय :- जी । माननीय सभापति महोदया, प्रदेश में बहुत सारे ऐसे विषय हैं, जो हमारे इस बजट में है । राजस्व को लेकर है, मैं हमारे युवा मंत्री जी को निवेदन कर रही हूँ कि जल जीवन मिशन देश की सबसे बड़ी योजना है, मेरा जो विधान सभा है, मैं जहां से जीतकर आई हूँ, वहां बिजली और पानी की सख्त जरूरत है, यह बजट में शामिल है, कृपया इसकी जहां-जहां जरूरत है, वहां-वहां देना चाहिये । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में अलग-अलग विषय को लेकर चिन्ता है, सब की अपनी जरूरत है और उसके हिसाब से लोक निर्माण विभाग में अच्छी सड़कें बनेंगी, अच्छी पुल-पुलिया बनेंगी, अच्छी भवन बनेंगी । माननीय सभापति महोदया, मैं सदन के समक्ष सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में बिजली, पानी, सड़क, भवन और सारी चीजें पहले से बन चुकी है, उसके रखरखाव की जवाबदारी हमारी है, हमारे सरकार की है । सभापति महोदय, यह रखरखाव न होने से दिनों-दिन यह जर्जर हो जाता है और उसके चलते हम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन इस बजट के माध्यम से रखरखाव करना, उसको सहेज कर रखना ज्यादा जरूरी है । सभापति महोदय, नये कुछ चीज बनें, उससे पहले पुरानी चीजों का रखरखाव अच्छे से करें और नया भी बनायें, इस प्रकार से बजट में जोड़ा गया है । सभापति महोदय, मैं इसके लिये धन्यवाद देती हूँ और एक विषय बोलकर अपनी बात समाप्त करती हूँ कि हमारे युवा मिनिस्टर जी अभी यहां नहीं है, जो खेल के माध्यम से बच्चों को अवेयरनेस कर रहे हैं, इससे प्रदेश को लाभ मिलेगा । सभापति महोदय, यह जो गांव-गांव में टॉवर के लिये धन राशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । सभापति महोदय, कभी यह कहा करते थे कि रोटी-कपड़ा-मकान हमारे जीवन का बहुत अभिन्न अंग है, ऐसे ही जहॉ टॉवर नहीं रहता है, वहां के बच्चे किस तरह से टॉवर खोज-खोज कर बात करने के लिये जाते हैं, इस योजना के माध्यम से गांव-गांव में व्यस्त स्थान हैं, वहां टॉवर के माध्यम से हमारे बच्चों को दूरस्थ स्थानों में जहां जनता रहती है, हमारे भाई-बहनों के पास यह टॉवर पहुंच जायेगा तो इसका भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा । सभापति महोदय, मैं इतना ही कहकर आज हमारे मुख्यमंत्री जी को और फायनेंस मिनिस्टर जी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनायें देते हुये यह कहना चाहूँगी कि एक बहुत अच्छा बजट छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित किये हैं, मैं उसके लिये बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुये अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ । धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के बजट भाषण के विपक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में शामिल किया है कि यह वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है । सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ युवा

प्रदेश है और यहां के युवाओं की औसत आयु 24 वर्ष है और हमारा यह प्रदेश 25 वर्ष का होने जा रहा है । सभापति महोदय, युवावस्था के इस प्रदेश में अगर कोई सर्वाधिक उपेक्षित कोई हुआ है तो युवा वर्ग हुआ है । इस सदन में हमारे बजट भाषण के पेज नंबर 40 जर्मन चांसलर ओलाथ स्क्लोच की घोषणा का भी जिक्र किया गया है । जर्मनी में भारत के कुशल वर्क फोर्स के लिए वीजा जारी करने की सीमा 20 हजार से बढ़ाकर 90 हजार कर दी गई है । मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह हमारे लिए उपलब्धि है या माननीय मंत्री जी ने देश के लिए तंज किया है । क्योंकि जिस देश में यहां स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं हैं तो लोग मजबूर होकर दूसरी जगह पलायन करेंगे ही । आज हम देखें तो आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंण्ड, जर्मनी, जापान, इटली यह इस तरह के देश हैं, जहां हमारे यहां के मैन पावर को मजदूरी करने के लिए लिया जाता है और जो पश्चिमी देश हैं, वहां हमारे देश के होनहार युवा पूरी तरह पलायन करते जा रहे हैं क्योंकि यहां पर अवसर नहीं हैं । हम देश से निकलकर प्रदेश के क्षेत्र की बात करें तो इस प्रदेश में भी हर साल 10 लाख से अधिक श्रमिक दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं । हम मजदूरी की बात कर लें, बिलासपुर रीजन की बात कर लें तो हमारे श्रमिक साथी लाखों की संख्या में दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और बहुत सारी घटनाएं हमें सुनने मिलती हैं, जिसमें आप सबके समक्ष कई बार बंधक बना लिया जाता है, कई बार उनके साथ मारपीट की जाती है, कई बार उनका वेतन उनको नहीं दिया जाता है । कुछ ही दिनों पहले की बात है, हमारे दंतेवाड़ा जिले के लगभग 25 से 30 मजदूर तेलंगाना में एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जिनमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, लगभग 20-25 मजदूरों की तबीयत खराब थी । हम बजट में तालियां बजवा लें, बहुत सारी बातें कह लें, लेकिन जो सच्चाई है, वह कुछ और दिखती है ।

माननीय सभापति महोदया, दो दिन पहले सरकार ने बजट पेश किया । बजट पेश किया तो बहुत तालियां बजीं । बड़े-बड़े समाचार-पत्रों में दो, तीन पेजेस के विज्ञापन आये और यह बताया गया कि बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया है । उसको पढ़कर, देखकर मुझे 2023 में विधान सभा चुनाव में मोदी जी की गारंटी याद आ गई । अब हम मोदी जी की गारंटी की बात करें तो हमारे आदरणीय मंत्री जी शायद भूल गए कि मोदी जी की गारंटी के नाम पर तो वोट ले लिए, लेकिन यह भी याद कीजिए कि आपने क्या कहा था ? आपने कहा था कि हम इनोवेशन हब बनाकर 6 लाख रोजगार देंगे । अब आपको सत्ता में आये एक साल से अधिक हो गया है । न स्टार्ट-अप पर कोई वर्क आउट है, न कोई इनोवेशन हब बना है, न कोई नौकरियों की बात हो रही है । आपने कहा था कि दो वर्ष में प्रदेश के सभी शासकीय रिक्त पदों को भर दिया जाएगा । हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर कुछ नहीं हुआ। खुद लिखने से काफी शिद्दत लगती है, मेहनत लगती है और अपनापन भी आता है । आपने लिखा है, यह अच्छा है, लेकिन उसमें एक पैराग्राफ सरकारी भर्ती पर लिख देते तो बड़ा आनंद आ जाता, लेकिन जाने

दीजिए । ऐसी कोई मंशा नहीं है इसलिए तो जर्मन चांसलर के विषय को सदन में रखा गया कि आप लोग पढ़ लिख लीजिए, जर्मनी में ज्यादा वीजा देने की बात हो रही है ।

मानननीय सभापति महोदया, मोदी जी की गारंटी थी-युवा सूचना क्रांति योजना। मोदी जी की गांरटी थी-टेबलेट-लैपटॉप वितरण योजना । अत्याधुनिक ओलम्पिक प्रशिक्षण एकेडमी, प्रत्येक जिले में खेल एकेडमी, छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, प्रतिभावान खिलाड़ियों को सालाना 75 हजार रूपए देने की बात थी । वह सब कहां गया ? कहीं नहीं है । जब हम चुनाव में जाते हैं तो हमें दिखता है कि हमें लोगों का वोट लेना है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है तो हम बोल देते हैं, लेकिन जब बजट में बात आती है तो केवल आपके पक्ष के लोग तालियां बजाते हैं, जनता उससे दुखी और आहत दिखती है । हम खेलों की बात करें तो छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक पिछली सरकार का एक बढ़िया आयोजन था । उसमें लोगों को आनंद आता था । माताओं-बहनों को घर से निकलकर इससे उनको अपना बचपन याद आ जाता था। उसे भी बंद कर दिया। कल शेरो-शायरी भी बहुत हुई है, एक शेर मैं भी इसी बात पर कह ही देता हूं कि -

जो जमीं के ना हुए, ओ आसमां के ख्वाब दिखाते हैं
सिलेंडर का दाम कम करने वाले, ब्लेंडर का दाम घटाते हैं।

ये सरकार सिलेंडर का दाम तो कम नहीं कर रही है लेकिन इन्होंने ब्लेंडर का दाम जरुर कम किया है।

श्री केदार कश्यप :- ब्लेंडर क्या है?

श्री देवेन्द्र यादव :- ब्लेंडर को आप जानते होंगे।

श्री केदार कश्यप :- आप ज्यादा जानते हो। इधर वाले नहीं जानते।

श्री देवेन्द्र यादव :- सब साथी लोग जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि सदन में इस पर बोलने की आवश्यकता है। आप ही लोगों ने बजट में घटाया है, आप ही लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपने बजट में लाया है, प्रावधान है, कैसे नहीं जानते हैं?

श्री रामकुमार यादव :- देवेन्द्र जी, रतिया पीके सूतथ, ती वाला हे ये ह। (हंसी)

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदया, ये सरकार महिला सम्मान की बात करती है कि सब माताओं-बहनों को 1200 रुपए देंगे। माताओं-बहनों को खुशी भी हुई, उसका लाभ भी महिलाओं को होगा लेकिन ये क्या हुआ कि सरकार चलते हुए कुछ ही समय गुजरा था कि अब आप पेंशनधारियों को पैसा नहीं देंगे, उसमें छंटनी करेंगे, आय देखेंगे, आपने उसमें बहुत सारे क्लॉज चालू कर दिए। मतलब ये भी राशन कार्ड जैसा हो रहा है, जैसा कि पिछले समय चलता था।

सभापति महोदया, मोदी जी की गारंटी में 500 रुपए में सिलेंडर मिलने वाला था, (सभापति महोदया की ओर इशारा) दीदी मिले हे का आपला? 500 रुपए में किसी को सिलेंडर नहीं मिला है, सब इंतजार कर रहे हैं।

सभापति महोदया :- समय का ध्यान रखेंगे।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदया, मैं बस अगले तीन-चार मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। माताओं को यहां तक कहा गया था कि खाने के साथ नाश्ते का भी प्रबंध किया जाएगा। नाश्ता तो छोड़िए, रेडी टू ईट वितरण प्रणाली को भी अभी तक आप लोग सही तरीके से डेलिवर नहीं कर पाए हैं। मोदी जी की गारंटी में था कि पिंक थाने खोले जायेंगे। भाई, पिंक थाने कहां खोले गये? बलात्कार, नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध जैसे बहुत सारे प्रकरण लगातार हम देखते हैं। आप सब जानते हैं, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा कि पिछले समय में इस तरह की कितनी घटनाएं हुई हैं लेकिन पिंक थाने की कहीं कोई सूचना हमें नहीं मिल रही है।

श्री केदार कश्यप :- यादव जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले समय में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, तो पिछली सरकार में क्या-क्या हुआ है, वह भी बता दीजिएगा। आप लोग पाइप लाईन में इतना छेद कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि किस-किस को हम बंद करें। इतना सारा गड़बड़ी करके निकलते हो और उसे ठीक करने का काम हम लोगों का रहता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 15 महीने में बच्चों के साथ रेप। (व्यवधान्

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदया, मतलब, आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं ना? आप जनता के सामने यह स्वीकार कर रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं। पिछले सवा साल में आप नहीं कर पाए।

श्री केदार कश्यप :- आप लोग इतना छेद कर दिए हैं ना कि छन्नी भी शरमा जाए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- 15 साल के छेद को हमने कम करने का प्रयास किया था।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपके बहुत सारे छेद हैं। आपके गिनायेंगे तो बहुत सारे हैं। आपका नशबंदी कांड है, नॉन घोटाला है, झरियामारी कांड है। गिनवाने चलेंगे तो आपके बहुत सारे छेद निकलेंगे।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठ जाइए। देवेन्द्र यादव जी कान्टीन्यू करिए।

श्री रामकुमार यादव :- एक मिनट दीदी। जवाब तो देना पड़ेगा ना। हमेशा हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बोलते हैं कि आपने ऐसा किया, तो हम ऐसा करेंगे। हर चीज को ऐसा क्यों करते हो? जैसे कि हमारे चन्द्राकर जी कुंआ में कूदिही त तुहूं कूद दिह का?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- नशबंदी कांड महिलाओं के लिए ही हुआ था।

श्री केदार कश्यप :- मेरी बात सुन लें जैसे माननीय नरेन्द्र मोदी जी वहां से प्रधान मंत्री आवास दिए, आपने कहा कि हमें नहीं चाहिए, प्रधान मंत्री जी का नाम होगा।

श्री रामकुमार यादव :-नगरीय निकाय में आप देवथ का? नगर पंचायत में एक भी पी.एम.आवास नहीं मिलत हे, एक भी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :-महंगाई को लेकर आपका ही नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार ने महंगाई कम किया है क्या? 500रुपए में सिलेंडर देने का वायदा किया था। आज स्मृति इरानी सर पर सिलेंडर को लेकर क्यों नहीं जाती हैं? (व्यवधान)

श्री केदार कश्यप :- आयुष्मान कार्ड में इन्होंने बोला कि हम यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लायेंगे। आप यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के बारे में बताइएगा कि आप किस तरीके से लाये थे। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आप भी ऐसा करेंगे ?

श्री केदार कश्यप :- नहीं, हम नहीं करेंगे। वह आप लोगों का काम है।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप मुझे बोलने दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमारी सरकार के समय सिलेण्डर थोड़ा सा क्या महंगा हुआ था आप लोग सिलेण्डर को सिर में उठा लेते थे। जबकि हम लोग उस समय 400 रूपये में सिलेण्डर दे रहे थे। आज आप सिलेण्डर को सिर में क्यों नहीं उठा रहे हैं ?

श्री देवेन्द्र यादव:- माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने बहुत सारे वायदे किये, बहुत सारी कसमें खायीं। इस सरकार ने कहा कि किसानों को एकमुश्त पैसा दिया जायेगा। हम देखते हैं कि इस बार धान खरीदी केंद्रों में जो हाल हुआ, वह एक ऐसी आपदा थी, जिससे प्रदेश के सभी किसान वर्ग पीड़ित और परेशान हुए। एकमुश्त पैसे की बात तो बहुत अलग है। यहां तो जो बीज के दाम है, किसानों को वह भी अत्यधिक दामों में खरीदी करनी पड़ी। आप पिछली सरकार के ऊपर यह आरोप लगाते थे कि कर्ज लिया जा रहा है, कर्ज लिया जा रहा है। आप देखेंगे कि पिछले 1 साल में यह सरकार कितना कर्ज ले चुकी है और कर्ज लेकर ही सरकार चला रही है और उसके बाद अपनी वाहवाही भी कर रही है कि यह कितनी बेहतर सरकार चला रही है।

सभापति महोदया, यदि हम अस्पतालों की बात करें तो हमर लैब का बट्टा बैठा हुआ है। यदि हम मोहल्ला क्लीनिक की बात करें तो वह एक ऐसी योजना थी जिससे माताओं, बहनों और गरीबों को उनके मोहल्ले में स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती थी। वह कहीं न कहीं ठप्प और बंद हो गयी है। हमने पिछले समय में ऐसे बहुत सारे प्रकरण देखे हैं, जहां पर गर्भवती माताओं बहनों के साथ कितना अन्याय हुआ है।

सभापति महोदया :- आप अपनी बात जल्दी समाप्त करिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदया, उनके लिये जो एम्बुलेंस जाती थी, वह एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती थी और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होने के कारण महिलाओं की मृत्यु तक हुई है।

हमारे प्रदेश में नाम बदलने की होड़ मची हुई है। आपने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यह एक ऐसी योजना थी, जो जनता की योजना थी, उस योजना को आपने बर्बाद कर दिया क्योंकि वह एक सफल योजना थी, जिसके लिए पूरे प्रदेश भर के जो अभिभावक और माता-पिता हैं, वह इस सरकार से कहीं न कहीं नाराज है और सरकार उनके लिये किसी भी प्रकार की गंभीरता नहीं दिखा रही है। मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं। हम लोगों को पिछली सरकार ने योजना दी। पिछली सरकार ने महिलाओं के लिये नये कार्यक्रम चालू किये। पिछली सरकार ने सी-मार्ट चालू किया। पिछली सरकार ने महिलाओं के लिए उद्योग को बढ़ाने के लिये कपड़ा फैक्ट्री की शुरूआत की। आज भिलाई के सी-मार्ट के अंदर भी ताला लगा हुआ है और जो फैक्ट्री 7 करोड़ रूपये की लागत से बन रही थी, जैसे ही सरकार बदली है, उसका काम भी आधे में रोक दिया गया है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह क्या हो रहा है ? यदि हम विपक्ष के विधायक हैं और यदि हमारे यहां किसी सरकारी योजना का काम चल रहा है तो क्या वह बंद कर दिया जायेगा ? हम यह पूछना चाहते हैं कि यदि किसी सरकारी योजना में 7 करोड़ रूपये की लागत से महिलाओं के लिए एक फैक्ट्री बन रही है और उस फैक्ट्री का आधा काम हुआ है, उसकी छत ढल गई है लेकिन उस फैक्ट्री का काम पूरा नहीं किया जा रहा है और पिछले एक साल से उसका काम बंद कर दिया गया है। क्या सरकार ऐसे ही चलती है ? क्या भिलाई की जनता, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता नहीं है ? उनका भी अधिकार है, वह भी टैक्स देते हैं लेकिन आज उन माताओं के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। मेरे विधान सभा में एक क्षेत्र हुडको है। वहां पर अधिकांश बुजुर्ग लोग रहते हैं और वहां पर पानी भराव की बड़ी समस्या है, जहां नाली बनाने के लिए पिछली सरकार के कार्यकाल के बजट में 7 करोड़ रूपये स्वीकृत थे। लेकिन इस बजट में भी उसका उल्लेख नहीं है।

समय:
3.03 बजे

(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)

वहां लोग कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अभी हमें पता चला है कि वहां गंदे पानी और केमिकल युक्त पानी के कारण पीलिया के केस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन शासन प्रशासन को कहीं पर भी होश नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, आप मुझे ज्यादा समय नहीं दे सकते और मैं ज्यादा वक्त लूंगा भी नहीं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी 21 मार्च तक यह सदन चलेगा। हम रोज सभी विषयों पर बोलेंगे और हम इस सरकार को सचेत करायेंगे कि आप ऐसी गहरी नींद में मत सोईये, यह मत समझिये कि आप अमर हो गये हैं। आप यह मत भूलिये कि यही जनता है, जिन्होंने

आपको लाया है। यह मत सोचिये कि अब आप कभी इस गद्दी से नहीं हटेंगे । आपको भी इस गद्दी से हटना पड़ेगा और यही जनता आपको इस गद्दी से हटायेगी क्योंकि आपकी सरकार, आपके नेता और आपकी ब्यूरोक्रेसी जो रवैया अपना रही है, उसको इस प्रदेश की जनता देख रही है। ऐसा भी नहीं है कि मैं केवल आपके ऊपर आरोप लगाऊंगा। मैं एक, दो विषय में आपका आभार प्रकट कर आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। आपने पिछले बजट भाषण में कहा कि वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण, जी.एस.डी.पी. में 77.51 प्रतिशत की वृद्धि है और देश में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और हमारी सरकार इस सदन में कहती थी कि छत्तीसगढ़ की जी.डी.पी. देश की जी.डी.पी. से ज्यादा है तो उस समय आप लोग विपक्ष में बैठकर चिल्लाते थे । आज आपने अपने बजट भाषण में उस बात को सच साबित किया है कि कहीं न कहीं हमारी पूर्व की सरकार ने वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2023 तक बेहतर काम किया है इसलिए हमारी जी.डी.पी. देश की जी.डी.पी. से बेहतर है। साथ ही साथ आपने यह भी उल्लेख किया कि इस प्रदेश में बैंकों की जो संख्या है वह 1500 से बढ़कर 6500 हो गई तो मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं उस कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्त्ता हूँ जिसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा बैकों की वृद्धि हुई क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया।

मानननीय सभापति महोदय,मैं इस सरकार को अंत में दो-तीन बातें और याद दिलाऊंगा और मेरे कुछ सवाल हैं। शायद इस विषय में माननीय संसदीय मंत्री जी प्रकाश डाल पायेंगे। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इसमें यह उल्लेख है कि हमारे द्वारा प्रदेश में अभी 74 हजार समूह सदस्यों को अलग-अलग गतिविधियों से जोड़कर लखपति दीदी बनाया गया। मैंने यह बजट भाषण में पढ़ा है। भाई, कहां 74000 समूह सदस्य हैं, यहां पर ऐसे कौन से समूह हैं जिनको प्रदेश में लखपति बनाया गया है। देश और प्रदेश को इसकी कोई जानकारी नहीं है। आप अपने भाषण में लिख दीजिए कि इस प्रदेश में महिलाएं लाखों रूपये कमा रही हैं और उनका काम छिन लो, यह काम सरकार कर रही है। माननीय ससंदीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय जी अभी 18 लाख आवास की बात कह रहे थे। हम आवास नहीं बनाना चाहते थे । इसलिए हमने आवास नहीं बनाया। आप तो प्रदेश में आवास बनाना चाहते हैं तो आपने कितने आवास बना दिया, कितने लोगों को आवास दे दिया। इसको पटल पर रखें। अंत में एक बात कहकर, अपनी वाणी को विराम दूंगा।, हमारे सभी लोग इस बात को सुन रहे हैं इस बजट में 550 करोड़ रूपये के जनसंपर्क की राशि का उल्लेख किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस राशि से सड़क, नाली का निर्माण तो नहीं होगा। यहां व्यवस्थाएं तो नहीं सुधरेंगी, लेकिन इस प्रदेश में बैनर-पोस्टर बढ़िया लगेगा और विज्ञापन बढ़िया आएंगें। इस सरकार में यह तो पक्का हो गया। हम इस बजट का विरोध करते हैं। जो बजट में 550 करोड़ रूपये जनसंपर्क के लिए रखता है और हमारे शहरी, नगरीय निकाय के लिए कितनी राशि रखी जाती है, आप उसकी तुलना कर लेंगे तो आपको यह समझ में आ

जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार कोई काम नहीं कर रही है। यह सरकार केवल और केवल भ्रष्ट आचरण में चल रही है और इनसे जनता कोसों दूर है। हम इसका विरोध करते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मेरे ख्याल से दो या तीन बाद हम माननीय सदस्य की आवाज सुनेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- आप लबारी बस मत कहिहौ। काबर मंत्री नइ बने हौं, तहू ला बताहू।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय यादव जीी, अभी तो में अपन भाषण शुरू नहीं करे हाववा।

श्री देवेन्द्र यादव :- इन्होंने बहुत बड़ी बात पूछ ली है। एला बताना पड़ही।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, मेहनत करे मुर्गी अउ अण्डा खाए फकीर।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से वक्ता बोल रहे हैं और जो भी बोल रहे हैं मुझे यह लगता है कि उन्होंने बजट पर बोलना नहीं सीखा है। इस सदन में दूसरी, तीसरी बार में विधायक चुनकर आये हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सारे के सारे लोग किसी विभाग की अनुदान मांगों में बात कर रहे हैं। इस बजट में कहीं पर भिलाई प्रिंट नहीं है। अगर आपको भिलाई क्षेत्र की समस्या रखनी है जिस विभाग की समस्या है। कल से डिमाण्ड मांग शुरू होगी, आप उसमें बात करना चाहिए। इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, सेहत क्या है, हम इसे कहां ले जाना चाहते हैं? आपने 5 सालों के कार्यकाल में इस प्रदेश को किस गर्त में डूबाया? किसी बजट का उद्देश्य क्या होता है? बजट क्यों बनता है? हम बजट कहां तक ले जाना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। अभी सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आये हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसी सत्र में जो जारी हुआ है, आप वित्त सचिव के स्मृति पत्र को पढ़ लीजिए। सभी ने यह बोला है। यह बजट 1 लाख 65 हजार करोड़ रूपये का है, जिसमें लगभग 16 प्रतिशत पूंजीगत व्यय है, यह 26 हजार करोड़ रूपये के लगभग है। आज तक का यह सबसे बड़ा बजट आयोजन है। जो पिछले साल की तुलना में 18 प्रतिशत वृद्धि हुई है। कभी वह वृद्धि नहीं हुई। छत्तीसगढ़ बनने के बाद एक साथ 18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई हो। आप 5 साल सरकार में थे, किसको समर्पित कर दूं, नेता प्रतिपक्ष जी तो ऊपर बैठते थे, जो कलाकार थे, वह नहीं हैं। देवेन्द्र यादव जी, वर्ष 2019-20 में जो पूंजीगत अनुमान था, लेखा का वास्तविक अनुमान था, आपने जनता को किस तरह का बजट दिया, वह -3542 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 में -4789 करोड़ रुपये, वर्ष 2022-23 में -3335 करोड़ रुपये, वर्ष 2023-24 में -3241 करोड़ रुपये, यानि आप जनता को क्या बताना चाह रहे थे कि लोग नहीं समझेंगे, लोग उनकी किताबों को नहीं पढ़ते? आप कुछ भी लिख दो, वह चलेगा। हम कुछ भी अनुमान लगाकर मेज थपथपा लेंगे, आप लोगों का काम मेज थपथपाने का था। आपका एक

भी साल लेखा का वास्तविक अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान सही नहीं था, माईनस था। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आपने गड़बड़ किया। पहली बार माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार आई, यह नौजवान वित्त मंत्री बनते हैं। नौजवान वित्त मंत्री जिनकी प्रशंसा अभी आप लोगों ने की पढ़ा-लिखा आदमी वित्त मंत्री बना है। मामा बोल रहे थे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- भांजा, मैं पढ़ा-लिखा की तारीफ किया हूं लेकिन मैं यह भी बोला हूं कि उसका लाभ नहीं मिल रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2024-25 में पहली बार इन 5 सालों में जो लेखा का पूंजीगत अनुमान है, वास्तविक अनुमान है या पुनरीक्षित अनुमान है, यह सबको देखें तो 693 करोड़ रुपये 12.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह पहली बार है, यह सत्य है और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ किसी तरह का [xx] नहीं किया। यह वित्त मंत्री का स्मृति पत्र बताता है। आप पढ़ लीजिए। उसमें अपनी कहानी पढ़ लीजिए। क्या मैं करतूत कहूं ? आप अपनी करतूत देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आपने कैसा व्यवहार किया, किस तरह के लेखे प्रस्तुत किये। वर्ष 2023-24 में 12 प्रतिशत और इस साल 2024-25 में 18 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वह अगले साल पता चल जायेगा। लेकिन पिछले साल पहली बार 5 साल में लेखा दुरूस्त हुआ है कि सच बोला गया है।

श्री रामकुमार यादव :- चन्द्राकर जी, तुमन अतेक चिल्लाय-चिल्लाय के भाषण देथव, आप मन एकव रुपये किसान मन के कर्ज माफ करे हवय का, तेला बतावा ? आप मोला यह बतावव कि किसान के एकव रुपये कर्ज माफ करिस हवय ? ऐसा लागत हे पूरा हमर छत्तीसगढ़ ला स्वर्ग बनाय देय हवय। किसान के एकव रुपये कर्ज माफ करे हवय का ? ठूठी-बीड़ी माफ करे हवय का ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं नई बोलत हवं। तोला बजट मिले हे, ओला पढ़ ले न। यदि बजट पढ़ना आता है तो पढ़िये नहीं तो सिर्फ ताली बजाईये।

श्री रामकुमार यादव :- नई तो आप मन के भी वही ताली बजाय वाली स्थिति बने हवय, कोई बहुत बड़ी स्थिति नई बने हवय। आप ला दो पाटन के बीच मा साबूत बने हावय।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने 05 साल में जो प्रावधानित बजट किये, आपने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ [xx] किया, [xx] किया और उसके लिए आपको उधर बैठना पड़ा। इनकी प्रावधानित बजट में जो कटौती हुई, वह एक भी साल प्लस में नहीं रही। वर्ष 2019-20 में 82099.86 करोड़ रुपये प्रावधानित बजट में कटौती, एक उहाहरण दे रहा हूं, बाकी को पढ़ूंगा तो समय लगेगा। 8809.74 करोड रुपये प्रावधानित बजट में कटौती, अनुमान गलत, आपके अनुमान से इतना माईनस गया। जो प्रावधानित बजट में कटौती है। यह वर्ष 2019-20 का बताया। वर्ष 2020-21 में वह कटौती 16542 करोड़ रुपये थी, उसके बाद 11268 करोड़ रुपये कटौती थी। भूपेश बघेल जी सुन नहीं रहे हैं, यदि सुन नहीं रहे हैं तो मेरे भाषण को निकाल कर पढ़वा दीजियेगा। आप लोगों ने कैसा छत्तीसगढ़

की जनता को [xx] है। उसके बाद वर्ष 2023-24 में 5308.81 करोड़ रुपये आपके प्रावधानित बजट में आपने कटौती की। उसके बाद 2023-24 आता है, हम प्रवेश करते हैं। 8971.59 करोड़ रुपये अनुमान से आधिक्य, नेता प्रतिपक्ष जी, यह मैं नहीं बोल रहा था, आपको जो बजट मिला है, वह बोल रहा है। आधिक्य पहली बार पिछले 5 सालों में इस नौजवान मंत्री के आने के बाद अनुमान ऐसा लगाया जाता है । असत्य वाहवाही लूटने के लिए बजट नहीं बनाया जाता है । अब उसके बाद वर्ष 2024-25 में 4254 करोड़ रुपये प्लस जो प्रावधानित बजट थे उसमें हमने प्लस लिया । अब वर्ष 2025-26 का भी अनुमान आएगा । अब आप छत्तीसगढ़ की जनता के साथ कैसा बजट बनाते थे यह आप देख लीजिए । आप किसी को कमज़ोर मत समझिए, किसी को बेवकूफ समझने की कोशिश मत कीजिए । तुरंत सबसे ज़्यादा मेंडेट के साथ, 54 सीटों के साथ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उधर से इधर ला दिया ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, आपने पता नहीं पहले क्या गलत काम किया था कि पहले आप 15 सीट पर ही सिमटे थे । हम लोग तो कम से कम 35 सीट पर हैं, आप तो 15 सीट पर ही सिमट गए थे ।

सभापति महोदय :- संगीता जी, बैठिए ।

श्री देवेन्द्र यादव :- आदरणीय, आप बेवकूफ और कमज़ोर किसको बोल रहे हैं इसको भी स्पष्ट कीजिये ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब यह तीसरी चीज़ । मैं अब इसके बाद आंकड़े नहीं पढ़ूंगा । माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप लाईन वगैरह मत लगाईए क्योंकि आप फ़र्जी आदमी नहीं हैं, आप सही आदमी हैं, संत आदमी हैं । आपकी fitness तो सही है न, कल तो मैंने पूछा था । आज भी शमा मोहम्मद का जो है वह social media में चल रहा है । रोहित जी जब जीते तब उसने स्वर बदल दिया । कल वह fitness पर बात कर रही थी, आपकी fitness करेक्ट है इसलिए मैं बोल रहा हूं ।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप तो अभी भी फिट हैं, उधर ध्यान क्यों नहीं दे रहे ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब आप देखिएगा कि राजस्व प्राप्तियों में अनुमान । मंत्री जी मैंने अभी जो-जो बोला है वह गलत तो नहीं बोला है न ? मैं 3 आंकड़े ही पढ़ूंगा, उसके बाद नहीं पढ़ूंगा लेकिन कुरूद की बात नहीं करूंगा, भिलाई की बात नहीं करूंगा । मैं बजट की ही बात करूंगा । जो अनुमान लगाया राजस्व राज्य से, केंद्र प्राप्ति से और पूंजीगत प्राप्तियों से तो वर्ष 2019-20 में 10,863 करोड़ मायनस, आपका अनुमान गलत । वर्ष 2020-21 में 17,10.44 करोड़ जो आपने राजस्व प्राप्तियों का अनुमान लगाया, वह गलत । यानी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ सिर्फ आपने गलत व्यवहार किया, सपने दिखाए और धरातल पर कुछ नहीं था । मैं बताउंगा कि बजट और कैसे बनाते थे । वर्ष 2021-22 में 10796 हजार करोड़ रुपए का अनुमान आपका गलत, आपने जो

अनुमान केंद्रीय राजस्व, राज्य के राजस्व और पूंजीगत राजस्व से जो अनुमान लगाया था उसमें भी मायनस । छत्तीसगढ़ का कैसे विकास होगा ? आपके छत्तीसगढ़ का किस तरह का विकास होगा ? उसके बाद हम वर्ष 2022-23 में आ जायें तो 4482 करोड़ फिर आप वर्ष 2023-24 में आ जायें तो माननीय चौधरी जी का धमाकेदार प्रवेश होता है, माननीय विष्णुदेव साय जी को ऐतिहासिक मेंडेट मिलता है । अनुमान जो है 8963.35 हज़ार करोड़ रुपए प्लस । आप समझ रहे हैं न । (मेजों की थपथपाहट) वर्ष 2024-25 में 4513 करोड़ रुपया प्लस । (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- लगे-लुगाए नौकरी ले निकाल देत हावओ अउ प्लस-प्लस बतात हावओ । ओसनहा बजट के का मतलब ? पहली बात 30 हजार शिक्षक भर्ती करिहा का, तेला बताओ ?

सभापति महोदय :- चलिये, यादव जी बैठिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- अब भूपेश बघेल जी होते तो भड़क जाते । यादव जी मैंने आपको कई बार बोला है कि जब अक्ल की बात होती है उस समय आप मत खड़े हुआ करो करके, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर ज्ञान ला देखकर के महाज्ञानी हमन जानत हन ।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा, बजट की समझ इनको तगड़ी है ।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर बजट में ये हा हावए कि नइ तेला बतावओ ?

श्री धर्मजीत सिंह :- ये हा अभी गणित विषय के शिक्षा देत है, गणित-वणित तो आवय नइ ता हम बइठे हन चुप, तहूं बैठ न भैया । चुपचाप बैठ जा ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी उनको बजट वगैरह समझ में आता है लेकिन यह है कि वित्तीय अनुशासन बाज़ार सब चीज़ को देखकर माननीय वित्त मंत्री जी के प्रयासों से उनको 500 नोट की झलकी अब नहीं मिलेगी । उनको झलक मिलेगी rest house या घर में तो गड्डी चाहे जितनी भी ऊंची हो, उसको 50-100 की ही मिलेगी । अब मैं आपको बता दूं कि जो वित्तीय विशेषज्ञ हैं, राजस्व मामलों के विशेषज्ञ हैं वह 10 प्रतिशत की कमी आती है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं । चलिए, 5-10 प्रतिशत ऊपर नीचे आती है। आपके समय में वर्ष 2019-20 में 11.9 प्रतिशत का अंतर था, जो उसमें राजस्व प्राप्तियों का अनुमान था, माने 10 प्रतिशत से ज्यादा था। दूसरे साल 17 प्रतिशत, तीसरे साल 11 प्रतिशत, चौथे साल 4.3 प्रतिशत अर्थात् आपने बजट नहीं बनाया। बजट के नाम से इस विधान सभा में एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत आपने स्वीकृति ले ली। वित्तीय वर्ष में मामा श्री इन्होंने कहा, इस वित्त मंत्री जी की मैं प्रशंसा करता हूं। इस सदन के नेता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बजट में शब्दों में FRBM लिखा है। इसमें FRBM एक्ट को एक्ट पढ़ लीजिये। कमिटमेंट यह कि हम अक्षरश: पालन करेंगे। सेल्फ कमिटमेंट। आपकी हालत क्या थी?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- 1 मिनट । आपने पिछले बजट में भी यही बातें बोली थीं। यही वचन दिए थे। आप पिछले बजट में बहस कर लीजिए, धरातल में देख लीजिए। माननीय वित्त मंत्री जी, एक थर्ड जेंडर के लिए घोषणा किए थे कि इसके लिए योजना बनाएंगे। अगर एक रूपया की योजना या एक रूपये की धनराशि खर्च हुई होगी तो आप बताइए। आपको तारीफ नहीं करनी चाहिए। फिर भी कर रहे हैं। आपका तो फर्ज है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिए न। एक लाइन सुन लीजिए। अभी आज मेज थपथपाना। छत्तीसगढ़ के हितों का सवाल है। वर्ष 2019-20 में 5.21 प्रतिशत घाटा, आपने उस एक्ट का पालन नहीं किया। वर्ष 2020-21 में 4.49 प्रतिशत घाटा, आपने उस एक्ट का पालन नहीं किया। वर्ष 2023-24 में 4.60 प्रतिशत घाटा। आपने उस एक का पालन नहीं किया। वित्तीय अनुशासन, वित्तीय अनुमान, बजट की प्रक्रिया बजट के अनुमान सबको आपने धो दिया। आपने मजाक बना दिया।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- नहीं-नहीं, आप अपने शब्दों के जाल से उसे दूसरा स्वरूप दे रहे हैं। अभी आपने अंतर बताया कि एक में केवल 1 प्रतिशत कम अंतर था, जो चलेगा करके बातें बोली। आप अपने शब्दों के जाल में छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिए, हो गया।

सभापति महोदय :- बैठिए।

श्री रामकुमार यादव :- ए मन जाली वाला हे। एमन बजट नहीं बनाए हे, एमन जाल बिछाये हे। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- अगर ये सत्य बोल रहे हैं तो मिर्ची लग रही है क्या? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए-बैठिए। टोका-टाकी मत करिए। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सिर्फ यह कागज के बजट में रहता है। धरातल में कोई चीज नहीं होता है। आप वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 का देख लीजिए। आप सर से ये बात कीजिये ना? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- यादव जी, बैठिए।

श्रीमती संगीत सिनहा :- आप पिछले बजट को देख लीजिए। अगर एक भी राशि दिए हो तो। एक भी राशि खर्च किए हो तो। चन्द्राकर जी, एक बड़ी-बड़ी बात करने से नहीं होता। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ए मन जब जगह जाल फैलाए हे।

सभापति महोदय :- बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं एक भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। जो बंडल मिला है, उन्हीं किताबों से बोल रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वही तो हम लोग भी बोल रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने एक आरोप नहीं लगाया है।

सभापति महोदय :- चलिए, बैठिए।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय चन्द्राकर जी, अभी आपको वर्ष 2025-26 पर भाषण देना चाहिए। आप वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 पर कहां पहुंच गये?

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उसमें भी आ रहा हूं। नहीं, मैं उसमें आ रहा हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- आइए न। आप आइए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं विषय से भटकूंगा ही नहीं। आपको इसलिए बता रहा हूं। आपने छत्तीसगढ़ का कितना घाटा किया? किस तरह से बजट बनाए? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, ये अपनी झल्लाहट हमारे ऊपर दिखा रहे हैं। आप अपनी झल्लाहट हमारे ऊपर न दिखायें। हम आपको जानते हैं। कुछ नहीं मिला है। आप अपना चेहरा हमें न दिखायें। हम समझ सकते हैं। हम इस सदन को समझते हैं। आप बजट की बात कीजिए न। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, इहां 2025-26 के बात करना चाहिए न, तो ये 1947 में जाथे। महाज्ञानी जी। वर्ष 2025-26 के भाषण पर आइए। कहां ले वर्ष 1947 में जाथे। वर्ष 2025-26 के बात करव। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने जनता के लिए क्या-क्या लाया है, वह बात कीजिए न।

श्री रामकुमार यादव :- बेरोजगारी की बात कीजिए न।

सभापति महोदय :- चलिए, अपना विषय रखिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चर्चा में आयेगा तो आप बोल लीजिएगा। पूर्ववर्ती सरकार में आप बाद में बोल लीजिएगा।

सभापति महोदय :- संगीता सिन्हा जी, आप बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब इस एक्ट का पालन करने से वित्तीय घाटा को नियंत्रित करने से छत्तीसगढ़ को क्या लाभ मिला? कितनी बार आपको इन्सेंटिव मिला? केंद्र सरकार से प्रोत्साहन मिला? 1000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि तो आपको अभी मिल गई, ये छत्तीसगढ़ कभी नहीं ले सका। (मेजों की थपथपाहट) ये आपके कु -वित्तीय प्रबंधन के कारण छत्तीसगढ़ को पिछले सालों में कितना नुकसान हुआ ये अनुमान लगा लें। आपके कोई अनुमान सही नहीं थे। अब 50 साल तक जो ब्याज फ्री दीर्घकालिक राशि मिलेगी, उसका लाभ हमें आपको वित्तीय अनुशासन के कारण मिलेगा। इसलिए मैंने इस नौजवान वित्त मंत्री जी की प्रशंसा की। इसीलिए मैंने इस सदन के नेता की प्रशंसा की और आप जो बोल रहे थे न पिछला बजट और नया बजट और अभी का बजट। ये अभी के बजट के ही आंकड़े हैं और मैं सिर्फ उतना ही इसलिए बोला कि 5 साल तक आपने जो वित्तीय सूचकांक होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, बजट के नाम से विधान सभा में लगातार आप गुमराह करते रहे और उसके कारण छत्तीसगढ़ में कोई पूंजीगत खर्च नहीं हुआ और उसका परिणाम क्या है ये बता देता हूं। नेता प्रतिपक्ष जी, पांच

साल में आप मुझे एक काम बताइए और मैं आपको एक काम बता देता हूं । उसके अतिरिक्त कोई काम बताइएगा जिसके लिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार याद की जाए । महात्मा गांधी कृषि वानिकी विश्वविद्यालय, वह भी पाटन में खोला । वह भी भर्ती के दायरे में है । उसके अतिरिक्त एक भी उल्लेखनीय कार्य मुझे बताओ मैं अपना भाषण रोक दूंगा । आप बताइए कि पांच साल में हमने याद करने लायक यह काम किया है ।

श्री देवेन्द्र यादव :- पीएमश्री किसकी योजना का नाम कर दिया ? कौन सी योजना का नाम आपने पीएमश्री किया । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आपने क्या दिया डेढ साल में, अंडा बटे पराठा ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमने पांच सालों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उजागर करने का काम किया और अरपा पैरी की धार, जिसको आपने बंद करने का प्रयास किया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बताते हैं उसको, अरपा पैरी की धार में बात करेंगे । एक भी ऐसा जनहित के विषय, एक भी उपलब्धि जैसे इन्होंने अपने भाषण में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का उल्लेख किया और संस्था बनाने का कमिटमेंट किया ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हमने आत्मानंद स्कूल खोला है जिसमें गरीब के बच्चों ने पढ़ाई की है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुन लीजिए आता हूं मैं, उत्तर तो नहीं दूंगा, अगर वे समय दें तो मैं पूरे पांच साल का उत्तर दूंगा । सभापति महोदय, एक उदाहरण दे देता हूं कि बजट कैसे बनता था, उपलब्धि कैसे होती थी । जेल जाने के लिए बजट बनाते थे क्या मैडम सिन्हा ? आपने बजट बनाया जेल जाने के लिए । कस्टम मिलिंग की राशि 120 रूपए कर दी, हम लोग ताली बजाते रहे । छत्तीसगढ़ के थ्रस्ट सेक्टर के 22-23 सौ मिलर्स को फायदा होगा । बजट अनुमोदित नहीं हुआ है और 60 रूपया कमीशन हमको । बजट से पैसा और यह मैं नहीं कह रहा हूं ।

श्री राम कुमार यादव :- फाईव स्टार होटल में, नया रायपुर में, मे-फेयर में किसने मांगा । समय आने दीजिए, मे-फेयर में किसने मांगा हम सब बताएंगे आने वाले समय में ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, यहां से निकले नहीं, प्रस्तुत नहीं हुआ। सिस्टम बन गया, यह मैं नहीं कह रहा हूं मेरा प्रिय भांजा, मैं उसको आर जी टैक्स बोलता था, आप थे । उस बजट के बाद से छत्तीसगढ़ में कहां है, पता ही नहीं है । तीन साल से गायब है, प्रदेश कांग्रेस का कोषाध्यक्ष कहां है मैं नहीं जानता या वह भी फरारी में है यह मैं नहीं जानता । कितने लोग उस 60 रूपए वसूली में अंदर हैं । बड़े बडे अधिकारी अंदर हैं । बजट से पैसा खाना और जेल जाना, देश में एक मात्र उदाहरण छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बनाया (शेम शेम की आवाज) ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, राईस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष का भी बयान वीडियो के माध्यम से जारी हुआ ।

सभापति महोदय :- आपका नम्बर आएगा ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- एसोसिएशन के अध्यक्ष का बयान सार्वजनिक रूप से आएगा तो उसको भी याद किया जाएगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- 60 रूपए वसूली वाले कहां है उनका पता पूछ रहे हैं ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- उहिच ला ता मे भी कहत हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मालूम हे तो बता दे पुलिस ला ।

श्री सुशांत शुक्ला :- कुंवर जी पूछ रहे थे कि पिछली वसूली का हिसाब नहीं मिल उसका दर्द बता रहे थे राईस मिलर्स के अध्यक्ष । पिछली वसूली का दर्द बता रहे थे, वे समझ नहीं पाए।

डॉ. चरणदास महंत :- ठाकुर साहब, कौन 60 रूपया लेता था, कौन कहां गया, कब जाएगा, यह क्यों कर रहे हो ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी, आपकी सज्जनता का मैं कायल हूं । आपकी बात का अनुमोदन करता हूं ।

डॉ. चरणदास महंत :- तो उसको छोड़िए आप । आज की बात करो ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बजट कैसे बनते थे उसका उदाहरण बताया ।

डॉ. चरणदास महंत :- वह तो वित्त मंत्री जी ने बता दिया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके बजट का जनहित से कोई संबंध नहीं था । बजट में आयोजन करके सीधे सीधे [xx] डालने का काम हुआ उसको मैंने बताया कि [xx] डाली जाती थी ।

डॉ. चरणदास महंत :- आप आज के बजट पर बात करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय वित्त मंत्री जी को फिर नवजवान कहता हूं । माननीय भूपेश बघेल जी बजट की प्रतिक्रिया में कह रहे थे कि कवि सम्मेलन हो रहा है कि बजट भाषण हो रहा है । यह अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है । यह शानदार बजट प्रस्तुत करके काव्यात्मक श्रद्धांजलि उन्होंने दी है, मैं उन्हें बधाई देता हूं । (मेजों की थपथपाहट) नेता प्रतिपक्ष जी, यदि कविता की बात हुई तो हिन्दी साहित्य में रीतिकाल होता है। कोई हिन्दी साहित्य का विद्यार्थी हो तो पूछ लीजिए जिसमें सिर्फ प्रशस्तिगान होता है। मसाल जैसे आंख हैं, पृथ्वीराज रासो पढ़िए। गज भर का सीना है, ऐसा एक से अनेक गाते थे। साहब, मैं थोड़ा पद्य वाला हूं, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचरण शुक्ल वाला हूं। मेरे दिमाग में कविता कम घूसती है। नामवर सिंह, दूधनाग सिंह इस लाईन का हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ काव्य में प्रशस्तिगान, रीतिकालीन कवि की एक खानदान की स्तुति ये सब तो समझ में आएंगे। अटल जी की कविता की भाषा और इनकी छत्तीसगढ़ के प्रति भावना, छत्तीसगढ़ के प्रति दायित्वबोध कहां

समझ में आएगा। (शेम शेम की आवाज) आपको लगेगा ही। यही बात वे किसी खानदान की प्रशस्ति में बोल देते तो आप ताली नहीं बजाते कूद देते, तुरंत दिल्ली रवाना हो जाते, हमारे वित्त मंत्री जी ने आपके खानदान की प्रशस्ति में लाईन कही, हम बताने आए हैं।

सभापति महोदय :- आदरणीय 20 मिनट हो गए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सारी बातें थोड़ी-थोड़ी हो चुकी हैं। आपने कहा कि उस बजट में नौजवानों के लिए, गांव के विकास के लिए 17 फूडपार्क बनाऊंगा। उसको बजटीय सपोर्ट दिया, उसको लेजिस्लेटिव सपोर्ट है, रीपा लागू की गई, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बोलते हैं। उसको क्या बजटीय सपोर्ट था, उसको क्या लेजिस्लेटिव सपोर्ट था ? किसी मद का पैसा कहीं लगा दिया गया, ये बहन जी जो बोल रही थीं कि हमने स्कूल खोला। बी.पी. पुजारी स्कूल में मेंटनेंस और पोताई के लिए किस-किस मद के पैसे लगे, आत्मानंद स्कूल के नाम से बजट में कितने पैसे थे, कितने पैसे के भर्ती हुई, कितना सेटअप बना, इस चीज में चर्चा होनी चाहिए। हवा हवाई स्कीम थी। एक आदमी की स्वेच्छाचारिता प्रदेश की इच्छा बन गई और ये ताली पीटते रहे। आज कहां हैं ? कोई सपोर्ट नहीं है। इस नौजवान मंत्री ने उन बेरोजगारों के लिए 17 फूडपार्क बजट से दिए और इसी बजट में किसी समय प्रिंट था कि मैं 200 फूडपार्क बनाऊंगा, आप पांच साल में कहीं पर एक भी फूडपार्क दिखाएंगे। (मेजों की थपथपाहट) मैं दिखा दूंगा जिसमें मेरे इस सत्र में भी प्रश्न है, सुकमा में भ्रष्टाचार करने के लिए 3 करोड़ रूपए के फूडपार्क बनाए हैं, वह भ्रष्टाचार है, यह आपने स्वीकार की है। ये अंतर है। छत्तीसगढ़ के प्रति प्रतिबद्धता, अपने नेता के प्रति प्रतिबद्धता, अपने विचार के प्रति प्रतिबद्धता है। ये बजट में झलकती है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पार्क खोलते हैं, औद्योगिक नीति बनाते हैं, जो छत्तीसगढ़ के लिए जरूरत है। 20 विभागों के लिए इज ऑफ डूईंग बिजनेस के लिए है, 20 विभाग के 216 कानून को सरलीकृत करेंगे। ये वही संकल्प है और विष्णुदेव के सुशासन में ओ.पी. चौधरी ही ले सकता है। मैं गंगाधरती लाऊंगा और पाप धोऊंगा जिसको भागीरथ संकल्प बोलते हैं। वह भागीरथ संकल्प है कि इन पार्कों को शुरू करके निवेश लाकर छत्तीसगढ़ को उसके लायक राज्य बनाकर बेरोजगारी से लेकर अग्रिम पंक्ति के राज्य बनाएंगे। आज ही प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है कि आगे ले जाने के लिए राज्य भूमिका निभाएं, वे एडवांश में राज्य की भूमिका के लिए ये वातावरण तैयार कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आज का स्टेटमेंट है। आपने कभी की है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, सुशासन और अभिसरण विभाग है। उसके बाद सेवाएं हैं, जितनी सेवाएं हैं, उसको ऑनलाईन करेंगे। ये छोटा-मोटा संकल्प नहीं है। खास तौर पर उस दौर में जब मैंने विधान सभा में पिछले सत्र में एक प्रश्न किया कि कोयला परिवहन ऑनलाईन था उसको आपने ऑफलाईन क्यों कर दी। अभी लोग कोयला

दलाली में अंदर हैं। इस सरकार का उत्तर है कि ऑनलाईन को ऑफलाइन करने के बाद राजस्व में वृद्धि हुई है। मैंने फिर पूछा कि राजस्व में कितनी वृद्धि हुई ?

श्री रामकुमार यादव :- आपमन छत्तीसगढ़ में सरकार में बइठे हो, तहान जंगल ला अडानी ला सौंप देओ। आप बइठते साठ अडानी ला सौंप देओ। आपमन हा हमला एक पेड़ लगवावत हो अऊ लाखों रूपया के पेड़ ला कटवावत हो। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शुक्ला जी, यादव जी, प्लीज आप बैठिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र की बात करे तो जब आपने शपथ ग्रहण किया तो दूसरे दिन से हसदेव कटना शुरू हुआ है। आपके शपथ लेने के पहले वह शुरू हो गया था। जब आप एक पेड़ मां के नाम पर बोल सकते हैं तो हसदेव को क्यों कटवाया गया ?

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप बैठिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जब आप इधर बैठती थीं तो मैंने यहां से अशासकीय संकल्प रखा था और माननीय महंत जी ऊपर बैठे थे। अडानी को हसदेव अरण्य को काटने की अनुमति आपके भूपेश बघेल जी की सरकार ने दी थी। यदि आप बोलेंगे तो मैं आपको इसको डेट के सहित बता दूंगा। (मेजों की थपथपाहट) (शेम-शेम की आवाज)

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, ओला रोकवा लो। अभी तो आपके सरकार हे। आप अभी तो ओला रोकवा सकत हो। आप कहां गेओ ? अब आप रोकवाओ न। आपमन यह आरोप लगाना बंद करो। आप ओला अब रोकवाओ। आपमन शपथ ले लिये हो। ए जंगल ला आपमन कटवाए हो, मां के नाम में पेड़ हमन लगाएन, बाप के नाम में पेड़ हमन लगाएन अऊ तुमन ओला काटो। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं निवेदन करती हूं कि अगर उसको उस सरकार ने किया था तो उसको सुधारने का मौका है। अभी आपकी सरकार है तो आप उसको रोकवा सकते हैं। अभी आपकी विष्णु देव साय जी की सरकार है तो आप हसदेव को कटवाने से रोकवा सकते हैं। आप उसको रोकवाइये। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संगीता जी, आप बैठिये। चंद्राकर जी, आपको 30 मिनट हो गये। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मैं थोड़ी देर में समाप्त कर रहा हूं। ऑनलाइन सेवाएं जारी थीं। कोरबा के सांसद बताते हैं और कई बार उसका उल्लेख करते हैं कि कोयला परिवहन को ऑफलाइन कर दिया गया। मैंने पूछा कि ऑफलाइन से कितना इंकम हुआ तो कहा गया कि जानकारी एकत्र की जा रही है। आज तक उसकी जानकारी मेरे पास नहीं आई है। उसको ऑफलाइन करने का

परिणाम यह निकला कि कोयला दलाली में अब बैरक में जगह नहीं है। माननीय गृहमंत्री जी उसमें रोज बैरक को इधर-उधर कर रहे हैं। मालूम नहीं कि वह क्या कर रहे हैं ? (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, अब प्रशासन की जवाबदेही तय करें। अधिकारी दीर्घा में bureaucrats बैठे हैं। कहा गया कि मैं pm excellence award की जगह में cm excellence award दूंगा। मैं आपकी इस कोशिश की बहुत प्रशंसा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) मैं इसकी प्रशंसा इसलिए करता हूं कि 5 साल तक वह भूल गये थे कि राज्य के प्रति हमारा दायित्व क्या है। जो अच्छे क्षमतावान अफसर थे, उनको भी इतने सारे power center थे, चूंकि मैं नाम नहीं ले सकता। यदि आसंदी मुझे नाम लेने की अनुमति देगी तो मैं बता दूंगा कि आप उसके पीछे घूमते रहो और आपकी क्वालिटी वह मानी जाएगी, जो हमको करेत्तर राजस्व का संग्रह करके देगा। (शेम-शेम की आवाज) (मेजों की थपथपाहट) मतलब, दारू से संग्रह चाहिए एक नंबर में, लेकिन दो नंबर में भी कौन लोग राजस्व संग्रह दे सकते हैं। यदि आपको ऐसे अफसर दिखते हैं तो जब वह लोग बाहर निकलेंगे तो आप उनको अलग से ऑफलाइन ईनाम दे देना कि आप लोगों ने एक व्यक्ति की बड़ी ईमानदारी से सेवा की थी और छत्तीसगढ़ के राजस्व को क्षति पहुंचाई थी, इसके लिए हम आपको ईनाम देते हैं। लेकिन उनके मनोबल के लिए, उनके सम्मान के लिए और उसकी अच्छी चीज के लिए आपने जो पहल की है, उसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- आप समाप्त करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, केवल थोड़ी देर।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- अजय जी, एक छोटी सी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आप विधान सभा के रेडी रिक्नर हैं। 5 साल तक जो सरकार में थे, उनका एफेलटेंट के माध्यम से आबकारी विभाग के अंतर्गत कितने बेघरों की कितनी प्राप्ति हुई? थोड़ा सा आप यह बता दीजिए।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- एक मिनट।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं समाप्त कर रहा हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं उनको बोलूंगा।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- आप मेरा बता दीजिए, फिर समाप्त करना।

डॉ. चरणदास महंत :- महाराज, आप तो जय जगन्नाथ वाले हैं। (हंसी) देवभोग से कितना चावल भागवान जगन्नाथ को गया है? आप इतना हिसाब बता दीजिये। आप कोयला दलाली की बात क्यों कर रहे हैं?

श्री पुरन्दर मिश्रा :- उसमें कितनी जमीन है, मैं वह भी बताऊंगा।

डॉ. चरणदास महंत :- बताइये न। आप कहां उल्टी-सीधी बात कर रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- जय जगन्नाथ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष को अटल जी के नाम से निर्माण वर्ष के रूप में 2 हजार करोड़ रूपये समर्पित है। हम सिंचाई की अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा करेंगे। कहा गया कि हमारा 5 हजार करोड़ रूपये का एक संकल्प है। गरीबी हटाओ के नाम से कांग्रेस ने सन् 1971 में चुनाव लड़ा। वह पीढ़ी पूरी नदारत हो गई। एकाध जिंदा होंगे तो जिंदा होंगे, लेकिन गरीब से कांग्रेस को चीढ़ कब से पैदा हुई, यह मैं नहीं जानता। आपको उन गरीबों से क्या दुश्मनी थी कि आपने 18 लाख मकान नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। (शेम-शेम की आवाजें) इस सरकार ने एक साल की अवधि में देने का संकल्प और उसके बाद केन्द्रीय मंत्री आये तो 3 लाख 75 हजार something मकान और देंगे। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके लिए अलग देंगे। जो surrender किए हैं, उनके लिए अलग देंगे। प्रधानमंत्री जनमन में अलग आवास देंगे। लेकिन गरीबों का आवास पूरा करेंगे, यह एक संकल्प है। (मेजों की थपथपाहट) जो welfare state है, कल्याण राज्य की असली अवधारणा यही है कि जनता तक योजना पहुंचे, जनता का जीवन स्तर ऊपर उठे, वही welfare state की कल्पना श्री ओ.पी. चौधरी जी, वही श्री विष्णु देव साय जी और उनके मंत्रीगण कर रहे हैं, मैं इस सरकार के उस संकल्प शक्ति की प्रशंसा करता हूं।

सभापति महोदय, कौशल विकास योजना, कहां कौशल विकास योजना होगा ? workforce, vibrant chhattisgarh यदि केरल नर्स को निर्यात कर सकता है, अपने मानव संसाधन के बल पर इकानॉमी बदल सकता है। यदि छत्तीसगढ़ का मानव संसाधन कुशल होगा तो हम अपनी ताकत पर अपने प्रांत की जी.डी.पी. बदल देगा। परन्तु कौशल विकास को बदल दिया, बंद कर दिया और नारा दिया - "छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, घुरवा, गरूवा, बाड़ी" उसका क्या हुआ, उससे क्या workforce मिला ? G.D.P. मे क्या ग्रोथ हुआ ? किसके जीवन स्तर में बदलवा हुआ ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदया, कौशल विकास योजना में..।

श्री रामकुमार यादव :- 4 लाख एकड़ ओखर बर हमन जमीन इकट्ठा करे हन। का बात करथव ?

श्री सुशांत शुक्ला :- नरवा, घुरवा, गरूवा, बाड़ी, आजकल तेलंगाना में हे। नरवा, घुरवा, गरूवा, बाड़ी देने वाला आजकल तेलंगाना मा दुकान खोले गय हे।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपको 26 करोड़ की राशि कम नहीं लगता ? आप उसमें राशि बढ़ा दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप एक भी उदाहरण बता दें कि नरवा, घुरवा, गरूवा, बाड़ी से इसके जीवन में कोई परिवर्तन आया हो ? सिर्फ corruption. आज मेरे प्रश्न मे हैं। RIPA मद, मैं इस प्रश्न को छोड़ूगा नहीं, मैं इस सरकार को बता रहा हूं कि RIPA मद से इतने

लाख लीटर गोबर के पेंट खरीदे गये हैं। अब यह RIPA मद क्या होता है। आप पूरा बजट देख लीजिये RIPA मद क्या होता है ? यदि आप कहेंगे तो मैं इस बात को पटल में रख दूंगा। नरवा, घुरवा, गरूवा, बाड़ी, ये आपके corruption हैं। यही RIPA है, यही छत्तीसगढ़ का भविष्य है और यही योजनाएं हैं ? छत्तीसगढ़ को चलाने के यही तौर-तरीके हैं ? ताकि लोग जेल जायें।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जो नये विषय हैं चाहे blockchain हो, artificial intelligence, interest of things हो, चाहे renewable energy हो, छत्तीसगढ़ का workforce अगली सदी के जो विषय है, उसके लायक बनें। नरवा, घुरवा, गरूवा, बाड़ी की सोच से ऊपर उठें, हम उस संस्कृति को संभालने के लिए तरीकें खोजें। परन्तु नवजवान बड़े सपने देखेंगे तो उनकी सोच अपने आप बड़ी हो जायेगी और वह संकल्प इस नवजवान मंत्री ने व्यक्त किया है। यदि आपके सपने बड़े होंगे, आप बड़ा सोचिये और उसके लिए जो जरूरत होगी, वह हम देंगे। विष्णु देव साय जी देगी, यह संकल्प बजट बताता है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, बजट कैसे बताता है। 50 करोड़ रूपये NIPT को दूंगा। किसके लिए ? यदि कंडरा टोकनी बनाता है, अच्छी टोकनी कैसे बनेगी और उसका value addition कैसे होगा ? कुम्हार की चीजों का value addition कैसे होगा, डोंगरा सिल्क का value addition कैसे होगा ? बेल मेटल का value addition कैसे होगा ? उस पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर, नवाचार से छत्तीसगढ़ की सेवा कैसे की जा सकती है।

श्री रामकुमार यादव :- ये हा कहां मेर के बजट ए, ये महाज्ञानी बताय कि कहां मेर के बजट मा ए। हमन ला कहत रहिस हे बजट मा बोलय, ओ बगल मा महाज्ञानी बैठे हे, ओला समझावा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब तै नरवा, घुरवा, गरूवा, बाड़ी के दौरान पहली बार विधायक बने हस, तोर सोच ला बदले बर तोला ओ.पी. चौधरी साहब के संगत कर। अभी तै गलत संगत मा हस।

श्री रामकुमार यादव :- तु मन गुरू बनाय हा, ओ हा बुलक जाही। गुरू बनावव जान के, पानी पीया छान के। मैं जान के गुरू बनाहव।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप राजेश अग्रवाल ला गुरू बनाव, फेर बताहय। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, तो पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक से छत्तीसगढ़ के इन कलाकारों का, इस परम्परागत सांस्कृतिक पहचान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो, यह संकल्प विष्णु देव साय जी की सरकार ने, इस नवजवान वित्त मंत्री ने व्यक्त किया है।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी। मैं बस दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। साहब, इसको आप पढ़ दीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि आपने आज तक के सबसे बड़े बजट में कौन-कौन से विभाग में कौन-कौन सी योजनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। इतनी वृद्धि की गई है। सभापति महोदय, आप समय नहीं दे रहे हैं। यह लिखा है कि प्रमुख विभागों में कितने प्रतिशत बजट की वृद्धि हुई है। मैं बधाई देता हूं कि आपने सभी विभागों को प्राथमिकता में रखा है और खासतौर पर आपने शिक्षा के बजट में सबसे ज्यादा वृद्धि दी है, जिसकी छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, नवाचार क्या है, उसको देखिएगा। शहरीद क्षेत्रों के उत्थान के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। यह नई योजना है। जब कल आपके विभाग में बोलूंगा तो इस विषय में बोलूंगा। मैं आज अपना भाषण लंबा नहीं करूंगा। "मुख्यमंत्री मोबाईल टॉवर" के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में बस्तर एवं सरगुजा के लिए एक अलग पन्ना है। मैं बालूंगा तो समय लगेगा। लेकिन उसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। वह पंडरिया का उल्लेख कर रही थीं। इधर चाहे राजनांदगांव का सबसे नीचे वाला इलाका हो, हमारा देवभोग क्षेत्र हो, गरियाबंद क्षेत्र हो या छूरा का इलाका हो, मुख्यमंत्री मोबाईल टॉवर कंपनियों से हम बात करके कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- आप बी.एस.एन.एल. के टॉवर लगवाईहौ। अडाणी, अंबानी के टॉवर मत लगवाईहौ।

सभापति महोदय :- आप बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, सी.एम. सुशासन फेलोशिप योजना, जिसके लिए हमारे नवजवान मंत्री ने IIIT एवं IIM के साथ मिलकर नवाचारों को G.Y.A.N. के साथ जोड़ा है। जो पहले साल G.Y.A.N. था, उसको अभी G.A.T.I. देनी है। ऐसे ही नवाचारी बजट आयोजन से मुख्यमंत्री परिवहन योजना को बजट में शामिल किया गया है। उन्होंने इस बात को अपने भाषण में बताई है कि परमिट लेने के लिए हर पांच मिनट में रायपुर-दुर्ग के बीच में होड़ है। मैनपुर से देवभोग के बीच में होड़ नहीं है, छुरा से मैनपुर के बीच वह होड़ नहीं है। मोहला से औंधी जाने के लिए नहीं है, यदि आदमी को जाना हो तो। मैं सुदूर बस्तर की जगह को भी गिना सकता हूं। लेकिन आशय समझ लीजिये, मैंने इसके लिए उदाहरण दिया। जो कभी उस गैप फिलिंग के लिए सोचा नहीं था, इसके लिए आप मेरी बधाई स्वीकार करें और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी को बधाई। मुख्यमंत्री बायपास रिंग रोड निर्माण योजना। कौन सा ऐसा शहर है, जहां पर परेशानी ना हो? आप छोटे से छोटे शहर का नाम बता दीजिये। मैंने उनसे कहा कि मेरा शहर इस प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है और उस लाईन में सबसे ज्यादा रेत खदान है। बाहर से ले जाने के लिए यदि आप सौ करोड़ देंगे तो मेरी दो सड़कों में हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा उसको सुन लीजिये कि हमने बजट हेड खोल दिया है। जितनी

राशि होगी, डी.पी.आर. बनेगा, उतनी राशि इसमें उपलब्ध कराई जाएगी। यह एक नवाचार है, जिसको सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना। आप निर्धारित समय से आवास निर्माण कर लेते हैं, प्रवेश कर लेते हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मेरे ख्याल से इसका ज्यादा विषय आपके अंदर में आएगा। मैंने अटल सिंचाई योजना का उल्लेख किया था। अब जो नई चीजें आई हैं, उसका मैं उल्लेख करूंगा। मैंने National Institute of Fashion Technology : NIFT का उल्लेख कर चुका। SSIP (Student Startup Innovation Policy), इसको भी मैंने उल्लेख किया। नवा रायपुर में फिल्म सिटी की स्थापना होगी। मैं इसमें थोड़ी देर के लिए रूकता हूं। अभी तक 15 सालों में शुरूआत के सात-आठ सालों के बाद से नारा की तरह हो गया है कि हम फिल्म सिटी बनायेंगे। अब आपने नई चीजें दी है तो ..।

सभापति महोदय :- चलिये, चन्द्राकर जी समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- हाँ, मैं आखिरी दो पेज पढ़ रहा हूं। जल्दी प्रशासकीय देंकर इसको शुरू कराईये।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर दशा ला देख कर दु:ख लागत हे। आप ला मांगे बर लाग हे। आप देने वाला रहे हौ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। मैं इसका सबसे ज्यादा स्वागत करता हूं। इसलिए नहीं कि वह मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है तो आपने उसको स्वीकृत कर दिया। मैं अब किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। रोज समाचार पत्र में छप रहा है कि सबसे बड़ा चर्च है। मैं उस वेटिकन सिटी में गया हूं कि आप चंगाई सभा कीजिये। भोले भाले लागों के साथ, जो सदियों से षड्यंत्र चल रहा है, यह आधुनिक ईलाज पहुंचेगा तो धर्मांतरण जैसे कोढ़ में छत्तीसगढ़ के कुनकुरी के जशपुर से भोले भाले जनता को मुक्ति मिलेगी (मेजों की थपथपाहट) जहां पूरा जनसांख्यिकीय आंकड़ा असम, बंगाल की तरह बिगड़ गया है। आप देखिये, तुम्हारे लिये है, कर लो शादी-वादी? आई.वी.एफ. से तुमको संतान सुख मिल जायेगा । आई.वी.एफ. से संतान सुख मिल जायेगा ।

श्री रामकुमार यादव :- देने वाला मांगथे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, गरीब माता-पिता महिलायें भी हैं, पुरूष भी हैं, निसंतान होने का कलंक छत्तीसगढ़ के समाज में कितना बड़ा होता है, यह सब ने देखा है । यह सिर्फ एक मेडिकल का आयोजन नहीं है, यह समाज में एक सम्मानजनक स्थान, जो गलत शब्द को अच्छे शब्दों में बता देता हूँ कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है । सभापति महोदय, पिछली बार भूपेश सरकार में दुर्ग का एक ठगड़ा तालाब जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, उसका नाम मोतीलाल वोरा जी के नाम से रखने के लिये निगम ने प्रस्ताव कर दिया है । समाज के लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं साहब

इसका नाम ठगड़ा बांध होना चाहिये, जिस आदमी ने उसको बनाया था, उसकी संतान नहीं थी, ऐसे शब्दों का उपयोग छत्तीसगढ़ी में होता है, इसमें अपमानजनक स्थिति से समाज को मुक्ति दे रहे हैं । सरकार ने इस तरह से सोचा है, मैं इसके लिये बधाई देता हूँ । माननीय सभापति महोदय, मैं इन बातों को रख देता हूँ, मैं दो-तीन चीजें छोटी-छोटी बोल देता हूँ । संस्कृति विभाग में बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ में योगदान के लिये बहुत अच्छी चीजों का उपयोग किया । आपने विवेकानंद जी का उल्लेख किया है, तुरतुरिया का उल्लेख किया है, बजट बुक के सामने में है । सभापति महोदय, सिरपुर में नागार्जुन जी रहे हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा शून्यवाद का प्रवर्तन इसी धरती पर हुआ है । (मेजों की थपथपाहट) वैसे ही योगदान भगवान वल्लभाचार्य की भूमि है, शंकराचार्य जी के जाने के बाद जो प्रमुख 5 आचार्य हुये, आज सनातन धर्म जिस स्थिति में है, उसमें जिन लोगों ने योगदान दिया, उसमें वल्लभाचार्य भी है । रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, माध्यमामार्च, 5 आचार्यों के नाम याद आ जायेंगे, लेकिन उससे बड़ी बात देश भर में 84 बैठक है, उसमें एक प्रमुख बैठक चंपारण है और उससे भी बड़ी बात कि भारतीय दर्शन की एक शाखा शुद्ध विशिष्ट द्वैत्वाद्वैत्व का प्रवर्तन छत्तीसगढ़ के इस महान संत वल्लभाचार्य जी ने किया, ऐसे अनेक चीजें हैं । सभापति महोदय, आपने इसको बजट के मुख्य भाषण में इसको शामिल करके छत्तीसगढ़ को एक आत्म स्वाभिमान दिया कि संस्कृति जिसकी हो, जिस राष्ट्र की संस्कृति नहीं है, जो राष्ट्र और समाज अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करता है, वह शव के समान है, यह मान लीजिए । सभापति महोदय, आपने उस भाव को जागृत किया । दूसरी बात, आपने जब संस्कृति से अपनी बात शुरू की तो मैं एक आग्रह कर देता हूँ कि डॉ.रमन सिंह जी के समय में, वैसे मुझे डिमांड मांग पर बोलना चाहिये, क्योंकि बजट से बाहर बात की तो विरोध किये थे, चूँकि संस्कृति की बात आई और आपने छत्तीसगढ़ को गौरव दिया, मैं भूपेश बघेल जी के कार्यकाल से 5 साल से लड़ रहा हूँ, अब यह लड़ाई मेरी समाप्त होनी चाहिये । सभापति महोदय, आप 18 भाषाओं में, बोलियों में, जिसमें भी शिक्षा देते हैं, उनके साहित्य को छपने के लिये छत्तीसगढ़ में लेखन के लिये आपने कहा कि छायावाद का प्रवर्तन हुआ, वैसे ही ठाकुर जगमोहन सिंह की जो श्यामा स्वप्न आप ही के इलाके के हैं, डिप्टी कलेक्टर उधर ही थे, वह पहला फैंटेसी वाला उपन्यास माना जाता है । इसको छपने के लिये हमारा ज्ञान बाहर जाये, छत्तीसगढ़ के योगदान को जानें, हिन्दी साहित्य ग्रंथ अकादमी बनाई थी और छत्तीसगढ़ में पहली ग्रंथ अकादमी बनी । मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहां पर है ? सभापति महोदय, मैं भूपेश बघेल जी को बोला था कि उत्तर दूंगा करके कि अरपा, पैरी के धार, अब आरोप तो नहीं लगाना चाहता ...।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें । 1 घण्टे हो गये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में एक उपलब्धि बताये कि 68 साल की महिला और उसके आड़ में कितना पैसा खाये, उसको नहीं बतायें हैं । मेरे प्रश्नों को देख लीजिएगा, आज तक पिछले पांच साल का हिसाब नहीं दे सके हैं । राजीव मितान क्लब के लगे,

डी.एम.एफ. के लगे, सी.आर.एफ. के लगे नहीं मालूम कि कितने सारे पैसे लगे ? सभापति महोदय, जब आपने छत्तीसगढ़ के योगदान से भाषण की शुरूआत की तो ग्रन्थ अकादमी दिखनी चाहिये । छत्तीसगढ़ के लेखक दलित आदिवासी से लेकर सामान्य जो लोग हैं, आज भी विनोद कुमार शुक्ल जैसे लोग हैं, उनसे मेरी असहमति हो सकती है । वामपंथ के आप आदमी हैं, दक्षिण पंथ के आदमी हैं, पर वे हैं तो छत्तीसगढ़ के । राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होते हैं, उनकी किताबें दूसरे राज्यों में कोर्स बुक में चलती हैं तो आप उसको जिंदा कर दीजिए । बाकी सब बात विभागीय चर्चा में होगी । आपने बहुत अच्छा बजट लाया है और खास तौर पर उस स्थिति में बहुत अच्छा बजट कहता हूं, आपने जो पूरी बजट पुस्तिका दी है, वह पॉच साल में कांग्रेस ने बजट बनाने के लिए जिन क्षेत्रों में जितना अनुमान किया और एक साल तो ऐसा आया है, जब राज्य के राजस्व से ज्यादा अनुमान देखें तो उनको केन्द्रीय राजस्व प्राप्त हुआ है । उस बजट में 43 प्रतिशत के आसपास केन्द्रीय राजस्व प्राप्त हुआ है, यह बजट बुक बोलता है, मैं नहीं बोलता । आपको ढेरो बधाईयां, हमारे साथियों की ओर से बधाईयां, जिन्होंने बधाईयां नहीं दी हैं । आपके और हम सबके नेता माननीय विष्णु देव साय जी को इस अच्छे बजट के लिए बहुत-बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । सभापति जी, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार । (मेजों की थपथपाहट)

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे विद्वान सदस्य माननीय अजय चन्द्राकर जी की विद्वता को नमन करता हूं, जिनके कारण हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है । हम केवल आंकड़ों से सरकार नहीं चला सकते । योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर होना चाहिए, केवल बजट बनाने से नहीं चलता । ज्ञान से शुरू होकर इस साल हम लोग गति पर आकर अटके हुए हैं ।

सभापति जी, आपने भाषण की शुरूआत बहुत अच्छी पंक्तियां से कीं । कविताओं के माध्यम से उसे सजाने का प्रयास किया । मैं भी अपनी बात इन पंक्तियों के माध्यम से शुरू करता हूं कि :-

नामावर अपना हवाओं को बनाने वाले,
नामावर अपना हवाओं को बनाने वाले,
अब न आयेंगे पलटकर कभी जाने वाले.
क्या मिलेगा तुझे बिखरे हुये ख़्वाबों के सिवा,
रेत पर चाँद की तस्वीर बनाने वाले,
रेत पर चांद की तस्वीर बनाने वाले ।

माननीय सभापति महोदय, बड़ी-बड़ी बातें हुईं, सबने बजट भाषण पर अपनी बातें रखीं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जिसे धान का कटोरा कहते हैं और आज यह अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने 1 लाख, 50 हजार मीट्रिक टन धान खरीद लिया है ।

व्यवस्थाएं अच्छी थीं, सुचारू रूप से परिवहन हो रहा है, संचालन अच्छा हो रहा है, लेकिन धरातल पर आज भी जाकर देखें कि व्यवस्था किस हालत में है । आज भी 50 प्रतिशत धान सोसायटी में, धान खरीदी केन्द्र में पड़े हुए हैं, जिसके परिवहन की व्यवस्था नहीं हो रही है । ये सूखत में आएंगे । जब हानि होगी तो सारी समितियां लॉस में चली जाएंगी । तब क्या होगा? हम कुछ-कुछ जगह निरीक्षण में गए थे, जब धान खरीदी की शुरूआत हुई थी तो हमने देखा कि बहुत सी ऐसी समितियां और धान खरीदी केन्द्र हैं, जहां पर मानक से कहीं ज्यादा धान लिए जा रहे हैं । प्रति क्विंटल में दो-तीन किलो ज्यादा धान लिए जा रहे हैं । हम भानुप्रतापपुर गए थे तो वहां पर इतने सालों से संचालित धान खरीदी केन्द्र हैं, जो समिति हैं-कैंवटी, जहां की समिति की राशि को लगभग गबन करके सारे लोग फरार हो चुके थे, वहां पर धान खरीदी एक महीने बाद प्रारंभ हुई । वहां के जनप्रतिनिधि ने मिलकर वहां की धान खरीदी प्रारंभ की । यह इनकी व्यवस्था है और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं । आपने बारदाने की व्यवस्था देखी है । पूरे प्रदेश में क्या स्थिति थी ? व्यापारी के पास बारदाना लेने के लिए किसान जा रहे हैं तो 10-12 रूपए का बारदाना 35 और 40 रूपए में खरीद रहे हैं, लेकिन बारदाना खरीदना उनकी मजबूरी है क्योंकि धान को काट चुके थे, उसे कहां रखते, कैसे रखते तो किसान जबरदस्ती 30-35-40 रूपए में बारदाना खरीदकर उसे धान खरीदी केन्द्र में, समिति में पहुंचाने का काम किये हैं ।

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य अपने कार्यकाल की बात बता रहे हैं या वर्तमान का है ? अपने कार्यकाल का भी बता दीजिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अभी का बता रहा हूं । मैंने आंकड़ा भी दिया था ।

श्री दयालदास बघेल :- आप जितना बता रहे हो, वह आपके कार्यकाल का है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैंने अपने कार्यकाल की बात ही नहीं की है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी, निषाद जी हमारे विद्वान साथी हैं । सारंगढ़ की घटना हैं । एक विधायक के पति ने धान खरीदी केन्द्र में क्या किया ? लगता है कि वे भूल गए । शायद उसकी पुनरावृत्ति उनको सपनों में याद आ रही है तो वे यहां सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- आप बजट पर अपनी बात रखिए ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- देखिए, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहूंगा। अगर जाना चाहें तो अभी मेरे साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में चलिए। आप जहां-जहां घूमना चाहें, मैं दिखाता हूं कि समितियों में धान खरीदी के क्या हालात हैं।

सभापति महोदय :- आप विषय पर आइए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- मैं विषय पर ही आ रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :-1 लाख 50 हजार मीट्रिक टन धान खरीदे हैं और 2 किलो कम हो गया, 100 ग्राम कम हो गया, ऐसा बोलेंगे तो थोड़ी चलेगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- 2 किलो कम हो गया, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बल्कि किसानों से प्रति क्विंटल 2-3 किलो ज्यादा ले रहे हैं। सोचिए कि किसान 100 क्विंटल बेचता है, तो 2 क्विंटल ऐसे ही चला जाता है, तो कम से कम उसका 6 हजार रुपए का घाटा हो जाता है। राईस मिलर्स हड़ताल पर रहे, कर्मचारी हड़ताल पर रहे, खरीदी प्रभावित हुई।

श्री सुशांत शुक्ला :- किसके कारण? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- केवल आपके कारण। आपकी अव्यवस्था के कारण। आप सुचारु रूप से संचालित नहीं कर पाए, इसके कारण हुआ। आपको तथाकथित पता है कि पूरे प्रदेश में क्या हुआ। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- राईस मिलर्स किसके कारण हड़ताल पर रहे, किसकी सरकार के कारण? बताइए ना कि राईस मिलर्स से वसूली करने वाले कहां हैं? माननीय अजय चन्द्राकर जी पूछे कॉग्रेस पार्टी के वे कौन हैं, जो राईस मिलर्स से वसूली करते थे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- (व्यवधान) क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी में हुआ यह पूरे प्रदेश की जनता जानती है और आप खरीदी के ऊपर बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, बिजली उत्पादन की बात किए कि 7300 मेगावॉट से 18 हजार मेगावॉट तक पहुंचा है लेकिन अभी पूरे प्रदेश में बिजली व्यवस्था के हालात क्या हैं? गांव में कब बिजली चली जाए, कोई ठिकाना नहीं। किसान पानी के लिए तरश रहे हैं और बिजली की व्यवस्था ठप्प पड़ी है। केवल बोल देने से कुछ नहीं होता। सरकारी खरीदी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जेम पोर्टल की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मेरा भी प्रश्न लगा था लेकिन नहीं आ पाया। सरकारी खरीदी में भ्रष्टाचार की जिस प्रकार से उन्होंने बात कही है, एक उदाहरण के तौर पर मैं गृह विभाग की एक बात कह देता हूं कि जेल विभाग, पुलिस मुख्यालय भंडार क्रय नियम का पालन करता है और उसी विभाग के अंतर्गत नगर सेना जेम के नियमावली का संचालन करती है, तो एक ही विभाग में इस प्रकार की विसंगति क्यों हो रही है? यदि पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो पारदर्शिता सबमें होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विद्वान साथी और हमारे वित्त मंत्री जी ने चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हुए सभाओं में और कोचिंग सेंटर्स में जाकर कहा था कि- कहर बनकर बरपूंगा, सरकार आने पर, लेकिन युवाओं को पता नहीं था कि वह ऐसे कहर बरपायेंगे कि युवाओं को उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और उनके सपने खत्म हो जायेंगे। 34 हजार युवाओं को शिक्षक की भर्ती के लिए उन्होंने पिछले साल बजट में जो सपने दिखाए थे, उनके वह सपने भी चूर हो जायेंगे, ऐसा कहर बनकर आज ये उभरे हैं।

माननीय सभापति महोदय, डी.एम.एफ. की राशि में भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही थी। सदन ने सुना, सबने अपनी-अपनी बातें की लेकिन मैं पूरे प्रदेश का नहीं कहकर अपने बालोद जिले की बात कहूं तो बगैर नियम, मापदंड के आचार संहिता लगी थी और बगैर भौतिक सत्यापन के वहां पर सोलर लाईट की स्थापना का प्लान कर दिए, जिसके संबंध में मैंने कार्यवाही के लिए पत्र लिखा है, लेकिन आज तक इसमें कोई कार्यवाही नही हुई, जबकि नियम ये कहता है कि ये केवल और केवल क्रेडा के माध्यम से क्रय होगा लेकिन इन सारे नियमों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए बगैर भौतिक सत्यापन किए वहां पर सोलर लाईट की स्थापना कर दी।

माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात आई कि एक गांव का दूसरे गांव से संपर्क जोड़ना है, पर अगर पूरे प्रदेश के बजाय बालोद जिले की बात करूं तो वर्तमान सरकार द्वारा बालोद जिले में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के सेटअप को उठाकर खैरागढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। तो बालोद की जनता ने क्या अपराध किया था कि वहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की इतनी सड़कें संचालित हैं, उनकी देखरेख कौन करेगा? ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय :- कृपया जल्दी समाप्त कीजिएगा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरूआत की है। अभी मुझे बोलते मुश्किल से 2-3 मिनट हुए हैं। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उस भेदभाव को खत्म करते हुए वहां जो परियोजना पहले से संचालित थी, उसे पुन: प्रारंभ की जाये। नगरीय निकाय क्षेत्र में विकास हेतु मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की जायेगी, इसके लिए बजट में 500 करोड़ रूपये का प्रावधान है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूर्व में नगरीय निकाय में अधोसंरचना मद से और अन्य मद से जो कार्य स्वीकृत हुए थे, जिनका भूमिपूजन हो गया था और वह कार्य होने थे। उन कार्यों को आचार संहिता के कारण रोक दिया गया और जब आचार संहिता खत्म हुई तो सारी राशि वापस चली गयी। उसमें केवल हम लोग ही शामिल नहीं थे, उसमें आपके सांसद भी शामिल थे। उस भूमिपूजन में राशि थी, वे उस सारी राशि को वापस ले गये। इन्होंने इस प्रकार से भेदभाव किया है और बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं। जिनका भूमिपूजन हो गया था और जिनके काम प्रारंभ होने थे, वह राशि वापस होनी चाहिए। इस प्रकार से बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है लेकिन आज भी जो पुराने ऐतिहासिक स्थल हैं, इस सरकार के द्वारा केवल उन्हें ही सजाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसे बहुत से पर्यटन स्थल है, जहां पर या तो सरकारें नहीं पहुंच पाती या संस्थान नहीं पहुंच पाता या विभाग नहीं पहुंच पाता। ऐसे बहुत से पर्यटक या ऐतिहासिक या धर्मिक स्थल है। उसका भी उन्नयन होना चाहिए। यदि मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो वहां गौरेया और कल्चुरी वंश का स्थान है। जैसे सिरपुर की खुदाई में मूर्ति निकली थी, वैसे ही वहां उससे कहीं ज्यादा मूर्तियां निकली हुई है लेकिन मैंने उनके

संरक्षण पर लगातार बातें की है परंतु आज तक उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ऐस बहुत से स्थल हैं, उस पर भी सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए और उनका संरक्षण् होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जब संस्कृति की बात आती है तो मैं छत्तीसगढ़ की धरा को निश्चित ही कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को प्रभु श्री राम चंद्र जी का ननिहाल और माता कौशल्या के नाम से जाना जाता है। पूर्व की सरकार में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा राम वन गमन परिपथ का निर्माण कर इसको संरक्षित करने का काम किया गया था। इसका और विस्तार करने की जरूरत है ताकि हम प्रभु श्री राम चंद्र जी के ननिहाल की याद को चिरस्थायी बना सके। इसमें केवल विवाद करने से या बात करने से या मूर्ति के बारे में बातें करने से कुछ नहीं होगा। सभापति महोदय, यदि हमारी राम के प्रति आस्था है तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हम केवल अयोध्या की बात न करें बल्कि हम छत्तीसगढ़ को भी सजाने का काम करें । छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बारे में लगातार बातें आती है कि इसका श्रेय माननीय अटल जी को है। हम बिल्कुल इसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने अपनी बातें सदैव पटल पर रखी, वैसे स्व. बिसाहु दास महंत जी, स्व. चंदूलाल चंद्राकर जी, स्व. खूबचंद बघेल जी, स्व. पवन दीवान जी और स्व. वासुदेव चंद्राकर जी के नाम का भी उल्लेख होना चाहिए। तब उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन तो हुआ परंतु अभी तक छत्तीसगढ़ की बोली को भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, यह 5 साल तक राजभाषा आयोग का गठन तक नहीं कर पाये और आज बात कर रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- राजभाषा आयोग का गठन हुआ है। आप समझ नहीं पा रहे हैं।

सभापति महोदय :- कुंवर सिंह निषाद जी, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप छत्तीसगढ़ की अस्मिता के नाम पर छद्म राजनीति करना बंद करें।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, राजभाषा आयोग का गठन 2008 में हुआ है, लेकिन उस समय आपकी सरकार रही और आप कुछ नहीं कर पाये।

सभापित महोदय :- चलिये, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, संस्कृति और बोली पर बातें हो रही है, इसलिए मैं बात करना चाहूंगा कि उस पर इनको ध्यान देने की जरूरत है। जब हम लोग 18 भाषाओं और 18 बोलियों की बात करते हैं, तो जब छत्तीसगढ़ की बोली की बात आती है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात आती है और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की बात आती है, तो इस पर हमको गहन विचार करना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ की बोली को उसका सम्मान मिल सके।

सभापति महोदय, हम नया रायपुर में फिल्म सिटी के निर्माण का बिल्कुल स्वागत करते हैं। उसका निर्माण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की परंपराओं को, छत्तीसगढ़ की कला को उसका सम्मान मिले। आपने जनजातियों की संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण की बात तो की है लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति, नाचा का जो प्रभाव है, उसे हम कभी भुला नहीं सकते। नाचा, एक ऐसी शैली है, एक ऐसी विधा है, जिसने आज लोक कला को मंच प्रदान किया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में नाचा, भर्तरी, पंथी, पंडवानी, सुआ, रहस, डंडनि का भी अलग महत्व है। यदि हम लोक कला के उद्‌भव की बात करें, जिसके कारण आज विभिन्न लोकमंच में लोग प्रस्तुती देते हैं तो उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म नाचा उसका है। इसके लिए भी एक बात होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि विदेशों में नाचा को जो महत्व मिला है । माननीय हबीब तनवीर जी हमारे बीच नहीं हैं। जिनको पद्‌म विभूषण की उपाधि मिली है। अगर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विदेशों में नाम देने का काम किया है, वह माननीय हबीब तनवीर जी हैं। आज हम नाचा के उस सिद्‌धस्थ कलाकार को याद करते हैं। चाहे वह भूलवा राम जी हो, चाहे मदन जी हों, चाहे किस्मत बाई हो, चाहे फीदा बाई, माला बाई हो। ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नाचा के नाम से ख्याति दिलाने का काम किया है। मैं यह कहता हूँ कि भारत भवन की तर्ज में छत्तीसगढ़ में एक संस्था बननी चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ के कलाकारों को सम्मान मिल सके। उन्हें पारितोषिक मिल सके और वे अपने जीवन को अच्छी तरीके से संचालित कर सकें। उनको यह सम्मान मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर स्वास्थ्य पर बड़ी-बड़ी बातें हुई हैं। सभी की स्वास्थ्य के संबंध में एक चिन्ता स्वाभाविक होती है, लेकिन केवल मेडिसिटी सेन्टर विकसित करने की योजना के प्लान तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपके पास जो मेकाहारा अस्पताल है हम उसका कैसे व्यवस्थित रूप से संचालन करें। क्योंकि लगातार हम लोग वहां जाते हैं हमारे परिजन और हमारे क्षेत्र के बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पर जाते हैं और हम उन्हें देखने जाते हैं तो वहां रात की जो स्थिति होती है, वह बड़ी भयावह होती है। वहां गली, सीढ़ियों और दीवार के सहारे लोग सोये रहते हैं। जिस हिसाब से वहां पर अव्यवस्थाएं हैं। क्या हम उनको व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर कैम्पस बड़ा है और जगह बहुत बड़ी है। अगर सुबह के समय हम हजार लोगों की परिकल्पना करें, वह शौच-प्रसाधन के लिए जाएं तो वहां गंदगी का आलम रहेगा। उसके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए।

सभापति महोदय :- अब हो गया। आपकी सारी बातें आ गईं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, मैं, आपसे एक, दो बातें कहूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। यहां पर शिक्षा के अधिकार के तहत बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं। यहां कक्षा पहली से 8 वीं तक के बच्चों को पास कर दिया जा रहा है। यदि जिसके बाद बच्चे हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी

तक पहुंचते हैं तो वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। वह फेल हो जाते हैं। फिर गांव के बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, दूसरे काम धंधों में लग जाते हैं। उसके बाद जीवन भर किसी के यहां मजदूरी करके अपने परिवार का पालन करते हैं। मैं तो केवल यह कहना चाहूंगा कि कौशल विकास और रोजगार हेतु योजनाएं ऐसी बनायी जायें ताकि जिन बच्चों ने कक्षा 8 वीं और 10 वीं कक्षा की पढ़ कर, अपनी पढ़ाई छोड़ी है, उनको स्कील के माध्यम से कोई न कोई रोजगार मिले ताकि वह आत्मनिर्भर और सक्षम बनें। हमारे द्वारिकाधीश यादव भाई ने एक बात रखी और यहां पर लगातार मांग आ रही है । मैं भी उसी बात को कहता हूँ कि पिछले बजट में बातें आयी थी लेकिन अभी इस बजट में नहीं दिख रहा है। तृतीय लिंग के द्वारा एक मांग की गयी थी कि उनके लिए ट्रांजिट हॉस्टल बनाया जाए। मतलब उनके द्वारा गरिमा गृह की मांग की जा रही है। यह रायपुर में तो बना है, लेकिन यदि यह प्रदेश के अन्य जिलों में बन जाए तो जैसे कि इस समुदाय के व्यक्ति हैं उनको वहां रखकर, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जा सके। हम आपके माध्यम से ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि इस बजट में ऐसा प्रावधान हो। मैं अंत में केवल यही कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से इनका बजट रहा है इन्होंने छत्तीससगढ़ की जनता को छलने का प्रयास किया है। इन्होंने छत्तीससगढ़ की जनता को [xx] देने का काम किया है। इन्होंने इस बजट में समावेशी बजट की बात की है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा :-

"जख्म से सेने से अब क्या होगा
राय दे देने से अब क्या होगा
सियासत की लाश बदबू देती है
कफन बदल देने से अब क्या होगा"।।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, जब यह बजट प्रस्तुत हुआ। सदन के बाहर हमारे प्रतिपक्ष के बड़े-बड़े नेताओं ने यह कहा कि यह कविता है, कवि सम्मेलन है, शेरो-शायरी है। आज मैं दिन भर से देख रहा हूँ कि विपक्षी दल के सारे लोग अपने बड़े नेता के उस उद्गार को नहीं समझ रहे हैं और यहां पर शेरो-शायरी झाड़ रहे हैं । यहां जो पा रहा है, वही शेरो-शायरी पढ़ रहा है या तो आपके नेता जी को शेरो-शायरी पसंद नहीं है तो आपको भी पंसद नहीं होना चाहिए। यदि आपको पसंद है तो माननीय नेता जी को भी पसंद होना चाहिए।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- हमारे नेता जी, अपना भाषण कबीर के दोहे के साथ शुरूआत करते हैं उनको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं कुछ-कुछ बातें बोलूंगा। मैं अजय चन्द्राकर जी के सरीखे इतने हजार करोड़ ज्यादा है और इतने हजार करोड़ रूपये कम है। मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। पूर्व में माननीय भूपेश बघेल साहब, वित्त मंत्री थे तो एक बार मैंने उनसे बाहर में कहा था कि जब सदन में वह बजट पेशा करके गये कि भाई, आपने क्या-क्या पढ़ा है, मुझे कोई ज्यादा पल्ले पड़ा नहीं है। बस इतना जानते हैं कि यहां बजट पास हो गया है तो इसमें क्या-क्या काम हुए हैं , उसको जरा देख लो और उतना ही देखते हैं। इसमें थोड़ा-थोड़ा नोट करके रख लिये हैं, उसी के बारे में बोलूंगा। अभी कांग्रेस पार्टी में लोकसभा, विधान सभा, नगरपालिका, पंचायत चुनाव, महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनाव के बाद से लगता है कि वहां पर केन्द्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व तक सब उद्वेलित और बेचैन हो गये हैं और कुछ भी बयान कभी भी किसी का आ रहा है। इनको शांति की तलाश बहुत जरूरी है। कल एक राष्ट्रीय पार्टी की महिला प्रवक्ता को टी.व्ही. में देखा, वह बहुत सुंदर महिला हैं। उन्होंने बयान दिया कि रोहित शर्मा की फिटनेश खराब है, रोहित शर्मा दुबई में आस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलने इंडिया का captain बनकर गया है। उस महिला का उसमें क्या फिटनेश देखनी थी? वह कौन सी फिटनेश में कमी पा गई?

सभापति महोदय :- विषय पर आईयेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, बजट पर ही आ रहा हूं। यह बजट का ही है कि इनको पहले शांतचित्त से बजट पढ़ना चाहिए। इनके एक सहयोगी अबू आजमी बोले कि औरंगजेब बहुत भला आदमी था। उसने अपने भाई दारा शिकोह का आगरा के किले में गला कटवा दिया था, उसको अच्छा आदमी बोल दिये। इनके एक नेता बोल दिये कि कुंभ बहुत बेकार चीज है, वहां नहाने से कोई फायदा नहीं है। आखिर क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जो भागीरथी गंगोत्री से गोमुख से गंगा निकाल कर धरती पर प्रयागराज तक लाये, उसमें नहाने में भी आपको तकलीफ है। सभापति महोदय, इसलिए अब मैं बजट पर आते हुए बात कर रहा हूं। ज्ञान और गति के बारे में भी प्रश्न उठाया गया। बिना ज्ञान और बिना गति के इंसान की जिंदगी किसी काम की नहीं रहती है। किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर ज्ञान नहीं है और उसको कुछ करने की गति नहीं है तो वह तो कहीं पर भी सड़क में बुरे हाल में घूमते हुए दिखता है। उसी को बिना ज्ञान और बिना गति का बोलते हैं। इनको ज्ञान और गति दिखाने के लिए यह बजट बना हुआ है। इस बजट में 20,000 नई भर्तियों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है और 12 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। आप लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार मतलब 12 नर्सिंग कॉलेज में बच्चे और बच्चियां ट्रेनिंग लेकर डिग्री लेंगे। वह केरल के सामान दूसरे प्रदेश में और विदेशों में जाकर के सेवायें देंगे। वहां से यह पैसा कमाकर छत्तीसगढ़ लायेंगे। यहां की बेरोजगारी दूर होगी, यहां के

लोगों को स्वरोजगार करने का अवसर मिलेगा। इसलिए इसका प्रावधान किया गया है। इसमें नई सड़कों के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक दिन में तो कोई सड़क बनती नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की स्थापना का 25वां वर्ष है, हम सिल्वर जुबली वर्ष मना रहे हैं। अगर 25 वर्षों में 2-2 हजार करोड़ रुपये की सड़क बनती तो अभी बहुत से infrastructure बनता, लेकिन इन्होंने उसमें जिक्र किया है। बजट में रामलला दर्शन के लिए 36 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। तीर्थ यात्रा योजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आपने तो कभी न तीर्थ यात्रा करवाई, न रामलला के दर्शन कराया। अब रामलला के दर्शन करने का अधिकार तो छत्तीसगढ़ की जनता को है और अगर यह सरकार दर्शन करा रही है तो इसमें आपको पीड़ा नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कविता वाली बात नहीं है। एक तो वित्त मंत्री जी ने बहुत शानदार हैंडराईटिंग में अपने हाथ से लिखा है। मैं तो शायद पहली बार ही देख रहा हूं, शायद इस राज्य में पहली बार आपके वित्त मंत्री की हैंडराईटिंग में यह बजट प्रस्तुत हुआ है। इसकी मेहनत के लिए आपकी सराहना करता हूं। आप जो दो लकीर लिखे हैं जिसे कविता, नाच-गाना जो भी कहा गया हो- "कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, पूंछ उन परिन्दों से जिसके घर नहीं होते।" इसमें छत्तीसगढ़ के उन 18 लाख गरीबों का दर्द छिपा हुआ है जो बिना मकान के 05 साल तक आपकी जिद के कारण वंचित रहे। (मेजों की थपथपाहट) आप इसलिए आवास नहीं बनने दिये, प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री की फोटो छप सकती है या उनका नाम आयेगा, इस जिद में आपने 18 लाख लोगों को बेखरबार कर दिया। उसी अपराध की सजा आपको मिली है। यह जो कवि ने जो भी यहां पर लिखे हैं, यह उन्हीं गरीबों के दर्द को बयां कर रहा है। हम 18 लाख गरीबों को आवास देने के लिए 8500 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किये हैं। 15 हजार नक्सल प्रभावित लोगों को बसाने के लिए और surrender किए हुए नक्सलियों को या उनसे पीड़ित नक्सल परिवार के लोगों को बसाने का अगर यह सरकार काम कर रही है तो आप ज़रा यह बताइए कि यह पुण्य का काम नहीं है, जनहित का काम नहीं है तो और क्या है ? अब आप खुद तो नहीं बनवा सके, दूसरा कोई बनवा रहा है तो आप हर बात में उंगली उठा रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों के लिए सम्मान निधि आपने 10 हज़ार रूपये दिया, इन्होंने 20 हज़ार रुपये कर दिया । जब भी यहां पर कोई नेता भाषण देता है, चाहे वह इधर से हो या उधर से हो, जब कुछ बोलते हैं और कुछ ऐसी बात आती है तो पत्रकार दीर्घा की तरफ देखते हैं पर देखने से और news छपवा लेने भर से कुछ नहीं होगा । कभी उन प्रजातंत्र के चौथे स्तम्भ के बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए और उन्हें अगर 20 हज़ार रुपये देने की बात हो रही है, एक करोड़ रूपये उनके press क्लब को जो कि रायपुर का है, उसके रेनोवेशन की बात हो रही है यह बहुत ही सराहनीय है । महतारी सदन के लिये 50 करोड़ रुपए का प्रावधान आपने किया है । गांव की हमारी माताओं-बहनों के बैठने के लिए 25 लाख-30 लाख रुपए का एक-एक भवन अगर बनेगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए

और मैं खासकर मातृ शक्तियों से तो यह कहता हूं कि आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि आपके क्षेत्र की बहुत सी माताओं और बहनों को गांव में बैठने की जहां जगह नहीं है वहां उनके लिए जगह देने की इस दूरगामी सोच के साथ वित्त मंत्री जी ने इसको किया है । डी.एम.एफ. मद से दंतेवाड़ा में medical college, आप डी.एम.एफ. मद का जानते हैं । पिछले 5 साल में डी.एम.एफ. के नाम से बहुत से आरोप-प्रत्यारोप लगे, बहुत सी जांच-पड़तालें हुईं, बहुत से उसके उपयोग और दुरुपयोग की बातें हुईं लेकिन आप दूरगामी सोच के वित्त मंत्री हैं । आपने डी.एम.एफ. का पूरा पैसा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है दंतेवाड़ा जैसे सुदूर रिमोट एरिया में आपने medical college खोलने के लिए इसमें प्रावधान किया है । धान का हम समर्थन मूल्य में लेते हैं, धान के समर्थन मूल्य के बारे में आपने भी दिया । आपने 4 किश्त में दिया, हमने यह बोला कि हम एक-बार में ही देंगे उसमें भी प्रश्न उठा लेकिन सबको पैसा दे दिया गया और धान की कीमत 3100 रुपए कुल में मिलाकर के पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा धान की कीमत देने वाला अगर कोई प्रदेश है तो वह छत्तीसगढ़ प्रदेश है और किसानों को इससे ज़्यादा मदद करने वाली कोई दूसरी सरकार पूरे हिंदुस्तान में नहीं है चाहे वह कोई भी प्रदेश हो ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धान के अलावा अब तिलहन और दलहन को भी MSP में खरीदने का प्रावधान किया गया है । यह भी किसानों के हित के लिए है । पेट्रोल को एक रूपया सस्ता में, अभी संगीता जी कहां गयीं ? एक रूपया क्या होता है ? आपको एक रूपया लग रहा है, 2 लीटर पेट्रोल का 2 रूपया कम हुआ । पूरे प्रदेश में जब पेट्रोल की बिक्री होगी, जब petrol के दाम में लाखों रूपये की कीमत कम होगी तो उनसे पूछिए और महीने में उनका जितना पैसा बचेगा उसका फ़ायदा उनको समझ में आएगा ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- राज्य सरकार 19 रुपए लेती है । माननीय सभापति महोदय, एक्साईज ड्यूटी 19 रुपए 48 पैसे हैं । आप स्टेट का 1 रुपए कम कर रहे हैं । आप उसमें 5 रुपए कम कीजिए न और 57 रुपए अभी रेट पर पेट्रोल की खरीदी हो रही है । 27 परसेंट वेट टैक्स है, उस पर कम क्यों नहीं कर रहे हैं ? 19 रूपए 48 पैसे पर केवल एक रूपए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अटल जी, मैं समझ गया । ज्ञान देने की बजाय पहले यह तो बताओ कि क्या आपने 5 साल में 50 पैसे भी कम किया था ? क्या 5 साल में 50 पैसे भी कम किया था ? अगर पचास पैसे भी कम करते तो 5 रुपए की मांग आपकी जायज होती, अगर इस सरकार ने 1 रूपये की कोशिश की है तो वह आगे चलकर 5 रूपये भी हो जायेगा लेकिन अभी तो आप 1 रूपया जो कम किए हैं, उसकी तो तारीफ करिए । (मेजों की थपथपाहट) रायपुर से दूर्ग तक metro चलाने के लिए सर्वे, अरे भई आपने सर्वे क्यों नहीं करा लिया था ? दुर्ग-भिलाई और रायपुर तो अब एक शहर हो चुका है । लोगों को जाने में कई घंटे लगते हैं, आधे घंटे में आदमी दुर्ग पहुंच जाएगा, भिलाई पहुंच जाएगा, वहां के लोग आएंगे तो अगर उसके लिए सर्वे का प्रयास जारी कर रहे हैं तो आज अगर सर्वे नहीं होगा और जब भी

सर्वे नहीं होगा तब तक वह metro की परिकल्पना साकार नहीं हो सकेगी और छत्तीसगढ़ में रायपुर से दुर्ग के बीच में ही metro चलना सुविधाजनक भी है, उपयोगी भी है और ज़रूरत भी है । इस सर्वे के लिये आपने वित्त मंत्री जी, अरे दिल्ली में, बम्बई में, नागपुर में, लखनऊ में सब जगह चल रहा है । हमारी राजधानी में भी चले पर प्रयास तो करिए। एक पत्थर तो उछालिए, कोशिश तो करिए । आपने 5 साल में कोशिश भी नहीं की । अब वह कर रहे हैं तो आपको तकलीफ़ हो रही है । एक रुपया कम कर दिए तो 10 होना चाहिए, 10 कम कर देंगे तो 15 होना चाहिए यह कोई अंत नहीं होता है । ईमानदारी की कोशिश दिखनी चाहिए । ईमानदारी से प्रयास जो हो रहा है उसको सराहना चाहिए । आपके यहां भी जैसे अच्छा काम हुआ था, मैंने इस सदन में यही बोला था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी थे तो आपने गांव के अंदर मुख्यमंत्री ग्राम गौरवपथ की जो शुरूआत की थी, वह बेहतरीन था, उसको इस सरकार ने नकारा नहीं है। इस सरकार ने उसको स्वीकार लिया। आपके अच्छे काम से हमको कोई नफरत नहीं है। आपके अच्छे काम से कोई मतभेद नहीं है। आपके अच्छे काम मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ को इस सरकार ने सहज स्वीकार किया, क्योंकि वह गांव के अंदर सुविधा देने वाला एक प्रोजेक्ट है और उसके लिए हमने किया। महतारी वंदन योजना में पहले 3500 करोड़ रूपये का प्रावधान था, अब 5500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अब महतारी वंदन ही तो इस प्रदेश का गेम चेंजर है और याद रखिए अभी तो 1000 मिल रहा है, हो सकता है ये सरकार कुछ दिनों के बाद इसको और बढ़ा देगी। आपके पास कोई काट भी नहीं है। महतारी वंदन योजना अचूक बाण है, जो आपको वहीं पर बैठने के लिए विवश कर देगी। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण के लिए भी है, शहर के लिए भी है। कृषि पंपों के नि:शुल्क विद्युत प्रदाय के लिए 35 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। किसान सम्मान निधि 10 हजार रूपये देने का भी प्रावधान किया गया है। 06 फिजियोथेरेपी के कॉलेज खुले हैं। अब इसमें आपको लगेगा कि 06 फिजियोथेरेपी के कॉलेज तो हैं। जरा चोट लग जाए, उस वक्त जब डॉक्टर बोलता है न, फिजियोथेरेपी कराओ तब पता चलता है। गांव में रहने वाले किसी आदमी को अगर फिजियोथेपी कराना है तो वह शहर आता है। आने-जाने का खर्चा और मुसीबत होती है और फिजियोथेरेपी ही उसका इलाज होता है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट उस कॉलेज में बनेंगे तो फिजियोथेरेपी का प्रचार-प्रसार गांव तक होगा और गांव में लोगों को सुविधा मिलेगी। वह रोजगार भी कमाएगा, वह गांव में लोगों की सेवा भी करेगा और हमको सुविधा से भी वंचित नहीं होना पड़ेगा और हमारे यहां लोग आएंगे।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज ये मार्गदर्शक मंडल मन ला फिजियोथेरेपी के जरूरत हे। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या बोले?

श्री रामकुमार यादव :- महाराज, मैं कहे हव कि मार्गदर्शक मंडल मन ला फिजियोथेरेपी के जरूरत हे। रगड़े अउ घसरे के उही जरूरत हे ए मन ला।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोला अभी आई.वी.एफ. वाला ला भाषण में बताए हों न। ओहा तोरे बर हे। ओखर लाभ उठा तेहा।

श्री धर्मजीत सिंह :- फिजियोथेरेपी की किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। यह हंसने की बात नहीं है। अगर अभी कुछ चोट लग जाए न तो फिजियोथेरेपी सेंटर में पता चलेगा कि फिजियोथेरेपी का महत्व क्या है, इसलिए इस महत्व को समझिए। सिर्फ 06 फिजियोथेरेपी कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन इसमें पढ़-लिखकर जो बच्चे निकलेंगे, वे हजारों लोगों की सेवा करेंगे और रोजगार पाएंगे। इसलिए फिजियोथेरेपी का सम्मान करिए। शराब की बिक्री का भी दाम कम कर दिए हैं। वित्त मंत्री जी विदेशी शराब का कुछ कम किए हैं क्या? अभी नहीं है क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन आजकल आप तो उससे दूर हो गए हो क्या? (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, मुझे कई की चिंता है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- तुमन आपस में गोठिया ले करव गा। खड़े होके गोडिया थव।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं उसको अभी दूसरे तरीके से बोल लेता हूं। अगर इसको नहीं किये है न तो थोड़ा कम करिए। अभी सदन में बार-बार प्रश्न उठता था कि हरियाणा का आ रहा है, बंगाल का आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, उड़ीसा से आ रहा है, अब वहां सस्ता मिल रहा है, इसलिए आ रहा है न। यहीं सस्ता कर दीजिए और पीयो जिसको जितना पीना है। कोई दिक्कत नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कुंवर जी, आदरणीय धर्मजीत भैया ने कभी नहीं छिपाया न। ऐसा नहीं है कि कुछ हिडन एजेंडा है। वे 20 साल में 10 बार हाउस में बोल चुके होंगे, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बिल्कुल नहीं छिपाता। अमरजीत भगत जी ने मुझसे पूछे कि आप पीते हैं या नहीं? मैंने कहा कि मैं तो पीता हूं और आप ही के संग पीया हूं, अब आपको याद नहीं है तो मैं क्या करूं? (हंसी) मुर्गा खाते हो या नहीं? मैंने कहा कि मैं खाता हूं, मुर्गा की मम्मी को भी खाता हूं, उसके बच्चे अंडे को भी खाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है और खाने-पीने का जो भी है, सब खुला होना चाहिए। बिंदास जीवन जीना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है, इसको बिंदास जीना चाहिए। बहुत कथरी ओढ़ के और घी खाने वाला काम नहीं करना चाहिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि हम 5 साल में बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आपने खींचते-खींचते आखिरी के साल में दिया और वह भी कुछ हजार लोगों को दिया । बेरोजगारों के संग [xx] तो आपने किया । शराब बंदी की बात की । गंगाजल उठाकर भी कसम खाई थी, ऐसा बोलते हैं, मैं तो जानता नहीं ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- गंगाजल की कसम किसी ने नहीं खाई थी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- चलिए, यमुना जल होगा, अरपा का जल होगा, कोई भी जल होगा । अगर

नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने कहा था शराब बंदी, उसको आपने नहीं किया । उस दिशा में भी कुछ हो सके तो कर लीजिएगा साहब ।

श्री कुंवर सिंह नेताम :- यहां तो लगातार शराब की भट्ठियां खुल रही हैं । आपने भी बात बंद करने की बात कही थी, लगातार धरना, प्रदर्शन किया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी शराब बंदी की बात चल रही है । अगले हफ्ते होली है । मंत्री जी, बैठे हैं । सदन के लोग टेस्ट लेते हैं । माननीय मंत्री जी, शराब बंदी, गंगाजल क्या-क्या चल रहा है, अगले हफ्ते होली है । जो सदस्य चाहते हैं वे मुझसे मिल लें ऐसा आप बोल दीजिए । सबके लिए होली का इंतजाम हो जाएगा ।

श्री रामकुमार यादव :- चौधरी साहब, कोको कोला ला नइ पिय आदमी हा तुम्हर दारू ला मिसा के पिही । छत्तीसगढ़ का दरवहा बना दे हौ दरवहा । दारू के रेट ला कम करके छत्तीसगढ़ का दरवहा बनाए के काम करत हौ ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं ईमानदारी से बताऊं, आप भले विश्वास नहीं करोगे । चुनाव में तो लगता ही है । मैं बहुत कोशिश किया कि सरकार की तरफ से कुछ मिले लेकिन वाह रे वित्त मंत्री, एक पव्वा नहीं दिया आपने, मान गया (हंसी) । होली की व्यवस्था करेंगे तो ठीक है ।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति जी, मेरे क्षेत्र में तो ऐसा है कि दारू कम पड़ गया तो छिन्द रस की शुरूआत कर दिया अभी वर्तमान सरकार ने ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मेरे बाप, हम छिन्द कहां से लाएं, हम ताड़ी कहां से लाएं? हमारे यहां तो हैंडमेड बन रहा है, लोफंदी में तो लफड़ा हो गया था, कुछ लोग गड़बड़ सड़बड़ हो गया था, वह छोड़िए वह सब हंसी मजाक की बात है । कुल मिलाकर कोई भी सरकार जनता के हित के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए बजट लाती है । एकाध दो खामियां कहीं हो सकती है लेकिन इरादा नेक रहता है, सोंच अच्छी रहती है, सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को लाया है और वित्त मंत्री जी का व्यक्तिगत व्यवहार, योग्यता और उनका ईमानदार प्रयास छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर ले जाएगा । मैं समझता हूं कि इस बजट के माध्यम से अगले एक साल छत्तीसगढ़ को विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाने में सफल होंगे । आप सबसे भी आग्रह है वित्त मंत्री जी आप सबके बीच के ही हैं । आपके ही गांव के बेटे हैं, उनकी इस सोच को उपहास में मत लीजिए, आप रचनात्मक विरोध करिये । तुलसी दास जी ने कहा है, बड़े बड़े संतों ने कहा है निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटि छबाय । बिन पानी, बिन साबुना, निर्मल करे सुहाय । अगर आपकी आलोचना नहीं होगी, अगर आप सचेत नहीं करेंगे । अगर आप खिलाफ में नहीं बोलेंगे, अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो इस बजट का भी मजा नहीं आएगा । हम लोगों के यहां बैठने का भी मजा नहीं आएगा । लेकिन बात बात में आप लोग दिन भर के लिए चले जाते हो, अपना कार्यक्रम देखने के लिए । ऐसा मत

करिए, पूरी तरह से भाग लीजिए, पूरी तरह से बोलिए, विरोध करिए, डटकर विरोध करिये । यह सरकार विष्णुदेव साय के नेतृत्व में साफ सुथरे दिल दिमाग से सुशासन की दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है । आपको एक एक बात का जवाब मिलेगा । आपके हर प्रश्न का जवाब इस सरकार के पास है । वित्त मंत्री की इच्छा शक्ति, नीति, नीयत सब साफ है । वे जरूर आपकी बातों का जवाब देते हुए सरकार के कामों को आगे बढ़ाएंगे । सभापति महोदय, अपने मुझे वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद् ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय सभापति महोदय, यह बजट अभी माननीय ओ.पी.चौधरी जी ने प्रस्तुत् किया । हम लोग विपक्ष में हैं तो विरोध करने के लिए ही खड़े होंगे । यह पहली बार हुआ है कि हस्त लिखित बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत् किया । सभापति महोदय, वित्त सचिवालय का काम अब खुद वित्त मंत्री करने लगे हैं । जो लिखाई पढ़ाई का काम है, इतनी गोपनीयता कि अपने सचिवालय पर ही विश्वास नहीं है । इसलिए इस बजट को उन्होंने अपने हाथ से लिखा यानी विश्वास की कितनी कमी है । यह 100 पेज की रफ कॉपी है। माननीय सभापति महोदय, कम से कम भाषा का तो ध्यान रखते, क्योंकि यह दस्तावेज है, ये हमेशा रहेगा लेकिन आपने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, वह बहुत हास्यास्पद है। आप हिंदी को अंग्रेजी में लिख रहे हैं, अंग्रेजी को हिंदी में लिख रहे हैं, आप कहें तो मैं उदाहरण भी दे सकता हूं, आप पेज नंबर 97 देख लीजिए। कम्प्लायंस बर्डन और ईज ऑफ डूईंग बिजनेस। यह आप हिंदी में लिख रहे हैं, उसी के नीचे अंग्रेजी में लिख रहे हैं। आपने भाषा का क्या मजाक बनाकर रखा है। आपने शुरूआत ही असत्य कथन से किया। रायपुर एयरपोर्ट में पहले 6 फ्लाइटें आती थी, अब 76 आती है। मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से पता किया, रायपुर में 28 फ्लाईटें आती हैं, किसी दिन 26 किसी दिन 30 फ्लाईटें आती हैं, आपने 76 फ्लाईट कहां से लाई? ओ.पी. जी कितना भी फेंकने की कोशिश करोगे लेकिन आप दिल्ली वाले जितना नहीं फेंक सकते। 76 फ्लाईट कहां से आ गया ? आपने शुरूआत में ही कहा। दूसरी बात, उन्होंने दूसरी बात कही कि हमने रिकॉर्ड तोड़ा, कैसे रिकॉर्ड तोड़ा। हमने 10 में से 10 नगर निगम जीता। हमने भी पिछले समय 10 में से 10 नगर निगम जीता था, बाद में 4 चुनाव और हुए तो 14 में से 14 जीते। आपने रिकॉर्ड बनाया है तोड़ा क्या ? ऐसा नहीं है कि आप 10 में से 11 जीत गए, आप किस प्रकार की बात कह रहे हैं। सभापति महोदय, ये सरकार जितनी भी उपलब्धियां हैं, 25 साल की उपलब्धि को अपने खाते में ले रही है। आपने कहा कि इतने मेडिकल कॉलेज खुले, पहले एक मेडिकल कॉलेज था, फिर जोगी जी के समय में 2 मेडिकल कॉलेज हुआ, रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल में 6 मेडिकल कॉलेज खुले, हमने पांच साल में 6 मेडिकल कॉलेज खोला। आपने कितने मेडिकल कॉलेज खोल ली ? आप अपने खाते में क्यों डाल रहे हैं। आप लगातार असत्य पे असत्य बोल रहे हैं। आप भाषण निकालकर देख लीजिए, अभी सब लोग 18 लाख आवास, 18 लाख आवास बोल रहे हैं। जब योजना बनी, सर्वे हुआ तब भी 18 लाख आवास था। आज भी आपकी सरकार ने आवास दिया, हमारी सरकार ने भी आवास के 7 लाख दिए। आपके समय

11 लाख आवास बना, हमने 7 लाख आवास बनाया। ये आवास प्लस की बात है। आप पंचायत मंत्री रहे हैं, आपने इसकी शुरूआत की। उस समय से बनना शुरू हुआ, उस समय भी 18 लाख आवास थे, आज भी कह रहे हैं कि 18 लाख आवास है, इसका मतलब जो बना है, वह आवास बना ही नहीं। सभापति महोदय, अभी आपने 6 लाख से उपर 7 लाख से कुछ कम राशि जारी की। कितना आवास बना है, कितने लोग गृह प्रवेश किए हैं ? मात्र 13 हजार लोग गृह प्रवेश किए हैं, मेरे प्रश्न के उत्तर में है, मैं आपको कॉपी दे दूंगा, 13 हजार मकान ही कम्प्लीट हुए। आपकी कितनी स्पीड है, ये भी पता चलता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा केवल आलोचना करना नहीं है। बजट प्रदेश के विकास का दर्पण होता है। हम किस दिशा में जा रहे हैं। आपने पिछले समय ज्ञान की बात की, अब ज्ञान के कल्याण की बात हो रही है। यदि गति की दिशा न हो तो दुर्घटना होना तय है, आपने दिशा क्या ली है। कल अमर अग्रवाल जी ने प्रारंभिक उद्बोधन दिया, बजट के पक्ष में भाषण दिया, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा, आपने लोन लिया, हमारे समय 43 हजार करोड़ था, आपने उसे 80 हजार करोड़ से उपर पहुंचा दिया, 40 हजार करोड़ रूपए लोन लिया, लोन लेने में बुराई नहीं है लेकिन आपने खर्च कहां किया है ? माननीय सभापति महोदय, अनुभव भी कोई बात है। हमने अनुभव से देखा कि बजट 5 हजार करोड़ रूपये से 60-70 हजार करोड़ रूपये तक पहुंच गया है, लेकिन आज किसान आत्महत्या कर रहा है, लोगों की भूख से मौत हो रही है, लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही है और बस्तर में स्कूल बंद हो रहे हैं। बस्तर में 3000 स्कूल बंद हो गये। उस स्थिति में हम लोगों ने पिछले समय जो तय किया कि विकास केवल कांक्रीट की बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, बल्कि विकास मानव के विकास से भी होता है और वह भी आवश्यक है। बिल्डिंग जरूरी है, सड़क भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ मानव का विकास भी होना चाहिए। सभापति महोदय, जब हमने सत्ता संभाली थी तो 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे थे। पूरे देश में छत्तीसगढ़ सबसे अव्वल था। 40 प्रतिशत। अब तो जनगणना होनी ही बंद हो गई है तो पता ही नहीं चलता है। वर्ष 2021 में जनगणना होनी थी। उससे पता चलता कि कितना कम हुआ, क्या हुआ ? लेकिन उस समय भी 18 लाख आवासहीन लोग थे। वह सब सरकारी आंकड़े हैं। उस समय हम लोगों ने कहा कि सबसे जरूरी यह है कि यह किसानों का प्रदेश है और हमने किसानों को ताकतवर बनाया। किसान एक धुरी है, जहां वह मजदूरों को भी रोजगार देने का काम करता है, वही उद्योग और व्यापार को चलाने में भी सहयोग कराता है।

श्री अजय चंद्राकर :- आप किसानों का उल्लेख कर रहे हैं। मैं आपको आपके समय का आर्थिक सर्वेक्षण दिखा सकता हूं कि आपके कार्यकाल में irrigation का रकबा भी घटा है और कृषि का रकबा भी घटा है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, इसलिए हमने यहां किसानों की ऋण माफी की और 2500 रूपये प्रति क्विंटल में धान की खरीदी की। अड़ंगा केन्द्र सरकार से लगा कि पूरे देश में जो

भी सरकार यदि किसानों को बोनस देगी तो हम उसका चावल नहीं खरीदेंगे। हम लोग यहां से गये भी थे। उस समय पीयूष गोयल जी खाद्य मंत्री थे। हमारी उनसे बात भी हुई। उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे और आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम धान को मार्केट में बेच देंगे, लेकिन किसानों को बोनस देकर रहेंगे और हमारा जो धान को 2500 रूपये में लेने का वायदा था, उसको हम पूरा करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) हमने अपना वायदा पूरा किया। सभापति महोदय, हम केवल 2500 रूपये तक नहीं रूके, बल्कि हमने उसकी कीमत को 2640 और 2800 रूपये तक पहुंचाया। आज यदि किसानों को धान का 3100 रूपये मिल भी रहा है तो पिछली सरकार के कड़े कदम उठाने के कारण से मिल रहा है। (मेजों की थपथपाहट) आपकी नीयत तो नहीं थी। आप तो समर्पण करवा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो। हमने केवल धान उत्पादक किसानों की सहायता नहीं की, बल्कि मक्का, गन्ना, मिलेट से कोदो, कुटकी, रागी और जो भी बोते हैं, उसको भी हमने प्रति एकड़ 10000 रूपये दिये। आज आपने केवल धान के 3100 रूपये दिये हैं। अभी मैं बजट में देख रहा हूं कि आपने गन्ने के बोनस के लिए इसमें 60 करोड़ रूपये रखा है। बचत जो मिलेट्स कोदो, कुटकी, रागी बोते हैं, आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं ? जो बरसात में सब्जी बो रहे हैं, उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? जो मक्का बो रहे हैं, उनको क्यों नहीं दे रहे हैं ? आपने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को बंद कर दिया। यही कारण है कि जो लोग बरसात में सब्जी लेते थे और जो लोग बरसात में मक्का बोते थे, अब वह सब खेत धान में पलटने लगे हैं। कृषि में विविधीकरण की जो बात है, वह स्वयं आपकी नीति के कारण समाप्त हो रही है। जो दूसरे फसलों की तरफ जा रहे थे, उसमें रूकावट आ गई।

माननीय सभापति महोदय, लघु उपज की खरीदी। आप कहां 17 लघु उपज खरीदते थे, उसको हमने 65 तक पहुंचाया है। आप ही के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के समय में काजू प्रोसेसिंग प्लांट बंद पड़ा था। उड़ीसा, जयपुर के सारे व्यापारी उसको 50 रूपये किलों में लेकर जाते थे। हमने उसकी शुरूआत की और उसी प्रकार से हमने अनेक मिलेट से लेकर सब चीजों को खरीदना शुरू किया। उसके कारण से बस्तर के लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। सभापति महोदय, उसी प्रकार से गौपालन किया। हमने गोबर खरीदा, आप भले ही परिहास कर लें, लेकिन उससे 5 लाख लीटर दूध उत्पादन बढ़ा है। चरी-चरागन हो रहा था, उसमें रूकावट आई थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है ? गौ तस्करी बढ़ गया है, वसूली चल रहा है। रायपुर में ही गौ मांस बिक रहा है। यह स्थिति आपकी नीति के कारण से हो रहा है। इसीलिए कह रहा हूं कि नीतियां ही दिशा देती हैं। माननीय सभापति महोदय, आप गति की बात कर रहे हैं। बिना दिशा के एक्सीडेंट होना है, दुर्घटना होना ही है।

माननीय सभापति महोदय, उसी प्रकार से हमने जितनी भी योजनाएं लागू की, उसका फायदा किसानों को हुआ, छत्तीसगढ़ के लोगों को हुआ, व्यापार-व्यवसाय को हुआ, उद्योग को हुआ। आप बस्तर

की बात कर ले। मेरे पास बस्तर के आकड़ें भी हैं। मैंने सदन में भी रखा। मैंने बीजापुर का उदाहरण भी दिया कि वहां 16 ट्रैक्टर से ज्यादा नहीं बिकता था। आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिकार्ड निकलवाकर देख लीजिये। जहां हमने ऋण माफ किया, 2500 रूपया क्विंटल में धान खरीदना शुरू किया, वन अधिकार पट्टा दिया, लघु वन उपज की खरीदी की तो वहां एक साल में 4 सौ ट्रैक्टर बिके। (प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) पूरे देश में आटोमोबाइल के जितने शो रूम थे, वहां शटर डाऊन हो रहा था। कोरोना काल में फैक्ट्री ने उत्पादन कम कर दिया था। उस समय छत्तीसगढ़ में कम्पनियां न ट्रैक्टर, न मोटर सायकिल, न कार की सप्लाई कर पा रहे थे। यह हमारे नीति के कारण से हुआ था।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात इसी से जुड़ा हुआ है। यदि आज नक्सलवाद की बात करें तो नक्सलवाद में लड़ाई किस बात की थी ? जल, जंगल, जमीन की लड़ाई थी। हमने जमीन का अधिकार भी दिया, जमीन वापस भी किया और लोगों को सक्षम भी बनाया, रोजगार भी दिया। उसका क्या फायदा हुआ ? नक्सलियों की भर्ती रूक गई। उनको जवान नहीं मिल रहे थे। उनके पत्र मिले और आज आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद मार्च, 2026 में खत्म कर देंगे। हम लोग देखेंगे, निश्चित रूप से हम लोग भी इंतजार करेंगे और नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। क्योंकि एक गृहमंत्री, ननकी राम कंवर जी केवल छः महीने में समाप्त करने की बात की थी। लेकिन वह छः महीना, छः साल क्या, सोलह साल बीत गया, लेकिन नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ। नक्सलवाद समाप्त हो, लेकिन उस स्थिति में कि वहां के लोगों को रोजगार मिले। बहुत अच्छी बात है आपने 3 हजार बस्तर फाइटर भर्ती की घोषणा की है। हमने भी भर्ती किया था। एक हजार से अधिक लोगों की बस्तर फाइटर में भर्ती की थी। सभापति महोदय, अब मैं उसमें आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। बस्तर फाइटर्स की भर्ती तो हो, लेकिन उस भर्ती को जिलों में बांट दीजियेगा, ताकि कांकेर जिले के लोगों की भी भर्ती हो तो सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के नवजवानों को भी मौका मिलना चाहिए। आप इस प्रकार की नीति बनाये ताकि वहां के लोगों को भी रोजगार मिले, वहां के लोगों को नौकरी मिले, यह कोशिश होनी चाहिए।

समय
4.48 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि यह अमृतकाल का बजट है। आप शेयर मार्केट के खिलाड़ी भी हैं। हमने आपके करोड़ों कमाने का वीडियो भी देखा कि लोग करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन अभी लोगों के 96 लाख करोड़ रूपये डूब गये। सन् 1996 के बाद यह पहली बार है, फिर चाहे nifty हो, चाहे share market हो, गोते पर गोते, गोते पर गोते, गोते पर गोता लगा रहा है। लोगों के 96 लाख करोड़ रूपये डूब गये। यही अमृतकाल है ? निवेशक यहां से पैसा निकाल-निकाल कर ले जा कर चीन में निवेश कर रहे हैं। यहां से एक लाख करोड़ निकाल रहे हैं और वहां दो लाख करोड़ निवेश कर रहे हैं। तो

आपकी नीति क्या है ? आपके यहां से पैसा क्यों निकाल रहे हैं ? आप अमृतकाल की बात कर रहे हैं। अभी एक पत्रकार ने फिटनेस की बात कर ली तो चिंता हो गई। धर्मजीत भईया, चिंता तो इस बात की होनी चाहिए..।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह पत्रकार नहीं था।

श्री भूपेश बघेल :- वह कांग्रेस का प्रवक्ता है। चलिये, वह कांग्रेस का प्रवक्ता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब कल फिटनेस की बात हुई थी तब आप नहीं थे।

श्री भूपेश बघेल :- आपको फिटनेस बहुत बढ़िया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नेता जी ने अपनी फिटनेस बताई कि उनका फिटनेस बहुत अच्छा है। आप बताईये कि आपकी फिटनेस कैसी है?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- मैंने कुछ नहीं बताया। आपने मुझसे पूछा और आपने मेरे Experience का हवाला दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपसे वही चीज पूछ रहा हूं कि आपकी फिटनेस कैसी है?

डॉ. चरणदास महंत :- अब वह आपके सामने आ गये हैं। आप निपट लीजिये। वह अभी तक तो नहीं थे। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- निपटने का समय आएगा तो निपटेंगे न। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जो सज्जन बोल रहे हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। लोगों की गरिमा यह कहती है कि यदि कोई पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहा है तो बार-बार ना टोके, लेकिन यदि आप नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी में बैठे हैं तो आप उनको बता दीजिये कि छत्तीसगढ़ के बजट में हो चर्चा रही है, न कि अंतर्राष्ट्रीय शेयर मार्केट में चर्चा हो रही है।

डॉ. चरणदास महंत :- मैंने भी देखा है कि आप भी छत्तीसगढ़ के बजट में कितना चल रहे थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मेरा भाषण निकाल कर देख लीजिये। मैंने एक भी लाईन इधर-उधर नहीं बोला है।

श्री रामकुमार यादव :- हमन पांच साल देखे हावन। आप बजट में एक भी नई बोलत रहे हौ।

डॉ. चरणदास महंत :- आप पूरे छत्तीसगढ़ के बजट के बाहर थे। यह पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और पूर्व वित्त मंत्री भी हैं। आप पूर्व वित्त मंत्री जी को जवाब दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह उस दिन भी अपनी उपलब्धि बता रहे थे और आज भी वही बात हो रही है। आप आगे बढ़िये। आप इस Fantasy से निकलिये। अब मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी बन गये हैं। (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. चरणदास महंत :- हम अपनी उपलब्धि बता रहे हैं और आप विरोध कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने कहा कि मैं ज्यादा नहीं टोक सकता। वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी मुझे इज्जत करनी पड़ेगी। मैं भी संसदीय कार्य मंत्री था।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिये, वह आपसे उम्र में भी बड़े होंगे। आप प्रणाम करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेकिन आप Fantasy से बाहर आईये। सत्ता बदल गई है। आपने क्या-क्या किया है, वह इतिहास बन बया है। जनादेश मिल गया है। अब सुधरिये।

श्री भूपेश बघेल :- बहुत अच्छी बात।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धरम भैया बजट से फिटनेस में चले गये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने पूछा है, उसी का जवाब दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अजय जी, रजत जयंती वर्ष है। हमने 25 साल का यात्रा पूरी कर ली है। अब एक बार मैराथन कराना पड़ेगा। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अजय चन्द्राकर जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आप उस Fantasy से निकलिये। जब आप मेरी तरफ एक उंगली करते हैं तो तीन उंगली आपकी तरफ है। सारे लोगों को भाषण में यह होता है कि पिछले शासनकाल में यह-यह हुआ। इससे आप लोग बाहर निकलिये। अभी वर्तमान में सरकार का कार्यकाल सवा साल हो गई है, आप लोग इसके बारे में चर्चा करिये। यदि आप लोग चर्चा करना छोड़ देंगे तो मैं जवाब देना भी छोड़ दूंगा। (मेजों की थपथपाहट) मुझे जवाब देने का शौक नहीं है। आप सवाल करते हैं इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। जब आप लोग यह तय कर देते हैं कि वर्ष 2022 में सबका मकान बन जाएगा, जब आप लोग कहते हैं कि वर्ष 2027 तक सबके घरों में नल पहुंच जाएगा तब राज्य सरकारों पर दबाव पड़ता है, तब अधिकारियों के ऊपर दबाव पड़ता है तब आप लोग हमें सवाल करते हैं पानी का स्त्रोत है ही नहीं, आपने टंकी कैसे बना दिया। यह दबाव भारत सरकार का है। आपकी सरकार ने ट्यूबवेल की कोई व्यवस्था की है? आपकी सरकार ने पूरे देश में पानी की क्या व्यवस्था की है? आपने शौचालय बनाया। जहां एक लोटा से काम चलता था, अब वहां पांच लीटर लगता है। मैं इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं हूं कि कोई शौच के लिए बाहर जाये। घर में शौचालय होना चाहिए कि लेकिन आपकी सरकार पानी की व्यवस्था तो कर दें। अब वे हर घर में नल लगाने की बात कर रहे हैं। अब पानी है ही नहीं और यदि पानी नहीं रहेगा तो टोटियां ..।

श्री लखेश्वर बघेल :- गांव में एक भी शौचालय नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- आप लोग शौचालय की स्थिति देख लीजिये कि क्या स्थिति है। नल कनेक्शन का भी वही हश्र होने वाला है। स्थिति यह है कि यदि अब हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं तो आपको मजाक सूझता है कि नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी। यही नरवा का कार्यक्रम है, जिसमें विष्णु देव साय जी जाकर पुरस्कार ले रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) आपने अचानकमार में भी जानवर आ रहे हैं तो नरवा

योजना के कारण आ रहे हैं। पानी होगा तो घास भी होगी, वनस्पित भी होगी, उसके बाद सभी जानवर भी आयेंगे। वहां खरगोश भी होगा, हिरण भी होग, भालू भी आयेंगे और जब सब कुछ हो जाएगा तो आखिरी में शेर आएगा। शेर तभी आता है जब सब कुछ हो जाये। शेर के आने का मतलब यह है कि वहां पर प्राकृतिक रूप से सारी व्यवस्था है। राजा तभी आता है जब सारी व्यवस्था हो जाती है। जब अचानकमार में चाहे हाथी, चाहे भालू आना शुरू हुआ हो, चाहे अभी शेर आने की बात हो, उसका कारण यही है। हमने काम की है, उसका इनाम आप लोग ले रहे हैं। यह अच्छी बात है। आपको इनाम लेनी चाहिए। पिछली सरकार ने अच्छा काम किया है उसका आप इनाम लीजिये। हमने जो काम किया है उस लकीर से आप बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं। हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्मय विद्यालय खोला, उसको आपने पी.एम. श्री स्कूल योजना कर दिया। हमने हॉट बाजार क्लिनिक योजना में जो हॉस्पिटल का जो रंग किया था, आपने उसका रंग बदल दिया, लेकिन क्या आप योजना बंद कर पा रहे हैं? आप कोई योजना बंद नहीं कर पा रहे हैं । आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या सोच है, आपने 1 जनवरी को 3000 बच्चों की नौकर खत्म कर दी है ? क्या आपके पास पद की कमी है, सारे सिलेक्ट हुये थे, उसको किसी जगह रख लेते, आप कोर्ट में जवाब दे देते कि हम इसको दूसरे जगह रखेंगे । सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, वह ठीक है, इसे मानते हैं, लेकिन यह हमारे ही बच्चे हैं । अध्यक्ष महोदय, अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के एनएचआरएम में क्या हो रहा है, जो महिलायें 15 साल से, 20 साल से महिलायें काम कर रही थी, आज चार-चार, पांच-पांच महीना का तन्ख्वाह नहीं मिल रहा है, तन्ख्वाह भी नहीं दे रहे हैं और निकाल भी नहीं रहे हैं, यह कौन सा तरीका है ? अध्यक्ष महोदय, आपने योजना को जारी रखा है, चना नहीं बॉट पा रहे हैं, बस्तर में गुड़ नहीं दे पा रहे हैं, क्या स्थिति है ? अध्यक्ष महोदय, रेडी टू ईट के बारे में कहते हैं कि हम खत्म कर देंगे, साल भर बीत गया, आपको किसने रोका है ? अध्यक्ष महोदय, अभी भी बजट में क्या कह रहे हैं कि हम क्रमश: करेंगे, क्रमश: कब करेंगे 5 साल तक ? पहले भी महिला स्व-सहायता काम कर रही थी, आप उसको दे दीजिए, रोका किसने है, फिर क्रमश: की बात कहां से आ गई, एक झटके में निर्णय करिये, उसका इम्पलीमेंट करिये, क्रमश: का क्या मतलब है, आपकी क्या नीयत है ? अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि आपके पास दिशा नहीं है, गतिहीन है, रोजगार के लिये कोई बात नहीं है । अभी आपने रीपा बनाया, शहरों में सी-मार्ट बनाया, आप सब निजी हाथों में दे रहे हैं, निजी हाथों में देने की बात हो रही है ? अध्यक्ष महोदय, रोजगार कैसे मिलेगा, मैं जानता हूँ । सरकारी नौकरी सब को नहीं मिल सकती है । 10 हजार देंगे, 20 हजार देंगे, 30 हजार देंगे, 40 हजार देंगे, उससे ज्यादा क्या देंगे, उसकी सीमा है । अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां वेल्यू एडिशन करने की बडी संभावनायें हैं, उससे लोगों को रोजगार मिले, वह काम तो आप नहीं कर रहे हैं ? भूपेश बघेल ने उस काम को किया है, इस कारण से नहीं करना है, लेकिन भूपेश बघेल ने जो शुरूआत की है, आप उसे रोक पा रहे हो ? आप इसको भी अपना लीजिए । अध्यक्ष महोदय, आपको गौठान के

लिये बनासकाठा का डेरी लाने की जरूरत नहीं है, गांव-गांव में गौठान बन गया है, आप नहीं चला रहे हैं उसके बाद भी लोग वर्मी कम्पोस्ड बना रहे हैं और बिक रहा है । अभी भी बहुत जगह रीपा चल रहा है, उसमें बहुत सारे लघु उद्योग चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं । इसे पूरी ताकत से चालू करिये ना, रोजगार मिलेगा, छत्तीसगढ़ का भला होगा, किसने रोका है, आपको सब भ्रष्ट्राचार नजर आता है, भ्रष्ट्राचार की जांच में क्या कर लिये ? गौठान के भ्रष्ट्राचार की जांच करेंगे, कहां है भई ? रीपा में भ्रष्ट्राचार है, कहां है भई ? नल-जल योजना में भ्रष्ट्राचार हुआ, उसका क्या हुआ ? आपने क्या कार्यवाही कर लिये हैं ? यह स्थिति है । यह दिशाहीन बजट है, इसमें भला होने वाला नहीं है, हमने जो पहले कर दिया, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आपने कर दिया, उसी को खींच रहे हैं । आप हाथ से लिखकर बहुत मेहनत किये हैं, लेकिन भाषा का भी ध्यान नहीं रखा है । अंग्रेजी को हिन्दी में लिख रहे हैं, कई बात तो समझ नहीं आ रहा है ? अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनको भी बोलना है, नेताजी को भी बोलना है, आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि बजट सही दिशा में जाये, यह हमारी कोशिश हो, लोगों को रोजगार मिले । अध्यक्ष महोदय, आपने किसानों को एम.एस.पी. के बढ़े अंतर की राशि तो दी नहीं है, उसे करना चाहिये था । आपके महतारी वंदन योजना में सनी लियोनी के खाते खुल जाते हैं, आपके सुशासन की स्थिति हमने लोहारीडीह और बलौदाबाजार में देख ही लिया है कि आप कितने सक्षम हैं ? अभी पंचायती राज चुनाव हो रहा है, बहुत पीठ थपथपा रहे हैं, अनिला भेंडिया जी को धरना में बैठना पड़ रहा है । अध्यक्ष महोदय, सावित्री मंडावी जी के यहां तीन जगह बैठक आहूत हो गया, सारे जनपद सदस्य बैठ गये, आपकी बहुमत नहीं थी, आपने कैंसिल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, अभी पंडरिया में एक खबर आई है, पंचायत राज का इससे बड़ा मजाक और क्या होगा ? अध्यक्ष महोदय, आप महिलाओं को 50 परशेंट आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन जब पंचों और सरपंचों का शपथ होता है तो महिला पंच के पति शपथ ले रहे हैं, 6 लोग हैं, आपके यहां यह स्थिति है ? आप इसे मजाक बनाकर मत रखियेगा, मैं आपसे कृपा करके यह कहना चाहूँगा कि पिछले समय तो आचार संहिता के बारे में प्रश्न पूछ दिया तो जेल ही भेज दिये ? एक ने सड़क निर्माण के भ्रष्ट्राचार के बारे में सवाल पूछ दिया तो मुकेश चन्द्राकर ऊपर चले गये ।

समय :-
5:00 बजे

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने क्या किया ? अभी आचार संहिता लगी है, आप अधिकारी को लेकर जहाज में बढ़िया घूमने जा रहे हो । जो बड़े ऊंचे पद में हैं, लोग उनसे उम्मीद करते हैं । आचार संहिता लगी है तो बड़े लोगों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, लेकिन वित्त मंत्री जी, आपने कड़ाई से पालन नहीं किया । दुर्भाग्यजनक बात यह है कि मुख्यमंत्री जी को प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है । आज विधान सभा में उनका प्रश्न भी था, आज बजट में उत्तर भी देना है । सभी माननीय सदस्य अपने-अपने

क्षेत्र के बारे में, अनेक योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आज दिन भर से सदन में अनुपस्थित हैं । क्या यही लोकतंत्र का सम्मान है, आप ऐसे ही लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, ऐसे ही सुशासन देंगे ? उन्हें सदन में रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी प्रश्न से भाग रहे हैं । अनेक बार देखता हूं कि जायसवाल जी उत्तर दे रहे हैं, वे हर बात उत्तर देते रहते हैं । यह एक बार नहीं हुआ है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यहीं पर हैं और अभी सदन में आ ही रहे हैं । आप यह मत कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रश्न से भाग रहे हैं । हमारे दल के कोई भी मंत्री प्रश्न से नहीं भाग रहे हैं । आप लोगों के ही कार्यकाल का प्रश्न है ।

श्री भूपेश बघेल :- मेरे कार्यकाल का हो, सरकार में कोई भी बैठे, जवाब तो उन्हें ही देना है, जो वर्तमान में सरकार में बैठे हैं । हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं । मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी सदन में बैठते हैं तो सदन की गरिमा बढ़ती है । आप सदन की गरिमा गिरा रहे हैं। प्रश्न का उत्तर कोई भी मंत्री दे देंगे, उसमें क्या है ? उत्तर सही दे, गलत दे, आधा उत्तर दे, अधूरा उत्तर दे, जैसा भी उत्तर दे। पर्ची आ जाये, उसको पढ़ दे । हम लोग कभी कहते हैं क्या ? अजय चन्द्राकर जी कितने बार बोलते हैं कि मैं प्वाइंटेड प्रश्न पूछ रहा हूं तो प्वाइंटेड उत्तर दीजिए । हम लोग भी अपेक्षा करते हैं कि प्वाइंटेड उत्तर आये । मुख्यमंत्री जी सदन में रहेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों के उत्तर में हस्तक्षेप करके कोई जवाब दे दें, कोई नई घोषणा कर दे । सदन में सबकी अपेक्षा होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी प्रश्न से भाग रहे हैं । एक बार होता तो समझ में आता । हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी की बहुत व्यस्तताएं होती हैं, लेकिन मैं हर बार देखता हूं कि जिस दिन उनका प्रश्नकाल रहता है, उस दिन गायब हो जाते हैं । आप लोग कवासी लखमा जी के बारे में बोलते थे, आज स्थिति यह है कि यह बात मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलना पड़ रहा है । यह बेहद दुर्भाग्यजनक बात है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खेल के बारे शुरूआत कर रहा था, लेकिन थोड़ा डायवर्ट हो गया था । मैं आखरी बात बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं । यह बहुत ही गंभीर बात है कि कोई अमृतकाल की बात, खिलाड़ियों की बात, देश-विदेश की बात सब हो गई । एक विदेशी राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा दें, यह कितनी लज्जा की बात है । क्या हमें जवाब नहीं देना चाहिए ? हमें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए । वह कौन होता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा दे, लेकिन एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं । क्यों नहीं ? भारत इतना कमजोर हो गया ? जवाब देना चाहिए । मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, आज सभी सदस्यों ने अपनी पूरी-पूरी बात कर ली । मेरे लिए कुछ नहीं बचा है । माननीय वित्त मंत्री जी जिस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर हैं । वे चले गए हैं क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- आप अपनी बात जारी रखिए, वे आ रहे हैं ।

(माननीय मुख्यमंत्री का सदन में आगमन)

डॉ. चरण दास महंत :- आपका स्वागत है सर । आपने मेरा सम्मान बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद । आपके वित्त मंत्री जी आंकड़ों के जादूगर हैं या आंकड़ों के बाजीगर हैं ? ठीक शब्द है ?

अध्यक्ष महोदय :- आज अजय से बार-बार प्रतिक्रिया मत पूछिए, फिर वह लगातार प्रतिक्रिया देने लगेंगे। आप इधर देखकर बोलें क्योंकि अब सी.एम. साहब आ गए हैं, आपका चेहरा यही होना चाहिए।

डॉ. चरण दास महंत :- आपको न देखूँ सर? (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आप मुझे देखकर बोल सकते हैं, पर आप उधर मत जाइए।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, वि□□त्त मंत्री जी motivational speaker हैं। उन्होंने बड़े अंदाज में जिस ढ़ंग से राजनीतिक भाषण दिया है, मैं कोशिश करुंगा कि उन्हीं के पन्नों को देख-देखकर बात करूं, ताकि चन्द्राकर जी यह न कह सकें कि मैं किताब से बाहर बात कर रहा हूं। जहॉ तक चन्द्राकर जी का सवाल है, वह बहुत गणितबाज़ हैं। गणितबाज़ शब्द असंसदीय भाषा नहीं है, इसलिए आप बुरा मत मानिए। वित्त मंत्री जी आ गए हैं, उनके आंकड़े की बाज़ीगरी को..।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी बात का तो मैं कभी बुरा नहीं मानता, सबको बता दिया हूं कि मेरे आपके तो अवैध संबंध हैं। (हंसी)

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है। वित्त मंत्री जी, आपने गणित की जो कलाबाजियॉ दिखाई हैं, उस पर हमारे उमेश पटेल जी, भाई राघवेन्द्र जी ने अपनी बात कह दी हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आपने छत्तीसगढ़ के बारे में एक यशोगान किया, उसका मैं जरुर उत्तर अपने शब्दों में नहीं बल्कि लक्ष्मण मस्तुरिया जी के शब्दों में देना चाहता हूं। आप पक्के छत्तीसगढ़िया हैं, समझ जाते होंगे।

मोर रग रग म हे मया दया
मैं महाभारत के गीता अंव,
मोर भुजा म लाखन लोग पलें
मै घर हारे जग जीता अंव
मोर गांव-गांव देवता धामी
अउ सहर-सहर विश्वकर्मा हे
कोरा-कोरा में अभिमन्यु

मोर भीम अर्जुन घर-घर मा हे
मोर हाड़ा बजुर बरोबर रे
मैं वीर दधीचि दानी अंव
मैं छत्तीसगढ के माटी अंव रे
मैं छत्तीसगढ़ के माटी अंव। (मेजों की थपथपाहट)

छत्तीसगढ़ की माटी के बारे में छत्तीसगढ़ी में कहें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। आपने अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद जी को याद किया, बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने आप रामगढ़ की पहाड़ियों में पहुंच गए और प्रेम की रचना लिखने वाले कालीदास जी को याद किया। अक्सर आपके साथ के लोग प्रेम की भाषा को तो जानते ही नहीं हैं, नफरत की भाषा को जानते हैं। मगर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रेम को याद किया। वित्त मंत्री जी, एक बात आपने गलत किया।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रेम को याद नहीं करते साहब, प्रेम को महसूस करते हैं। (हंसी) आप महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, आप जानें पर प्रेम याद करने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की चीज़ है। आप सुधार लीजिए।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, आपने कह दिया, गलती से किया हो तो मैं कहता हूं कि खेद व्यक्त कर देना कि पिछली सरकार ने लोकतंत्र की इसी विश्वास की हत्या की और विश्वास को चोट पहुंचाया। माननीय मंत्री जी, ये थोड़ा आपत्तिजनक है और आपको यह नैतिक अधिकार नहीं बनता कि हमको [xx] का आरोप लगाएं। [xx] किस सरकार में हुई है, सब लोग जानते हैं, मैं इसे यहॉ दोहराना नहीं चाहता।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, भूपेश बघेल जी अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहे थे कि हमारा देश कमजोर हो गया है, प्रधान मंत्री जी कमजोर हो गए हैं, तो जब बजट भाषण में अंतर्राष्ट्रीय बात हो सकती है, तो ऐतिहासिक बात भी हो सकती है। आपने आपातकाल लगाया है, [xx] की है। उसमें क्या बुरा है?

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मैं इनकी किताब पढ़-पढ़कर देख रहा हूं, बाहर नहीं जा रहा हूं। आप जनादेश परब मनाइए। सत्ता में बैठकर कोई भी शासकीय तंत्र के माध्यम से दुरुपयोग करके कोई भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी हो, जनादेश परब मना सकता है। हम भी आयेंगे तो हम भी मनायेंगे, आप उसकी चिन्ता मत करिए।

अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए चल रहे विकास की गाड़ी। आपने पिछले एक साल में क्या विकसित किया है ? आपको एक साल तो हो ही गया है। आप मुझे एक बड़े संस्थान का नाम बता दीजिये, जिसकी नींव आपने रखी हो ? मैं कुछ और कहूं ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ भी देख लेता हूं। आपने 15 सालों का जिक्र करते हुए कह दिया कि

इतने विश्वविद्यालय खुल गये। यहां आपके एक पितृ पुरूष ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय खोला था। क्या आज तक उसमें 1500 से ज्यादा विद्यार्थी आये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, क्या मैं इंटरप्ट कर सकता हूं ?

डॉ. चरणदास महंत :- एक मिनट रूक जाईये फिर आप कर लेना । क्या उसमें कुलपति हैं ? आपने हमारे जमाने में जो कुलपति बनाया, वह भी आर.एस.एस के थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिये। माननीय रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे। आप लोगों ने जिस दिन दो यूनिवर्सिटी, रायगढ़ की और वानिकी विश्वविद्यालय को लेजिस्लेट किया तब मैंने बताया कि इस विधान सभा में तीन विश्वविद्यालय बनने का रिकॉर्ड है, जो ऑल इण्डिया रिकॉर्ड है। जो विशिष्ट श्रेणी का विश्वविद्यालय होता है, उसमें विद्यार्थियों की संख्या नहीं गिनी जाती।

डॉ. चरणदास महंत :- Very good.

श्री अजय चन्द्राकर :- आप वर्धा विश्वविद्यालय, जो केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। उसको कितना पैसा ग्रांट मिलता है और वहां कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, इसे पता करिये। जो विशिष्ट होती है और रिसर्च की संस्थाएं होती है, उसमें संख्या का उल्लेख नहीं होता। उसमें तो यदि एक व्यक्ति तैयार हो जाये और उसका उद्देश्य सफल हो जाये तो वह पर्याप्त है।

डॉ. चरणदास महंत :- हुजूर, मैं तो यह कह रहा हूं कि आपने पिछले 25 वर्ष का जिक्र करके एन.आई.टी., एम्स, आई.आई.आई.टी., सी.पी.ई.डी. और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का जिक्र किया है और शाबाशी से अपनी पीठ थपथपायी है। क्या इसे आपने बनाया है ? क्या यह आपके कार्यकाल का है ? 2047 तक देश और प्रदेश में कितने उद्योग लगेंगे ? चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे खनिज साधन हो और सार्वजनिक प्रतिष्ठानें हों, चाहे रेल की बात हो, जहां पानी जहाज रूकता है, उस पोर्ट की बात हो। आपने अभी तक कितने संस्थानों को बेचा और आप कितने संस्थानों को 2047 तक बेचेंगे ? यदि इसकी सूची बन गई हो तो हमको बता दीजियेगा। आपने पिछली बार ज्ञान की बात कही है और उसके बाद गति की बात तो कर ही रहे हैं। वह गति कहा जायेगी, यह पता नहीं। ज्ञान में आपने पहले गरीब को लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय, आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसको गरीब मानते हैं ? क्या आप गांव में बसने वाले मजदूर को गरीब मानते हैं ? क्या आप जंगलों में बसने वाले आदिवासी को गरीब मानते हैं ? क्या आप शहरों में दिहाड़ी का काम करके आजीविका चलाने वाले लोगों को गरीब मानते हैं ? आप किसको गरीब मानते हैं और पिछले एक वर्ष में आपने इनके लिये क्या किया है ? गांव में बसने वाले गरीबों को तो आपने 18 लाख आवास देने का सपना दिखा दिया। मैं एक बात कहूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ? (सत्ता पक्ष की ओर पत्रिका दिखाते हुए) वित्त मंत्री जी, यह तो हमारी सरकार ने नहीं छापा है। यह आपका ही छापा हुआ है। हुजूर, इसमें

आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में 8वें नंबर में आंकड़ा है। आपने वर्ष 2023-24 में तो 0-0 आंकड़ा दिखा दिया, यह बहुत अच्छी बात है। इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है परंतु वर्ष 2025 में भाई साहब ने थोड़ा ज्यादा बोल दिया कि 13,000 आवास बन चुके। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2025 में सिर्फ 6 आवास बने हैं। (शेम-शेम की आवाज) यह गलत है। इसे छापने वाले को फांसी लगा दीजिये या निलंबित करिये। अगर यह सही है तो आपके भौतिक रूप से सिर्फ 6 आवास बने हैं। आप यह पढ़ लीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय नेता जी, यह मेरे पास भी यह जानकारी है। अभी जो उत्तर आया है, उसमें यह आंकड़ा 13 हजार लिखा है। क्योंकि वह पहले छपा होगा। अभी मेरे पास उत्तर आया है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा कि यहां आप किसको गरीब मानते हैं तो आप इसमें जवाब दे सकते हैं तो मुझे दे दीजिए। आपके प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए घोषणा की थी कि हम उनको 45 रूपये बोनस देंगे। क्या आपने किसी को बोनस दिया ? क्या आपने उसको वर्ष 2024-2025 के अनुपूरक बजट में शामिल किया ? आपने यह शामिल नहीं किया। तीसरा गरीब वह जो अब शहरों में रिक्शा चलता है, घरों में काम करता है, महिला या पुरूष है। क्या आपने उसके लिए एकाध आवास बनाये हैं ? यहां पर आपने घोषणा तो कर दी कि हम इनको आवास देंगे । क्या पिछले वर्ष आपने इन्हें एक भी आवास दिया है ? या आने वाले सालों में आप उन्हें आवास देंगे ? तो मैं यह कह रहा था कि आपने गरीबों को देना है तो G से ज्ञान तो बना लिया अब हम युवा के लिए Y में आ जाते हैं। आज की तारीख में प्रदेश में 17 लाख युवा बेरोजगार हैं। पूर्व में हमने थोड़े दिनों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया था आपने सरकार में आते ही उस भत्ते को बंद कर दिया। आपने यह बजट पेश होने के बाद कोई कोशिश की ? कि इस प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ करें ? आपने प्रदेश में भर्तियां निकालीं और प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कीं। मगर कृषि विभाग में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की, उसकी भी राजभवन में जांच हो गई और जांच के बाद हाईकोर्ट में चला गया। महाराज, आपके राजनांदगांव जिले में पुलिस की भर्ती होनी थी, वहां उसकी भी जांच चल रही है। आप लोग कहते हैं कि सदन में किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, एक बृजमोहन अग्रवाल जी हुआ करते थे। चूंकि इस प्रदेश के वह मंत्री थे तो यहां पर मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अगर आपको यह याद हो तो उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में ही कहा था कि प्रदेश में हम 33 हजार शिक्षकों की भर्ती करेंगे। मैंने उनसे खड़े होकर, यह प्रश्न पूछा कि आप यह भर्ती कब करेंगे ? तो उन्होंने यह कहा कि हम लोक सभा के चुनाव के बाद करेंगे। मैंने उनसे यह पूछा कि क्या आपको वित्त विभाग की स्वीकृति मिल गयी है तो उन्होंने यह कहा कि हमें वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है। आज कल 33 हजार लोगों को नौकरी देने वाले दिल्ली में भटक रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान, आपके, हमारे और सबके अन्नदाता हैं। क्या सिर्फ वही किसान होता है जो खेतों में केवल खरीफ फसल तक काम करता है। क्या सब्जी उत्पादक किसान नहीं होते हैं ? क्या टमाटर, आलू, बगीचे में काम करने वाले किसान नहीं होते हैं ? क्या गन्ने का उत्पादन करने वाले किसान नहीं होते हैं ? आपके पण्डरिया में गन्ने के माध्यम से जो शक्कर बनता था, वह कारखाना बंद हो गया है। सूरजपुर का कारखाना बंद हो गया है। इस प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को बाजार में गन्ना देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे पण्डरिया के भाई साहब धर्मजीत सिंह जी बैठे हैं, वह गुड़-गुड़ बना-बना कर, हमको भी देते हैं और आपको भी देते होंगे। महाराज, अब वह सीरा बन रहा है। उनके पास तो कोई शक्कर बनाना नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह राब है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसे "राब" कहते हैं। क्या आपको यह पता है कि वह राब कहां जा रहा है ? अब वह राब शराब बनने के लिए जा रहा है। उससे शक्कर नहीं बन रहा है। उसमें गुड़ कम बनता है तो अब वह सीधे जा रहा है जहां शराब बनती है। प्रदेश की गली-गली में शराब बिक रही है इसलिए गली-गली में दुकानें बढ़ा रहे हैं, दुकानें खुल रही है और लोगों को मार रहे हैं। जैसा कि आप यह समझते हैं। आपने इस प्रदेश की नारियों का सम्मान बढ़ाया। पिछले 2024 के कलेण्डर वर्ष में प्रदेश में महिला उत्पीड़न बलात्कार के 3191 मामले दर्ज हुए हैं। यह आपके प्रश्नों के उत्तर में है। इसमें मेरी कोई खोजबीन नहीं हुई है। इसमें पहला रायपुर है, इसमें द्वितीय बिलासपुर है और तृतीय कोरबा है। अभी ऐसा पत्र वालों ने लिखा है कि प्रदेश में 3 घण्टे में एक महिला का बलात्कार हो जाता है(शेम-शेम की आवाज) बीजापुर में एक साल में 37 महिलाओं की गुमशुदगी के प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। यह आपके GYAN का आपने जो भी इन एक सालों में किया है। वह GYAN है अब उसको GATI कैसे देंगे, भाई ने यह बता ही दिया है, मैं उसमें आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं यहां पर बार-बार उसी शब्द को नहीं दोहराना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके विभाग में सुशासन और अभिसरण कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका विभाग है, उसमें कितना कहें, कुछ समझ में नहीं आता। 19 फरवरी को एक समाचार पत्र में छपा था कि सुशासन की परिकल्पना साकार करने के लिए हुई बड़ी पहल। आपकी फोटो, वित्त मंत्री जी की फोटो है और आप लोग दो एन.जी.ओ. दिल्ली से ला रहे हैं, उन दोनों की फोटो है। क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि प्रदेश शासन में पारदर्शिता सिखाने के लिए, प्रदेश सरकार की जवाबदेही बताने के लिए, नीति निर्माण के लिए और स्वच्छ प्रशासन कराने के लिए आपके पास अधिकारी नहीं हैं? क्या एन.जी.ओ. के लोग आकर आपको सिखायेंगे कि किस तरह से आपको पारदर्शी प्रशासन चलाना है, किस तरह से आपकी नीति का निर्धारण होना है, किस तरह से आपकी योजनायें बनेंगी? अगर बुरा न मानें तो मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है, गर्व हो रहा है कि हमारे मुख्य सचिव के साथ- साथ 7 आई.ए.एस. अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने business management में

मास्टर की डिग्री प्राप्त की है। सही है या गलत है, आप लोग बता दीजियेगा। 03 आई.ए.एस. अधिकारी ऐसे हैं, यहां नाम बताना तो गलत हो जायेगा, शायद उनको भोगना पड़े, आपके और उनके अधिकारी यू.एस.ए. से टॉप यूनिवर्सिटी में डिग्री प्राप्त करके आये हैं। मुख्य सचिव जी के सहित 34 आई.ए.एस. अधिकारी देश के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में B.E., B.Tech और M.Tech की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। 10 आई.ए.एस. अधिकारी देश के चिकित्सा संस्थानों में M.B.B.S. की डिग्री प्राप्त किये हैं। सुशासन और अभिसरण विभाग को देखने वाले तो P.G.D.M. और Marketing and telecom की डिग्री हासिल किये हुए हैं। इतने सक्षम अधिकारी होते हुए क्या आपको एन.जी.ओ. की सुननी पड़ेगी जो मात्र डिग्री लेकर या कहीं से भी बने हैं? माननीय वित्त मंत्री जी, क्या उसके माध्यम से कुछ इधर से उधर करना चाहते हैं? आप उसको देख लीजिए। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा लगता हो तो चलाईये, हमें कुछ नहीं करना है। आपने खरीदी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कहा है कि Gem Portal के माध्यम से हर खरीददारी होगी। बहुत अच्छी बात है। देश में Gem Portal के बारे में क्या चर्चा है, आप लोगों ने सुना है। गुजरात में Gem Portal सब फिक्स हो जाता है। गुजरात में कौन फिक्स करता है, कहां से होता है, क्यों होता है, यह तो आप जानें। मुझे चिंता छत्तीसगढ़ के उन छोटे-छोटे व्यापारियों की है जो बहुत छोटे-छोटे उद्योग धंधे करते हैं। आपकी तरफ देख रहे हैं कि नई सरकार आई है और संघर्षशील, गतिवाले, ज्वलनशील सभी प्रकार के आपमें गुण हैं। आप उनको कुछ अच्छा देंगे, ऐसा वह विश्वास करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दंतेवाड़ा में डी.एम.एफ. फंड से 250 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज बनायेंगे। इसमें डी.एम.एफ. का भ्रष्टाचार कैसे रूकेगा? इसमें भ्रष्टाचार रोकने का कुछ रास्ता है? आप बुरा न मानें तो वित्त मंत्री जी एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे जांजगीर, बिलासपुर, कोरबा का डी.एम.एफ. का काम रायगढ़ वाले आकर कर रहे हैं। इनके जमाने में दुर्ग और रायपुर के लोग करते थे। आपके जमाने में रायगढ़ आकर कर रहे हैं। आपने दंतेवाड़ा में 250 करोड़ रुपये का मेडिकल कॉलेज बना दिया तो दंतेवाड़ा में क्या डी.एम.एफ. का प्रशिक्षण चलेगा?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता जी, आपका जमाना क्या यहीं आकर रूक गया है?

डॉ.चरणदास महंत :- आप कह रहे हैं कि रोड प्लान बनायेंगे, 2030 तक बहुत बढ़िया प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने जो-जो गति के लिये रास्ते बताये हैं, उनको बता रहा हूं । अभी-अभी आपने देखा होगा कि रायपुर राजधानी में एक मोवा ब्रिज बना है, उसको डिप्टी सी.एम. साहब देखने के लिये गये थे और जनता भी गयी थी । वह कैसे टूटकर धराशायी हो गया ? आपने उसका उदाहरण देख लिया कि आज भी भ्रष्टाचार वहीं है, सुधर नहीं रहा है । आप एन.सी.आर. की तर्ज पर एस.सी.आर. बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत करेंगे लेकिन यह जो मेट्रो रेल जायेगी वह कहां से जायेगी ? वह शहर के बाहर से जायेगी या शहर के बीच से जायेगी ? चंद्राकर जी कहां गये ? अपने

[xx] के रूप में जो एक स्काईवाक खड़ा हुआ है अगर वह उधर से जायेगा तो उसका क्या होगा ? चंद्राकर जी नहीं हैं, धर्मजीत भाई उसका क्या होगा ? स्काईवाक से क्या होगा ?

श्री रामकुमार यादव :- मोला याद हे इही हा बोले रिहिस हे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, मैंने तो बोला था कि इसको बुल्डोजर से तोड़वा दो तो उन्होंने हां बोला था लेकिन तोड़वाया नहीं था तो अब क्या होगा, वह वहां पर है ।

डॉ. चरणदास महंत :- मैंने तो सुना है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- धर्मजीत भैया, आपने बोला था कि वहां चाकू मारेंगे, वारदात होगी, घटनाएं होंगी ।

श्री रामकुमार यादव :- लेकिन आप ला मानना पड़ही ।

श्री भूपेश बघेल - वह तोड़ने के लिये ज्यादा पैसा लगता है । (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- भैया, मैंने तो सुना है कि अभी 50 करोड़ का उसका टेंडर हुआ है । अभी आपने उसको बनाने के लिये 50 करोड़ रूपये का टेंडर लगाया है। आप उसके ऊपर से मेट्रो टेन में कैसे वहां जाओगे, यह आप ही देखें । वित्त मंत्री जी निवेशकों को राज्य में आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिये हाल ही में मुख्मयंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली और मुम्बई में इन्वेस्टर कनेक्ट नाम का कार्यक्रम हुआ है जिसमें आप लोगों ने दिनांक 23 फरवरी को दिल्ली में एक मीटिंग की जिसमें एन.जी.ओ. वाले मिले थे और शायद 25 तारीख को मुम्बई में किया । आपने दिल्ली में 1 करोड़ 3 लाख रूपये खर्च कर दिये, आपने मुम्बई में मीटिंग के 1 करोड़ 61 लाख रूपये खर्च कर दिये । मीटिंग का क्या नतीजा निकला वह पता नहीं और मैंने सुना है कि अब आप लोगों ने 31 लोगों को छांटा है, उनको चिट्ठी लिख-लिखकर बुला रहे हैं कि हमारे यहां आओ और यहां इंडस्ट्री डालो । अब मैं उसका पता वगैरह मांगूंगा तो आप नाराज होंगे कि देंगे यह पता नहीं लेकिन हमारी सरकार द्वारा व्यापारियों को आमंत्रण देना पड़ रहा है कि आओ । आपके पास ऐसा नियम हो, ऐसा कानून हो, उनकी सुरक्षा का अधिकार हो, ऐसा जमीन देने की बात हो, ऐसे उनको सुविधा दिलाने की बात हो कि हमारे यहां वे कूद-कूदकर आयें, भाग-भागकर आयें । आपने 31 लोगों को चिट्ठी लिखी है कि आ जाओ, हम आपके लिये तैयार बैठे हैं, मीटिंग करेंगे, बहुत अच्छी बात है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो हमारे यहां जितने उद्यानिकी के किसान हैं उनको शिक्षण-प्रशिक्षण दे दीजिये, उनको बताईये । हम लोग भी बहुत दिनों से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कुछ-कुछ करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाये, यह बात अलग है लेकिन इतनी सारी व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेंगी । मुझे आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहना है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैं आंकड़ों के खेल में नहीं जाउंगा । वित्तमंत्री जी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी । आपने लिखा है कि - हिंदू किसी मजहब का नाम नहीं है, जीवन पद्धति है ।

सर्वे भवन्तु सुखिन: के भाव पर आधारित है, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन इसको आप मानते क्यों नहीं हैं ? आप यह कहते क्यों नहीं थक रहे हैं, आजकल आप यह कह ही रहे हैं कि...।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

वित्तीय वर्ष 2025 - 2026 के आय - व्ययक सामान्य चर्चा (क्रमश:)

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यही कह रहे हैं कि जो कुंभ में नहीं नहायेगा वह हिंदू नहीं है । आप यहां कुछ दूसरा कह रहे हैं और वहां दूसरा कह रहे हैं । मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन सुना है कि मोहन भागवत जी कुंभ में नहाने नहीं गये थे । आप उनसे पूछ लीजियेगा कि वे हिंदू हैं कि नहीं हैं ? आपने तीर्थराज प्रयाग में एक पवेलियन बना दिया, कौन बनायेगा, कैसे बनायेगा, टेंडर आमंत्रित किया, बुलाकर दिया, आप जानिए । मेरे ख्याल से आपने 25 करोड़ तो उन्हीं बनाने वालों को दे दिया । उसमें खाने-पीने की व्यवस्था थी, यह जानो । मैंने पता किया तो मुझे बताया गया कि भैया वहां कार्ड लेते हैं, उसके बाद वहां प्रवेश करने देते हैं और उसमें छत्तीसगढ़ के लोग तो आ ही रहे हैं, महाराष्ट्र के भी आ रहे हैं, बिहार के भी आ रहे हैं, मध्यप्रदेश के आ रहे हैं। मुझे जानकारी मिली थी कि 50 हजार लोग आए थे। वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि सवा करोड़ लोग आए थे, आप उसका हिसाब दीजिएगा कि उस पवेलियन में कितने लोग गए? आपने भव्य राम मंदिर की स्थापना के लिए और भांचा राम के भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के लिए जो प्रशंसा की है, मैं उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं पूछना चाहता हूं, भैया यहां राम वन गमन पथ बना है, उससे आपको क्या तकरीफ है? राम वन गमन पथ को पिछली सरकार ने बनाया। उसमें रामचंद्र जी की मूर्ति लगी है। हम तो जिस पथरा को बिठा देते हैं, वह शंकर जी हो जाता है, मान लो थोड़ी बहुत गलत मूर्ति बनी है, लेकिन रामचंद्र जी की तो मूर्ति है। हमने राम वन गमन परिपथ बनाया..।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, वह जो मूर्ति है, वह राम की है, करके कोई समझ ही नहीं पा रहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- तो दिख दीजिए कि राम की मूर्ति है। (हंसी) इसमें क्या तकलीफ है? रामचंद्र जी की मूर्ति है, लिख दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, मेरे बार-बार आग्रह के बाद आप ऊपर बैठते थे, चंदखुरी में नहीं लिखवाया कि भगवान राम की मूर्ति हम लोगों ने बनवाया है।   डॉ. चरणदास महंत :- आप तो हनुमान की ऐसी मूर्ति बना रहे हैं, उसमें लिखना पड़ रहा है कि हनुमान जी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष जी 10 टाइम्स, 10 बार बोला हूं कि चंदखुरी में जो मूर्ति लगी है, वह किसकी है? और उसका घोटाले की जांच के लिए तो आज तक..।

डॉ. चरणदास महंत :- भैया, बनाने वाले आपके लोग।

श्री अजय चन्द्राकर :- वाह, चंदखुरी की मूर्ति तो बाजू वाले ने बनवाया है।

डॉ. चरणदास महंत :- टेंडर देने वाले आपके लोग। पथरा चूनने वाले आपके लोग।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिए, उसमें अभी जाकर आपके विधायक दल से लिखवाइए कि ये मूर्ति राम भगवान की है।

डॉ. चरणदास महंत :- हम लोग तो जिस पद्धति के हैं, उसने बताया न। हम तो कण-कण में भगवान को मानने वाले हैं तो कण-कण में राम को क्यों नहीं मान सकते? हो सकता है थोड़ा बहुत इधर-उधर टेढ़ा हो गया हो। मगर भगवान तो भगवान हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि मूर्ति पर आप कुछ मत करो। मेरा सिर्फ यह कहना है की राम वन गमन पथ पर हम लोगों ने इतना खर्च कर लिया है, उसमें सालभर में एकाध ईट तो लगा दो। 15 महीने हो गए। अगर इसी तरीके से आप 15 महीने और गुजारोगे तो वहां राम भगवान की मूर्ति की जगह टूट-फूट हो जाएगा। लोग तोड़ डालेंगे।

श्री बघेल लखेश्वर :- ये लोग राम को नहीं मानते, श्री राम को मानते हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- एक ही बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है, राम वन गमन पथ का मतलब जो भूपेश बघेल जी चाहे, वह राम वन गमन पथ है। अच्छा चम्पारण में हम राम वन गमन पथ है करके मूर्ति लगवाएंगे। यहां मूर्ति लगा देंगे, पहले उसको तो स्पष्ट कर लो राम वन गमन पथ है क्या चीज?

श्री अटल श्रीवास्तव :- अजय भईया, वह राम वन गमन पथ एक पर्यटन परिपथ था, जिसमें पर्यटक जाएगा। जहां-जहां राम के निशान मिले हैं। पर्यटन परिपथ बनाया गया था। अगर पर्यटक थोड़ा चम्पारण की तरफ चला जायेगा तो आपको तकलीफ क्या है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अटल जी..।

श्री सुशांत शुक्ला :- तो उसमें रतनपुर का रामटेकरी नहीं था क्या?

श्री रामकुमार यादव :- तुमन न राम लो मानो, न श्याम ला मानो, न शिव जी ला मानो, श्री राम ला मानने वाला हव। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- शिवरीनारायण में भी तो राम ने शबरी के जूठे बेर खाये थे। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप राम वन गमन पथ को मानते हैं या नहीं? यह बताइए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अटल जी, आप तो सिर्फ पोस्टर हो। आप पर्यटन मंडल के अध्यक्ष में पोस्टर ब्वाय थे। उसके पीछे जितना खेल हुआ है, वह विधान सभा के दस्तावेज में है। उसकी जांच करवाओ। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ये सरकार में खेला होगे हे। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- अटल जी, पोस्टर में कोई और था, इसलिए ऐसा हो गया कि रामटेकरी चूक गया।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिए, सुशांत जी, आप अच्छा बोलते हैं, अब आप बैठ जाइए। आपकी आवाज जरूर तेज है, मगर बोलते अच्छा हैं। मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा कि आप 2 नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। मगर मैंने सुना है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि जहां-जहां मेडिकल कॉलेज हैं, वहां ही नर्सिंग कॉलेज खोले जाएं ताकि नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को ठीक से ट्रेनिंग दिया जा सके। उसमें थोड़ा बहुत संशोधित कर लीजिए। आगे बढ़ा लीजिए। मुझे इसे कैंसिल करने के लिए नहीं कहना है, क्योंकि इसमें जांजगीर-चांपा का भी नाम है। (हंसी) आपने यहां 06 नये फिजियोथेरेपी कॉलेज बनाने की बात कही है। वित्त मंत्री जी सोकर आ गए। वित्त मंत्री जी तो जाग रहे हैं, आप सोकर आ गए? स्वास्थ्य मंत्री जी अभी सो रहे थे। तो मेरा निवेदन है भैया यहां एक फिजियोथेरेपी कॉलेज है। आप कभी गए हो? आपने देखा है कि किस हालत में है? पहले उसको देख लीजिए, उसमें कुछ करा दीजिए, उसकी बहुत बड़ी दुर्दशा चल रही है और 06 नहीं, 10 खोलिए, स्वागत् करेंगे आपका । 33 हजार शिक्षकों की भर्ती के बारे में मैं कह चुका हूं, हमारे साथियों ने सब बातें कह दी हैं । एक बात और कहना है नवीन फायर स्टेशन निर्माण एवं क्षमता वृद्धि के लिए 44 करोड़ का प्रावधान रखा है । वित्त मंत्री जी, सी.एम. साहब के विभाग में रायपुर में एक ट्रान्सफार्मर डीपो है, आपने सुना होगा । अभी-अभी उसमें बहुत भयानक आग लगी थी, चन्द्राकर जी को पता होगा । मैं यह पूछना चाहता हूं, इतने महीने हो गए, एक फायर फाइटर आया क्या ? एक और एक्स्ट्रा फायर फाइटर आया क्या ? अब 44 करोड़ आप कब देंगे उसको सोचिए और एकाध फायर फाइटर की व्यवस्था कर दीजिए ।

बालको कैंसर अस्पताल और सत्य सांई अस्पताल । ये नवा रायपुर में हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है । सत्य सांई अस्पताल में सिर्फ छोटे-छोटे बच्चों के हार्ट का इलाज होता है और बालको कैंसर अस्पताल में कैंसर का इलाज होता है । यहां आप नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे तो कॉलेज के बच्चे 26 किलोमीटर पढ़ने कहां जाएंगे? यहीं आएंगे या वहां उनके लिए अलग कॉलेज खोला जाएगा ? यहां आकर फिर जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, यह आप देख लीजिए । माननीय वित्त मंत्री जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है वेडिंग डेस्टीनेशन के रूप में नवा रायपुर पहचान बन गया है या पहचान बनाई जा

रही है । किसी की शादी हुई भइया वहां ? किसी करोड़पति के अलावा, किसी लखपति की शादी हुई है वहां ? कोई एक बाहर का मे-फेयर होटल है वहां शादी होती है, करोड़ो रूपए लगते हैं । आप डेस्टीनेशन बना रहे हैं तो गरीबों के लिए तो बना दीजिए । भले जय जगन्नाथ जी के पास चल दें । हमारे गरीबों के लिए क्या है ? सिवाय करोड़पतियों के वहां किसी की शादी नहीं होती। आप क्यों बनाना चाहते हैं और अगर बन गया तो क्यों श्रेय लेना चाहते हैं, यह आप देखिए । अच्छा, हम लोगों के पहले भी था शायद । एक नेशनल गोल्फ टूर्नामेंट के लिए गोल्फ कोर्स बन रहा है । क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि हमारे 90 विधायकों में से कितनों को गोल्फ खेलना आता है, पूछ सकता हूं ? हमारे पूरे प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग गोल्फ खेलते होंगे ? गोल्फ कोर्स के लिए आप कितने पैसे बर्बाद कर रहे हैं । गोल्फ कोर्स के नाम से कितनी जमीन दे दी है । गोल्फ कोर्स के नाम से वहां भवन बन रहा है, सर्किट हाऊस और क्या-क्या बना रहे हैं ? कैसे करेंगे? हम अमीरों के लिए कुछ करना चाहते हैं या गरीबों के लिए ? माननीय छत्तीसगढ़िया वित्त मंत्री जी आप सोच लीजिएगा ।

आपने यहां कहा है कि मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत महतारी वंदन योजना में 3000 करोड़ का प्रावधान पिछले साल रखा था । इस बार 5500 करोड़ का बजटीय प्रावधान है, खैर यह तो बढ़ता रहता है । मैं आपसे कहना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि आप के अनुसार बार-बार यह कहा गया है कि 700 करोड़ रूपए प्रतिमाह का भुगतान करते हैं तो एक साल में कितना हुआ जी ? 8400 करोड़, तो यह 5500 करोड़ से कैसे पूरा हो जाएगा ? क्या महिलाओं का नाम उसमें से काटने जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है । इसलिए मेरे घर में पूछ रहे थे कि ये क्या है ? आत्मानंद स्कूल को आपने पीएमश्री बना दिया, सब कह रहे हैं । आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, उनका 2272 करोड़ का बकाया था, 1741 करोड़ आ चुका, अभी लगभग 1091 करोड़ बाकी है । ये केन्द्र प्रवर्तित योजना है इसको आप किस ढंग से सुचारू रूप से करना चाहते हैं, इसमें आपकी बहुत ताकत लगेगी । इसलिए मैं आपको इंगित करवा रहा हूं । नि:संतान दंपत्तियों के लिए तो हमारे भाई ने सोच ही लिया है। चंद्राकर जी, कैसा क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेकाहारा में कैंसर का संस्थान खुला है, उस संस्थान में तीन मशीनें हैं, गलत स्पेलिंग हो जाएगा, मैं नहीं जानता जिसको पैट मशीन कहते हैं, वह बंद है, एम.आर.आई. मशीन कहते हैं, वह बंद है, जो सीटी मशीन कहते हैं, वह भी बंद है, केवल सेकाई या सिंकाई आप जैसा समझते हो, जिसमें सिंकाई होती है, वही मशीन बस चालू है। आप ऐसे कैंसर संस्थान की रक्षा सुरक्षा नहीं करेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि आपने बजट में अच्छी व्यवस्था की है ? उसी तरीके से हार्ट के मामले में एक रोटावेलेटर होता है, जिस धमनी में या आट्रिच में कैल्शियम जमा हो जाता है, उसको ठीक करने का काम आता है। वह मशीन नहीं है, उसके लिए बहुत दिन से मांग रहे हैं। एक वह मशीन आती है जो हार्ट फेल हो जाती है तो तत्काल उसको चालू करने का कुछ काम आता है, वह मशीन भी नहीं है, बहुत दिन से मांग रहे हैं। वहां ए.सी. नहीं है जबकि इस तरह

के अस्पतालों में ए.सी. की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, वह बिल्कुल भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर बुरा न माने तो मैं जानना भी चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं। क्या आप आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर में पढ़े हैं ? आपने ही शिक्षा प्राप्त की है।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल-बिल्कुल।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय वित्त मंत्री जी ने आपकी कॉलेज को 4 करोड़ रूपए दिए हैं और वही हल्दी और अदरक के लिए 5 करोड़ रूपए दिए हैं। आप अध्यक्ष महोदय के कॉलेज को सुदृढ़ीकरण करने के लिए 4 करोड़ रूपए देते हैं और हल्दी और अदरक के लिए 5 करोड़ रूपए दे रहे हैं। (हंसी)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आपने इस बजट पुस्तिका को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं सुन भी रहा था, मैं सो नहीं रहा था। आपने उसको ढंग से नहीं पढ़ा लगता है, आप जिन मशीनों की बातचीत कर रहे हैं उसको वित्त मंत्री जी ने बजट में दे दिया है।

डॉ. चरणदास महंत :- आप मेरी तरफ से धन्यवाद दे दीजिए। (हंसी) मैं धन्यवाद दे दूंगा कल पेपर में उल्टा छप जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष जी ने वित्त मंत्री जी की तारीफ की और मेरी ऐसी-तैसी हो जाएगी। (हंसी)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- मैंने आपकी ओर से बधाई दे दी।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, हममें से बहुत सारे लोगों को एक बात पता ही होगा कि इसी साल लगभग 138 करोड़ का धान समाप्त हो गया, सड़ गया, गल गया, मिट्टी में मिल गया, वित्त मंत्री जी आपको ज्ञात तो होगा ही न ? ये किसका नुकसान हुआ ? हम लोग 40 लाख टन धान को नीलामी के माध्यम से विक्रय करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से उसमें 8 हजार करोड़ की हानि होगी तो किसी हानि होगी ? आपकी, सरकार की या हम सबकी हानि होगी ? इस तरह से मेरी बातें हैं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं सक्ती में रहता हूं, आपको पता ही होगा। आप खरसिया क्षेत्र के हैं। हम दोनों की बाउंड्री आजू-बाजू में बहुत लंबी मिली है, मगर मेरे क्षेत्र तरफ कुछ नहीं आया। आपकी हमारी विधान सभा की बाउंड्री लगी हुई है, खरसिया, जशपुर और अंबिकापुर तरफ ही जा रहा है, बाउंड्री की इस तरफ नहीं आ रहा है। उसमें कोई बंधन है क्या, उसको देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- छलकेगा तो उधर ही आएगा। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैं बहुत देर से आपको बोलना चाह रहा था। दो मिनट में अपनी बात रख रहा हूं।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं बैठ जाऊं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- आप खड़े भी रहेंगे बैठ भी जाएंगे दोनों चलेगा।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं भी सांस ले लेता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने इनवेस्टर मीट के बारे में बताया कि आपके बुलाने से नहीं आ रहे हैं। पिछली सरकार में यहां से एक मंत्री टोक्यो गये थे, वे वहां पर ऑटोमोबाईल की खोज करने के लिए गए थे। हम लोगों ने पूछा कि आप कौन सी ऑटोमोबाईल के बारे में बात करके आए हो, उनको इधर उधर घुमा दिए जहां ऑटोमोबाईल था ही नहीं। (हंसी) साहब, मैं एक बात और बता रहा हूं। मैं इसी सदन में वहां बैठा था। एक कृषि मंत्री यहां पर बैठा करते थे। उनके पास पशुपालन विभाग भी था। वह किसी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए बहुत बड़े कान्फ्रेन्स में स्वीडन या कहीं गये थे। जब वह वहां पर गये तो वहां का दरवाजा बंद हो गया था और कान्फ्रेन्स समाप्त हो चुका था। यह तो हाल रहता है। क्या करोगे, थोड़ी तकलीफ होती है। वह वहां से एक दूध की मशीन लेकर आये थे। उसको गाय के थन में लगा दो तो वह 50-100 लीटर दूध दुह लेती है। उसी संबंध में मैंने उनसे प्रश्न पूछ लिया था तो बड़ी बहस हो गई थी। (हंसी)

डॉ. चरणदास महंत :- आपको तो पूछना ही नहीं था। राजनांदगांव में तो बहुत सारी गायों में थन की मशीनें लगी हुई हैं। उसमें से तो सैकड़ों लीटर दूध निकलता है। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने उनसे उसका उपयोग कहां है, यह पूछ लिया था।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यही कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी को बड़ी चिंता है कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है। उसके लिए शासन बहुत प्रयास भी कर रहा है। हम सब लोग चिंतित हैं। यहां तक कि हाई कोर्ट ने भी हैरानी जाहिर की है कि क्या हो रहा है ? साइबर अरेस्ट हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं तो मेरा यह सोचना है कि उसके लिए आपको कुछ कहना चाहिए और करना चाहिए। बाकी तो आप जैसा कर रहे हैं, वह कर ही डालिये। मुझे तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मेरे साथियों ने बहुत कुछ कह दिया है। यदि वित्त मंत्री जी इधर देख रहे हो तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि :-

लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है,
तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय वित्त मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले सवा साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन की ईमानदारी के साथ, सुशासन के साथ सेवा करने का।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी का भाषण हो रहा है करके माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कक्ष से आये और हम लोग भी यहां पर बैठे हैं। चाहे आपने जैसा भी बोला हो, प्रशंसा की हो, आलोचना की हो। लेकिन आपके बाजू वाले भाषण देकर

कहां भाग गये ? क्या आपकी गरिमा आपके दल में ही नहीं है ? नेता प्रतिपक्ष जी के भाषण में आपके सहयोगी भाषण देकर उठकर चले गये। यह क्या है ? आपके साथ यह क्या हो रहा है? आपका इतना अपमान क्यों हो रहा है ?

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप इजाजत दे तो मैं कुछ कह सकता हूं कि यह तो आपके और हमारे बीच का रिश्ता है। वैध हो या अवैध हो। आजू-बाजू वालों को पसंद आये, यह कोई जरूरी है क्या ? (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सवा साल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन की ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ सेवा कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने वर्ष 2023 में जो ऐतिहासिक जनादेश दिया था, उसको बार-बार दोहरा रही है। वर्ष 2023 के चुनाव में 46 प्रतिशत वोट बैंक के साथ छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन ने हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया था। यह अपने आप में रिकॉर्ड था और यह ऐतिहासिक जनादेश था। (मेजों की थपथपाहट) उसके 5 महीने बाद लोक सभा का चुनाव हुआ तो फिर से छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन ने आशीर्वाद स्वरूप छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जनादेश प्रदान किया। रायपुर-दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में उप चुनाव का समय आया तो भी छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन व उस विधान सभा क्षेत्र की जनता-जनार्दन ने हमारी सरकार के काम पर मुहर लगाया। अभी कल के वक्तव्य में हमारे कांग्रेस पार्टी के एक साथी बोल रहे थे कि आप पंचायत चुनाव में जीत गये तो क्या हुआ ? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत चुनाव छत्तीसगढ़ और पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। उसके संबंध में इस प्रकार की कोई आलोचना करता है तो वह लोकतंत्र में उचित आलोचना नहीं है। जो हमारी स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, वह छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन की जो वास्तविक सोच होती है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि हमने अपनी स्पीच में गलत बात लिखी है, बजट भाषण में गलत वक्तव्य लिखा है कि 10 में 10 नगर निगम चुनाव जीते, वह रिकार्ड नहीं है। वह कह रहे थे कि हमने पिछली बार रिकार्ड बनाया था, उसे आपने दोहराया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वह 10 में 10 नगर निगम चुनाव जीते जरूर थे।

डॉ. चरण दास महंत :- मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा पूछना भूल गया था। मुझे दिल्ली से किसी ने फोन करके बताया कि सन् 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने वित्त मंत्री के रूप में हस्तलिखित भाषण पढ़ा था, यह सही है क्या ? आप पता करके बताईयेगा।

श्री ओ.पी. चौधरी :- जरूर पता करके बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि 10 में नगर निगम 10 जीते थे और उन्होंने रिकार्ड बनाया था।

लेकिन वह सबको ज्ञात है, मैं उसी बात को आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं कि 10 में नगर निगम 10 जीते जरूर थे, लेकिन इसके पहले स्थानीय चुनाव में शहरी जनता के 2 वोट डालने के अधिकार को 1 वोट कर दिया था। (शेम-शेम की आवाजें)

श्री अजय चन्द्राकर :- horse trading

श्री ओ.पी. चौधरी :- horse trading तो था ही, सीधा-सीधा जनता के 2 वोट डालने के अधिकार को 1 वोट कर दिया था। 1 व्यक्ति को रायपुर का मेयर बनाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों के सिस्टम को बदल दिया था, चुनाव के सिस्टम को बदल दिया था। (शेम-शेम की आवाजें) क्योंकि वह व्यक्ति डायरेक्ट इलेक्टन में चुनाव नहीं जीत सकता था, वह व्यक्ति अभी पार्षद का चुनाव हार गया है। उस व्यक्ति को जीताने के लिए पूरे स्थानीय निकायों के संवैधानिक व्यवस्था को चूर-चूर कर दिया था और उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन में बड़े गर्व के साथ बोल रहे हैं कि हमने 10 में 10 नगर निगम चुनाव जीता था। तो इस प्रकार के लोकतन्त्र में एक तरह से जनता के अधिकारों की हत्या करके अगर 10 में 10 चुनाव जीते थे और उसे अपना रिकार्ड मानते हैं तो ऐसे रिकार्ड उन्हीं को मुबारक है।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट कहना चाहूंगा। कल डौण्डीलोहारा जनपद का चुनाव होना था। तिथि भी निर्धारित थी, उसके बाद भी वहां पर चुनाव नहीं होने देना, यह कहां के लोकतन्त्र की भाषा है ?

श्री रामकुमार यादव :- ये लोकतन्त्र तुमन ला मुबारक हो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जहां-जहां हमारी पार्टी के अध्यक्ष बनना है, आपने वहां-वहां स्थगित करवा दिया।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से 10 में 10 चुनाव जीते थे, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको वापस लेने का निर्णय लिया, हम जनता के 2 वोट के अधिकार को 1 वोट कर दिया गया था, उसे वापस 2 वोट का अधिकार देंगे। यह किसी भी सरकार के लिए स्थानीय चुनाव में डायरेक्ट इलेक्शन कराना एक तरह का उसका जनमत संग्रह होता है। उस जनमत संग्रह को कराने की किसी ने हिम्मत की तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने हिम्मत की है। (मेजों की थपथपाहट) डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से जनता के सामने गये, जनता के दरबार में गये, हमारी सरकार गई, हमारी पार्टी गई। विजय प्राप्त करना एक चीज होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन में विजय प्राप्त करना एक चीज होता है। 10 के 10 नगर निगमों में सीधा जनता ने वोट देकर दो-तिहाई वोट देकर 75 प्रतिशत तक वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों को जीताया है, इससे बड़ा जनादेश का उदाहरण नहीं हो सकता है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले बार के बजट के GYAN में अन्नदाता किसान महत्वपूर्ण अंग था। अभी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि विकास केवल कांक्रीट का नहीं होना चाहिए, मानव का विकास होना चाहिए और उसमें किसान एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ फैक्टस आपके सामने रखना चाहता हूं। यह बोल रहे थे कि किसानों के लिए ..।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिये न। किसान की चिंता कर रहे थे, लेकिन अभी वह नहीं हैं। पाटन में किसानों की सामूहिक आत्महत्या हुई थी। उसमें हम लोग जांच करने गये थे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी। अब वह रहते तो मैं उस बात को बताता कि पाटन में किसानों की सामूहिक आत्महत्या क्यों हुई थी ?

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाते थे। उसके माध्यम से कितनी राशि का कितना भुगतान किया गया है, मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। इन्होंने सन् 2019 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना अन्तर्गत पूरे एक धान खरीदी सीजन के लिए कुल 5,627 करोड़ रूपये का भुगतान किया। चार बार चार किस्तों में भुगतान किया। वर्ष 2020 में कुल 5553 करोड़ रूपये का भुगतान किया एवं वर्ष 2021 में 7,005 करोड़ रूपये का भुगतान किया। यह पांच हजार, साढ़े पांच हजार, सात हजार करोड़ रूपये के रेंज में भुगतान करते थे और वह भी चार किस्तों में किसानों को तड़पा-तड़पा कर भुगतान करते थे, लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्ष की धान खरीदी में हमने एकमुश्त 13,320 करोड़ रूपये का भुगतान किया है (मेजों की थपथपाहट) और इस वर्ष धान खरीदी में हमने 12,000 करोड़ रूपये का भुगतान किया है।

श्री रामकुमार यादव :- 170 रूपये हा कहां हे?

श्री अटल श्रीवास्तव :- हमने एक साल में किसानों का 10,000 करोड़ रूपये कर्जा माफ किया था। क्या वह आपने किया था? आपने अभी किसानों का कर्जा माफ किया है?

श्री रामकुमार यादव :- हमने कर्जा माफ किया था। आप मन 1000 रूपये ला खा देहे हो, ओला आप बताववौ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, उन्होंने 17 जनवरी का सिर्फ अंतर राशि दिया था। आपने आचार संहिता के चलते पैसा चुनाव में दिया।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ के किसान पूछत हावय कि दिल्ली से जो 170 रूपये आय हावय, ओला आप मन पॉकिट खर्चा बना ले हौ। आप ओला बताववौ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, वित्त मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप सभी बोल चुके हैं। आपको पूरा समय मिला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यादव जी, आपके लिए बजट में आई.वी.एफ. तकनीक है। अब आप ज्यादा मत बोलिये, सिर्फ उसका लाभ लीजिये। (हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक तुलना बता रहा था कि वह कहां पांच हजार, साढ़े पांच हजार करोड़ रूपये का भुगतान चार किस्तों में करते थे और हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 13,320 करोड़ और 12,000 करोड़ रूपये का भुगतान एकमुश्त एक-एक किस्त में की है। उसके बाद वे किसानों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। तथ्य जनता के सामने सादन के माध्यम से आना चाहिए। पिछले सवा साल में किसानों को जो भुगतान हुए हैं, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। धान खरीदी के माध्यम से वर्ष 2023-2024 एवं 2024-2025 में दोनों खरीदी वर्षों को मिलाकर कुल 94,915 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पी.एम. किसान सम्मान निधि योजना की ओर से 2,328 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) कृषि से जुड़े हुए जो हमारे भूमिहीन कृषक मजदूर साथी होते हैं, उन्हें दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 562 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है। गन्ना बोनस के रूप में 125 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) गन्ना के एम.एस.पी. के रूप में दोनों वर्षों में क्रमश: 375 करोड़ और 210 करोड़ रूपये का भुगतान हुआ है। हमारी सरकार ने 13 दिसंबर की तारीख को शपथ लिया और 13 दिसंबर की तारीख के मात्र 12 दिन बाद 25 दिसंबर को श्रद्धेय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी, छत्तीसगढ़ के संस्थापक की जयंती आई और हमने मोदी की गारंटी के तहत् मात्र 12 दिनों बाद 13 लाख किसानों को 3,716 करोड़ रूपये का भुगतान किया। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तथ्यों के साथ सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सवा साल में हमारी सरकार ने किसानों को कुल एक लाख करोड़ रूपये से अधिक का भुगतान किया है। (मेजों की थपथपाहट) इतना बड़ा भुगतान हमारी सरकार ने किसानों के किया है इसलिए जनता का आर्शीवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को और हमारी पार्टी को मिल रहा है। थोथे वादों से और अनावश्यक ब्लेम गेम की राजनीति से जनता त्रस्त हो गई है और जो डिलीवर कर रहा है, उसको जनता आशीर्वाद दे रही है। अभी बहुत चर्चा हो रही थी। अभी आदरणीय उमेश पटेल जी नहीं हैं। वे चर्चा कर रहे थे, फिर राघवेन्द्र भाई भी कुछ Financial data पर बात कर रहे थे, उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। जो विकास की दर है, हम लोगों ने आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। वर्ष 2024-2025 में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जी.एस.डी.पी. (सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि दर 7.51 प्रतिशत रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.37 प्रतिशत रही है। डाटा स्पष्ट कहता है, आंकड़े स्पष्ट कहते हैं कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में हमारा छत्तीसगढ़ एक प्रतिशत से ज्यादा और तेजी से विकास कर रहा है। वहीं वर्ष 2023-2024 के लिए भी मैं आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहूंगा क्योंकि वर्ष 2023-2024 में लगभग 9 माह कांग्रेस सरकार का कार्यकाल था। वर्ष 2023-2024 में भारत की जी.डी.पी. वृद्धि की राष्ट्रीय औसत थी,

वह 8.15 प्रतिशत थी, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ की 7.31 प्रतिशत थी अर्थात राष्ट्रीय औसत से हमारे प्रदेश की विकास दर वर्ष 2023-2024 में कमजोर थी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह तथ्य आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूँ, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, तीनों क्षेत्रों में इस वर्ष 2024-2025 में राष्ट्रीय औसत के साथ हम तीव्रता से विकास कर रहे हैं, जो हमारी सरकार के सुशासन के प्रयासों से ही संभव हो पा रहा है । अध्यक्ष महोदय, भाई राघवेन्द्र जी ने एक तथ्य रखा था कि हमारे 70 प्रतिशत और कई आंकड़े 80 प्रतिशत तक बोलते हैं कि किसानों की संलग्नता खेती से है, उसका जी.डी.पी. में कांट्रीब्यूशन कान्सटेंट प्राईज में 17 परशेंट के आसपास ही बैठता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य को और पूरे सदन को बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की भागीदारी जी.डी.पी. पर बढ़ती जाती है, इसलिये परशेंटेज टर्म में कृषि का जो योगदान है, वह कम होता है । अध्यक्ष महोदय, आज कृषि भी हमारे प्रदेश में 5.38 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, वहीं भारत की राष्ट्रीय औसत 3.76 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है । अध्यक्ष महोदय, हमारी निश्चित रूप से 70-80 प्रतिशत आबादी है, वह कृषि पर निर्भर है । हमको उस आबादी को सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों की ओर उस जनसंख्या को हमको शिफ्ट करने की जरूरत है, ताकि हम विकसित छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से आगे बढ़ सकें और हमारे कम लोग कृषि में संलग्न रहें तो भी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ, ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता के साथ, इस बात को आगे की विकास की रणनीति को हमको तय करने की जरूरत है ।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ । बोलने का विषय उस कम्पेरिजन को सिर्फ यही था कि जब 70 से 80 प्रतिशत हमारी जो जनसंख्या है, वह कृषि में है । यहां जरूरी नहीं है कि सब खेती में जाये । अलाईड एक्टिविटीज, कृषि से जुड़े हुये उद्योग की एक्टिविटीज में उनकी सहभागिता बढ़ानी जरूरी है, यह मेरा आपसे निवेदन था, जो आपकी पॉलिसी में आना चाहिये ।

श्री ओ.पी.चौधरी :-अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य के इन विचारों से निश्चित रूप से पूर्णत: सहमत हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में हम लगातार प्रयास करेंगे । अध्यक्ष महोदय, उमेश पटेल जी ने और राघवेन्द्र जी ने एफआरबीएम जो एक्ट है, उसके संबंध में कुछ चिंतायें जाहिर की थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फायनेंस के आर.बी.आई. के, एफ.आर.बी.एम. कमेटी के जो गाईड लाईन्स हैं, उसके हिसाब से टोटल लोन जी.एस.डी.पी. के 25 परशेंट से एक्सीड नहीं करनी चाहिये । यह निश्चित रूप से फायनेंस कमीशन का टारगेट है, यह गाईड लाईन है । अध्यक्ष महोदय, उमेश पटेल जी कुछ ऑकड़े बता रहे थे कि 28 परशेंट, 29 परशेंट तक रिवाईज्ड एस्टीमेट में चला गया है, मैं आपके माध्यम से प्रदेश को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि फायनेंस कमीशन का कोई भी गाईड लाईन है या

भारत सरकार को कोई भी गाईड लाईन है, आर.बी.आई. का कोई भी गाईड लाईन है, उसको अक्षरश: पालन करेंगे, मैंने बजट भाषण के माध्यम से भी यह बात स्पष्ट किया है । अध्यक्ष महोदय, जो ग्रास लोन रहता है, उसमें एससीए यानी स्पेशल कैपिटल असिसटेंस और जी.एस.टी. लोन को माईनस करके नेट लोन निकाला जाता है और उसी को भारत सरकार सारे पैरामीटर्स पर काऊंट करती है । अध्यक्ष महोदय, मैं उस दृष्टिकोण से स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ का वर्तमान में जो रेश्यो है, वह 19 परशेंट के लगभग ही बैठता है, 25 परशेंट से हम काफी अच्छी तरह से सेफ स्थिति में फायनेंशियली बने हुये हैं । अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके बाद भी अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते समय बताया था कि 19 हजार करोड़ रूपये का अनुपूरक बजट सम्मානनीय सदन में तृतीय अनुपूरक के रूप में प्रस्तुत किया था । अध्यक्ष महोदय, जब यह अनुपूरक बजट बना रहे थे तो मैंने कहा था कि उस समय भी मेरे मन में कन्फ्यूशन था कि एक तरफ हम राजस्व घाटे का 7000-8000 करोड़ का ...।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एफआरबीएम की जो कल बात हुई थी, हम लोगों ने जो ऑंकड़े रखे थे कि यह 28 परशेंट और 29 परशेंट के आसपास जा रहा है । आप उस पर अगर कह रहे हैं तो आप ही का डेटा कहता है कि 29.6 परशेंट पर यह है । अगर वह आंकड़े 20 से नीचे है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आसपास है तो उसका एक्जैक्ट डेटा हम लोगों को उपलब्ध करवा दें क्योंकि हम लोगों के आंकड़े और जो सरकारी आंकड़े जो अभी छपे हैं, वह 28 या 29 प्रतिशत के आसपास जा रहा है । यदि आपका कहना है कि वह 20 प्रतिशत से नीचे है तो वह सराहनीय भी है, लेकिन उन आंकड़ों को हम लोगों को उपलब्ध करवा दें क्योंकि मेरी जो समझ कहती है कि टोटल Outstanding Liabilities से अगर हम GSDP को Divide करते हैं, तब वह बात आती है तो अगर Special Assistance की बात है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वह आंकड़ें आप हमें उपलब्ध करवा दें ।

श्री ओ. पी. चौधरी :- निश्चित रूप से । सी.ए. के आंकड़े, Special Capital assistant के आंकड़े और जो GST loan है, उसको Minus करके ही भारत सरकार या RBI या Finance commission calculate करते हैं और इस मामले में मैं बताना चाहूंगा कि हमने 19 हजार करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट रखा था, उस समय मेरे मन में यह विचार था कि Loan न लें, राजस्व आधिक्य भी पूरे साल दिखाएं। जो GSDP की 3 प्रतिशत की जो सीमा है, उसका पूरा पालन करके दिखाएं। मैं व्यक्तिगत स्तर पर बड़ी वाहवाही ले सकता था, लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि राज्य का हित और व्यक्तिगत प्रशस्ति में राज्य हित को ही हमको चुनना चाहिए और हमने भी वही चुना ।

अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के द्वारा बजट में कई जगहों पर गड्डे किए गए थे, पर हमने पिछली बार यह तय किया कि उन गड्डों को पाटें, भले ही इससे हमारे Revenue Defecate दिखे और हम फिर भी FRBM के सारे Criteria को fulfill कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें पिछली बार हमने Road Development corporation loan को चुकाने का काम, पुलिस हाऊसिंग के लोन को चुकाने का काम, जीएडी क्वाटर्स बनाने के लिए हाऊसिंग बोर्ड द्वारा लिए गए लोन को चुकाने का काम, लोन के रि-पेमेंट के काम, इन सारे कामों को हमने किया क्योंकि आगे-पीछे वे विकास के रास्ते में गड्डे बनकर हमारे मार्ग को अवरूद्ध कर दें । जब लोन की इतनी सारी बात होती है तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि off Budget स्टेट गारंटी से कितने लोन थे, जब पिछली सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ, वह भी सदन के समक्ष होना चाहिए । Off Budget loan जो इस लोन के डेटा में जब 2023 की बात की जाती है तो नहीं आता, उसमें मार्कफेड का लोन 18,800 करोड़ रूपए, उसमें नॉन का भुगतान 3770 करोड़ रूपए पेंडिंग था, 2023 की स्थिति में *Fortified Rice* का भुगतान 85 करोड़ रूपए पेंडिंग था, चना का भुगतान 450 करोड़ रूपए पेंडिंग था, नमक का भुगतान 85 करोड़ रूपए पेंडिंग था । शक्कर का भुगतान 45 करोड़ रूपए पेंडिंग था, गुड का भुगतान 50 करोड़ रूपए पेंडिंग था, पीडीएस डीलरों के मार्जिन का भुगतान 170 करोड़ रूपए लंबित था । स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रूपए का भुगतान लंबित था, Medicine और Medical equipment के supply का भुगतान 700 करोड़ रूपए पेंडिंग था, ऊर्जा विभाग में Three face electricity जो कृषि पम्प के लिए दिया जाता है, उसका भुगतान 2200 करोड़ रूपए लंबित था और other जो off budget loans थे, उसका भुगतान 7100 करोड़ रूपए लंबित था । पिछली सरकार के लोन के जो भी डेटा हैं, उसमें off budget loan और राज्य के ऊपर जो Liability थी, वह 34,970 करोड़ रूपए की अतिरिक्त Liability थी । इस बुनियाद पर और इस विरासत पर हम छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, महतारी वंदन योजना में बहुत सारी बातें होती हैं । मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि वर्ष 2018 में कांग्रेस का जन घोषणा-पत्र जो आया था, उसमें प्रति माह माताओं एवं बहिनों को 500 रूपए भुगतान का वादा लिखित में कांग्रेस ने किया था, लेकिन इन 5 सालों में एक भी माता या एक भी बहिन को 5 रूपए तक का भी भुगतान कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। जब हमारी सरकार आई है और यहां पर बहुत सारी बातें होती है तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज किस राज्य में कितने कवरेज के साथ महतारी वंदन योजना चल रही है । छत्तीसगढ़ में Project Population के हिसाब से माताओं और बहनों की संख्या लगभग 1 करोड़, 53 लाख मानी गयी है । उस हिसाब से हम 70 लाख माताओं और बहिनों को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं । यह माताओं और बहिनों के कुल जनसंख्या की तुलना में लगभग 46 प्रतिशत है, जबकि इसमें 1 साल से 21 साल तक की माताएं और बहिनें इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं। इसी तरह से झारखण्ड जहां पर कांग्रेस के समर्थन की सरकार चल रही है, वहां पर कुल 52 लाख लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा

है । वहां की माताओं और बहिनों की कुल जनसंख्या 1 करोड़, 96 लाख है । वहां योजनाओं का प्रतिशत केवल 27 प्रतिशत है । कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहॉ पर कुल जनसंख्या 7 करोड़ 71 लाख है और उसमें से 1 करोड़ 21 लाख लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है और योजना का percentage मात्र 39% है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इस योजना से जिन माता-बहनों को जोड़ा गया है, वह किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक है, इस बात का ज्ञान हमारे सदन को और सभी सम्मानित सदस्यों को होना चाहिए। इस योजना के माध्यम से माता-बहनों की जिन्दगी में किस प्रकार से परिवर्तन आया है, उसे आज गांव-गांव, गली-गली में देखा जा सकता है। सम्माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी बीच में आरोप लगा रहे थे कि सरकार असत्य बोल रही है, महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के किसी भी कार्यक्रम में जहां माता-बहनें हों, हाथ खड़ा कराकर कोई भी देख सकता है क्योंकि वहां 90% से अधिक माता-बहनें हाथ खड़ा करती हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे आगे बढ़ते हुए, कल जैसा सम्माननीय सदस्य राघवेन्द्र जी बोल रहे थे कि उन्हें अन्य गतिविधियों से भी जोड़ा जाना चाहिए, यह अच्छा विषय है और इस दिशा में हमारी सरकार मुख्य मंत्री जी और हमारी महिला बाल विकास मंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। महतारी शक्ति ऋण योजना बैंक द्वारा प्रारंभ की गई है और उसके माध्यम से बिना mortgage के 25 हजार रुपए के लोन देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें आज हजारों महिलाएं लोन लेकर आर्थिक रूप से अपने पैर पर खड़ी हो रही हैं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में जो दानसरा गांव है, उन दानसरा गांव में जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण माता-बहनें कर रही हैं, वह इस योजना की सफलता और इसके अन्य आयामों को भी बताता है कि किस तरह इस योजना ने माता-बहनों का आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सशक्तिकरण किया है और परिवार के भीतर भी उन माता-बहनों के मान-सम्मान को बढ़ाने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में डी.ए. के संबंध में एक और महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा। अभी बजट में हमने एलान किया है कि अप्रैल माह का जो भुगतान होगा, वह भारत सरकार के बराबर के डी.ए. 53 प्रतिशत के साथ होगा। आज हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार 53 प्रतिशत डी.ए. दे रही है। ऐसी स्थिति में मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस शासित राज्यों के क्या हालात हैं। हिमाचल प्रदेश में कॉग्रेस की सरकार है और वहॉ पर खटाखट पार्टी वाले 42 प्रतिशत डी.ए. दे रहे हैं। कर्नाटक में कॉग्रेस की सरकार है और वहॉ पर 45 प्रतिशत डी.ए. दिया जा रहा है। पंजाब में इंडी गठबंधन अर्थात् इन्हीं के दोस्त-यार लोगों की सरकार है और वहॉ पर 42 प्रतिशत डी.ए. दिया जा रहा है। तेलंगाना में जहॉ इनके खुद की कॉग्रेस की सरकार है, ये खटाखट पार्टी वाले 26 प्रतिशत डी.ए. दे रहे हैं और वेस्ट बंगाल जहॉ इंडी गठबंधन के पार्टनर वाले चला रहे हैं, वहॉ पर मात्र 14 प्रतिशत डी.ए. दिया जा रहा है। तो यहॉ पर दुनियाभर की ब्लेम-गेम की राजनीति करने से पहले खटाखट पार्टी वालों को अपनी खुद की पार्टी की सरकारों द्वारा देश में क्या किया जा रहा है, उसकी भी चिन्ता करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज आदरणीय मुख्य मंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की वित्तीय चुनौतियों के बीच काम कर रहे हैं और पूरा प्रयास है कि चाहे 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर 21 क्विंटल धान की खरीदी हो, उसका एकमुश्त भुगतान हो, उसे हम पूरा कर रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, 26 इंच सीना वाले सरकार ला सुन लो, 15 लाख ला घलो हिसाब करव ये मेर। 15 लाख करके बात करे रहिन तेला, 56 इंच सीना वाला ल।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, अनर्गल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति का लोकतंत्र में जनता जवाब देती है और दे रही है। पूरे देश में दे रही है कि देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी वर्ष 2001 में पहली बार किसी सरकारी पद पर आए। पहली बार वह गुजरात राज्य के मुख्य मंत्री बने और वर्ष 2001 से 2025 तक लगातार 24 सालों तक या तो वे राज्य के प्रमुख मुख्य मंत्री रहे या देश के प्रमुख प्रधान मंत्री रहे और उन्होंने राजनीति में anti-incumbency की अवधारणा को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। अनर्गल आरोप लगाने से भारत देश की जनता-जनार्दन को गुमराह नहीं किया जा सकता। यह इसका उदाहरण है। विपक्षी पार्टी के लोग एक भी उदाहरण दिखा दे, जब आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने यह कहा हो कि मैं 15 लाख रूपये किसी खाते में डालूंगा। यह बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है और इसी का जवाब देश की जनता ने बार-बार दिया है।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, वीडियो है। आप कलेक्टर रहे हैं। आप सुन लीजिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आपके गृहमंत्री जी ने बोला था कि यह तो जुमला है।

श्री रामकुमार यादव :- मोदी जी हा कहिसे कि ये देश के पैसा हा विदेश में जमा हे।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, आपके गृहमंत्री जी ने कहा कि यह जुमला है।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ी में एक कहावत हे कि मार दे धकेल, धकेल के। ओ हर का कहिसे कि यहां के पैसा विदेश में जमा हे, ओला लाबो तो प्रति व्यक्ति ला 15-15 लाख रूपये मिल सकत हे। आपके मंत्री जी के द्वारा अइसने बात कहे गे हे।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में इस बात का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जवाब अगर कोई देता है और माना जाता है, तो वह जनता जनार्दन का जवाब होता है। इस बात का जवाब देश की जनता जनार्दन ने एक बार नहीं तीन बार हैट्रिक आशीर्वाद देकर नरेन्द्र मोदी जी को दे दिया है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राघवेन्द्र जी बोल रहे थे कि हम देश में सेल्फ रिलायंट की ओर आगे बढ़े। निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा बिंदु है। लेकिन उन्होंने राजीव गांधी जी के रिफरेंस से यह बात कही थी। राजीव गांधी जी की माता जी ने 1970 में गरीबी हटाओ का नारा लगाया था लेकिन गरीबी हटाओ नारे को रखते हुए जुमला वाली जो बात है, वह कहीं न कहीं इंदिरा

गांधी जी की गरीबी हटाओ वाले नारे पर लागू होती है। यदि गरीबी हटाने का वास्तविक अर्थों में किसी ने प्रयास किया है तो नरेन्द्र मोदी जी ने उसे एक नई ऊंचाई में ले जाकर प्रयास किया है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इस बात पर मेरी आपत्ति है कि जो इस सदन का हिस्सा नहीं है, आप उनकी बात कहकर उनको नेगेटिव्ह कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने जुमला किया या नहीं किया। यह तो फैक्च्यूअल फिगर पर बात हो सकती है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा। यह तो तथ्य और फैक्ट्स हैं। यह इस सदन की बात नहीं लेकिन देश की बात है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोलते थे। मैं उनका नाम नहीं लेता हूं, नाम को छोड़ देता हूं। इनकी पार्टी के नेता बोलते थे कि खटाखट खटाखट पेमेंट होगा। तो आखिर क्यों कर्नाटक में 4 महीने से गृह लक्ष्मी योजना का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? इन्हें इस बात का जवाब इस देश की जनता को देना चाहिए।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप यह तो बता दीजिये कि आप 500 रूपये सिलेण्डर कब देंगे ? वह भी आपका ही वायदा था।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आलू से सोना बनाने वाले बाबा तो बोल सकते हैं ना ?

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- मंत्री जी, यह बात इस सदन में बार-बार की जा चुकी है कि यह वक्तव्य नरेन्द्र मोदी जी का है। यह राहुल गांधी जी का वक्तव्य नहीं है। आदरणीय उमेश पटेल जी ने कहा है कि हम वीडियो पटल पर रख देते हैं। हम पूरा वीडियो देख लेते हैं। आप बार-बार सदन को गुमराह करना और असत्य बोलना बंद करिये।

श्री रामकुमार यादव :- यह सब असत्य बात है। यही तो आप मन के पार्टी के खासियत हे। आप लोग गुमराह करना बंद करें।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप पटल पर वीडियो रखवा लीजिये। पूरी बात सामने आ जायेगी। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- (व्यवधान) कोई सबूत हो तो। लेकिन यह बार-बार गुमराह करना बंद करिये। आपके गृहमंत्री बोलते हैं कि पहले इंटर करिये फिर बी.कॉम. करिये। आप उसको कैसे भूल गये ?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं विधान सभा के 22वें बजट में शामिल हो रहा हूं और कई प्रकार की सरकारें यहां थीं। हर वित्त मंत्री कंपेरिज़न करके ही बतायेंगे। आपकी कर्नाटक की सरकार में आपने वायदा करके नहीं दिया। पंजाब की सरकार में आपने क्या किया ? कहां की सरकार में हमसे ज्यादा है, कहां हमसे कम है ? वह तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से यहां पर आंकड़ा देना ही पड़ेगा।

उसमें आपको बुरा क्यों लग रहा है ? आपकी पार्टी के नेता ने कर्नाटक में बोला था कि खटाखट देंगे। कहां है खटाखट ? सफाचट है, सफाचट है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सारे वित्तीय नॉर्म्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है और इस अवसर पर मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की पिछली सरकार के समय जो एक Vicious circle चलता था। वह एक पूरा Vicious circle था। यहां बहुत सारे सम्मानीय सदस्य नये हैं लेकिन वह भी दूर से देख रहे थे। वह किस तरह का Vicious circle था ? आदरणीय अजय चन्द्राकर जी अपने वक्तव्य में बोल रहे थे कि कैसे सरकार के खजाने के पैसे को खजाने से बाहर निकालकर भ्रष्टाचारियों की जेब में पहुंचाने का काम किया जा रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, जेब में पहुंचाने का नहीं। वह डायरेक्ट बैठकर सरकार के खजाने से लूटते थे। शराब के घोटाले में यही हुआ था। दो रैक लगती थी, एक सरकारी सप्लाई की और एक गैर सरकार सप्लाई की। वहां का पैसा सीधा आता था जो अभी टिकट मांगने के लिये नियम बदलवाया गया था। करोड़ों रूपये वहां से आता था।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सुशासन पर भरोसा करती है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सुशासन के माध्यम से आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमने पिछली बार भी किसी टैक्स में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की। इस बार भी हमने पेट्रोल के दाम में 1 रूपये की कटौती की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार भी हमने पंजीयन का जो शुल्क होता है, उसमें स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर 12 प्रतिशत का जो सेस लगता है उसको समाप्त किया है। (मेजों की थपथपाहट) इन सब छूटों के बाद भी अगर इस वित्तीय वर्ष 2024-2025 में हमारे पंजीयन की जो आय है, अगर वह 19 प्रतिशत बढ़ता है हमारा परिवहन में जो आय है, अगर वह 17 प्रतिशत बढ़ता है तो अगर हम जी.एस.टी. में देश के Best Performing Three States में हैं। निश्चित रूप से कल कंसर्न, आदरणीय राघवेन्द्र भाई बता रहे थे कि जी.एस.टी. में जो लक्ष्य है उससे हम कम हैं। मैं निश्चित रूप से यह स्वीकार करता हूँ कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें वेट के मामले में कमी है। जी.एस.टी. में भी थोड़ी कमी है, लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि हमने पिछली बार 35 प्रतिशत का बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। उसके कारण हम लक्ष्य से कम दिखते हैं, लेकिन आज आप फरवरी माह तक के डेटा को निकालकर देखेंगे तो पूरे देश के Best Three performing states में जी.एस.टी. के इंक्रीमेंट में, ग्रोथ में हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश है। इस तरह से हमारे सारे इंकम बढ़ रहे हैं केवल और केवल गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन के माध्यम से बढ़ रहे हैं। उसी सुशासन के माध्यम से बढ़े हुए पैसे को हम महतारी वंदन योजना में दे रहे हैं। हम किसानों को दे रहे हैं, हम प्रधान मंत्री आवास में दे रहे हैं। हम भूमिहीन मजदूरों को दे रहे हैं, हम रामलला दर्शन करा रहे हैं। साथ ही साथा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बजट को भी दोगुना बढ़ा रहे हैं। (मेजों की

थपथपाहट) ताकि इंवेस्टमेंट हो,यहां औद्योगिक विकास हो, हम उन सब पक्षों को ध्यान दे सकें। सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अभी यह कह रहे थे कि गोल्फ हो गया, गोल्फ में क्या होगा? क्या कोई गोल्फ खेलना जानता है ? जब हमको किसी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होता है तो बहुत सारे इंवायरमेंट क्रियेट करने पड़ते हैं। आपके माध्यम से सम्माननीय सदन और नेता प्रतिपक्ष जी को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि देश के बहुत सारे Developed country ऐसे हैं बहुत सारे देश के अंदर के भी इंवेस्टर्स ऐसे हैं जहां गोल्फ नहीं रहता तो वह इंवेस्ट करने नहीं जाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। मैं जापानियों, कोरियाई लोगों का उदाहरण देना चाहूंगा। जापान के लोग वहां जाकर इंवेस्ट ही नहीं करते हैं जहां पर कोई गोल्फ नहीं रहता है। ऐसे देश के अंदर भी अनेक लोग हैं, अनेक इंवेस्टर हैं एक इंवेस्टर फ्रेंडली माहौल बने। हमारे छत्तीसगढ़ को आपने भी महसूस किया होगा। हम भी यह महसूस करते हैं हम कभी दिल्ली में बोलते हैं हमें बहुत दु:ख के साथ यह कहना पड़ता है। आप कहां से हैं तो हम यह कहते हैं कि छत्तीसगढ़ से हैं। अचानक कोई बोल देता है कि अच्छा-अच्छा, जो बिहार से अलग हुआ है। कभी यह बोलते हैं कि अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से हैं उसकी राजधानी रांची है क्या? इस तरह से हमको Perception problem से अनेक बार जूझना पड़ता है। कई बार हम बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं तो कई व्यक्ति बोलते हैं कि आप वहां सुरक्षित रहते हैं या नहीं? हमने कहा कि नहीं-नहीं। मैं तो रायपुर में रहता हूँ तो यह कहते हैं कि वहां भी सुरक्षित रहते हैं या नहीं? हमको कई बार इस Perception problem से गुजरना पड़ता है। यह अर्थव्यवस्था में किसी राज्य के लिए, पर्यटन के विकास के लिए, इंवेस्टमेंट के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए बाधक होता है इसलिए अपने प्रदेश, राजधानी को राष्ट्रीय नक्शे पर लाना बहुत जरूरी होता है। अगर रायपुर में गोल्फ टूर्नामेंट हो रहे हैं तो यह छत्तीसगढ़ और हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को राष्ट्रीय मैप पर लाने का एक प्रयास है। (मेजों की थपथपाहट) मैंने अपने बजट भाषण में वेडिंग डेस्टीनेशन (Wedding destination) पर जो बात लिखी थी । सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष जी थोड़ा उपहास कर रहे थे। मैं, आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूँ कि Wedding destination बनाने से अमीर शादी यहां आएंगे, अमीर जो पैसा कमाया है अगर उसे अर्थव्यवस्था में खर्च कराकर, गरीबों तक पहुंचाया जाता है तो उस व्यवस्था की तारीफ की जानी चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) अगर एक अमीर, धनाड्य व्यक्ति करोड़ों रूपये जो कमाया हुआ है, अपने बेटा या बेटी की शादी में अगर हमारे छत्तीसगढ़ आता है और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आकर शादी करता है तो उससे फूल, टेंट, वेटर, सफाई वाले को रोजगार मिलता है। यही अर्थव्यवस्था को विकसित कराने की रणनीति है। अमीर व्यक्ति से पैसा निकले और गरीबों तक वितरीत हो। इस तरह का कोई भी काम हो।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप):- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की मंशा यह थी कि वह बैंकाक में क्यों खर्च न करें ?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने क्या कहा ? मैं समझ नहीं पाया ?

श्री केदार कश्यप :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैंने यह कहा कि कुछ लोग बैंकॉक में खर्च करते हैं उनसे यह कहिए कि यहां रायपुर आएं।

डॉ. चरणदास महंत :- क्या रायपुर में बैंकाक जैसी व्यवस्था हो गई है ?(हंसी)

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र में इस तरह से अलग-अलग तरीके से गति दी जाये, छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास किया जाये और छत्तीसगढ़ के गरीबों को उसका लाभ पहुंचे सके, यह रणनीति है। मैं चाहता हूं कि एक सकारात्मक, रचनात्मक विपक्ष के रूप में इस तरह के प्रयासों को विपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री जी आरोप लगा रहे थे कि केन्द्र सरकार अडंगा लगाती थी। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जब वर्ष 2018 में हमारी पार्टी की आपके नेतृत्व में सरकार थी, तब धान खरीदी में सेन्ट्रल पूल का चावल का कोटा 24 लाख मीट्रिक टन था और 36 लाख मीट्रिक टन धान से अर्थात दो तिहाई जो चावल निकलता है, 36 लाख मीट्रिक टन धान से निकले हुए 24 लाख मीट्रिक टन धान को केन्द्र की सरकार सेन्ट्रल पूल में लेती थी। अध्यक्ष महोदय, लेकिन केवल दो साल के अंदर उस 24 लाख मीट्रिक टन चावल का कोटा केन्द्र ने बढ़ाकर 61 लाख मीट्रिक टन किया था। (मेजों की थपथपाहट) एक गैर भा.ज.पा. शासित राज्य में केन्द्र की नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ढाई गुना की वृद्धि किया था। 61 लाख मीट्रिक टन चावल अर्थात लगभग 93 लाख मीट्रिक टन धान के चावल को सेन्ट्रल पूल के माध्यम से लिया जाता था। अगर पिछली सरकार के समय में धान खरीदी हो पाई तो उसके लिए अगर किसी को क्रेडिट देना चाहिए तो केन्द्र की सरकार को देना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- चौधरी साहब, मैं आप ला याद दिलाना चाहव हवं, वही आप के केन्द्र ला सरकार कहे रहिस हे कि अगर 2100 रुपये समर्थन मूल्य में धान लोगे तो मैं आपके सेन्ट्रल पूल में धान के चावल को नहीं खरीदूंगा। इहू ला बता दिहा। ओकर लिये हमला आप के केन्द्र सरकार के डर मा अलग से योजना बनाये लाहिस रहे हवय।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत वह धान का अतिरिक्त पैसा देते रहे, उसके बाद भी केन्द्र सरकार ने 24 लाख मीट्रिक टन चावल के कोटे को लगभग ढाई गुना बढ़ाकर 61 लाख मीट्रिक टन चावल का कोटा किया था। (मेजों की थपथपाहट) 61 लाख मीट्रिक टन चावल मतलब 93 लाख मीट्रिक टन धान होता है। इनके आखिरी साल में 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, उसे अगर छोड़ दिया जाये तो पिछली सरकार के समय अधिकतम धान खरीदी 95 लाख मीट्रिक टन ही हुई थी। उस 95 लाख मीट्रिक टन में से अधिकांश धान

का चावल अगर किसी ने लिया है तो सेन्ट्रल पूल में लिया गया है इसलिए यह धान खरीदी कर पाये। अगर इसका क्रेडिट हम सबको देना चाहिए तो केन्द्र की सरकार को देना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- चौधरी जी, वर्ष 2019-20 की धान खरीदी हुई, जो भी किये, 85 हजार टन धान सड़ा या नीलाम किये। कितना घाटा हुआ, वह आज नहीं बता पा रहे हैं। 40 हजार टन अभी भी निस्तारण के लिए बाकी है, वह 40 हजार टन धान कहां पर है? कल के मेरे प्रश्न में है और यह बोले कि जब तक उसका निस्तारण नहीं होगा, तब तक हम कितना घाटा हुआ, उसको नहीं बता सकते। अभी उसमें आप जांच करवाईये। इनकी कारगुजारी दिखेगी कि धान का खेल कैसे किये थे।

श्री ओ.पी.चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज धान खरीदी पर तरह-तरह के सवाल उठाते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लास्ट एक साल की खरीदी को छोड़ दें तो अधिकतम धान खरीदी 95 लाख मीट्रिक टन थी। मैं आखिरी साल के धान खरीदी की बात करूं तो 1 करोड़ 20 मीट्रिक टन ही धान खरीदी थी। पिछले साल की हमारी सरकार के नेतृत्व में जो धान खरीदी हुई, उसमें 1 करोड़ 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई जो छत्तीसगढ़ में एक नया रिकॉर्ड था। (मेजों की थपथपाहट) इस साल की जो धान खरीदी हुई है, 1 करोड़ 49 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान खरीदी हुई है। हमने 25 लाख 49 हजार किसान भाईयों से 1 करोड़ 49 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। उसके लिए 31 जनवरी तक धान की खरीदी चली और मात्र 7 दिन बाद 7 फरवरी की तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने एक साथ 12 हजार करोड़ रुपये release करने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, उस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में थे, उन्होंने जब यह घोषणा की तो उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि आज मैंने भाषण में स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि पैसा चला जाएगा, वह किसानों के खाते में पहुंचेगा कि नहीं ? तो मैंने भी घबराकर बैंक को फोन लगाया कि किसानों के खाते में यह पैसा आज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ? तो बैंकवालों ने कहा कि सरकार से 12 हज़ार करोड़ रूपए तो हमको release हो गया है लेकिन इतना बड़ा amount है कि एक दिन में Computer process ही नहीं कर पाएगा और किसानों के खाते में जाने के लिए कम से कम लगभग दो दिन का समय लगेगा । इतनी बड़ी राशि अगर एकमुश्त किसी ने किसान भाइयों के खाते में अंतरित की है तो हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने की है । (मेजों की थपथपाहट) जो लोग 5 हज़ार- 6 हज़ार करोड़ रूपए को चार किस्तों में एक-एक, डेढ़-डेढ़, दो-दो हज़ार करोड़ रूपए करके भेजते थे उनको क्या पता चलेगा कि एक दिन में 12 हज़ार करोड़ रूपए Computer process नहीं कर पा रहा था ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नक्सलवाद पर भी बहुत सारी बातें कही । उन्होंने कहा कि हमने भी प्रयास किया था । अभी मुझे याद आता है कि बीजापुर में लगभग 22 जवानों की शहादत हुई थी और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी असम के चुनाव में उस शहादत की खबरें

टीवी में आने के बाद road show कर रहे थे । (शेम-शेम की आवाज) पूरे 5 सालों में उनके खुद के बयानों में नक्सलवाद को लेकर, नक्सलियों को लेकर इतना विरोधाभास रहा जिसके कारण जनता तो confuse रही ही रही, बस्तर में फोर्स भी confuse रही और किस तरह से Operation ठप्प पड़ गए थे, इसे सब कोई जानते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे उप मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से एक साल के अंदर सैकड़ों की संख्या में नक्सली मार गिराए गए, हज़ार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया । इसके अलावा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बस्तर में Home stay policy लाना, बस्तर को नैचुरोपैथी की दिशा में आगे बढ़ाना, धुड़मारास जैसे गांव को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय map पर लेकर आना, Nursing College की परिकल्पना करना, Physiotherapy College की परिकल्पना, पहले आपके नेतृत्व के समय में Education city की स्थापना करना, छू-लो आसमान project चलाना, नन्हें परिंदे जैसे project चलाना, पोटा केबिन चलाना, लाईवलीहुड कॉलेज चलाना, प्रयास विद्यालय चलाना, आज इतने सारे प्रयासों के बलबूते पर...।

अध्यक्ष महोदय :- इन्हीं योजनाओं का क्रियान्वयन जब आप जिलाधीश थे उसी का फल आपको अभी मिल रहा है ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आशीर्वाद है । इस तरह के प्रयासों के कारण बस्तर में पूरा परिवेश बदला है, पूरी एक ऊर्जा आई है और हम सब मिलकर के नक्सलवाद की समाप्ति करके बस्तर में एक नये विकास का अध्याय इस कार्यकाल के अंदर ही लिखेंगे । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शेयर मार्केट की भी बात कर रहे थे । 96 लाख करोड़ रुपए डूब गए, यह भी बात कर रहे थे । मैं परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सार्वजनिक बहस शेयर मार्केट में करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, लाईव रहेगा । (मेजों की थपथपाहट) मोदी जी के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को कैसे तेजी मिली है, देश के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में और स्टॉक मार्केट में भी उसकी गूंज कैसे सुनाई पड़ी है ? इसके लिए एक विश्लेषण की ज़रूरत है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. की सरकार थी । वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक के 10 सालों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. की सरकार थी । वर्ष 2004 में भी हम दुनिया में 10वें नम्बर की अर्थव्यवस्था थे और 10 साल बाद वर्ष 2014 में भी हम 10वें नम्बर की ही अर्थव्यवस्था में हैं । वर्ष 2014 से 2024 तक मोदी जी ने जब काम किया तो वर्ष 2014 की 10वें नम्बर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगाते हुए हम 5वें नम्बर की अर्थव्यवस्था में आ गये । (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- चौधरी साहब, अभी नीचे आ गे हे ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में हम वर्ष 2024 में बने और मोदी जी के इस कार्यकाल के 5 वर्षों के भीतर हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जायेंगे । (मेजों की थपथपाहट) 5वें नम्बर की अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में हमें गुलाम बनाने वाले देश ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ा । (मेजों की थपथपाहट) आज इन 5 सालों में हम जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ने के लिए खड़े हैं । पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस निफ्टी की बात कर रहे थे, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब अप्रेल 2020 में कोविड आया था तो भारत देश की स्टॉक मार्केट का निफ्टी 7611 था । जिस दिन मार्केट ने लो बनाया था। 23 मार्च, 2020 को देश की निफ्टी का स्तर 7611 था। वहां से छलांग लगाते हुए इन साढ़े 4 सालों के लगभग अंतराल में हमारे देश के स्टॉक मार्केट की निफ्टी 7611 से ऊंचाई की छलांग लगाते हुए 26,000 के इंडेक्स को पार करी है। (मेजों की थपथपाहट) 26,000 से जब करेक्ट हो कर आज की तारीख में 22,300 पर निफ्टी खड़ी है और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने नेता का अनुसरण करते हुए बोलते हैं कि 96 लाख करोड़ रुपए डूब गए। जिस दिन भी मार्केट का fall आता है, उस दिन ये विश्लेषण करने लगते हैं कि इतना पैसा कम हो गया। अध्यक्ष महोदय, जाकर देश के inverstors के portfolio का अध्ययन करें। उन्होंने कोविड के fall से लेकर इन पांच सालों में कितना wealth बनाया है? उनमें से छोटा एक inverstor मैं भी रहा हूं, जो बोल रहे थे। आज 22,000 की निफ्टी पर यूं cry कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, देश की जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2004 से 2014 तक देश की देश की इकॉनामी की हालत कैसी थी? देश के बैंकों की हालत कैसी थी? बैंकों में किस तरह का बबल था? इसे आज देश की जनता को समझने की जरूरत है। वर्ष 1947 से वर्ष 2008 तक के 61 सालों में भारत देश की बैंकिंग व्यवस्था ने कुल 16 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया था। वर्ष 1947 से वर्ष 2008 के 61 वर्षों में भारत देश की बैंकिंग व्यवस्था ने 16 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया था।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, विजय मालिया तुम्हर पैसा लेके भाग गेहे, निकाल लो।

अध्यक्ष महोदय :- आपको समझा नहीं आएगा। आप थोड़ा बैठिए।

श्री ओ.पी. चौधरी :- वर्ष 1947 से वर्ष 2014 तक 61 सालों में 16 लाख करोड़ रुपए का लोन देश की बैंकिंग व्यवस्था ने दिया था। वर्ष 2008 से 2014 तक यू.पी.ए. टू के कार्यकाल के मात्र 06 सालों में 18 लाख करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया और वह लोन कैसे दिए गए? मोबाइल बैंकिंग होती थी। आका लोगों का फोन आता था। कोई भी बैंक किसी को भी कितनी भी राशि दे दिया करती थी। देश के एक बैंकर थे, राणा कपूर। मुझे पता नहीं, नाम ले सकता हूं या नहीं ले सकता, उस राणा कपूर जी ने..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मान लीजिए कि आप किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं, जिसको आकर सफाई देने की जरूरत पड़े, ऐसे छोड़कर सारे नाम आप ले सकते हैं। राणा कपूर का नाम लें तो उसकी पेंटिंग ढाई करोड़ रूपये में बिकी थी न? अब भी राणा कपूर की पेंटिंग की खरीदी-बिक्री हो रही है ।

श्री ओ.पी. चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, राणा कपूर, इनकी शहजादी पता नहीं क्या पेंटिंग बनाती हैं कि 2 करोड़ रूपये में इनकी शहजादी की पेंटिंग को खरीदा था। देश में अकाउन्ट में विस्थापित तथ्य है। इस तरह की बैंकिंग व्यवस्था चलायी और अगर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो पी.एस.यू. बैंकिंग इंडेक्स को आज आकर स्टडी करें, सदन में उसका ग्राफ दिखाएं कि वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक पी.एस.यू. बैंकिंग इंडेक्स कहां से कहां 10 सालों तक धराशायी हुई थी? मोदी जी के समय में वह पी.एस.यू. बैंकिंग सेंसेक्स इंडेक्स आज कहां से कहां पहुंचा है?

श्री रामकुमार यादव :- 10 लाख के सूट ला कोन पहनथे?

श्री ओ.पी. चौधरी :- इस तरह के अनावश्यक ब्लेम गेम की राजनीति से बचना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज 3.7 ट्रिलियन डॉलर की हमारे देश की इकॉनामी है और हमारे भिलाई में स्कूलिंग पढ़ाई किए हुए एक इकोनॉमिस्ट हैं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे। उन्होंने अब एक पुस्तक लिखी है, India@100. भारत आजादी के 100 सालों में 2047 तक कहां होगा? उन्होंने आकलन किया कि आज 3.7 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनामी 55 ट्रिलियन डॉलर इकॉनामी पहुंचेगी। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, क्या मैं एक बात अपनी बोल सकता हूं? आदरणीय आप जो बोल रहे हैं, आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत भी हूं और असहमत भी। आप जो ट्रिलियन पर बार-बार एक जोर डाल रहे हैं। अगर आप शुरू से इकॉनामी के फिगर्स को देखेंगे तो ये power of compounding भी है। हम उसको क्यों जाते हैं? अगर इंडियन इकॉनामी की अगर बात करें तो पहले कितने सौ करोड़ की थी? फिर कितने हजार करोड़ की आई, वह कितने लाख करोड़ की हुई? फिर ट्रिलियन की तरफ जो आ रही है, उसमें power of compounding भी है और वह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के आ जाने के बाद वह ट्रिलियन नहीं हो गई। उसके पहले उन नंबर्स का एक लंबा सफर रहा है और ये बात मुझसे आप बेहतर फिगर्स को जानते हैं, आप मुझसे बेहतर संख्याओं को समझते हैं तो इस बात को सिर्फ ये न कहा जाए कि ये ट्रिलियन इकॉनामी आने में suddenly मोदी जी का हाथ आ गया। उसके पहले की भी एक गाथा है। कहां से इकॉनामी शुरू हुई, कितने rural debt से शुरू हुई और कहां तक आई, ये तो इकोनॉमिक्स का power of compounding है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको हम क्यों भूल जाते हैं?

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य पावर ऑफ कम्पाउंडिंग की बात कर रहे हैं । वारेन बफे ने कहा है पावर ऑफ कम्पाउंडिंग वह 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड । निश्चित रूप से मैं उससे

सहमत हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि कहां गई थी वह कम्पाउंडिंग जब 1947 से हम 40 साल तक आगे बढ़ते बढ़ते 1991 में गए थे और सोने को गिरवी रखकर हमको देश की अर्थव्यवस्था को बचाना पड़ा था। क्या उन 44 सालों में देश की इकोनॉमी को कम्पउंडिंग करने का अवसर नहीं मिला था ? क्या 1947 से लेकर 1990 के बीच में साउथ कोरिया की इकोनॉमी ने नया इतिहास नहीं रचा था । क्या उस पीरियड में दुनिया के अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं ने नए कीर्तिमान् नहीं रचे । उसकी भी जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी ? 1991 में क्यों देश को इस परिस्थिति में आना पड़ा था । अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राघवेन्द्र भाई कल कह रहे थे कि सबके कंट्रीब्यूशन को हमको याद करना चाहिए । आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबके कंट्रीब्यूशन को याद करना चाहिए । 1947 से लेकर जिस भी तरह की पॉलिसी हमने अपनाई, उसकी हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए । 1991 के जाते-जाते किस तरह की पेथेटिक सिचुवेशन में हमारी इकोनॉमी पहुंची थी । उस 1991 के समय जो न्यू इकोनॉमिक रिफार्म लाया गया, उसके लिए मैं आदरणीय पी.व्ही.नरसिम्हा राव जी की, आपके माध्यम से तारीफ भी करना चाहता हूं । वे कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे फिर भी मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं कि उनका पॉलिटिकल विल था कि देश में इकोनॉमिक रिफार्म्स लागू हो सके । लिबरलाजेशन की पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी, ग्लोब्लाइजेशन की पॉलिसी आ पाई । वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी जरूर थे मगर मेजर रिफार्म्स हुए थे वे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एण्ड कॉमर्स में हुए थे और वह डिपार्टमेंट उस समय पी.व्ही.नरसिम्हा राव जी के पास था । उन्होंने सारे रिफार्म्स इंट्रोड्यूज़ किए थे । उन्होंने देश की इकोनॉमी को एक नई दिशा देने के लिए पायनियर स्टेप उठाकर काम किया । लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चौधरी जी, पी.व्ही. नरसिम्हा राव जी की आपने प्रशंसा की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई । ये बेचारे कांग्रेस वाले उसको दो गज जमीन नहीं दिए ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, नरसिम्हा राव जी की मैं तारीफ कर रहा हूं । निश्चित रूप से उनके कंट्रीब्यूशन को आज मैं याद कर रहा हूं । लेकिन मैं आप के माध्यम से सदन में विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं कि हमारी तो छोड़िए क्या अपनी पार्टी के अंदर के पी.व्ही.नरसिम्हा राव जी के कंट्रीब्यूशन को इन्होंने रिकोग्नाइज़ किया ? आज देश के सामने पूरी तरह से सवाल यह है, हमारे विपक्षी साथियों को इस बात पर मंथन करना चाहिए ।

श्री लखेश्वर बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इनको प्रमोशन करके संसद भवन भेज दीजिए । यहां के लायक नहीं लग रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वित्त का काम संसद से ही जुड़ा है ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- यहां के तो पूरे तार वहीं से जुड़े हैं चाहे कोयला का हो या आयरन-ओर का हो । सब तार वहीं से जुड़े हैं ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि उन पी.व्ही. नरसिम्हा राव जी के कंट्रीब्यूशन को भी कांग्रेस ने कभी रिकेग्नाइज़ नहीं किया । उनकी मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस कार्यालय में भी नहीं रखने दिया गया । उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में नहीं करने दिया गया । उनके पार्थिव शरीर को आंध्र प्रदेश भेज दिया गया । सबके अलग-अलग स्थल बने लेकिन उनके अंतिम संस्कार स्थल को कांग्रेस ने नहीं बनाया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- और उनकी लाश भी पूरी नहीं जली थी, चपरासी के भरोसे छोड़कर आ गए थे । अधजली लाश पड़ी थी हुसैन सागर के तट पर ।

श्री ओ.पी.चौधरी :- अध्यक्ष महोदय, रेडी-टू-ईट पर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री के नेतृत्व में हम लोग माताओं को बहनों को यह काम सौंप रहे हैं । पूरे सिस्टम को इन्होंने बदलकर रख दिया था । पहले चरण में पांच जिलों में यह काम चालू किया गया तो उस पर माननीय पूर्व मुख्यमत्री जी आपत्ति कर रहे थे । मैं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, हालांकि यहां नहीं हैं, आखिर क्या बात थी कि छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों के हाथ से छीनकर एक ठेकेदार के हाथ में उन्होंने इस काम को क्यों दे दिया, क्या मजबूरी थी, उनके पास किसका फोन आया था ? यह भी सदन को बताना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, आज विभिन्न विषयों को रखने का प्रयास किया । इस बजट में हमने GYAN के कल्याण के लिए गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण के लिए GATI की रणनीति की बात की है । हमारे बजट का मूल थीम है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में रणनीति होनी चाहिए । अगर हमको GYAN का कल्याण करना है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी का कल्याण करना है, अगर हमको समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति का कल्याण करना है, अगर हमको अंत्योदय करना है, अगर हमको समावेशी विकास करना है तो आर्थिक विकास जरूरी है। जब हम आर्थिक विकास करेंगे तभी गरीब कल्याण के लिए आर्थिक व्यवस्था में वित्तीय प्रबंधन कर सकते हैं। जब हमारा आर्थिक विकास नहीं होगा तो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं आगे न पीछे कोलैप्स कर जाएंगे। इस बात को हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भली-भांति समझती है, इसीलिए हमने GATI की रणनीति पर यह बजट प्रस्तुत किया है। GATI की रणनीति में Good Governance सबसे इंपारटेंट कंपोनेंट माना है। Infrastructure को आगे बढ़ाना हमने Important components माना है। Technology और Industrial Growth को हमने Important components माना है। अध्यक्ष महोदय, ये केवल GATI की रणनीति की शाब्दिक बिन्दु नहीं है, केवल भाषण के बिन्दु नहीं हैं, आप इस पूरे बजट को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में Good Governance के लिए हमने किस-किस तरह के कदम उठाए हैं। हमारा प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन करके स्पष्ट किया कि सुशासन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज इस तरह के सैकड़ों स्टेप पिछले सवा सालों में आप देख सकते हैं कि हमने Good

Governance को कितना फोकस किया है। यही Governance है जिसके परिणामस्वरूप बिना टैक्स बढ़ाए हमारे कलेक्शन में इंप्रूवमेंट हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमने Infrastructure पर बात की, ये केवल बजट का नारा मात्र नहीं है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 2 हजार करोड़ रूपए के नये सड़कों का प्रावधान हुआ है। PWD के बजट में 20 प्रतिशत का ग्रोथ हुआ है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के बजट में 19 प्रतिशत की ग्रोथ है। हम एक साथ बात कर रहे हैं कि पांच हजार करोड़ रूपए आगामी वर्षों में खर्च करके सिंचाई की पुरानी लंबित परियोजनाओं को ठीक करने का काम करेंगे। उसको पूरा करने का काम करेंगे और एक लाख नये कृषि भूमि हेक्टेयर को सिंचित बनाने का काम करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) हम Infrastructure प्रयासों के तहत् मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना की बात कर रहे हैं, 500 करोड़ रूपए का प्रावधान उस योजना के अंतर्गत किया गया है जो 14 नगर निगमों के लिए ही है जिसके तहत् हम शहरी Infrastructure को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। किसी भी इकॉनमी के ग्रोथ का सेंटर अर्बन सेंटर होता है, हम अर्बन सेंटर से जब इकॉनमी में पैसा जनरेट करते हैं तब ग्रामीण क्षेत्रों की भलाई कर सकते हैं। देश का अर्बन सेक्टर 3 प्रतिशत एरिया में ही है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में, जी.डी.पी. में 60 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन अर्बन एरिया का है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नवा रायपुर, रायपुर इन सब अंचल को एक अर्बन ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित करें। इसके लिए हम स्टेट केपिटल रिजन की रणनीति के साथ इस बजट में आए हैं और इस बार स्टेट केपिटल रिजन का ऑफिस उसका सेटअप भी लेकर आए हैं।

अध्यक्ष महोदय, Infrastructure के तहत् महानदी, इंद्रावती जैसी नदियों को जोड़ने के लिए, अन्य अनेक नदियों को जोड़ने के लिए हम सर्वे कराने का काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेट्रो एक अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी जरूरत है, रायपुर से लेकर दुर्ग तक मेट्रो के विकास के लिए हम लोग सर्वे कराने का संकल्प लेकर इस बजट में आए हैं। इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के बजट में दोगुना वृद्धि हुई है। इंडस्ट्री सब्सिडी के बजट में लगभग तीन गुना की वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, पुरानी सरकार की 700 करोड़ रूपए की पुरानी सब्सिडी पेंडिंग थी, ये क्या इंडस्ट्रीयल डेपलपमेंट करते। उन 700 करोड़ की इंडस्ट्री सब्सिडी को भुगतान करने का काम हमने पिछले सवा साल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। GYAN के कल्याण के लिए GATI हमारी रणनीति है। हमने अनेक प्रकार की इनोवेटिव प्रोजेक्ट भी इस बजट में लेने का प्रयास किया है। जो हमारी कृषक उन्नति योजना है या प्रधानमंत्री आवास योजना है या महतारी वंदन योजना है, हम इन सबको पूरा करेंगे ही, इसके अलावा हमने मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना जो छोटे-छोटे अर्बन सेंटर हैं, उनके लिए सोचकर आए हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमने इस बजट में 17 स्थलों पर नालंदा परिसर के निर्माण की बात की है। आज रायपुर में बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान स्थापित हो गए। अब उस कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए हम निफ्ट की बात कर रहे हैं, हम जल्द ही निफ्ट को स्थापित करके दिखाएंगे। हमने इसी

बजट में 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। नवा रायपुर में मेडीसिटी की स्थापना, नवा रायपुर में एजुसिटी की स्थापना, नया रायपुर में डेटा सेंटर का मार्ग प्रशस्त हो गया है। नया रायपुर में सेमीकंडक्टर का मार्ग प्रशस्त हो गया है। फोर्स ला एंड आर्डर की दृष्टि से हम NSG की जगह पर Special operation group स्थापित करने जा रहे हैं। इंडस्ट्रीयल ला एंड आर्डर को इंश्योर करने के लिए CISF की तर्ज पर SISF (State Industrial Security Force) की स्थापना करने जा रहे हैं। हम बस्तर में होम स्टे पॉलिसी लेकर आए हैं। पिछली सरकार ने तीर्थयात्रा योजना को बंद कर दिया था, उसे हमने पुन: प्रारंभ किया है। हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत सारे प्रयास किये हैं। विशेषकर फिजियोथैरिपी के 6 सेंटर खोलना उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, जितनी 1 फिजियोथैरिपी सेंटर को 1 साल में 1 से बढ़ाकर 7 कर देना है। (मेजों की थपथपाहट) इसी तरह से आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में 8 नर्सिंग कॉलेज खुले थे। उस 8 की संख्या को बढ़ाकर हम 20 तक ले जाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमने पूरा प्रयास किया है कि इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विकास को नई ऊंचाई व नई दिशा दी जाये। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि हाथ से लिखे हुए बजट में कई विसंगतियां हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा और सभी सदस्यों व विपक्ष के उन सदस्यों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस हाथ से लिखे गये बजट के लिये मुझे appreciate, motivate और प्रेरित किया। अध्यक्ष महोदय, हाथ से लिखना कोई विशेष बात या अलग बात नहीं है, लेकिन मैं अपने emotions, जो मैं feel कर रहा था, उसे लिखना चाहता था। (मेजों की थपथपाहट) आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कुछ 92 नंबर के पृष्ठ पर जाकर मैंने कोई शब्द अंग्रेजी में लिखा है, उसके लिए बोल रहे थे कि भाषा का ध्यान नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, उनकी स्पीच की वीडियो को आप भी देख सकते हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी के भाषण के समय मैं केवल 5-7 मिनट तक अवलोकन कर रहा था कि वह हिंदी में भाषण दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कितनी बार अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया तो 7 मिनट के अंदर मैंने observe किया कि उन्होंने हिंदी के अधिकारी शब्द का प्रयोग न करके उसको officer शब्द बोला, उन्होंने business management बोला, उसके लिए उन्होंने हिंदी शब्द नहीं बोला, masters शब्द बोला, उसके लिए कोई हिंदी शब्द नहीं बोला, top शब्द बोला, उसके लिए कोई हिंदी शब्द नहीं बोला, विश्वविद्यालय की जगह पर university बोला।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सर, वह हिंग्लिश चलता है। उसको हम लोग मान लेते हैं। आपने हिंग्लिश में कहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, एक मिनट। यह अंग्रेजी और हिंदी के बारे में क्या बोलेंगे? यदि आप पेपर हटा लेंगे तो हिंदी का भाषण अंग्रेजी में लिखा रहता है। यह एक शब्द न अंग्रेजी बोल पाएंगे और न ही हिंदी बोल पाएंगे। आपको बोलने का पॉवर है। कई बार राज्यपाल महोदय ने भी वहां पर बोला है और 50 बार अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग किया है।

श्री ओ.पी. चौधरी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने B.E. शब्द का प्रयोग किया। bachelor of engineering के लिए हिंदी शब्द लेकर वह नहीं आये। B.Tech. शब्द का प्रयोग किया। bachelor of technology के लिए हिंदी शब्द लेकर वह नहीं आये। M.Tech. शब्द का प्रयोग किया, master of technology उसके लिए वह हिंदी शब्द लेकर नहीं आये। portal शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए हिंदी शब्द लेकर नहीं आये। fix शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए हिंदी शब्द लेकर नहीं आये। अध्यक्ष महोदय, आप वीडियो को देख सकते हैं। मैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से भी निवेदन करूंगा कि वह अपनी वीडियो को स्वयं देखें। अध्यक्ष महोदय, बोलचाल की भाषा में लगता है कि यदि कोई अंग्रेजी शब्द ज्यादा समझ में आएगा तो इस उद्देश्य से मैंने कई शब्दों को अंग्रेजी में लिख दिया है। यदि मेरी गलती है तो मैं उस गलती को स्वीकार करता हूं। लेकिन मैंने एक emotions के साथ इस स्पीच को लिखा था। इस बात को मैंने यहां पर रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी इस चर्चा में भाग लेने वाले हमारे पक्ष एवं विपक्ष के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं। विपक्ष की ओर से आदरणीय उमेश पटेल जी, आदरणीय राघवेन्द्र जी, आदरणीय दलेश्वर साहू जी, आदरणीय संगीता सिन्हा जी, आदरणीय रामकुमार यादव जी, आदरणीय द्वारिकाधीश यादव जी, आदरणीय देवेन्द्र यादव जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय चरणदास महंत जी ने विपक्ष की ओर से इस चर्चा में भाग लिया। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे सत्ता पक्ष की ओर से परम आदरणीय अमर अग्रवाल जी, आदरणीय राजेश मूणत जी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष व इस सदन के सदस्य किरण देव जी, आदरणीय सुनील कुमार सोनी जी, आदरणीया भावना बोहरा जी, आदरणीया गोमती साय जी, आदरणीय अजय चंद्राकर जी, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने भी सत्ता पक्ष की ओर से इस चर्चा में भाग लिया है। मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब बजट भाषण प्रस्तुत हुआ, उसके बाद आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि कविता पाठ खत्म हुआ, कवि सम्मेलन खत्म हुआ। इस तरह से वह एक उपहासजनक स्वर और बॉडी लैंग्वेज के साथ कह रहे थे। किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी समाज के जीवन में और किसी राष्ट्र के जीवन में साहित्य और कविता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज में सकारात्मकता अंधकार से घिरे हुए किसी व्यक्ति या समाज के जीवन में प्रकाश की तलाश, निराशा और हताशा से डुबे हुए व्यक्ति को आशा, उत्साह और ऊर्जा कोई दे सकता है तो कविता और साहित्य दे सकता है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी बहुत अच्छी कविताएं सुनाई और हम सबने मेजें थपथपाकर उनका अभिवादन किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैंने वीर नारायण गुण्डाधुर जी के शौर्य की चर्चा की, उनको उस बात से समस्या थी ? घासीदास जी के समानता का विषय उठाया, उस

बात उनको समस्या थी ? छत्तीसगढ़ की तुलना चारों धाम से की, इस बात से उनको समस्या थी ? मैंने रग-रग हिन्दू को व्याख्यित किया, उस बात से उनको समस्या थी ? मैं छत्तीसगढ़ को माता कौशल्या की भूमि कहा, उस बात से उनको समस्या थी ? माता सीता के वनवास के समय इस माटी ने उन्हें शरण दिया, इस बात उनको समस्या थी ? बाल्मिकी के तपोभूमि छत्तीसगढ़ को कहा, इस बात उनको समस्या थी ? दोनों हाथ उठाकर छत्तीसगढ़ की माटी के लिए नमन किया, इस बात उनको समस्या थी ? उनको इस बात का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ी की बात [xx] के रूप में करना और छत्तीसगढ़ की भावनाओं को दिल में अपनाकर चलना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को जवाब देना चाहिए कि इन बातों में से किन बातों से समस्या थी ?

अध्यक्ष महोदय, साहित्य और कविता हमें जीवन में प्रेरित करती है। चाहे विपक्ष के साथी भी उसे सकारात्मक अर्थों में लेकर आयेंगे तो हम विपक्ष का भी Appreciate करेंगे और हमारे पक्ष के साथी लेकर आयेंगे तब भी हम उसे Appreciate करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) केवल आलोचना के लिए आलोचना, केवल राजनीति के लिए आलोचना उचित नहीं है। विपक्ष के रूप में लोकतन्त्र में सकारात्मक भूमिका विपक्ष निभायें, यह मैं निवेदन करता हूं। इस बजट में हमने छत्तीसगढ़ के बेहतर भविष्य को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ सुनिश्चित करने की हमारी रणनीति को रखने का हम लोगों ने प्रयास किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दीर्घकालिक लक्ष्य 2047 को प्राप्त करने के लिए, मध्यकालिक लक्ष्य 2030 को प्राप्त करने के लिए और हर साल के लक्ष्य को बजट के माध्यम से प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अच्छे बजट और उसके बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिए बधाई।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार दिनांक 06 मार्च, 2025 को 11.00 दिन तक के लिए स्थगित।

(सायं 6 बजकर 57 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 06 मार्च, 2025 (फाल्गुन-15, शक संवत् 1946) को पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छ.ग.) **सचिव**

दिनांक : 05 मार्च, 2025 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**